

सोवियट रूस का आर्थिक विकास

बी० सी० टण्डन

असिस्टेन्ट प्रोफेसर

वाणिज्य विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

WUS BOOK BANK
WORLD UNIVERSITY SERVICE
ALLAHABAD UNIVERSITY



गर्ग ब्रदर्स १, कटरा रोड, प्रयाग

प्रकाशक
गर्ग ब्रदर्स
१, कटरा रोड
इलाहाबाद

प्रथम संस्करण
फरवरी १९६०
—मूल्य ६।।

मुद्रक
आर० एन० गर्ग
गर्ग प्रेस, प्रयाग

विषय-सूची

खण्ड 'अ'

अध्याय

५०

प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व रूस की प्रारम्भिक प्रगति (१८१७-१८२७) (१-७६)

१. सोवियट संघ—एक परिचय १-८
२. अक्टूबर १९१७ की क्रान्ति तथा उसके पूर्व रूस की अर्थव्यवस्था ९-३०
३. नियन्त्रित पूँजीवाद युग—क्रान्ति के बाद प्रथम आठ महीने ३१-४१
४. युद्ध कालीन साम्यवाद (जून १९१८ से मार्च १९२१) ४२-५४
५. नवीन आर्थिक नीति (१९२१-१९२८) ५५-६५
६. आर्थिक विकास के प्रारम्भिक वर्ष तथा कैची रूपी संकट ६६-७६

खण्ड 'ब'

सोवियट रूस की योजनात्मक प्रगति (१९२७-१९६५) (७७-१६५)

७. सोवियट रूस में प्रारम्भिक नियोजन ७७-८२
८. प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-१९३२) ८३-१०२
९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९३३-१९३७) १०३-११६
१०. तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९३८-१९४२) ११७-१२२
११. द्वितीय महायुद्ध काल में आर्थिक स्थिति तथा नियोजन १२३-१२९
१२. चौथी पंचवर्षीय योजना (१९४३-१९५०) १३०-१४६
१३. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (१९५१-१९५५) १४७-१६१
१४. छठी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६०) तथा सप्तवर्षीय योजना (१९६१-१९६५) १६२-१६५

खण्ड 'स'

सोवियट संघ की अर्थव्यवस्था का संगठन तथा संचालन	(१६६-२६८)
१५. सोवियट कृषि संगठन तथा संचालन	१६६-२१८
१६. औद्योगिक संगठन एवम् नियोजन संचालन	२१९-२२७
१७. यातायात साधन	२२८-२३३
१८. सोवियट ट्रेड यूनियन संगठन	२३४-२४४
१९. सोवियट रूस में सामाजिक सुरक्षा	२४५-२५१
२०. सोवियट रूस का विदेशी व्यापार तथा नीति	२५२-२६४
२१. सोवियट अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन	२६५-२८०
परिशिष्ट	२८१-२९४
Bibliography	२९५-२९८

नक्शे

	पृष्ठ
मशीन-निर्माण उद्योग	१७४
कृषि-क्षेत्र का घनत्व एवम् प्रमुख कृषि पदार्थ	१८२
सोवियट संघ में विद्युत्	१९१
प्रमुख खाद्यान्न एवम् टेक्स्टाइल उद्योग	१९३

सोवियट संघ--एक परिचय

(१)

विश्व की वर्तमान दशा को देखते हुए सभवतः यह सोचना व समझना कठिन है कि सोवियट रूस केवल गत ४० वर्षों में एक अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्र बन गया है। कुछ समय पहिले अमेरिका या पश्चिमी योरप की दूसरी शक्तियाँ यह मानने को तैयार भी न थीं कि सोवियट रूस विश्व की प्रधान शक्तियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U. S. A.) का भ्रम था कि सोवियट रूस एक पिछड़ा हुआ निर्धन देश है जिसका साम्यवाद के मार्ग पर पतन निश्चय है। पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यह भ्रम अब दूर हो गया है, क्योंकि खुशचेव का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हाल का निमंत्रण तथा स्वागत ही इस बात का द्योतक है कि अमेरिकन राष्ट्र ने सोवियट रूस को अपने ही समकक्ष शक्तिशाली राष्ट्र मान लिया है। यही नहीं योरप और अमेरिका के दूसरे राष्ट्रों ने भी रूस को एक महान शक्ति का प्रतिरूप समझकर अपनी विदेशी तथा घरेलू नीतियों का हाल में अनेक बार पुनर्संगठन भी किया है।

सोवियट रूस के विषय में कुछ लिखना सरल नहीं है। यह एक ऐसा देश है जिसके बारे में लोगों को अब भी पूरा ज्ञान नहीं है। सोवियट रूस के विषय में अनेक भ्रामक धारणायें अभी भी प्रचलित हैं। वास्तव में सोवियट रूस ने पिछले कुछ ही वर्षों में जो चमत्कार दिखलाये हैं उन पर विश्वास करना साधारण व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। १९२८ के बाद से रूस की योजनात्मक प्रगति प्रारम्भ हो गई थी। यद्यपि १९४२-४५ के बीच सारी अर्थ व्यवस्था एक बार अस्त-व्यस्त हो गई, फिर भी १९४५ के पश्चात् पुनः विशाल उत्पादन तथा विज्ञान के चमत्कार ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। जान गंधर ने लिखा है कि जब अमेरिका में उन्होंने लोगों को बतलाया कि

“सोवियट संघ ने गत वर्ष २७,०००,००० वोटलें अच्छी शैम्पेन का उत्पादन तथा उपभोग किया, उनको एक भीपण आघात पहुँचा।”^१ न्यूयार्क में एक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत महिला से सेंट होने पर जब उन्होंने उसे बतलाया कि सोवियट संघ अपने लिए आवश्यक मोटर गाड़ियाँ (automobiles) स्वयं निर्मित करता है, उसकी सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। हममें से कितने लोगों को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष सोवियट संघ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा चार गुने अधिक डाक्टर डिग्री प्राप्त करते हैं ? केवल अँग्रेजी पढ़ाने के लिए गत वर्ष ४^१ हजार शिक्षक सोवियट संघ में थे और २,०००,००० विद्यार्थी सोवियट कालिजों में शिक्षा पा रहे थे जबकि सारे पश्चिमी योरप के देशों को मिलाकर भी विद्यार्थियों की संख्या इतनी न थी। मास्को विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी को केवल निःशुल्क ही शिक्षा नहीं मिलती बल्कि सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। रूस ने अमेरिका से पहिले हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया तथा अनेक स्थानों पर अणुशक्ति का प्रयोग भी कर रहा है, जब कि दूसरे देशों में यह सुविधा अब तक न हो सकी है। रूसी राकेट के आविष्कारों ने सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि रूसी विज्ञान के आविष्कार तथा खोज प्रशंसनीय हैं, और इस बात को सिद्ध करते हैं कि रूसी वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको रिसर्च से भक्ति है और वे एक निश्चित उद्देश्य तथा लगन से एकाग्रचित्त होकर काम कर रहे हैं।

दूसरी ओर उपभोक्ताओं की दशा चिन्ताजनक है। खुशचेव ने स्वीकार किया है : “यह उचित होगा अगर मार्क्स के सिद्धान्तों में सुधार करने के साथ-साथ रोटी एवम् मांस के टुकड़े का भी प्रबन्ध किया जावे।” उपभोग पदार्थों की न्यूनता लोगों को साम्यवाद का दूसरा रूप दिखला रही है। जब खुशचेव अभी हाल में अपने परिवार सहित वाशिङ्गटन में उतरे उस समय सोवियट राकेट लुनिक तृतीय के चौदह तक पहुँचने का समाचार अमेरिकन लोगों को विस्मित कर चुका था। वे सोवियट रूस की इस आश्चर्यजनक, अतुल्य तथा अद्वितीय उन्नति से बहुत ही प्रभावित थे। पर यह भी किसी से छिपा न रहा कि खुशचेव परिवार की महिलायें अत्यन्त गंवारू लबादा (“dowdy garments”) पहिने थीं जिससे सोवियट रूस के उपभोग क्षेत्र में असफलता भी साफ भलक रही थी। यह रूस के दो परस्पर विरोधी पहलू हैं। एक ओर तो शिल्प कला, विज्ञान, बृहत् उद्योग इत्यादि का अनूठा उत्थान और दूसरी ओर सोवियट रूस

१. John Gunther : Inside Soviet Russia (Hamish Hamilton, London, 1958)

की आवश्यक उपभोग पदार्थों के प्रति उदासीनता, निर्पेक्षता तथा उनकी अत्यधिक न्यूनता ।

सोवियट रूस की आर्थिक प्रगति का इतिहास पढ़ने का एक विशेष कारण उपर्युक्त चित्र के परस्पर दोनों विरोधी पहलू हैं । अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानना चाहता है कि वास्तव में रूस की अर्थ व्यवस्था कैसी है और क्या प्रदर्शित करती है । उसे मालूम होना चाहिए कि रूस का स्थान विश्व की महान शक्तियों में इतना ऊँचा होने के क्या कारण हैं और उसने इस स्तर पर पहुँचने के लिए क्या-क्या बलिदान किए हैं । इसके अतिरिक्त सोवियट रूस विश्व के इतिहास में पहला ऐसा देश है जिसकी शासन व्यवस्था, ऐसा कहा जाता है, कि सर्वहारा वर्ग के हाथों में (dictatorship of proletariat) है जिसने समाजवाद को स्थापना करके पूँजीवाद का पूरा उन्मूलन कर दिया है और जो आधुनिक युग में पूर्ण साम्यवाद की ओर अग्रसर है । स्पष्ट है कि इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इस विषय पर कम से कम इतनी जिज्ञासा तथा अनुराग अवश्य दिखलायेंगे जितना १८८९ की क्रान्ति के बाद फ्रांस के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षित समाज उत्सुक था । यही कारण है कि सोवियट रूस का आर्थिक इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका वर्तमान काल में बड़ा महत्त्व है ।

सोवियट रूस १९१७ के पहले एक पिछड़ा हुआ देश था जो देखते ही देखते एक शक्तिशाली, प्रगतिशील राष्ट्र बन गया है । पिछड़े हुए तमाम देशों के लिए यह एक चेतावनी है । रूसी व्यवस्था की नींव एक ऐसा विचारधारा है जिसकी अपनाने का प्रलोभन भी और जिससे भय भी है । एशिया के प्रत्येक निर्धन देश का दृष्ट इस समय सोवियट रूस का आर है । जिसने थोड़े से वर्षों में ही अपने सम्पूर्ण देश का कायाकल्प कर दिया है । प्रत्येक देश यह जानना चाहता है कि सोवियट रूस का उन्नति का मूल कारण क्या है, उसके क्या तरीके हैं, उसका कैसा क्षमता है, क्या विशेषता है और किस दिशा में उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है ।

(२)

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम काल तक रूस की आधी से अधिक जनसंख्या खेती से बँधी थी । रूस में 'आधीन कृषकों' की दशा मध्यकालीन पश्चिमी योरोप में 'आधीन कृषकों' की दशा से कहीं अधिक खराब थी । वे पशुओं की भाँति पाले जाते थे । १८६१ के मुक्त विधान (peasant emanci-

paration laws) द्वारा किसानों को उतनी भूमि अवश्य दे दी गई थी जितनी उन्हें खेती करने के लिये 'कुलक' से मिली थी। पर इससे कोई सुधार न हुआ, बल्कि देश में बड़ा असंतोष था। इस समय रूस के सम्राट ('ज़ार') का भी जनता पर अन्याय काफी बढ़ गया था। उसका विश्वास था कि हिंसा तथा दमन से ही अप्रम क्रान्ति को रोका जा सकता है। १८७२ में मार्क्स की महान् पुस्तक "कैपिटल" के प्रथम भाग का अनुवाद रूसी भाषा में प्रकाशित हुआ। देश में पूँजीवाद का विस्तार भी बढ़ गया था। क्रान्तिकारी घटनाएँ भी उतनी बढ़ गयी थीं तथा राजनैतिक एवम् आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी कि फरवरी १९१७ को ज़ार ने निराश होकर शासन की बागडोर "ड्यूमा" (संसद) को सौंप दी। राजधानी में अराजकता फैली थी। स्थान-स्थान पर लूट तथा बलवा हो रहे थे। बोलशेविक पार्टी के शासन सूत्र पा जाने के बाद भी दशा सुधर न पाई थी। देश में काफी गड़बड़ी थी। श्रमिक समझते थे क्रान्ति द्वारा समाजवाद स्थापित हो चुका था और पूँजीवाद का किसी प्रकार ठहरना असह्य था। लेनिन का विचार था कि क्रान्ति तो केवल एक क्रमोन्नति है, कार्य प्रक्रिया है। "नियन्त्रित पूँजीवाद" एक दूसरी प्रक्रिया है जो उस समय कार्यान्वित होनी चाहिए थी। "नियन्त्रित पूँजीवाद" नीति मई १९१८ के बाद न चल पायी यद्यपि लेनिन ने अनेक प्रकार से लोगों को इस नीति का महत्त्व समझाया। श्रमिकों में भ्रष्टाचार बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने श्रमिक-संघों को कारखानों के प्रबन्ध करने का केवल आश्वासन ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता भी दे दी थी, जिससे वे सीमा से बाहर हो रहे थे और उनमें अराजकता बढ़ गयी थी। वे भूल गये थे कि सोवियट सरकार की स्थापना हो चुकी है। बहुत से काम वे बिना सरकार की अनुमति के कर रहे थे। समाजवाद के सारे सिद्धान्तों का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्रमिक सारे उद्योग, सारा व्यवसाय, सारे क्षेत्र तथा तमाम धन्ये अपने हाथ में ले लेना चाहते थे। वे 'समाजवाद' का यही अर्थ समझते थे। लेनिन ने लोगों को बराबर समझाया कि क्रान्ति के बाद समाजवाद की स्थापना एकदम नहीं हो सकती। यह एक महान् अप्रिम कार्य है जिसमें धीरे-धीरे पूँजीवाद को हटाना होगा और समाजवाद को बढ़ाया जावेगा। इस परिवर्तन में शीघ्रता न होनी चाहिये।

क्रान्ति के आठ महीने बाद तक लेनिन की बराबर यही कोशिश थी कि पूँजीवाद को नियन्त्रित रूप से रक्खा जावे। पर मई में राष्ट्रीयकरण की गति बढ़ चुकी थी। २८ जून १९१८ को सामान्य राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गयी जिसके अनुसार रूस के सारे उद्योग-धन्यों का बिना किसी भेद-भाव के राष्ट्रीयकरण कर

दिया गया। पर यह नीति सफल न हो सकी। इससे बड़ी क्षति पहुँची। लेनिन ने स्वीकार भी किया था कि गत वर्षों में जो कुछ हुआ था वह दीर्घकाल के दृष्टिकोण से अनुचित था। १९२१ के बाद नवीन आर्थिक योजना अपनाई गयी जो पूँजीवाद तथा समाजवाद का मिश्रित समन्वय था। इस नवीन नीति के अन्तर्गत देश ने प्रगति की। वर्ष प्रति वर्ष विकास होता गया। समस्त उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं करती थी। धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि अगर सरकार सारे उद्योगों का प्रबन्ध व संचालन स्वयम् करेगी तो सम्पूर्ण संरक्षण नियोजन द्वारा होना चाहिये। जैसे-जैसे लेनिन तथा उनके साथियों को शासन सम्बन्धी अनुभव हुये उनका विश्वास बढ़ता गया कि देश की अर्थ व्यवस्था बिना नियोजन के नहीं चल सकती है। योजना की रचना केवल धीरे-धीरे सम्भव थी। प्रारम्भ में तो निरीक्षण, अनुभव, विवाद, तर्क इत्यादि द्वारा नियोजन सामग्रियाँ तथा सांख्यिकी संग्रहित की गईं जिनका कुछ समय के बाद सदुपयोग किया गया। गोयलरो (Goelro) नामक एक विद्युत नियोजन आयोग स्थापित हुआ जिसको १९२१ में ही एक राष्ट्रीय योजना आयोग (National Planning Commission) में मिला दिया गया। इस आयोग को “गास-प्लान” (Gosplan) की संज्ञा दी गयी।

चार-पाँच वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद १९२५-२६ में नियन्त्रित अंक (control figures) प्रकाशित हुए। प्रत्येक वार्षिक योजना इसी के आधार पर बनाई गयी। सांख्यिकी की दशा को सुधारने पर अधिक जोर डाला गया और १९२७-२८ तक नियन्त्रित अंकों का परिमाण काफी बढ़ गया। पाँच वर्षों के नियन्त्रित अंकों को मिलाकर पंच वर्षीय योजना तैयार की गई। आज तक जितनी भी रूस ने प्रगति की है उसका श्रेय उन योजनाओं को है जिनका प्रारम्भ १९२८ में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना १९३२ में समाप्त हुई; द्वितीय पंचवर्षीय योजना १९३८ में तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना १९४२ में सफल हुई थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद, १९४६ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई गई। १९५१ में पाँचवीं योजना, १९५६ में छठी योजना तथा अन्त में वर्तमान सप्त वर्षीय योजना ने रूस का चित्र बिल्कुल बदलने का आयोजन किया है। विश्व का प्रत्येक देश और विशेषतया शिक्षित वर्ग इस विषय पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।

(३)

सोवियट संघ विश्व का सर्व महान् राजनैतिक क्षेत्र है जो क्षेत्रफल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रायः तीन गुना बड़ा है। इसके अन्तर्गत १५ गणतंत्र

राज्य हैं। यह विश्व का पहला समाजवादी देश है और इसका शासन एक ही पार्टी द्वारा चलाया जाता है। यह विश्व की कम से कम दूसरी औद्योगिक तथा सैनिक शक्ति है—शायद स्पुटनिक तथा अन्तर महाद्वीपीय ज्ञेयस्त्र (I.C.B.M.) के बाद पहली राजनैतिक सत्ता हो गई है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से सोवियट संघ का विस्तार २२,४०४,००० वर्ग किलोमीटर है जिसकी पश्चिम से पूर्व की न्यूनतम दूरी ६,००० किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की दूरी ४,५०० किलोमीटर है। इसका विस्तार सारे लैटिन अमेरिका से तथा चीन एवम् भारतवर्ष के क्षेत्रफल से भी अधिक है। यही नहीं केवल योरोपीय रूस का क्षेत्रफल शेष योरप के क्षेत्रफल से अधिक है। विश्व के किसी भी देश से इसका आकार दूना है। क्या यह जानकर आश्चर्य न होगा कि मास्को से व्लाडीवोस्तोक (Vladivostok) की दूरी मास्को से न्यूयार्क की दूरी से अधिक है। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के बाद तो सोवियट संघ का आकार और भी बढ़ गया है। उसके अनुसङ्गी देशों की संख्या भी बढ़ गयी है। इस्टोनिया (Estonia) लैटविया (Latvia) तथा लिथुएनिया (Lithuania) जो प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हो गये थे, उनपर उसने पुनः कब्जा कर लिया था। इसी तरह पूर्वी प्रुसिया (East Prussia) भी अब रूस के पास है। बिसारेबिया (Bessarabia) रुथेनियाँ (Ruthenia) फिनलैण्ड (Finland) तथा सुदूर पूर्व में क्यूराइल्स (Kurails) तथा दक्षिण सखालिन (Southern Sakhalin) के द्वीप हैं जो रूस के अधिकार में हैं।

एक नाविक अधिकारी ने हिसाब लगाया है कि सोवियट राष्ट्र का विस्तार १९४५-१९५० में पचास-साठ वर्ग मील प्रति घंटा की दर से बढ़ा है यद्यपि उसी युग में कुछ क्षेत्र उसके हाँथ से चले भी गये हैं जैसे आस्ट्रिया, ग्रीस, ईरान तथा फिनलैण्ड, परन्तु जो भाग रूस के पास बच गये हैं उन्होंने इसकी आर्थिक एवम् राजनैतिक शक्ति बड़ी प्रबल कर दी है। अगर सोवियट रूस की सीमा के अन्दर ही दृष्टि दौड़ावें तो पता चलता है कि कारपेथियन्स से लेकर चीन के किनारे तक यूरोसियन मैदान अनेक प्रकार के प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण है। उत्तरी अक्षांशों पर रूस के कम से कम ५० नगर स्थापित हैं—जिन अक्षांशों पर लोग नक्षों में अधिकतर अपनी दृष्टि ले ही नहीं जाते। समतल मैदानों का कहना ही क्या है! आप हज़ारों मील यात्रा करिये, कहीं भी सौ फीट से ऊँचा आप को कोई भाग नहीं दिखलाई पड़ेगा। बहुत से इतिहासकारों का कहना है, जिसमें स्पेगलर (Spengler) का नाम प्रमुख है, कि इस विशेष गुण ने सोवियट निवासियों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला है। यही नहीं, यूराल के पहाड़ भी रूस के

लिये योरप तथा एशिया के बीच सीमान्त (frontier) का काम नहीं करते, बल्कि वे विस्तृत समतल देश के ऐसे भाग हैं जिनका खनिज सम्पत्ति के लिये अद्वितीय महत्त्व है और जिनकी ऊँचाई भी किसी स्थान पर १६,००० फीट से अधिक नहीं है। सारे देश में कहीं भी प्राकृतिक भूत्त्वक् (natural upheaval) का उभार नहीं है जो किसी भी ओर से सोवियट रूस की सीमा को बाँट सके। मैदान का काफी भाग घने वनस्पति से भरा है। स्टेपिज़ (Steppes) का मैदान है जहाँ की मिट्टी साधारण मिट्टी से कहीं अच्छी है। इसके अतिरिक्त “विशाल कृषक त्रिभुज” (the great agricultural triangle) का प्रदेश अद्वितीय उर्वर तथा साधन सम्पन्न है।

विस्तृत मैदानों पर अनेक नदियाँ बहती हैं जो यातायात के लिये उपयोग की जाती हैं यद्यपि उनमें से अनेक वर्ष के कुछ महीने बर्फ से जमी रहती हैं। विश्व की ६ बड़ी-बड़ी नदियों में से चार सोवियट रूस की ही बड़ी नदियाँ हैं जिनमें ओबि (R. Ob) का स्थान विश्व में चौथा है। वाल्गा नदी (R. Volga) जिसकी क्यूबशेव (Quibyshev) पर चौड़ाई दो मील की है, पश्चिमी प्रदेशों की सिंचाई का अच्छा साधन समझा जाता है।

१९५६ की जनसंख्या के अनुसार रूस की जनसंख्या २००,३००,००० है जो कि सारे विश्व की जनसंख्या का १/१० हिस्सा है। अगर चीन और दूसरे अनुसङ्गी देशों को मिला लिया जावे तो सम्पूर्ण जनसंख्या ६००,०००,००० अर्थात् विश्व की जनसंख्या का १/३ होगा। अनुमान लगाया गया है कि साम्यवादी मत मानने वालों की संख्या विश्व में काफी बढ़ गयी है। अगर सारे रूस के निवासियों को योरप के निवासी माना जावे तो प्रत्येक दो योरप के निवासियों के बीच एक साम्यवादी आ जाता है। विश्व के बहुत से देश रूस की इस प्रगति से चिन्तित हैं। समाज शास्त्र के एक विद्यार्थी के लिये यह एक अच्छा विषय है जिस पर वह जानकारी प्राप्त करे और रूस की अर्थ व्यवस्था के संचालन को समझे। वर्तमान काल में फ्रांस, इटली तथा दूसरे देशों में भी साम्यवादियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यों तो कई ऐसे देश हैं जिनकी नीति साम्यवादी देशों से काफी मिलती-जुलती है जैसे इन्डोनेशिया आदि। रूस की २००,३००,००० जनसंख्या में १,१७,०००,००० श्रमिक हैं और ८३,०००,००० ऐसे कृषक हैं जो सामूहिक खेतों पर काम करते हैं। १९२६ में कृषक बहुमत में थे और आज यह वहाँ का एक अल्प संख्यक वर्ग है। वर्तमान काल में रूस के नगरों में आबादी ८६,०००,००० है जब कि २० वर्ष पूर्व २६,०००,००० से अधिक न थी। सोवियट संघ आज एक देश नहीं है बल्कि ६० विभिन्न जातीय-

ताओं (nationalities) के मिलने से बना । एक ऐसा राष्ट्र है, जिसको पुनः १६९ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । इनमें से २०-२५ प्रतिशत लोग गैर-स्लाव प्रजातियाँ के (non-Slav) हैं और २२ प्रतिशत जनसंख्या “अश्वेत” (non-white) है जिनमें अधिकतर “मंगोल” हैं । इनमें नीग्रो जाति के लोग बहुत ही कम हैं । यद्यपि धर्म सम्बन्धी आँकड़े संकलित करना कठिन है, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग २५,०००,००० मुसलमान (Moslem) और २,५००,००० यहूदी (Jews) हैं । स्पष्ट है कि रूस ऐसा देश है जहाँ अनेक प्रजातियाँ हैं, अथाह भूमि है, भिन्न-भिन्न जलवायु है और नाना प्रकार की प्राकृतिक बनावट हैं । फिर भी रूस एक मत मानने वाला देश है, साम्यवाद की ओर अप्रसर, जहाँ एक राजनैतिक दल है और एक ही विचार-धारा तथा जहाँ एक ही सार्वजनिक योजना है । ऐसा क्यों है ? ऐसा कैसे है ? और क्या यह सब सच है ? यह सब प्रश्न किसके मन में न उठते होंगे । समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिये यह अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है ।

द्वितीय अध्याय

अक्टूबर १९१७ की क्रान्ति तथा उसके पूर्व रूस की अर्थ व्यवस्था

यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि १९१७ के पहले रूस की अर्थ व्यवस्था न तो उन्नतिशाली राष्ट्रों की भाँति अत्यन्त प्रभावशाली थी और न एशिया के पिछड़े हुये देशों की भाँति केवल खेतिहर थी। बल्कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधे अनेक स्थानों पर अच्छी तरह जम चुके थे और उनके उत्पादन व स्वामित्व में एकाग्रता (concentration) भी काफ़ी भाग में आ गई थी। उदाहरणार्थ दक्षिणी हिस्सों में स्थापित लोहा गलाने की भट्टी (blast furnace) का आकार (size) केवल जर्मनी के उद्योग की अपेक्षा अधिक ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के मुकाबिले में आधे से अधिक और अमेरिका की औसत भट्टी की आकृति का $\frac{2}{3}$ भाग से किसी प्रकार कम न था। देश में पूँजीवाद काफ़ी जम गया था। ऐसे कारखानों की संख्या जिनमें ५०० से अधिक श्रमिक काम करते थे, ५३ प्रतिशत से अधिक थी जब कि अमेरिका ऐसे देश में भी इतनी प्रबलता पूँजीवाद में न थी। ऐसे उद्योग-धंधे वहाँ इस समय ३१ प्रतिशत से अधिक न थे। उत्पादन व स्वामित्व में एकाग्रता की प्रबलता इस बात से अधिक स्पष्ट है कि रेलों के सामान का $\frac{1}{10}$ भाग केवल ७ बड़े-बड़े कारखानों में निर्मित होता था और तेल के उद्योग में केवल ६ ऐसे कारखाने थे जो सम्पूर्ण उत्पादन का $\frac{2}{3}$ हिस्सा स्वयं उत्पादन करते थे। रूस के कुल उद्योग-धंधों को ध्यान में रखते हुये ऐसा कहा गया है कि उनके उद्योगों की औसत शक्ति माप (horse power per worker) इंग्लैण्ड की शक्ति माप का $\frac{1}{3}$ और अमेरिका के उद्योग की शक्ति माप का $\frac{1}{4}$ भाग के बराबर था। यह स्थिति फ्रान्स और जर्मनी की अपेक्षा कहीं अच्छी थी। फ्रान्स या जर्मनी के उद्योगों में ऐसी बातें न थी। इससे स्पष्ट है कि रूसी पूँजीवाद उच्चकोटि का था और कारखानों का आकार भी साधारण न था।

रूस में अधिकतर उद्योग-धंधे जो उस समय जमे थे विदेशियों के आधिपत्य में थे। यह रूस के औद्योगिक संगठन की विशेषता थी। विदेशी पूँजीपतियों ने अपनी बहुत सी पूँजी रूस के उद्योग-धंधों में विनियोग किया था और विदेशियों का ही अधिकतर विशाल उद्योगों में आधिपत्य था। १९१४ के युद्ध से पूर्व २००० लाख रुबल की औसत दर से प्रत्येक वर्ष रूस में पूँजी आयात की जाती थी। ऐसा अनुमान किया गया था कि सम्पूर्ण विदेशी पूँजी जो रूस के उद्योगों में उस समय लगी थी ३२ प्रतिशत फ्रान्स की २२ प्रतिशत ब्रिटिश और शेष में से अधिकतर जर्मनी व स्पेन की थी। जो कारखाने स्थापित थे अधिकतर विदेशी थे; विदेशियों का उन पर अधिकार था; विदेशी वित्त से सज्जित थे और विदेशी प्रबन्धकों व कार्यकर्त्ताओं द्वारा संचालित थे।^१

यों तो यह सत्य है कि रूस में कारखाने बड़े पैमाने के थे और उनकी मशीनों का आकार कहीं-कहीं असाधारण था पर वहाँ औद्योगिकरण विस्तृत रूप से सन्निविष्ट न हो पाई थी। सम्पूर्ण जनसंख्या के केवल १५ प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे जिनमें कठिनाई से १० प्रतिशत ही ऐसे लोग थे जिनकी जीविका उद्योग-धंधों पर पूर्ण रूप से निर्भर थी। वास्तव में रूस एक कृषि प्रधान देश था जहाँ पर लोगों का मुख्य धंधा खेती ही करना था।

रूस के कारखानों में काम करने वालों की दशा भी बड़ी विचित्र थी। ये पूर्ण रूप से सर्वहारा वर्ग (proletarian) के न थे। वे अर्द्ध-सर्वहारा वर्ग (semi-proletarian) कहे जा सकते थे क्योंकि कारखानों में काम करने के साथ-साथ जब खेतों पर अधिक काम रहता था, अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से वे गाँव जाकर खेतों पर भी काम करते थे। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से औद्योगिक श्रमिक नहीं कहे जा सकते थे। फैक्टरी में काम करने के साथ-साथ खेतों पर भी पारिश्रमिक पर काम करते थे। फसल कटने के समय गाँव लौट जाना उनका प्रत्येक वर्ष का काम था और फसल कटने के बाद पुनः शहरों में आ जाते थे। यही नहीं एक दूसरी पद्धति भी उस समय प्रचलित थी जिसे कार्य बाहर भेजने की प्रथा (putting out system) कहते थे। कारखानों में आकर कार्य करने के स्थान पर गाँव में ही काम भेज दिया जाता था और कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उसे कारखानों में पहुँचा कर पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता था। यह प्रथा बहुत से उद्योगों में प्रचलित थी और बहुत ही सुविधाजनक प्रतीत होती थी।

इस युग में लोहे का उद्योग काफी बढ़ा चढ़ा था जिसका उत्पादन इंग्लैंड से कई गुना अधिक था। रूस का लोहा विदेशों को भी जाता था और इसकी प्रतिस्पर्धा विशेषकर स्वीडन के लोहे से थी। इस उद्योग का संगठन दो प्रकार से किया गया। कुछ स्थानों पर सरकारी कारखाने (state factories) थे जिसका प्रबंध राज कोष (Treasury) से होता था। कुछ स्थानों में निजी व्यवस्थापकों द्वारा कारखाने चलाये जाने की प्रथा अधिक प्रचलित थी जिनको सरकार से कहीं-कहीं सहायता भी मिलती थी।

१९वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग ने भी काफी उन्नति की। परन्तु श्रमिकों की कमी इसकी एक बड़ी समस्या थी क्योंकि श्रमिक वर्ग अधिक कुशल न था। इसका प्रबन्ध घर पर काम भेज कर (putting out system) कराया जाता था। सूत कातने का काम अधिकतर गाँवों में ही होता था। अर्द्ध-सर्वहारा वर्ग (semi-proletarian) तमाम काम कारखाने से अपने घरों में लाकर पूरा करते थे और शहरों में जाकर पारिश्रमिक का भुगतान ले आते थे। कुछ समय बाद वाष्पशक्ति करवा (steam power loom) के प्रयोग से कारखानों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई और इस उद्योग को १८६६ के बाद बड़ा प्रोत्साहन मिला। दूसरे उद्योगों की तरह इसका भी संचालन विदेशियों द्वारा हुआ जिसमें उन्हीं की पूँजी और प्रबन्ध था। अधिकतर विदेशियों के ही हाथ में बारीक व कुशल कार्य थे। उत्पत्ति स्वामित्व में एकग्रता आ रही थी।

लोहे के उद्योग को भी सरकारी सहायता बराबर मिली जिससे इसको प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। पर्याप्त मात्रा में कोयले और कच्चे लोह की खाने पास-पास होने के कारण ईंधन या शक्ति की कमी न थी और १८८० के बाद यातायात सुविधाएँ प्राप्त होने से यह रूस का एक महान उद्योग समझा जाने लगा। नये-नये लोह के उद्योग-धंधे बड़े पैमाने पर चलाये गये। लगभग १८८० के अन्त तक २९ लोहे गलाने का भट्टियाँ (blast furnace) स्थापित हो चुकी थी और १२ भट्टियों को स्थापना व निर्माण का कार्य आधे से अधिक हो गया था। कारखाने इतने बड़े थे कि अधिकतर एक-एक कारखाने में लगभग १०,००० आदमी काम करते थे। १८८५ और १८९८ के बीच कच्चे लोहे के उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई थी। कुछ ही समय में उत्पादन बीस लाख टन से अधिक हो गया था। इसके बाद १५ वर्ष में ही उत्पादन दुगुने से अधिक (४६ लाख) हो गया जब कि फ्रान्स में कच्चा लोहा इसी समय ५२ लाख टन से अधिक और संयुक्तराष्ट्र में १० लाख टन से अधिक उत्पन्न न होता था।

इन तमाम उद्योगों में जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है संकेन्द्रण

(concentration) व स्वामित्व में एकाग्रता उच्च स्तर पर थी। व्यापारिक संघ भी काफ़ी स्थापित थे। एकाधिकार संगठन (monopolistic organisation) में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। यह गति रूस के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। १९०२ में लोहे इस्पात उद्योग सिन्डीकेट ने सम्पूर्ण उत्पादन का ६ भाग अपने अधिकार में कर लिया था। बैंकों का प्रभाव देश की पूँजी, वित्त बाजार व उत्पत्ति साधनों पर १९ वीं शताब्दी के अन्त तथा २० वीं शताब्दी के आरम्भ में काफ़ी पाया गया था।

इसके साथ-साथ श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब थी। वे गरीब थे और उनकी परिस्थित विपत्तिग्रस्त थी। उनके रहने के स्थान गंदे व उनकी जीविका के साधन अपर्याप्त थे। १९०८ में एक आयोग (commission) ने पता लगाया कि वस्त्र उद्योग में काम करने वालों में से ६० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक कमरे में एक से अधिक कुटुम्ब के साथ रहते थे और अगर माध्य निकाला जाय तो यह आश्चर्यजनक बात न थी कि एक कुटुम्ब के पास १० वर्ग फीट से अधिक निवास स्थान न था। बहुधा लोग बैरेकों (barracks) में रहते थे जो अत्यन्त गंदे और संकीर्ण थे और जिनकी अवस्था किसी प्रकार भी उन अस्तबल से अच्छी न थी जहाँ घोड़े या जानवर बाँधे जाते थे। रूस के इतिहास में यह एक विरोधाभासी घटना बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

कानून ऐसे कठोर व क्रूर थे कि श्रमिकों के बीच किसी प्रकार का मेल, समझौता या संघ नहीं बनाया जा सकता था। ऐसे संघों को अवैधानिक करार कर दिया गया था। परन्तु तमाम नियंत्रणा के बावजूद भी क्रान्तिकारी श्रमिक संघों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, जिसका १९१७ के विनाश व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से बड़ा सम्बन्ध है। रूस का प्रधान धंधा कृषि था जिस पर तीन चौथाई जनसंख्या निर्भर थी। उद्योग-धन्धों में पूँजीवाद की प्रबल नींव होते हुए भी रूस एक खेतिहर देश बना रहा जहाँ औद्योगिक उन्नति यद्यपि उच्चकोटि की हुई, तथापि उसका दायरा तथा विस्तार इतना संकुचित था कि केवल एक चौथाई जनसंख्या उद्योग-धन्धों में सम्मिलित हो पाई थी। भूमि की उर्वरता व खाद्यान्न की उत्पत्ति इतनी कम थी कि रूस की तुलना किसी भी पिछड़े हुये कृषि प्रधान देश से भली प्रकार की जा सकती थी। कितनी अद्भुत व विरोधाजनक बात है कि एक ओर तो उच्चकोटि का पूँजीवाद और दूसरी ओर निम्नकोटि की कृषि; एक ओर तो बड़े आकार के उद्योग-धन्धे और दूसरी ओर श्रमकों की दयनीय व निर्धन अवस्था। १९०५ में लेनिन ने रूस की अर्थ-व्यवस्था की विवेचना इस प्रकार की थी :—

“रूस एक ऐसी अर्थ व्यवस्था का प्रतिरूप है जिसमें एक ओर तो आधुनिक पूँजी-साम्राज्यवाद अच्छी तरह लपटी हुई है, दूसरी ओर पूँजीवाद स्थापना से पूर्व विस्तृत होने वाली जागीरदारी प्रथा (कृषि में) से सम्बन्धित पात्रों का घना जाल सा बिछा हुआ है। एक ओर तो उसके पुराने गाँव तथा पिछड़ी हुई कृषि पद्धति है पर दूसरी ओर बहुत ही प्रगतिशील औद्योगिक और वित्तीय पूँजीवाद स्थापित है।”^१

कृषि में उर्वरा शक्ति बहुत ही कम थी। इसके अनेक कारण थे :

(१) यद्यपि रूस का बहुत बड़ा भाग काली भूमि का हिस्सा था, जो कि योरप की सबसे अच्छी मिट्टी कही जाती थी, तथापि मिट्टी की उर्वरता जलवायु की शुष्कता के कारण नष्ट हो जाती थी; ऐसे भागों में वर्षा की भी कमी थी।

(२) पुरानी खेती करने की रीतियों के प्रचलन के कारण भी उपज में कमी थी। तृ-भूमि पद्धति (three field system) अच्छी प्रकार प्रचलित थी जिसके कारण प्रत्येक भूमि का एक हिस्सा हर तीसरे वर्ष खुला छोड़ दिया जाता था। कुछ भागों में तो इस पद्धति से भी खराब रीतियाँ प्रचलन में थी। इसका प्रभाव यह पड़ता था कि भूमि का एक बहुत बड़ा अंश परतपी छोड़ दिया जाता था जिसके कारण उत्पादन में काफी हानि होती थी।

(३) किसानों के पास सारी भूमि एक ही स्थान पर न थी। दूर-दूर पर छोटी-छोटी पट्टियाँ छितरी थीं, जिससे बड़े पैमाने पर खेती करना असम्भव था। कभी-कभी ये पट्टियाँ बहुसंख्यक थी। एक कुटुम्ब के पास १०० पट्टियाँ होना आश्चर्यजनक बात न थी।

(४) एक अच्छी फसल के लिये यह आवश्यक होता है कि घास के मैदान व खेती योग्य भूमि एक निश्चित अनुपात में हो, ताकि खेती के लिये पशु पाले जा सकें, और उनके लिये घास के मैदान भी बनाये जावें। अच्छी खेती के लिये दोनों प्रकार की भूमि का संतुलन होना अत्यन्त आवश्यक है। रूस में इस प्रकार के संतुलन का अभाव था। दक्षिण के भाग में घास के मैदानों की कमी थी, और इसलिये पशुओं की भी कमी थी जिसके कारण प्राकृतिक खाद का भी अभाव था। इसके प्रतिकूल उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भागों में जहाँ घास के मैदानों की अधिकता थी वहाँ भी कृषकों के निस्तार (peasant emancipation) के बाद अच्छे घास के मैदानों को जमींदारों ने अपने पास रख लिया, और कृषक वर्ग के हाथ केवल निम्नकोटि की खेती योग्य भूमि पड़ी। गरीब किसानों के पास खाद न थी, पूँजी न थी, वे निर्धन थे, निर्बल थे और साथ ही साथ घास

के मैदान न मिलने के कारण पशुओं का अभाव तथा उनकी संख्या में न्यूनता इत्यादि ऐसी समस्याएँ थीं जो खेती के लिये बड़ी हानिकारक सिद्ध हुईं ।

(५) पूँजी की कमी के कारण कोई वैज्ञानिक सुधार होने का प्रश्न ही न उठता था । भूमि की उर्वरता इस अभाव के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गई ।

बहुत ही पुराने साधन, सामान व औजारों का प्रयोग होता चला आया था और किसी भी समय किसी भी प्रकार का सुधार लाने की चेष्टा भी न की गई थी । किसान वर्ग इतना गरीब था कि उसके पास बीज, औजार, खाद इत्यादि खरीदने के लिये पूँजी न थी बल्कि वे तमाम करों के भार से दबे जा रहे थे । अधिकतर सामान लकड़ी के ही थे और हाथ से ही फसल बोने और काटने का काम किया जाता था । पूँजी की कमी एक जीर्ण रोग बन गई थी । किसान दरिद्रता का एक अच्छा खासा पुतला था । कृषक वर्ग में सामाजिक भेद-भाव बड़ा व्यापक था । गाँव के धनी पुरुष 'कुलक' कहलाते थे, जिनके पास सम्पत्ति पशु और खेती के सारे सामान थे । वे सर्वसम्पन्न थे । उन लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी थी । लगभग सारा गल्ला जो बाजार में विक्रय के लिये जाता था इसी वर्ग की अतिरिक्त उत्पत्ति (surplus produce) थी । इन कृषकों के पास असीमित, भूमि थी जिस पर ये अधीन किसानों से खेती कराते थे ।

गरीब कृषक वर्ग में आम तौर से ऐसे किसान थे जिनके पास न भूमि थी और न ऐसी आय ही प्राप्त थी कि जीवन निर्वाह करने के अतिरिक्त भी वे कुछ बचा सकें । उनके पास बेचने के लिये उत्पत्ति का कोई भी अंश ऐसा न था जो वे अपनी आवश्यकता से ही किसी प्रकार बचाकर बेच सकें । तमाम करों से लदे होने के कारण उनको कुछ गल्ला मजबूरन बेचना पड़ता था ताकि वे राजकीय कर अदा कर सकें और उस महान उत्तरदायित्व से कुछ समय के लिये बच सकें । धनी कृषकों के पास पशु मुँड या घोड़े थे, हल थे, गाड़ियाँ थी जो वे किराये पर निर्धन कृषकों को दिया करते थे । और उत्पादन का अधिक अंश उसके भुगतान में बाँट लेते थे । वे अपने पड़ोसियों को भी जो गरीब थे तमाम कर्ज व खेती का सामान या तो उत्पत्ति के बहुमूल्य अंश को लेकर देते थे, या उसके भुगतान में अपने खेतों पर उनसे काम करवाते थे । इन दोनों प्रथाओं में से दूसरे प्रकार की प्रथा का अधिक प्रचलन था यद्यपि दोनों रीतियों में गरीब कृषक का शोषण अच्छी प्रकार किया जाता था । अमीर व गरीब किसानों के इस संबंध में निर्धन किसानों को बराबर नुकसान पहुँचता था । यही नहीं धनी व गरीब किसानों का संबंध दूसरे प्रकार से भी बढ़ रहा था । गरीब किसानों को अधिक ब्याज पर बीज इत्यादि दिया जाता था जिसका भुगतान फसल के बाद

वे या तो सस्ते दाम पर उत्पत्ति बेच कर पुराना व ऊँचे दर का सूद अदा करते थे या उत्पत्ति को ही देकर उत्तरदायित्व से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे। अधिकतर कृषकों की तो ऐसी दशा थी कि वे फसल काटने पर उपज शीघ्र ही बाजार में सस्ते दाम पर बेच डालते थे क्योंकि वे तमाम उत्तरदायित्व से लदे रहते थे और शीघ्र से शीघ्र उनसे मुक्ति पाना चाहते थे। धनवान पुरुष उसे खरीद कर रख लेते थे और छः मास बाद जब गरीब कृषक अपने उपयोग या बीज के लिये पुनः गल्ला खरीदना चाहते थे तो वे ही लोग उसे पुनः विक्रय करते थे और ऊँचे भाव पर बेच कर अत्यधिक लाभ उठाते थे। इस प्रकार धनी किसान दोनों प्रकार से अपने हित की बात सोचता था और गरीब किसानों का शोषण करता था। यह ऐसी प्रथा थी कि अमीर लोग अपने पड़ोसियों की आवश्यक वस्तुओं से, यहाँ तक कि उनकी निर्धनता से, लाभ उठाते थे। धनवान पुरुष अत्यधिक धनवान होते जा रहे थे; उनकी पूँजी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। यही कारण है कि रूस के धनी कृषकों को कलंकित करते हुये 'कुलक' कहा गया है जिससे तात्पर्य 'मुट्टी' या 'मुष्टि' से है अर्थात् जिसने धन कमाने के लिये मुष्टि-प्रहार रूपी हिंसा का प्रयोग किया हो। रूसी ग्रामीण जीवन के विद्यार्थियों ने कुलक वर्ग की घोर निन्दा की है और इसको भीषण अत्याचारी एवम् उत्पीड़क नाम से दोषित किया है। १८९५ में स्टेपनिक ने इस वर्ग पर निम्नलिखित शब्दों में लांछन लगाया है :

“इस वर्ग का विशिष्ट गुण कठोर एवम् स्थायी निर्दयता है—ऐसी निर्दयता जो केवल ऐसे गँवार पुरुष में पायी जाती है, जो जन्मतः निर्धन था पर कालान्तर कुछ सम्पत्ति एकत्रित कर लेता है और सोचता है कि प्रत्येक विवेकशील पुरुष का जीवन में एकमात्र ध्येय धनोपार्जन ही करना है।” बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक जर्मन अर्थशास्त्री ने लिखा कि कुलक “ग्रामीण रूस में एक रोचक चरित्र है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अत्याचारी सूदखोर के हाथ बड़े ही कलंकित थे।” उसने कुलक का नामकरण “ग्राम-भक्षक” (village eater) किया।

डाक्टर डिलन ने इस वर्ग की निन्दा निम्नलिखित शब्दों में की है, “इस प्रकार का पुरुष साधारण तौर से “कुलक” या “फिस्ट” कहा गया जिससे दया, तरस या करुणा के प्रतिकूल अतिशय निर्दयता से उसकी समानता की जा सके। देशाटन करते समय जिन मानवीय-दानवों से हमारी मुलाकात

हुई शायद रूसी कुलक के अतिरिक्त दूसरे इतने दुराशय और घृणित न थे। १९०५ और १९१७ की क्रान्ति का वह अधिदैव था, एक भूतिमान पिशाच।”

सामाजिक भेद-भाव ने गरीब कृषकों की दशा बहुत ही खराब कर दी थी। इस भेद-भाव का प्रभाव रूसी किसानों के आर्थिक जीवन पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेती के अतिरिक्त उन्हें कारखानों में या घरेलू दस्तकारी इत्यादि से अपनी जीविका चलाने के लिए अलग से काम करना पड़ता था। कुछ खानों में और कुछ कारखानों में काम करते थे। इस प्रकार यह श्रमिक वर्ग सामयिक एवम् लापरवाह था। इनका मुख्य धन्धा खेती था पर समय-समय पर कारखानों में, खानों में व दस्तकारी के काम में भी ये हाँथ बटाते थे। भारी संख्या में स्थानीय कुलक ने इन्हें खेती-बारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से या तो अपने खेत पर काम करने के लिए या स्थानीय कारखानों में जिसके वे मालिक थे पारिश्रमिक पर काम करने के विचार से इन्हें नियुक्त कर लिया था। इस प्रकार रूस में इस समय औद्योगिक सर्वहारा समुदाय (industrial proletariat) के अतिरिक्त ग्रामीण अर्ध-सर्वहारा की संख्या भी कम न थी जो ऐसे लोग थे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में न तो भूमि थी जिससे वे अपनी जीविका भली भाँति चला सकें और न उसके पास पशु या खेती के आवश्यक यंत्र ही थे जिनकी उन्हें खेती में आवश्यकता पड़ती थी। यही नहीं, यह वह वर्ग था जिसको सूद, सरकारी कर और दूसरे बोझ दबाए हुए थे। दुःख की बात है कि उद्योग-धंधों के उत्थान और कुलक वर्ग के कल्याण के लिए यह निर्धन ग्रामीण—अर्ध-सर्वहारा वर्ग एक बहुमूल्य निहित शक्ति संचय का द्योतक था जिनका धनवान कृषक अच्छी प्रकार शोषण करते थे।

अठारवीं शताब्दी के अन्तकाल तक रूस की जनसंख्या का १/३ भाग दासत्व प्रथा से जकड़ा था। आधे से अधिक कृषक या तो निजी जमींदारों (private lords) के या राजा के अधीन थे। उनकी दशा दिन प्रति दिन खराब होती गई। रूस के निर्धन कृषकों की दशा मध्यकालीन पश्चिमी योरप के अधीन कृषकों की दशा से अधिक निन्दनीय थी। सामान्त (lord) उन पर अपनी इच्छानुसार कार्य और भार निश्चित कर देते थे। इस भार से राहत पाने के लिये किसान कहीं अपील नहीं कर सकता था। भू-स्वामी किसानों को दंड दे सकता था, केवल मृत्यु-दंड छोड़कर, वह उनको दीर्घकाल के लिये साइबेरिया में निष्कासित (exile) कर सकता था, अथवा जो शायद इससे भी भयंकर था—सैनिक सेवा के लिये भेज सकता था। कानून और रीति व्यवहार में किसान भू-स्वामियों की पूर्णतया सम्पत्ति (chattel अर्थात् cattle मूक पशु) थे। भू-स्वामी

उनको केवल सरेआम नीलाम नहीं कर सकता था और न सेना में अनिवार्य भरती (military conscription) के समय उनको बेच सकता था। इन दो अपवादों को छोड़कर वह उनको (serfs) खेतों सहित अथवा वैसे भी बेच सकता था।^१

कुछ आधीन पुरुष गृह अनुचर के रूप में काम करते थे। कुछ को इतनी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी कि वे भू-स्वामी के तमाम कर के उत्तरदायित्व को पूरा करने के अतिरिक्त कुछ और भी कर सकें। बहुत से किसानों को आधे से अधिक अपना समय भू-स्वामी की सेवा में व्यतीत करना पड़ता था। ऐसे किसान जो सम्राट के आधीन (crown serfs) थे उनकी दशा औरों से कुछ अच्छी थी।

भू-स्वामी और आधीन कृषक, दोनों वर्गों का आचार भ्रष्ट हो चुका था। कुछ भू-स्वामी छोटे पद के (petty landlord) कुछ सामान्य स्तर (medium landlord) के और कुछ बड़े पद (great landlord) के थे। छोटे पद के भू-स्वामी उन कुलक को कह सकते हैं जिनके आधीन १०० से अधिक कृषक न थे; सामान्य स्तर के भू-स्वामी के आधीन लगभग १०० से १००० कृषक होते थे और बड़े पद के कुलक के आधीन हजारों की संख्या में कृषक थे, जिनसे वे काम लेते थे, पशुओं की तरह उन्हें पालते थे और उनका अच्छी तरह शोषण करते थे। इन आधीन कृषकों का रहन-सहन तथा जीवन-स्तर इत्यादि निम्नकोटि का था। वे अपने कार्य से विमुख, अनिच्छुक तथा लापरवाह थे। भू-स्वामियों के कार्यों को करते-करते उनमें अक्षमता एवम् कामचोरी कूट-कूट कर भर गई थी। वे अपने काम में भी उत्साहहीन हो गए थे। उनकी कार्य क्षमता निम्नकोटि की थी। एक रूसी निवासी ने अपने लोगों के विषय में लिखा था : “वह निर्धन है—एक शराबी अपने समुदाय के प्रति निरुत्साही, अपने पड़ोसियों से व अपने परिवार से उदासीन तथा अपने भाग्य पर भी न विश्वास करने वाला लापरवाह व्यक्ति।”

कुछ भी हो ग्रामीण कृषक की एक बात की तो प्रशंसा की ही जानी चाहिए कि उनमें कुछ उत्कृष्ट नैतिक साधुता भी थी जैसे धैर्य, दृढ़ता, भू-स्वामियों के प्रति कर्तव्य-पालन, तथा विश्वास। इस दृष्टिकोण से वह प्रशंसनीय है निन्दनीय नहीं। ये सारे गुण तथा अवगुण उनमें पीढ़ियों से चले आये थे और उनमें भली भाँति समा गए थे।

रूस के इतिहास में १८६१ का मुक्त विधान एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता

है। इस विधान द्वारा कृषकगण आधीनता से मुक्त कर दिए गए; उनको विधिमान्य स्वत्वाधिकार मिल गया और उन्होंने स्वाधीनता पूर्वक भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस मुक्त विधान का मौलिक सिद्धान्त यह था कि आधीन किसानों को उतनी भूमि दे दी गई जितनी उनको खेती करने के लिए कुलक से मिली थी। राज्य सरकार ने जमींदारों को ब्याज सहित प्रतिज्ञा पत्र प्रतिकर के रूप में तत्काल दिए और ब्याज सहित मूलधन वार्षिक विमोचन (annual redemption) द्वारा ४६ वर्षों में संग्रह कर लेने का आयोजन किया गया।

मुक्त-विधान द्वारा दो प्रकार के आधीन पुरुष स्वतंत्र हुए (१) गृह अनुचर (domestic servant) तथा (२) ऐसे कृषक जिन्होंने अपने स्वामी की भूमि बिना किसी भू-अधिकार के प्राप्त की थी और कम से कम पारश्रमिक पर वे उसे जोतते थे। गृह अनुचर को स्वतंत्रता मिलने से उद्योग-धन्यों में जो श्रम की कमी थी, काफी दूर हो गई और वे पँजीवाद प्रथा के अर्न्तगत कारखानों में सर्वहारा वर्ग के साथ हो गए। कुछ ऐसे काश्तकारों (tenant) को जिनके पास भूमि सामुदायिक रूप में थी, सामुदायिक स्वामित्व प्रदान की गई। इस विधान के अर्न्तगत यह भी सम्भव था कि अगर कोई काश्तकार कारखानों में दिन में कुछ समय के लिये (part time) काम करना चाहे, तो कर सकता था। उसको यह भी अधिकार था कि उन महीनों जब खेत पर काम नहीं रहता, शहरों में आकर अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी कारखाने में सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर, धन उपार्जन करे और फसल कटने के समय वह गाँव पुनः लौट जाये।

मुक्त-निर्णय का प्रभाव

मुक्त-निर्णय के प्रभाव में एकरूपता या समानता न थी। रूस में बहुत से भाग ऐसे थे जहाँ खेती योग्य भूमि तथा घास के मैदानों के बीच उचित संतुलन न था और बहुत से ऐसे थे जो कम उपजाऊ थे। इन बातों को ध्यान में रख कर मुक्त निर्णय नहीं किया गया था। कृषकों का बन्दोबस्त एक ही आधार पर हुआ। स्थानीय परिस्थितियों पर पूरा ध्यान न दिया गया। चारों ओर इस महान विधान के बाद भी बड़ी अशान्ति रही। पूर्वी हिस्सों में मिट्टी अच्छी होने के बावजूद भी वर्षा की इतनी कमी थी कि भूमि की उर्वरता काफी नष्ट हो गई थी। जनसंख्या भी इस हिस्से में कम थी और लोग अत्यन्त पुराने ढंग से विस्तृत खेती करते थे। लगातार अवैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग से कुछ समय के बाद भूमि की उर्वरता बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी। अधिकतर उत्पत्ति बड़े पैमाने पर ख विस्तृत रूप में होती थी, जिसका काफी अंश काला सागर (Black Sea)

और आज़व सागर (Sea of Azov) द्वारा निर्यात किया जाता था। इसके प्रतिकूल पश्चिमी भाग अधिक उपजाऊ और घना आबाद था। प्रगाढ़ खेती पद्धति प्रचलित थी। उत्तरी और दक्षिणी भागों में भी अधिक असमानता थी। दक्षिणी काली मिट्टी का प्रदेश उत्तरी जंगली प्रदेश से बहुत भिन्न था। उत्तरी भाग में खेती योग्य भूमि कम थी और गेहूँ के स्थान पर राई का उत्पादन अधिक था। वे सूखे जंगलों से घिरे और पिछड़े इलाके थे, जहाँ खेती को न्यूनतम स्थान दिया गया था। उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों के बीच में कुछ ऐसे देश थे जहाँ के कुछ भाग अवश्य साफ किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साइबेरिया प्रदेश खनिज सम्पत्ति और पशु समुदाय में सम्पन्न तथा दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा भौतिक तथा भौगोलिक स्थित में बिल्कुल भिन्न था। अतः—

(क) उत्तरी भागों में जहाँ अनुपजाऊ भूमि अधिक थी कृषकों के हिस्से में भूमि अधिक पड़ी क्योंकि उन भागों में भूमि अधिक और कृषकों की कमी थी। दूसरे भागों में ऐसा न था।

(ख) भूमि का वितरण हर हिस्सों में केवल असमान ही न रहा बल्कि वार्षिक विमोचन की दर भी हर स्थान पर भिन्न थी। सबसे अधिक असंतोष जनक बात तो यह थी कि उन क्षेत्रों में जहाँ उर्वरता कम थी कृषकों के ऊपर विमोचन का भार अधिक था। भूमि का बाजार मूल्य कुछ भागों में दूसरे स्थानों की अपेक्षा लगभग दूने से अधिक था। इसलिए कृषक वर्ग ने इन प्रदेशों में मुक्त प्रबन्ध के प्रति हमेशा विमुखता दिखलाई।

(ग) इसके अतिरिक्त असंतोष का कारण भू-स्वामियों की स्वार्थपरता थी। अच्छी से अच्छी भूमि उन्होंने अपने पास रख ली। वंजर व जंगली भूमि कृषकों को सौंप दी। यही नहीं अच्छे अच्छे घास के मैदान व चारागाह भू-स्वामियों के पास रह गये थे तथा कृषकों की खेतीबारी सम्बन्धित सविधाओं का उचित ध्यान न दिया गया था। काली मिट्टी के प्रान्तों में कृषकों को दी गयी भूमि का भाग केवल कम ही नहीं, बल्कि जो भूमि उनको मिली थी, वह बहुत ही निम्नकोटि की थी और खेतीबारी में सन्तुलन व स्थिरता न रह पाई थी।

(घ) अशान्ति इस कारण भी थी कि शाही कृषक इस परिवर्तन से बिल्कुल ही प्रभावित न थे।

(ङ) अर्द्ध-श्रमिक वर्ग को भी इस विधान द्वारा कोई विशेष लाभ न हुआ और बहुत से श्रमिकों को तो इसके द्वारा पूरी स्वतंत्रता भी न मिल पायी थी। कारखानों तथा खानों में काम करने वाले अर्द्ध-श्रमिक वर्ग व ग्रह अनुचरों को स्वतंत्र तो अवश्य कर दिया गया था पर उनको भूमि का कोई अंश प्राप्त न था।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, रूस में अधिकतर श्रमिक इसी वर्ग के थे जो कारखानों में काम करने के साथ-साथ खेती में भी अपना दखल रखते थे और समय-समय पर अपना जीवन निर्वाह करने के लिये गाँव में जाकर भूस्वामी का काम करते थे। ऐसे श्रमिकों का अधिकार भूमि से जाता रहा।

मुक्त-कानून से कोई विशेष लाभ, सुधार या परिवर्तन न दिखलायी पड़ा। लोगों में असंतोष बढ़ गया। कुलक के पास भूमि, जो पहले २७४० लाख एकड़ थी, १९१६ में २००० लाख एकड़ रह गई थी। भूमि पर कृषक वर्ग का स्वामित्व अवश्य स्थापित हो गया था पर उनकी दशा में कोई सुधार न हो पाया था। उनमें असंतोष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था।

१९०५ और १९१७ की क्रान्ति के चित्र में अशान्ति ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसने रूस की काया पलट दी और विश्व के इतिहास को एक नया दृश्य दिखाया।

बढ़ता हुआ असंतोष (rising discontent)

देश का संपूर्ण वातावरण असंतोष से भरा हुआ था। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अशान्ति ने १८६८ में रूस की समाजवादी पार्टी (Russian Socialist Party) को जन्म दिया जिसकी विचारधारा मार्क्स के सिद्धान्त पर आधारित थी। श्रमिकों के असंतोष का कारण उनकी आर्थिक दशा तो थी ही पर रूस के सम्राट 'ज़ार' का जनता पर अन्याय भी विशेषकर उत्तरदायी था। 'ज़ार' कृषकों को उन्नति करने से रोकते थे। उनके लिये शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के पक्ष में वे न थे, क्योंकि उनका विचार था कि अच्छी सुविधाएँ प्रदान करने से उनमें जागरण होगा और क्रान्ति की सम्भावना बढ़ जावेगी। वे सारी सुख-सुविधाएँ जो जनता को सरकार से मिलनी चाहिये थीं न मिल सकीं। १९१४ में सारे रूस-साम्राज्य में केवल २०,००० डाक्टर थे। माध्यमिक शिक्षा पाने वालों की संख्या १० लाख से अधिक न थी। 'ज़ार' और उनके कर्मचारियों को बराबर यह डर व शंका थी कि जनता में शिक्षा का प्रचार क्रान्ति का कारण हो सकता है। इसी कारण उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि कम से कम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त 'ज़ार' का विश्वास था कि श्रमिकों की अशान्ति को हिंसा द्वारा ही रोका जा सकता है। १९०५ में एक शान्तिपूर्वक जलूस को जो 'ज़ार' के पास प्रार्थना-पत्र लेकर जा रहा था, निर्दयता से कुचल डाला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हड़तालें हुईं, बलवा होने लगे और क्रान्ति की आग सारे देश में फैल गयी। १९०५ में देश की राजनैतिक दशा बड़ी डौंवाडोल हो गई थी। लूट, हत्या तथा हिंसा की तमाम घटनाएँ बढ़ती जा रही थीं।

१९१४ की लड़ाई ने दशा और बिगाड़ दी। युद्ध के कारण रूस के अर्थपर्याप्त साधनों पर बड़ी खींचा-तानी रही और १९१६ तक तो देश में असंतोष काफी फैल गया था। यातायात संगठन अस्त-व्यस्त हो गया था। काफी व्यापार नष्ट हो चुका था और मुद्रा स्फीति ने श्रमिकों के जीवन-लागत को काफी बढ़ा दिया था। १९१५-१६ के बजट में भारी घाटा हुआ जो यह सिद्ध करता है कि सारे शासन संगठन में अस्तव्यस्तता अत्यधिक बढ़ गई थी। वास्तविक पारिश्रमिक में हास व जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि एक साथ हुई। इस समय हर वस्तु की देश में कमी थी। खाना, वस्त्र व ईंधन अर्थपर्याप्त मात्रा में मिलते थे, खाद्यान्न आयात में भी करीब-करीब शून्यता थी और सारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि क्रान्ति का किसी समय आना असम्भव न था।

१९१७ की सोवियट क्रान्ति व उसके आर्थिक कारण व प्रभाव

इन दिनों बहुत से क्षेत्रों में यह चर्चा थी कि रूस में जागीरदारी प्रथा का (feudalism) क्या रूप है। अगर पश्चिमी देशों की भाँति जागीरदारी प्रथा यहाँ प्रचलित न थी, तो फिर जो प्रथा उस समय थी, उसमें क्या विशेषता थी और योरप की प्रचलित जागीरदारी प्रथा से किन किन बातों में भिन्न थी। इसी चर्चा के आधार पर अनेक राजनैतिक संघ व दल बन गए थे जिनके अलग-अलग विचार थे। 'नारोडनिकि' दल (Narodniki) का विश्वास 'ग्राम कम्यून' (village commune) या 'मीर' (mir)^१ पर आधारित था।

इस दल का विश्वास था कि रूस में 'ग्राम कम्यून' का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस मत के अनुसार क्रान्ति द्वारा परिवर्तन करने के पूर्व यह आवश्यक नहीं है कि किसी देश में पूँजीवाद पहले बढ़े और तब उसका उन्मूलन किया जावे। प्रारम्भिक काल में ही जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर देने से देश में कृषक-साम्यवाद या 'ग्राम कम्यून' पद्धति पनप सकती है। इसके लिये यह आवश्यक

१ शिक्षित समाज के विद्यार्थियों ने एक आन्दोलन चलाया था और गाँव गाँव जाकर उन्होंने कृषकों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें पुरानी व्यवस्था को तोड़ कर नयी व्यवस्था बनाना है। यह कार्य क्रान्ति द्वारा ही हो सकता है। इस आन्दोलन का प्रभाव कृषक समुदाय पर अधिक न पड़ा क्योंकि वे समझते थे कि शहर में रहने वाले पुरुषों को ग्रामवासियों की अवस्था का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। परन्तु कुछ ही समय बाद 'ज़ार' की पुलिस ने इस दल को अच्छी प्रकार कुचल डाला और इनके नेताओं को बन्दी कर लिया। १८७६ में एक संस्था पुनः बनायी गई जिसने कि कृषकों के बीच जागरण आन्दोलन चलाना चाहा। उनकी मांग थी कि भूमि का पुनः वितरण होना चाहिए। ३ वर्ष के बाद इस दल में दो पक्ष हो गये। एक ने हिंसात्मक साधनों पर विश्वास किया और दूसरे का शान्ति-पूर्वक आन्दोलन चलाने का विचार था।

नहीं है कि पहले पूँजीवाद उन्नति करे तथा निर्धन पुरुषों का शोषण हो और तब पूँजीवाद की हत्या की जावे। उनका विचार था कि रूस में 'मीर' या 'ग्राम कम्यून' प्रथा भली प्रकार प्रचलित होने के कारण कृषक वर्ग की अन्तर्जात प्रवृत्ति या अन्तः प्रेरणा जातिगत समानता की ओर अग्रसित है, जो बात जर्मनी या फ्रान्स के कृषकों में भी न आ पायी थी। रूस के कृषकों का विचार था कि भूमि पर अधिकार केवल उस पर खेती करने से प्राप्त होता है। खेती करने का वास्तविक अधिकार स्वामित्व के किसी कानून द्वारा नहीं प्राप्त होता। यह ऐसी विचारधारा थी जो रूसी कृषकों की अन्तरात्मा में अच्छी प्रकार समा गयी थी। 'मीर' या 'ग्राम कम्यून' का मत था कि किसी भूमि विशेष पर स्थाई रूप से किसी का व्यक्तिगत अधिकार न होना चाहिए। बल्कि उसका अदल बदल कर बराबर वितरण होना चाहिये। इस मत के अनुसार भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व में एकाग्रता (concentration of land ownership) न आनी चाहिये थी। यही नहीं पूँजीवाद प्रथा में जैसा होता चला आया है कि बिना भूमि के सर्वहारा वर्ग की एक बड़ी सेना संचय की जाती है या सुरक्षित रहती है, वैसी कोई बात 'मीर' या 'ग्राम कम्यून' के अन्तर्गत न आने पाई थी। यह दल इसी मत को आधार मान कर आन्दोलन करने का आयोजन कर रहा था।

इसी समय देश में दूसरे मत भी फैल रहे थे। १८७२ में मार्क्स की महान पुस्तक "कैपिटल" का पहला भाग रूसी अनुवाद छपा जिसने शिक्षक समाज को बड़ा प्रभावित किया। लेनिन ने अपनी सारी शक्ति मार्क्स आन्दोलन में लगा दिया था जिसका उद्देश्य श्रमिकों को आधीनता तथा निर्धनता से स्वतंत्र करना था। लेनिन का मुकाबला शुरू से ही इस ओर था। जब वह एक स्कूल का विद्यार्थी था, उस समय से ही उसे "नारोडनिकि" दल से चिढ़ थी और वह उनका विरोध करता था। द्वितीय ऐलेक्जेंडर (Alexander II) के बंधव 'नारोडनिक' दल में सम्मिलित होने के अपराध में जब लेनिन के बड़े भाई को मृत्युदण्ड मिलने का खबर उन्हें दी गई, तब लेनिन ने अपने दाँत पीसते हुए कहा : "हमको उस मार्ग पर कदापि न चलना चाहिये। हमको उस रास्ते जाने की आवश्यकता भी नहीं है"। अपने भाई की पुस्तकों से उन्होंने मार्क्स के विचारों का अच्छी तरह अध्ययन किया। उन्होंने 'नारोडनिकि' विचारों की घोर आलोचना की और उनकी निन्दा करते हुए मार्क्स के सिद्धान्तों को अच्छी प्रकार समझाया। उन्होंने कहा कि 'नारोडनिक' विचार अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर प्रतिकार करने की ओर अग्रसर है। अपने भूत को गौरवान्वित करने में व वर्तमान व्यवस्था को अनुकूल बनाने में उस मत के पक्षपातियों ने वास्तविक उन्नति में

रुकावट डालने की चेष्टा की है। अपने इस आन्दोलन को लेनिन ने बड़ी होशियारी के साथ चलाया। १८९७ में जब साइबेरिया में लेनिन का तीन वर्ष के लिये निर्वासन हो गया, उन्होंने अपनी महान रचनायें “रूस में पूँजीवाद का विकास” नाम से प्रकाशित की। लेनिन ने इन रचनाओं द्वारा सिद्ध किया कि पूँजीवाद का जोर रूस में इस समय काफी बड़े पैमाने पर है और केवल औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि ग्रामीण रूस भी इसके चंगुल में अच्छी प्रकार फँसा हुआ है।

लेनिन ने बराबर इसी सिद्धान्त का प्रदर्शन किया कि पूँजीवाद एक ऐसी ऐतिहासिक शक्ति है जो आर्थिक विकास में होने वाले स्वयम्-सिद्ध प्रमाणा का प्रचार करता है। पूँजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है जो समाजवाद व्यवस्था को स्थापना का क्रिया में एक भारी शक्ति का काम करता है। पूँजीवाद शक्ति द्वारा (१) उत्पादन में एकाग्रता और सामाजिक श्रम का उत्पादक इकाई में वृद्धि, तथा (२) श्रम का सामाजिक रचना उत्पन्न होता है, जिनका महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। पूँजीपति बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा कर सर्वहारा वर्ग को जन्म देते हैं, जिनका कार्य क्षमता से वे पूरा लाभ उठा कर अपना पूँजा बढ़ाते हैं। वे इस वर्ग का शोषण करते हैं जिससे सामाजिक भेदभाव तथा असंतोष बढ़ता है। वर्ग-संघर्ष का जन्म होता है। यह प्रवृत्ति रूस के उद्योग धन्धों में पर्याप्त मात्रा में आ गई थी और लेनिन ने इस ज्वाला को और बढ़ाया। लेनिन का कहना था कि ग्रामों में भी यह आन्दोलन बढ़ना चाहिये क्योंकि कृषकों का भी श्रमिक वर्ग की भाँति शोषण हो रहा है। बड़े पैमाने पर खेती प्रारम्भ हो चली थी तथा भूमि का क्रय-विक्रय उसी प्रकार होने लगा था जैसे औद्योगिक निर्मित पदार्थ विक्रय होते हैं। कृषक वर्ग तो पूर्ण कृषक न थे। वे पारिश्रमिक पर उसी प्रकार काम करते थे जैसे श्रमिक कारखानों में कर रहे थे। इस क्षेत्र में व्यवस्थापक प्रवृत्ति (entrepreneur character) जागृति हो चली थी; गतिहीनता तथा स्थानीय प्रथकता जो युग से जमी थी, अब नष्ट हो चली थी, और बड़े पैमाने पर खेती यन्त्रों व मशीनों द्वारा होते दिखलायी पड़ने लगी थी। सामाजिक भेदभाव बहुत ही गन्दी तरह देश में विद्यमान था। कुलक छोटे और आधीन कृषकों का वैसे ही शोषण करते थे जैसे पूँजीपति श्रमिकों का करते हैं।

लेनिन ने इस आर्थिक स्थिति का सामाजिक निदान (diagnosis) बड़ी योग्यता से किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उनका भविष्य कृषकों पर नहीं बल्कि श्रमिक वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग पर निर्भर है। लेनिन का विचार था कि जैसे-जैसे पूँजीवाद उन्नति करे और श्रमिक वर्ग विस्तृत हो वैसे-वैसे इस वर्ग

को सुगसंठित किया जाय ताकि समय आने पर वे क्रान्ति कर सकें और पूँजीवाद को नष्ट करके समाजवाद की स्थापना कर सकें। लेनिन ने इसी आधार पर सर्वहारा वर्ग के महत्त्व पर बड़ा जोर दिया। उसने देश में पूँजी-श्रम संघर्ष के आन्दोलन में बड़ी जान डाल दी। लेनिन ने लोगों को समझाया कि श्रमिक और कृषक दोनों वर्ग का एक ही उद्देश्य होना चाहिये क्योंकि दोनों का शोषण एक ही प्रकार से होता है। कुछ लोगों का मत था कि क्रान्ति का सम्बन्ध केवल सर्वहारा वर्ग से ही है, पर लेनिन ने चेतावनी दी कि केवल कृषक-श्रमिक संधि ही क्रान्ति उत्पन्न करके समाजवाद स्थापित कर सकती है।

क्रान्ति तथा हिंसा का जोर दिन प्रति दिन बढ़ रहा था। कई दल बन गये थे, पर सब दलों के मत व तरीके जो भी हों, उनका एक ही उद्देश्य था—देश से पूँजीवाद का उन्मूलन। १९०५ में ग्रामों में जो अशान्ति व क्रान्ति थी उसको पैदा करने में लेनिन का बहुत बड़ा हाथ था। उसने लोगों को समझाया कि श्रमिक समुदाय आन्दोलन का केवल एक रास्ता है और वह है क्रान्तिकारी व हिंसात्मक आन्दोलन। उसने कृषकों व श्रमिकों में एकता बढ़ाने का प्रयास किया और उसका यही नारा था : “१९०५ की क्रान्ति एक कृषक क्रान्ति है, जिसको चलाने वाला श्रमिक-समुदाय है”^१ लेनिन का यही उद्देश्य था कि रूस की सोवियट सरकार श्रमिक व कृषकों के समुदाय की प्रतिनिधि होगी। दूसरे दल के नेताओं ने इस मत का विरोध अवश्य किया और वे सर्वहारा वर्ग की सरकार के (government of proletariat) स्थान पर व्यवसायियों की सरकार (bourgeoisie government) बनाना चाहते थे। लेनिन का कहना था कि हमारा युद्ध पूँजीवाद से है। हमें उसका नाश करना है। और क्योंकि श्रमिक समुदाय अभी उतना कुशल, सचेत तथा अभिज्ञ नहीं हो पाया है, इसलिये व्यवसायी वर्ग सरकार ही कुछ समय शासन करेगी। परन्तु क्रान्ति का दूसरा कार्यक्रम व्यवसायी वर्ग सरकार से राज्य की डोर लेकर सर्वहारा वर्ग सरकार के हाथ में देना है। रूस की बालशेविक पार्टी का यही प्रधान उद्देश्य था।

इसके विरुद्ध मेनशेविक पार्टी का कहना था कि ‘ज़ार’ सत्ता को हटा कर व्यवसायी वर्ग सत्ता स्थापित करना चाहिये। इसी दिशा की ओर जनता को चलाना चाहिये नहीं तो क्रान्ति का उद्देश्य अधूरा रह जावेगा।

सारे देश में वातावरण भी गम्भीर था। ‘ज़ार’ सरकार का स्थायी रहना

^१ लेनिन का विचार था कि इस क्रान्ति का रूप इस प्रकार होना चाहिये :

“A peasant revolution led by the proletariat.”

असम्भव हो गया। १९०५ की क्रान्ति के समय 'ज़ार' ने यह आश्वासन दिया कि एक वैधानिक सरकार (constitutional government) शीघ्र स्थापित की जावेगी और लोगों से शान्ति रहने की प्रार्थना की। एक सामयिक सरकार (provisional government) का निर्माण भी कुछ समय बाद हुआ। पर असंतोष जारी रहा, आन्दोलन बढ़ता गया और श्रमिक उत्तरोत्तर शक्तिशाली एवम् आशावादी होते गये। वैधानिक तौर से सारी शक्ति सरकार के हाथ में थी, परन्तु वास्तव में सोवियट (श्रमिकों) के हाथ में शक्ति बढ़ रही थी। इस प्रकार शक्ति का द्विवाचक रूप (dual character) था। यद्यपि उस सामयिक सरकार के हाथ में वैधानिक शक्ति थी पर वह कमजोर व निर्धन होती जा रही थी। इसके विरोध में सोवियट शक्ति दिनोंदिन बढ़ रही थी। लेनिन का नारा था कि सामयिक सरकार व्यवसायिक दल की अस्थायी सरकार है, उसका अन्त शीघ्र से शीघ्र किया जाये और देश में समाजवाद स्थापित किया जावे। लेनिन ने श्रमिकों को सिखलाना चाहा कि उद्योग-धन्धों का कैसे प्रबंध किया जाये, उत्पादन की बागडोर अपने हाथ में लेकर अनुशासन सहित कैसे काम किया जाये और किस तरह क्रान्ति उत्पन्न करके सारा शासन अपने हाथ में कर लिया जाये।

१९१४ के प्रथम महायुद्ध ने दशा और बिगाड़ दी। देश में युद्ध की आवश्यक सामग्रियों की कमी थी। १९१५ में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया रूस के पास जर्मनी की अपेक्षा गोले बारूद लगभग दस गुना कम थे और १९१७ तक तो दशा और गम्भीर हो गई थी। सरकार ने युद्ध सामग्री आयात का प्रबन्ध पूर्णरूप से करने की चेष्टा की, पर यातायात सुविधायें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न थीं। व्लाडीवोस्तोक से (Vladivostok) आयात करने पर सामग्री ट्रांस-साइबेरियन रेलवे लाइन (Trans-Siberian Railway) पर से हजारों मील चलकर केन्द्र पर कहीं पहुँच पाती थी। इंग्लैण्ड इत्यादि भिन्न राष्ट्रों द्वारा भेजा हुआ तमाम सामान यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण बन्दरगाह पर हो पड़ा रह गया और आन्तरिक प्रदेशों में न पहुँच पाया। युद्ध सामग्री के अतिरिक्त लोह तथा इस्पात का उत्पादन १९१६ में १९१४ की अपेक्षा $\frac{1}{2}$ भाग कम था और कोयला उत्पादन भी $\frac{1}{10}$ भाग कम हो गया था। १९१६ में, रेलवे इंजनों की लगभग $\frac{1}{2}$ भाग शक्ति कार्य पर से हट चुकी थी और १९१७ तक तो सम्पूर्ण शक्ति का $\frac{1}{2}$ भाग बेकार हो चुका था।

यही नहीं तमाम उच्च रेलवे पदाधिकारी युद्ध के काम पर बुला लिये गये थे और बहुत से रेलवे व्यवसाय रेलवे-सामग्री उत्पादन करने के स्थान पर युद्ध

यन्त्र का निर्माण करने लगे थे। रेलवे यातायात की अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र था जिसका कार्य यातायात असुविधा के कारण अस्त-व्यस्त न हुआ हो।^१

युद्ध कार्य में लगभग १५० लाख व्यक्ति का प्रवृत्तिकरण (mobilisation) हो चुका था। कृषि तथा उद्योग धन्धों से एक तिहाई संख्या में श्रमिकों को निकालकर युद्ध कार्य में लगाया जा चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन प्रान्तों में जहाँ पुरुष जाति कृषि व्यवसाय को सम्हाले थी, पुरुष श्रमिकों की अधिक कमी पड़ी। १९१६ तक सस्य क्षेत्र (crop area) १० प्रतिशत, आलू क्षेत्र (potato area) १५ प्रतिशत और चुकन्दर क्षेत्र (sugarbeat area) २० प्रतिशत कम हो गई। प्रति एकड़ उत्पादन में भी ह्रास हुआ। यातायात असुविधा के कारण कृषकों ने उत्पत्ति को बाहर भेजने या विक्रय करने में भी उदासीनता दिखलाई। गल्ले के क्रय-विक्रय परिणाम में भी काफी कमी हो गई थी।

गल्ले के उत्पादन में भारी कमी होने के कारण मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई। इस महान अर्थ संकट ने १९१६ के बाद अधिक प्रबलता दिखलाई। इसका एक विशेष कारण यह था कि कृषकों ने गल्ले को बेचकर १९१६ से पहले मुद्रा की एक बड़ी राशि को अनजान में चलन में आने से रोक लिया था। १९१६ के बाद बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। तमाम मुद्रा को चलन में पुनः छोड़ दिया गया, क्योंकि कृषकों का विश्वास मुद्रा की ओर से हट गया था। वे मुद्रा के स्थान पर सामग्री संचय करने में अधिक विश्वास करने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि निर्मित सामान की कमी बढ़ गई और मुद्रा स्फीति ने अधिक प्रबलता दिखलाई। खाद्य-पदार्थ, निर्मित सामान तथा सारी आवश्यक वस्तुओं की कमी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। कर्मचारियों, श्रमिकों तथा कृषकों को अत्यधिक कष्ट मिला। क्रान्तिकारी तथा हिंसात्मक घटनायें पुनः सुनायी पड़ने लगी। चारों ओर क्रान्ति की आग लग चुकी थी और उसका रुकना साधारणतया असम्भव सा प्रतीत होने लगा। उकसाने तथा उभारने के लिये युवक जन ने नारे लगाये कि जब खाने को रोटी नहीं है तो जीना कैसा। देश की सारी पार्टियों ने इस प्रवृत्ति को उकसाया और क्रान्ति रूपी अग्नि में बराबर तेल डालते रहे।

फरवरी १९१७ को निराश होकर 'ज़ार' ने शासन की बागडोर संसद को (जिसको ड्यूमा कहते थे) दे दी। राजनैतिक परिस्थिति को काबू करना ड्यूमा के लिये आसान न था। ११ मार्च १९१७ को ड्यूमा के सभापति ने 'ज़ार' को तार

द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जिससे मालुम होता है कि परिस्थिति काफी बिग गयी थी :

“यातायात एवम् ईंधन की पूर्ति पूर्ण रूप से विस्तृङ्खल हो गई है। राजधानी में अराजकता। सरकार निःसहाय हो गई। साधारण असंतोष में उत्तरोत्तर वृद्धि—सड़कों पर बलबा तथा गोली चलना।”

महारानी ने भी अपने पत्र में ‘ज़ार’ को लिखा : “यह गुंडों का आन्दोलन है। युवक पुरुष जन समुदाय को उत्तेजित करने के लिये चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि खाने को रोटी नहीं है और उनके साथ ऐसे श्रमिक दल हैं जो दूसरों के काम पर बाधा पहुँचाते हैं।”

‘ज़ार’ ने अपना राज्य शासन मार्च १२, १९१७ को त्याग दिया और अस्थायी रूप से एक सामयिक सरकार ने (provisional government) शासन अपने अधिकार में ले लिया। ‘ज़ार’ की सरकार ने स्वयम् १९१६ में खाद्यान्न व्यापार को नियन्त्रित कर रक्खा था। उत्पत्ति का एक अंश अनिवार्य रूप से निश्चित मूल्य पर खरीद लिया जाता था। मार्च २५, १९१७ से नयी सरकार ने इस दिशा में कुछ नये कदम उठाये और शीघ्र ही खाद्यान्न व्यापार में राज्य एकाधिकार स्थापित किया गया। निजी व्यापार (private trade) पर पूर्ण रोकथाम रक्खा जाने का आयोजन किया गया। पर सारी राज्य कार्यवाहियाँ सफलतापूर्वक प्रचलित न की जा सकी। निजी व्यापार थोड़ा-बहुत हाता रहा। कृषि पदार्थों के मूल्य कई गुना बढ़ गये। १९१७ में १९१४ का अपेक्षा रोटों का मूल्य ३ गुना, दुग्धशाला पदार्थ का ५ गुना, मांस इत्यादि का मूल्य ७ गुना बढ़ गया तथा निर्मित माल और ईंधन के मूल्य में इससे भी अधिक वृद्धि हुई। यद्यपि नगद पारिश्रमिक में वृद्धि, रोटी के बढ़े हुए मूल्य की अपेक्षा अधिक हो गई थी, फिर भी मांस तथा निर्मित सामान के मूल्य की अपेक्षा अधिक न थी। औद्योगिक श्रमिकों ने ही नहीं, बल्कि कृषक वर्ग ने भी हड़तालें कीं। सामयिक सरकार ने एक मुख्य आर्थिक समिति (Chief Economic Committee), जीवन को सुसंगठित एवम् व्यवसायिक बनाने के उद्देश्य से, स्थापित की थी। पर इस समिति पर किसी का विश्वास न था; इसका कोई निश्चित नियम न था और शीघ्र ही इसका अन्त हो गया। यातायात अव्यवस्था और ईंधन अकाल ऐसी घटनाएँ थीं जिन्होंने सारा वातावरण चिन्ताजनक एवम् हिंसात्मक बना दिया। कायले का उत्पादन १९१७ में गत वर्ष से कम था। लोह तथा इस्पात की मट्टियाँ में काफी काम रुक गया था और गत वर्ष की अपेक्षा २० प्रतिशत उत्पादन कम था। कुछ जिलों में वस्त्र उद्योग के कारखाने बन्द हो गये और आटे का चक्कियाँ

भी बहुत सी स्थगित कर दी गई थीं। उद्योग-धन्धे पतन की ओर अग्रसर थे और सामान्य आर्थिक दशा सोचनीय थी।

भूमि सम्बन्धी भ्रष्टता एवम् स्वेच्छाचार

(agrarian lawlessness)

अनेक महान शक्तियों नवम्बर की क्रान्ति की ओर देश को उन्मुख कर रही थी। कृषक समुदाय भूमि पर अवैधानिक रीतियों से अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। सरकार ने कृषकों को विश्वास दिलाना चाहा कि भूमि सम्बन्धी विधान शीघ्र ही बनेगा और उनकी अवस्था में सुधार किया जायेगा। पर कृषकों को धैर्य न था, और वे प्रतीक्षा करने के पक्ष में न थे। वे जानते थे कि वैधानिक रूप से सुधार होना आसान नहीं है। भ्रष्टता व स्वेच्छाचार की तमाम घटनाएँ सुनने में आती थीं। हिंसा तथा बबोदी बढ़ गयी थी। बहुत से गाँवों में जमींदारों के मकान जला दिये गये। बहुत सी भूमि को कृषकों ने जब्त कर लिया और अवैधानिक रूप से उस पर अधिकार कर लिया गया। सितम्बर तथा अक्टूबर के महीने में अधिकतर हिंसात्मक तथा क्रान्तिकारी घटनाएँ घटीं। कृषकों के विचार बदल गये थे। पुराने समय में वे जिस भूमि पर काम करते थे उसे भूस्वामी को भूमि समझते थे, पर अब भूमि के स्वामित्व पर उनका ध्यान अधिक था।^१

उद्योग सम्बन्धी भ्रष्टता एवम् स्वेच्छाचार

(industrial lawlessness)

उद्योगों और कारखानों में भी प्रत्यक्ष रूप से बलवा हो रहा था। सामयिक सरकार के हाँथ-पॉव फूल गये थे। सर्वहारा वर्ग सामयिक सरकार को शासन से तुरन्त हटाना चाहते थे। अनेक स्थानों पर श्रमिकों ने संचालकों व यान्त्रिकों को घंटों कैद रक्खा और कारखानों का काम न चलने दिया। श्रमिकों ने अपने संघ बनाए जिन्हें श्रमिक-संघ या फैक्टरी समिति की संज्ञा दी गयी। इस समिति ने डायरेक्टरों व कारखानों के मालिकों को कारखानों से निकाल

१ दास वृत्ति (serfdom) के समय एक कृषक मोचता था : “We are the landlord's, but the land we work is ours” अब समय इतना बदल चुका था कि वही कृषक मोचता था . “The landlord is our landlord . we worked for him and his property is ours” *L. Owen : The Russian Peasant Movement—p. 132-52*

देने की धमकी दी और बहुत से स्थानों पर भीषण घटनाएँ घटीं। कहीं कहीं तो अगर एक निश्चित अवधि के अन्दर फैक्टरी संचालकों ने श्रमिकों की सारी माँगें पूरी करने का आश्वासन न दिया था, तो उन्हें बहुत सताया गया। उद्योगपतियों के एक समुदाय ने श्रम-मंत्री (minister of labour) के पास शिकायत भेजी : “अपराधियों को बड़ा से बड़ा अपराध करने पर भी दण्ड नहीं मिलता है,” और निवेदन किया, कि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही होनी चाहिये। एक स्थान पर २४ घंटे से अधिक एक कारखाने के प्रबन्धकों को श्रमिकों ने बन्दी कर रक्खा था। स्थान-स्थान पर हड़तालें हो रही थीं और शायद ही कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बच गया हो जहाँ से हिंसात्मक घटनायें सुनने में न आई हों।

देश के तमाम राजनैतिक दल इस परिस्थिति को और गंभीर बना रहे थे। १९१७ के पूर्व देश में दो दल थे, (क) समाजवादी प्रजातंत्र श्रम दल (Social Democratic Labour Party), जिसके अनुयायी श्रमिक वर्ग तथा शिक्षित नागरिक (urban intelligentsia) थे। बाद में चल कर इसके दो दल हो गये (१) बालशेविक (Bolshevik) तथा मेनशेविक (Menshevik)। (ख) समाजवादी क्रान्तिकारी दल (Social Revolutionary Party), जिसके अनुयायी कृषक वर्ग तथा ग्रामीण पुरुष थे। इस क्रान्तिकारी दल ने ‘ज़ार’ व दूसरे पदाधिकारियों के विरुद्ध षडयन्त्र रचे तथा अनेक आतंकवाद कार्य किये। इस दल का उद्देश्य था—भूमि का समाजीकरण करना और कृषक वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। इस दल के नेताओं का विशिष्ट नारा था “भूमि से स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता से भूमि।” १९१७ तक इस पार्टी में दो पक्ष हो गये।

(१) गरम दल (Left Wing)

(२) नरम दल (Right Wing)

नरम दल का मुकाब अधिक समृद्धि कृषकों की ओर था और वे उन्हीं के हित की नीति भी अपनाना चाहते थे। इस प्रकार ग्राम के धनवान कृषकों की यह एक पार्टी हो गई। परन्तु इसके विरुद्ध गरम दल निर्धन, असहाय तथा दुर्बल किसानों का एक बहुत बड़ा दल था, जिसने कि हिंसा तथा क्रान्ति को आधार मान कर गाँवों में परिवर्तन लाने की ठान ली थी और १९१७ में कृषक वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधि तथा प्रवक्ता (spokesman) के रूप में इसने महान कार्य किये थे। इस दल के उद्देश्य बालशेविक पार्टी से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे और लेनिन ने जब कृषक तथा श्रमिक की सन्धि का आन्दोलन चलाया यह दोनों पार्टियाँ आपस में मिल गयीं और एक ही दिशा की ओर काम करने लगीं। नयी सोवियट सरकार, जिसको शीघ्र ही स्थापित करने की कल्पना रूस की जनता करने

लगी थी, बालशेविक पार्टी तथा गरम दल के आन्दोलन का परिणाम था। सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर के महीनों में जितना भी राजनैतिक कार्य तथा क्रान्तिकारी बलवा देश में हुआ उसको चलाने वाली रूस की ये दो पार्टियाँ थीं, जिन्होंने लोगों के दिल तथा दिमाग पर नयी सोवियट सरकार का चित्र खींच दिया था और बड़ी अधैर्यता से वे पुरानी रीतियों का, पुराने शासन का तथा पूँजीवाद का उन्मूलन करके सोवियट सरकार स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे। फरवरी १९१७ से ही देश भूखा, बेचैन, अधीर तथा चंचल हो गया था। बालशेविक पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ गया था। इसने विश्वास दिलाया कि शासन शक्ति पाने के बाद जनता के कष्ट दूर किये जावेंगे। जनता की चार माँगे थी जिन्हें पूरा करने का आश्वासन इस पार्टी ने दिया।

(क) सब के लिये रोटी का प्रबन्ध ;

(ख) शीघ्र शान्ति का प्रबन्ध ;

(ग) कृषकों के लिये भूमि का प्रबन्ध ;

(घ) सर्वहारा वर्ग के शासन का प्रबन्ध ;

सारे देश ने अपने भाग्य को लेनिन तथा ट्राट्स्की को सौंप दिया, जिन्होंने अक्टूबर की क्रान्ति को अपनी असाधारण योग्यता से सुसंगठित किया था।

तीसरा अध्याय

नियन्त्रित पूँजीवाद युग

क्रान्ति के बाद प्रथम आठ महीने

शासन सत्ता पाने के बाद बालशेविक पार्टी ने सोवियट संघ को एक नई दिशा की ओर उन्मुख किया। इसके अन्तर्गत कुछ कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कुछ के उत्पादन एवम् संचालन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाये गये। पर किसी विशेष उद्योग का सम्पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण न हुआ और न सरकार ने किसी उद्योग के तमाम कारखानों को विस्तृत एवम् व्यापक रूप से अपहरण ही किया। इसके प्रतिकूल कुछ नियन्त्रणों की प्रतिसीमा में पूँजीवाद का प्रतिपादन किया गया।

क्रान्ति के बाद जब बालशेविक पार्टी ने शासन की डोर सम्हाली, रूस की सारी जनता एकदम समाजवाद चाहती थी। जनता भावुक थी, डरी हुई थी, अधैर्य थी, पीड़ित थी और क्रान्ति के उपरान्त अपनी स्थित में शीघ्र परिवर्तन होने का स्वप्न देख रही थी। वह कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि सोवियट संघ बन जाने के बाद भी पूँजीवाद पर देश अवलम्बित रहेगा और उसका उन्मूलन करने के स्थान पर उसे केवल नियन्त्रण में ही रखा जावेगा।

लेनिन ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किये। उसने लोगों को बतलाया कि समाजवाद की स्थापना रूस में एकदम नहीं हो सकती। क्रान्ति से यह तात्पर्य नहीं है कि समाजवाद स्थापित हो गया है। क्रान्ति तो केवल एक क्रमोन्नति है; प्रगति है, कार्य प्रक्रिया है। समाजवाद की पूर्ण स्थापना करने के लिये इस प्रकार की और तमाम क्रियाओं को भी पूरा करना होगा। एक बार अगर पूँजीवाद का विनाश हो भी जावे पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजवाद स्थापित हो चुका है। इसके अतिरिक्त पूँजीवाद का तुरन्त उन्मूलन कोई अपने हित की बात न थी। लेनिन का विचार था कि यद्यपि नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न

हो गई हैं फिर भी इस नये वातावरण में नवीन सामाजिक सम्बन्ध अचानक स्थापित नहीं हो सकते। सोवियट सरकार अभी शासन सम्बन्ध में अनुभवहीन थी। समाजवाद के विशाल ग्रह निर्माण की नींव भी इसी युग में पड़नी चाहिये थी। पर यह महान कार्य एक दिन में होना असम्भव था। क्रान्ति तो केवल एक असमयिक दुर्घटना है। लेनिन का विचार था कि पूँजीवाद-समाजवाद परिवर्तन काल में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होंगी, जिनका हल करना सरल न था। इस महान कार्य में प्राचीन पद्धतियों को त्यागकर नवीन पद्धति को व्यापक रूप में अपनाना कोई साधारण बात न थी। लेनिन ने सोवियट जनता को यह पाठ अच्छी प्रकार पढ़ाया। इसने कहा कि हमको नये सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने में ऐसी कुशलता दिखलानी है कि प्राचीन पद्धतियाँ कम से कम परिस्थितिबश अस्त-व्यस्त हों और इनके स्थान पर नवीन पद्धतियाँ अधिक से अधिक ग्रहण की जावें।^१

इस प्रकार श्रमिकों तथा कृषकों के ऊपर महान उत्तरदायित्व आ गया था जिसे वे न समझ पा रहे थे और जिसे समझाने का पूरा प्रयास लेनिन ने किया था। निःसन्देह श्रमिक एवम् कृषक वर्ग समाजवाद चाहते थे, पर इसकी स्थापना से पूर्व कितना काम उन्हें स्वयम् करना था, इस पहलू पर किसी का ध्यान भी न गया था। नयी सोवियट सरकार ने यह निर्णय किया कि उत्पत्ति साधन तथा उत्पादन पर कठोरतम नियन्त्रण रक्खा जावेगा और श्रमिक तथा कृषक वर्ग से यह आग्रह किया गया कि खाद्यान्न, उद्योग, यन्त्र, उत्पादन, यातायात इत्यादि की सुरक्षा एवम् निरीक्षण उन्हें उसी प्रकार करनी है जैसे अपने शरीर के किसी अंग की की जाती है। जितनी सावधानी एवम् तत्परता से वे इस कार्य को करेंगे उतनी शीघ्रता से समाजवाद स्थापित हो सकेगा। यह ऐसा परिवर्तन काल था जिसमें श्रमिकों को उद्योग सम्बन्धी अनेक कार्य सीखना तथा अधिक से अधिक व्यवहारिक अनुभव करना था। उनको मालूम होना चाहिये था कि कारखाने कैसे संचालित किये जावें, उत्पत्ति वितरण कैसे हो तथा उत्पत्ति साधन सामग्री का किस प्रकार संग्रह हो। इन कार्यों में आकुलता एवम् विह्वलता की आवश्यकता कदापि न थी।

१४ नवम्बर को सोवियट सरकार ने यह प्रादेश (decree) प्रकाशित किया कि प्रत्येक कारखाने की श्रमिक-समिति को यह अधिकार दिया जावे कि वे अपने व्यवसाय का प्रबन्ध और न्यूनतम उत्पादन का निर्णय स्वयम् कर सकें।

साथ ही साथ यह भी निर्णय किया गया कि व्यापारिक लेखे तथा पत्र व्यवहार तक उनकी पूरी पहुँच हो और वे उसका नियमानुसार निरीक्षण तथा जाँच कर सकें। इस प्रादेश के साथ-साथ सोवियट सरकार ने श्रमिकों को यह चेतावनी भी दी थी कि अनुचित ढंग से अगर वे कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ ले लेंगे तो बनता हुआ काम बिगड़ जावेगा और समाजवाद की स्थापना में बाधा पहुँचेगी। सोवियट सरकार ठीक समझती थी कि समाजवाद स्थापना प्रारम्भिक युग में एक ऐसा कोमल कार्य था, जिसकी ओर प्रत्येक कदम सावधानी से उठाना चाहिये था। लेनिन ने लोगों को बतलाया कि इस परिवर्तन काल की विशेषता यह थी कि इसमें पूँजीवाद एवम् समाजवाद दोनों के मूल सिद्धान्तों का ऐसा समन्वय किया गया था जिसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख गुण उपस्थित थे।

यह एक ऐसी नवीन अर्थव्यवस्था थी जो न तो पूर्ण पूँजीवाद की और न पूर्ण समाजवाद की प्रतिनिधि थी। यह एक ऐसा मिश्रण था जो पूँजीवाद तथा समाजवाद के कणों को मिलाकर बना था। लेनिन ने १९१८ में एक पुस्तिका निकाली जिसमें उन्होंने पूँजीवाद तथा समाजवाद समन्वय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों में किया : "This form of economy contained elements, particles, pieces of both capitalism and socialism."^१

इस नीति के अनुसार किसी उद्योग का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। केवल उन्हीं व्यवसायों को सरकार ने अपने हाथ में लिया जिनका किसी विशेष कारण से सरकार के हाथ में आना अत्यन्त आवश्यक था। जिन कारखानों का राष्ट्रीयकरण हुआ वे निम्नलिखित कारणों में से किसी न किसी एक से अवश्य प्रभावित थे :

- (१) अमुक व्यवसाय देश के लिये महत्त्वपूर्ण हो।
- (२) कारखाने के मालिकों द्वारा श्रमिक-नियन्त्रण निर्णय (decree on worker's control) का प्रतिषेध (refusal) हो।
- (३) मालिकों ने कारखाना संचालन कार्य स्थगित कर दिया हो।
- (४) हड़तालियों द्वारा मिलों में अन्तर्ध्वंस एवम् अशान्ति उत्पन्न की गयी हो।
- (५) मालिकों द्वारा श्रमिकों की छूटनी का निर्णय किया गया हो।
- (६) श्रमिकों का काम न करने का ध्येय हो।

^१ Lenin : Selected Works. p. 165, 170,

(७) किसी अन्य कारणवश व्यवसाय स्थगित कर दिया गया हो।

मई १९१८ तक किसी भी उद्योग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण न हुआ। इसी मास चीनी के उद्योग को एक सरकारी मण्डल के प्रशासन (administration) में रखा गया। एक मास पश्चात् तेल के उद्योग में भी राज्य-एकाधिकार की घोषणा की गयी और इसके पश्चात् सरकारी हस्तक्षेप बराबर बढ़ता गया। मई १९१८ के पूर्व जितने भी कारखानों में राज्य का प्रशासन हुआ, वह या तो श्रमिकों के काम न करने के कारण था, या मालिकों की उदासीनता के कारण अथवा किसी ऐसी अचानक घटना के कारण, जिससे उत्पत्ति में हास हुआ हो।

१७ दिसम्बर १९१७ को संयुक्त पूँजी बैंकों को राज्य बैंक में विलीन कर दिया गया क्योंकि राज्य बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी। गल्ले के व्यापार में तो सामयिक सरकार के समय से ही राज्य-एकाधिकार था। इस क्षेत्र में कोई नई बात इस समय न हुई केवल इसके कि कृषि सम्बन्धित यंत्र तथा गल्ला गोदामों के राष्ट्रीयकरण की नीति को कठोरता से चलाया गया। प्रारम्भ के कुछ महीनों में ही इस क्षेत्र के आधे से अधिक व्यक्तिगत व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण यही था। श्रमिक वर्ग सारे कार्य अवैधानिक रूप से अपने हाँथ में लेना चाहते थे और मशीनों का अर्न्तर्ध्वंस कर रहे थे। बहुत से स्थानों पर मिल-मालिकों ने मिलें बन्द कर दीं थीं क्योंकि वे इस अशान्त वातावरण में मिल चलाने के विपक्ष में थे। ऐसे कारखानों को भी सरकार ने तुरन्त ले लिया। बहुत से व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण केवल इसलिये किया गया कि वे राष्ट्र के लिये बहुत ही उपयोगी थे। आवश्यकतानुसार या परिस्थितवश होकर ही कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सम्पूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण की यह कोई सामान्य तथा व्यापक नीति न थी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इस युग में कुछ व्यवसायों का तो राष्ट्रीयकरण किया गया और कुछ को केवल नियन्त्रण में ही रखा गया। निजी व्यापार तथा निजी व्यवसाय को राज्य व्यापार तथा राज्य व्यवसाय के साथ-साथ चलने का आयोजन किया गया। संयुक्त नियन्त्रण मण्डल (joint controlling bodies) बनाये गये जिनके सदस्य श्रमिक संघ, निजी कम्पनी तथा सरकार के प्रतिनिधि थे। लघु उद्योगों में लगभग इसी प्रकार का मिलता-जुलता एक संयुक्त नियन्त्रण मण्डल, जिसे “सेन्टर” कहते थे, बनाया गया। प्रत्येक उद्योग का अलग-अलग मण्डल था। इन मण्डलों का प्रमुख कार्य नियम बनाकर श्रमिक समितियों (कारखाना समितियों) के पास भेजना था और प्रत्येक समिति अपने व्यवसाय

का प्रबन्ध उन्हीं के आदेशानुसार करती थी। इस प्रकार लघु उद्योगों में स्थानीय प्रबन्ध पर अधिक जोर दिया गया।

भारी उद्योगों में (heavy industries) केन्द्रीयकरण अधिक था और उनका प्रबन्ध 'ग्लैवकी' या सर्वोच्च आर्थिक परिषद के उप-विभागों (sub-departments of Supreme Economic Council) के आदेशानुसार किया गया। इस परिषद में सरकारी विभागों तथा श्रमिक संघों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। प्रारम्भ इसी प्रकार किया गया। पर इस नीति का कोई स्थायी रूप न था। दिन प्रति दिन केन्द्रीयकरण की प्रगति होती रही। नियन्त्रित पूँजीवाद युग में अग्रिम समाजवाद की स्थापना के लिये पुष्ट नींव की आवश्यकता थी, जो पूँजीवाद के अनुभव तथा ज्ञान पर ही आधारित थी।

कुछ व्यवसायों में जहाँ विदेशी पूँजी लगी थी यह प्रस्ताव रक्खा गया कि मिश्रित कम्पनियाँ (mixed companies) बनायी जावें। जिसका तात्पर्य ऐसी कम्पनियों से था जिनमें निजी पूँजीपति तथा सरकार के संयुक्त अंश हों। मास्को के एक धनवान विदेशी व्यापारी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि अगर सरकार को स्वीकार हो तो धातु के उद्योग में विदेशी निजी पूँजी तथा सरकारी पूँजी साथ साथ लगायी जाये। सरकारी क्षेत्रों में इस विषय पर बड़ा मतभेद था और अन्त में जब यह बात लेनिन के सम्मुख आयी उसने इसको अस्वीकार कर दिया और कहा : "भारी उद्योगों में हमें अंशभागी (shareholders) नहीं चाहिये, हमें तो यंत्रकार (engineers) चाहिये।"

श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीयकरण नीति का दुरुपयोग

(malpractices through nationalisation)

राज्य पूँजीवाद (state capitalism), या नियन्त्रित पूँजीवाद (controlled capitalism या directed capitalism) अर्थव्यवस्था नीति मई १९१८ के बाद न चल सकी। श्रमिकों ने धैर्य त्याग दिया और आर्थिक दशा बड़ी चिन्तनीय हो गयी। प्रचलित राजनैतिक अवस्था में यह असम्भव सा प्रतीत होने लगा कि राज्य-पूँजीवाद प्रतिपादन कर सकेगा। श्रमिकों में भ्रष्टाचार एवम् दुराचार बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने श्रमिक संघ को कारखाने के प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता दे दी थी, जिसका उन्होंने सीमा उलंघन कर पूर्ण दुरोपयोग किया। बहुत सी व्यवसायी समितियों ने अवैधानिक रूप से कारखाना संचालन कार्य को अपने अधिकार में कर लिया। जिस प्रकार साम्यिक सरकार के समय श्रमिक एवम् कृषक वर्ग प्रत्यक्षा रूप से विद्रोह कर रहे थे,

उसी गति को निरन्तर जारी रखा। वे यह भूल गये कि अब सोवियट सरकार स्थापित हो चुकी है और यह प्रवृत्ति हितकर नहीं है। इतिहासकारों ने इसीलिये इसको “क्रान्ति का मौलिक युग” (“elemental period of revolution”) की संज्ञा दी। इस युग में अधिकतर कार्य विषमवर्गिक थे जिनमें केन्द्रीय सरकार का अधिक हाथ न था। वे स्थानीय प्रभावों के अन्तर्गत थे।

१९१८ की वसंत ऋतु तक कारखाने समितियों (श्रमिक समितियों) की प्रबल धारणा हो गई थी कि हर एक कारखाने का संचालन श्रमिकों द्वारा होना चाहिये। इसका परिणाम यह हुआ कि कारखानों से अनुशासन जाता रहा। कार्य में असावधानी एवम् अनियमिता बढ़ जाने से उत्पादन में क्षति पहुँची। अनेक स्थानों पर श्रमिकों के मन में वर्गीय, जातीय एवम् प्रान्तीय भेदभाव आदि ऐसी स्वार्थतत्परता आ गयी थी जिससे राष्ट्रीय हित पर कुठाराघात हुआ। श्रमिकों का तो यह हाल हो गया था कि वे केन्द्रीय नियन्त्रणों का डट कर विरोध करते थे और उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय कार्यों में हस्तक्षेप करने के प्रतिपक्ष में थे। राष्ट्रीय हित के स्थान पर उनका अपने हित की ओर अधिक ध्यान था। इस वेग में उन्होंने बहुत से निन्दनीय एवम् दुष्टाचारी कार्य किये। उत्पत्ति एवम् विक्रय में भी सरकारी हित का ध्यान न देकर वे बिना उचित समन्वय एवम् सहयोग के स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने लगे। किसी ने लिखा : “एक क्षेत्र में खनिज पदार्थ व्यवसायी ने एक दूसरे व्यवसायी को कोयला तथा लोहा साख (credit) पर देने से इन्कार कर दिया और राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान न देकर लोहे को कृषकों के हाँथ बेचा डाला।” सच बात तो यह थी कि व्यवसायियों में आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय का अभाव था तथा श्रमिकों में अनुशासन की कमी थी।

‘वेसान्खा’ नामक एक ऐसी समिति थी जिसका प्रधान कार्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना था। बिना इसकी अनुमति के कोई व्यवसाय सरकार अपने हाँथ में न ले सकती थी। तमाम स्थानों पर ऐसा हुआ कि श्रमिकों ने न तो कोई राय ‘वेसान्खा’ से ली और न उसे व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने की सूचना ही दी। जो भी आदेश ‘वेसान्खा’ द्वारा भेजे गये उनका श्रमिक-समितियों ने उलंघन किया। जैसे-जैसे ‘वेसान्खा’ ने केन्द्रीय नियंत्रण को प्रोत्साहित किया वैसे-वैसे श्रमिक समितियों ने उनकी अवहेलना की। कई स्थानों पर श्रमिक समितियों ने मालिकों के विरुद्ध आन्दोलन चलाकर कारखानों को अपने अधिकार में कर लिया। इन अवैधानिक कार्यों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। जुलाई १९१८ के पूर्व लगभग १०० ऐसे व्यवसाय थे जो बिना ‘वेसान्खा’ की

सम्मति से राज्य में मिला लिये गये थे और लगभग ४०० ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण स्थानीय प्रभावों के कारण अथवा श्रमिकों के अशान्ति फैलाने के कारण किया जा रहा था। एक “मोलेसेस तथा स्टार्च” के कारखाने का जब राष्ट्रीयकरण करके, ‘वेसान्वा’ ने उसे एक प्रबन्धक (administrator) को सौंपा, श्रमिक-समिति ने उसे हस्तांतरित करने से इन्कार कर दिया। उसी प्रकार जब उत्तरी राज्यों में धातु सम्बन्धी कार्य करने वालों में सहयोग प्रदान करने के लिये तथा उत्पत्ति में सम्पूर्ण नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से सरकार ने निरीक्षक नियुक्त किये, श्रमिक समितियों एवम् निरीक्षकों में बड़ा संघर्ष हुआ और श्रमिकों ने प्रत्यक्ष रूप से उनका सामना किया। श्रमिकों ने हर क्षेत्र में असीमित अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। रेलवे कम्पनी के श्रमिकों ने सारे देश के श्रमिक संघ या समितियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संघ बनाया जिसका उद्देश्य था कि राजकीय नियंत्रण के स्थान पर उन्हें स्थानीय स्वतन्त्रता दी जावे और हर कारखाने के श्रमिकों के हाँथ में अत्याधिक अधिकार रहे ताकि वे उनका प्रबन्ध स्वेच्छानुसार कर सकें। समाजवाद के सारे सिद्धान्त का उन्होंने दुरुपयोग किया। राज्य द्वारा प्राप्त सीमित अधिकारों से श्रमिक-समितियाँ सन्तुष्ट न थी। वे सारे उद्योग, सारा व्यवसाय, सारे क्षेत्र तथा तमाम उद्योग-धंधे अपने हाथ में ले लेना चाहती थीं और इसी की समाजवाद समझती थीं।

बालशेविक पार्टी के अन्दर व बाहर भी लोगों में बड़ा मतभेद व विरोध उत्पन्न हो गया था। पार्टी के अन्दर साम्यवादी दल के व्यक्तियों ने लेनिन की “नियंत्रित पूँजीवाद” नीति की निन्दा की और लेनिन पर धनवान पुरुष एवम् पूँजीपतियों से मिल जाने का दोषारोपण किया। वास्तव में बात यह थी कि लेनिन ने तमाम कुशल एवम् धनवान, यंत्रकारों तथा अर्थशास्त्रियों को उच्च नौकरी प्रदान की थी और उनसे उद्योग सम्बन्धी काम सीखने का प्रबन्ध किया था। विपक्षियों ने इस बात की आलोचना की और लेनिन एवम् उसके साथियों को पूँजीपतियों से मिल जाने का लांछन लगाकर दोषित ठहराया। ट्रेड यूनियन की वार्षिक बैठक में वैज्ञानिक प्रबन्ध (scientific management) एवम् औद्योगिक संगठन के सिद्धान्तों पर पूर्ण ध्यान दिया गया। उन सिद्धान्तों को अनुकरण करने का आयोजन किया गया। परिणाम यह हुआ कि बालशेविक पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने अपना पद त्याग दिया और लेनिन को दोषित ठहराने की शपथ खायी। श्रमिक यह सोच नहीं सकते थे कि रूसी उद्योगों में पूँजीवाद उन्मूलन के उपरान्त भी औद्योगिक संगठन एवम् वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त कभी ग्रहण किये जावेंगे। आवेग में उन लोगों ने इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को

पूँजीवाद-शोषण के ध्वंसावशेष" ("relics of capitalist exploitation") के म से कलंकित किया। बालशेविक पार्टी के एक सदस्य ने रेलवे में उचित लब्ध करने का सुझाव पूँजीवाद देशों में रेलवे प्रबन्ध एवम संचालन को आधार न कर किया था, जिसका फल यह हुआ कि विपक्षियों ने इसी घटना पर लशेविक पार्टी को कलंकित करने की पूरी चेष्टा की।

सरकारी प्रवक्ताओं ने वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा औद्योगिक संगठन के अनेक द्धान्तों के महत्त्व पर विचार किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि "यत्रित पँजीवाद" अर्थव्यवस्था के संचालन के लिये उनका अनुकरण आवश्यक। राजकीय प्रवक्ताओं तथा बालशेविक पार्टी के सदस्यों ने बताया कि ई. इकार्ड के अनुसार पारश्रमिक वितरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध इत्यादि ऐसी द्योगिक प्रथाएँ हैं जिनका पूँजीवाद से सम्बन्ध अवश्य है, पर वे समाजवाद भी एक नेक स्थान रखती हैं। इस नयी अर्थव्यवस्था में जब कि पूँजीवाद त्याग कर समाजवाद अपनाया जा रहा है, यह आवश्यक है कि बहुत सी तैयारियाँ, जहाँ पूँजीवाद प्रथा में कलंकित हो चुकी हैं, एक नये आधार पर प्रारम्भ जावे। वे समाजवाद की स्थापना के कार्य में बड़ी सहायक होंगी। पूँजीवाद प्रथा के अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति या विवेकीकरण इत्यादि प्रथाएँ इसलिये लेती हैं कि पूँजीपति श्रमिक शोषण द्वारा अत्यधिक लाभ उठा सके। परन्तु क शोषण का प्रश्न रूस की नवीन अर्थ व्यवस्था में नहीं उठता था। बल्कि प्रथाओं का इस नवीन परिस्थिति में प्रचलित होना बड़ा लाभप्रद था। लेनिन तलाया कि इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, पारश्रमिक अधिक होगा और म दूसरी सुविधाएँ भी उपलब्ध हो सकेंगी। रूस एक श्रमिक देश है अतः कों के शोषण का प्रश्न यहाँ निर्मूल है।

लेनिन ने अशान्ति दूर करने के दृष्टिकोण से "राज्य पूँजीवाद" ("state talism") शीर्षक नामक एक पत्रिका निकाली जिसमें उसने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किये। उसने पुनः बतलाया कि क्रान्ति के उपरान्त समाजकी स्थापना एकदम नहीं हो सकती। ऐसा असम्भव है। वास्तव में इस र्त्तन के लिये अधिक समय की आवश्यकता थी। यह एक महान अभिमत था। यह एक ऐसा युग था जिसमें पूँजीवाद एवम समाजवाद दोनों के गुण त थे। शनैः-शनैः पूँजीवाद हटा जावेगा और समाजवाद बढ़ता जायेगा, यकरण योजना धीरे-धीरे विस्तृत होगी, राजकीय नियंत्रण दिन प्रति दिन ; श्रमिकों पर उत्तरदायित्व समयानुसार बढ़ेगा और जितनी शीघ्रता से वे कार्य में निपुण होते जावेंगे उसी अनुपात से धनवान यंत्रकार व प्रबन्धकों

से देश को छुटकारा मिलता जावेगा। इस परिवर्तन में तत्परता की आवश्यकता न थी। लेनिन को डर था कि कहीं जल्दबाजी में समाजवाद एक स्वप्न ही न रह जावे।

युद्धकाल में बहुत से पश्चिमी योरोप के देश भी इसी प्रकार की अर्थ व्यवस्था चलाये थे जिसके अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण प्रत्यक्ष व कड़े थे और कुछ में जनता को केवल सीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी। जिन पदार्थों की कमी थी, उन पर अधिक प्रतिबंध थे, सरकारी सहायतार्थ तथा समान वितरण का पूरा प्रबंध था। सोवियट रूस ने लगभग इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का चित्र खींचा था और उसी को कुछ समय तक अपनाने की योजना भी बनायी थी। ऐसा सोचा गया था कि जब सत्ता बढ़ेगी, उत्पादन तथा वितरण सुधर जावेगा तथा श्रमिकों पर अधिक विश्वास हो जावेगा, तब पूँजीवाद को पूर्ण रूप से त्याग देंगे व समाजवाद की प्रगति हो सकेगी। अभी तो वह समय था जब समाजवाद की ओर अग्रसर होने के लिये सारा देश तैयार किया जा रहा था। समाजवाद के बोझ को समझाने के लिये एक दृढ़ नीति की आवश्यकता थी और लेनिन उसी की पुष्टि कर रहे थे। क्रान्ति के उपरान्त लेनिन का यह कभी विचार न था कि पूँजीपतियों का तिरस्कार किया जावे, वरन् उसकी तो योजना थी कि उनको व्यवसायों में उचित वेतन पर रखकर उनसे काम सीखा जावे—कारखाने का प्रबन्ध करना, उत्पादन आयोजित करना, उत्पत्ति को बेचना, उसका वितरण इत्यादि, जो ऐसी कठिन समस्याएँ थीं जिनका सुलझाना पूँजीपतियों से सीखा जा सकता था। लेनिन ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर आवश्यकता पड़े तो योग्य एवम् सांस्कृतिक पूँजीपतियों को मुद्रा का प्रलोभन देकर अपने बस में करके उनसे कार्य संचालन की कुशलता सीखी जावे। ऐसा करने से वे समाजवाद को घृणित न समझ कर, पूँजीवाद नियंत्रण के अन्दर सरकार के आदेशानुसार संलग्न रहेंगे तथा अपना सहयोग इस नवीन अर्थव्यवस्था में देकर श्रमिकों के लिये एक समझदार कुशल तथा अनुभवी संगठन कर्त्ता के रूप में काम करते रहेंगे।

लेनिन ने अपने एक व्याख्यान में कहा : “हम जानते थे जब हमने शासन अपने हाँथ में लिया, पूँजीवाद प्रथा को समाजवाद प्रथा में परिवर्तन करके कोई यथार्थ रूप हमारे पास तैयार न था। हमें कोई ऐसे समाजवाद व्यवस्था का पता भी न था जहाँ ये समस्याएँ कभी सुलझाई गई हों हमको अपने अनुभव के अनुसार चलना है एक बार हमको अनुभव करने का सुअवसर मिला है, हमें चाहिये कि जैसे-जैसे सोवियट राज्यसत्ता बढ़ती जावे, हम इससे पूर्ण लाभ उठाते जावें।” रूस की जनता एवम् श्रमिकों

में अंशान्ति बनी रही। क्रान्तिकारी श्रमिक तुरन्त ही सारा राज्य तथा शासन अपने हाँथ में लेना चाहते थे। वे प्रतीक्षा करने के पक्ष में न थे।

लेनिन ये बतलाया कि जब श्रमिक प्रतिनिधि मण्डल (worker's delegation) मेरे पास कारखानों के प्रबन्धकों की शिकायत लेकर आया, मैंने उनसे हमेशा यही कहा : “तुम अपनी फैक्टरी का राष्ट्रीयकरण चाहते हो। बहुत ही अच्छा है। यह निर्णयपत्र तैयार है और एक क्षण में इस पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। परन्तु तुम्हीं बतलाओ। क्या तुम सारी संस्था अपने हाँथ में ले सकते हो ? क्या तुमने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है ? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कितना व कैसे उत्पादन करते हो ? और क्या तुम्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा उत्पात्ति में क्या सम्बन्ध है—इसका थोड़ा भी ज्ञान है ?” इसका उत्तर यही था कि वे कुछ न जानते थे। बालशेविक या मेनशेविक या किसी भी समाजवाद पार्टी के पास ऐसा कोई ग्रन्थ भी न था जिसमें ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी होतीं। लेनिन को इन तमाम समस्याओं की गंभीरता एवम् व्यापकता का कुछ ज्ञान अवश्य था और इसीलिये वह राष्ट्रीयकरण नीति में किसी प्रकार भी तत्परता दिखलाने को उत्सुक न था।

क्रान्ति के बाद आठ मास तक सरकार का यही प्रयत्न था कि पूँजीवाद को नियंत्रित रूप से रक्खा जाये क्योंकि समाजवाद की स्थापना कोई साधारण बात न थी। अक्टूबर १९१७ से जून १९१८ तक राज्य पूँजीवाद (state capitalism) या नियंत्रित पूँजीवाद (controlled capitalism अथवा directed capitalism) की अर्थव्यवस्था बनाये रखी गयी। मई के महीने से ही कारखाने के राष्ट्रीयकरण करने की गति तीव्र हो चुकी थी और २८ जून १९१८ को लेनिन ने मजबूर होकर सामान्य राष्ट्रीयकरण का निर्णय पत्र (decree of general nationalization of June 28, 1918) प्रकाशित किया, जिसके अनुसार रूस के सारे उद्योग-धन्धों का बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीयकरण हो गया। यह नीति उन सभी कारखानों पर लगाई गयी जिसमें पूँजी दस लाख रबल या उससे अधिक थी।

जून २८, १९१८ की तिथि ने सोवियट इतिहास का एक परिच्छेद समाप्ति किया और युद्धकालीन साम्यवाद नीति का दूसरा भाग प्रारम्भ हुआ। परन्तु ये विद्यार्थी के लिये यह एक आश्चर्यजनक बात होगी कि सोवियट सरकार ने अचानक सामान्य राष्ट्रीयकरण नीति को कैसे ग्रहण कर लिया और ऐसी क्या बात थी जो साम्यवाद के प्रति उसका इतना झुकाव एकाएक हो गया। इसका मुख्य कारण एक आकस्मिक घटना थी। रूस का युद्ध इस समय जर्मनी से हो

रहा था। मास्को में यह आशंका थी कि यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेने के बाद जर्मन फौजें दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में न बढ़ें और देश के व्यवसायी, राष्ट्रीयकरण नीति के डर से, अपनी कम्पनी को जर्मन के हाथ सौंप न दें। लारिन जो इस समय वाणिज्य प्रचारक मण्डल (commercial mission) के साथ बर्लिन में थे, २५ जून को तार द्वारा लेनिन को सूचना दी कि मास्को में जर्मन राजदूत शीघ्र ही ऐसे कारखाने तथा व्यवसायों के नाम का सूचीपत्र पेश करने वाला है जो कि जर्मनी के नागरिक के स्वामित्व में हैं। जर्मनी के मतानुसार, ये सारे व्यवसाय सोवियट रूस द्वारा राष्ट्रीयकरण नहीं किये जा सकते थे। इस अग्रिम 'मुसीबत' से बचने के लिए 'वेसान्खा' ने रातों-रात बैठकर एक विस्तृत सूची तैयार की और ४८ घंटों के अन्दर एक नया निर्णयपत्र प्रकाशित किया। सम्भवतः यह उसी समय हुआ जब जर्मन सम्पत्ति को रूस से बचाने के लिये जर्मन पदाधिकारीगण अपनी कूट-नीतिज्ञ लिखा-पढ़ी कर रहे थे। यह महान परिवर्तन देखते ही देखते हुआ। यद्यपि सामान्य राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी गई थी, तद्बापि सम्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा और जब तक कि सरकार ने किसी व्यवसाय को पूर्ण रूप से जप्त न कर लिया, पूर्व अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे अपने व्यवसाय का प्रबन्ध तथा प्रशासन उसी प्रकार करें जैसे कर रहे थे। आगामी आठ-दस महीनों में बहुत से कानून भी बने और धीरे-धीरे तमाम उद्योगों पर सरकारी अधिकार पूर्ण रूप से स्थापित हुए। १९१८ के अन्त तक राष्ट्रीयकरण व्यवसायों की संख्या १००० हो गयी थी, जो १९१९ की शरद ऋतु तक ३००० से ४००० हो गयी थी।

युद्धकालीन साम्यवाद

(जून १९१८ से मार्च १९२१)

क्रान्ति के अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध ने भी रूस की अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट किया था और औद्योगिक क्षेत्र में तो दशा बड़ी गंभीर थी। कोयले की उत्पत्ति ६० प्रतिशत; लोहा ७५ प्रतिशत; सस्य-क्षेत्र (crop area) ५० प्रतिशत और चुकन्दर (sugarbeet) की उत्पत्ति ६० प्रतिशत कम हो गयी थी। देश में हर वस्तु की न्यूनता थी। क्षुधा पीड़ित लोग सड़कों पर इधर-उधर मारे-मारे फिरते थे। इस समय एक तो थोड़ी ही हर वस्तु की कमी थी, दूसरे युद्ध ने न्यूनता अत्याधिक बढ़ा दी थी। कोयले व ईंधन की कमी ने औद्योगिक नागरिक एवम् सैनिक क्षेत्रों के वातावरण को अधिक गंभीर बना दिया था। १९१६ में ईंधन की पूर्ति १६१७ की अपेक्षा ५० प्रतिशत और १९१६ की अपेक्षा ४० प्रतिशत घट गई थी। १९१३ में रूस का ७५ प्रतिशत लोहा-द्रव और ६० प्रतिशत कच्चा लोहा डानटेज बेसिन से आता था। यूराल का पहाड़ी प्रान्त जो १९१८-१९ में युद्ध क्षेत्र था, कुल कच्चा लोहे के उत्पादन का १६ प्रतिशत प्रदान करता था और शेष २१ प्रतिशत का आधा से अधिक पोलैण्ड से आता था। इन सारे क्षेत्रों में जर्मन फौजों ने घेरे डाल दिये थे और सोवियट रूस की इस अकथनीय क्षति ने उसको बहुत ही दुर्बल एवम् शक्तिहीन बना दिया था। जो भाग सोवियट रूस के पास अब भी थे, वहाँ भी दशा चिन्तनीय थी। मध्य भाग में लोहे गलाने की भट्टियों की संख्या जो १९१८ में १३ थी, १९१९ में नौ तथा १९२० में पाँच या उससे भी कम रह गयी थी।

मशीन निर्माण कारखानों की संख्या जो १९१८ में चौदह थी, १९२० में सात थी और कच्चे लोहे का उत्पादन जो १९१९ में गत वर्ष की अपेक्षा $\frac{1}{2}$ था १९२० में $\frac{1}{3}$ शेष रह गया। यंत्रकला उद्योग एवम् युद्ध सामग्री उद्योग में

धातुओं की न्यूनता बड़ी प्रचुरता से अनुभव की गयी। परिणाम यह हुआ कि रेलवे यातायात साधन अस्त-व्यस्त हो गये। इसमें संदेह नहीं कि रेलवे यातायात के बड़े दुर्दिन थे - एक ओर तो ईंधन की न्यूनता दूसरी ओर सैनिक एवम् युद्ध सामग्री यातायात की वृद्धि। रेलवे पर अधिक भार क्रान्ति काल से ही था। युद्ध काल में रेलवे लाइनों का और अधिक पतन हुआ और रेलवे प्रबन्ध में भी असामर्थ्य तथा अयोग्यता काफी आ गयी थी। लगभग ३६०० रेलवे पुल, १२०० मील स्थायी मार्ग, ३८० इंजन डिपो और रेलवे दूकानें, ३६०० साधारण पुल तथा ५०,००० मील तार एवम् टेलीफोन लाइन विनिष्ट हो गयीं।

खाद्यान्न एवम् ईंधन की कमी के साथ-साथ यातायात साधनों के विनाश ने मिलकर उद्योग-धन्यों पर घोर संकट उत्पन्न कर दिया। औद्योगिक उत्पादन का अत्यन्त हास हुआ। भूख तथा निर्धनता ने श्रमिकों की कार्य क्षमता को बहुत क्षति पहुँचाई। श्रमिकों की अनुपस्थिति दिन प्रति दिन बढ़ती गयी। कार्य में लगे रहने पर भी वे अनुपस्थित तथा शून्य चित्त रहने लगे। उनके लिये काम करने का न तो उचित वातावरण था और न कार्य उत्तेजना ही थी। अत्याधिक निर्धनता के कारण उनमें चोरी तथा गवन जैसे अवगुण उत्पन्न हो गये थे। १९२० में उद्योग-धन्यों के श्रमिकों की संख्या १९१४ की अपेक्षा आधी थी। औसत उत्पत्ति प्रति-पुरुष ३०-३५ प्रतिशत शेष रह गयी थी और कुल औद्योगिक उत्पादन केवल १४.५ प्रतिशत अवशेष था। श्रमिकों के अनुपस्थित होने की मात्रा प्रायः ६० प्रतिशत तक पहुँच जाती थी, जब कि साधारण रूप से ३० प्रतिशत लोग तो हमेशा ही अनुपस्थित रहते थे। एक लेखक का कथन था कि मास्को के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक को केवल इतना पारिश्रमिक मिलता था जो प्रति मास ११, १३ दिनों के लिये ही पर्याप्त होता था। उसे प्रायः अवैधानिक रूप से धनोपार्जन करना पड़ता था।

मुद्रा प्रचलन दिन प्रति दिन सोवियट सरकार बढ़ाये जा रही थी। नवम्बर १, १९१७ को मुद्रा प्रचलन २२४ करोड़ रुबल थी। जून, १, १९१८ को यह ४०३ करोड़ तथा जनवरी १, १९१९ को ६०८ करोड़ पहुँच गयी थी। १९१८ में गत वर्ष की अपेक्षा मुद्रा प्रचलन में वृद्धि ११९ प्रतिशत थी जो १९१७ में १९१६ की अपेक्षा १८० प्रतिशत थी। १९१८ के उपरान्त मुद्रा स्फीति की विनाशकारी गति ने सोवियट रूस को अत्याधिक हानि पहुँचाई। १९१९ में वस्तु-मूल्य तीन गुना बढ़ गया और १९२० के मूल्य में वृद्धि ४०० प्रतिशत से अधिक थी। अक्टूबर १९२० में रुबल की क्रय शक्ति १९१७ की अपेक्षा केवल एक प्रतिशत रह गयी थी। सोवियट सरकार ने मुद्रा स्फीति संकट से औद्योगिक श्रमिकों को बचाने के

लिये बहुत से प्रयत्न किये। श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान, जहाँ तक सम्भव था, प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं के रूप में किया गया। परन्तु अर्थव्यवस्था में सामान्य न्यूनता होने के कारण यह प्रथा अधिक प्रचलित न हो पायी। मुद्रा स्फीति ने निम्न दो वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रकार से प्रभावित किया।

(१) धनवान वर्ग को क्षति, मुद्रा की क्रय शक्ति ह्रास ने पहुँचायी।

(२) कृषक वर्ग को हानि हुई क्योंकि :—

(क) अपनी उत्पत्ति को बेचकर वे धन संचय करते थे, जिसके कारण जनको लाभ के स्थान पर हानि होती थी क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति दिन प्रति दिन घट रही थी।

(ख) कारखाने के निर्मित सामान का मूल्य कृषि पदार्थ के मूल्य की अपेक्षा अधिक था। सामान खरीदने में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देना पड़ता था और इस प्रकार दोनों ओर से कृषक को हानि उठानी पड़ती थी। मुद्रास्फीति को रोकने की एक रीति यह थी कि कृषक वर्ग अपने पदार्थों को बेचने के बाद द्रव्य संचय न करें। १९१६-१९१७ के समय ऐसा ही किया गया था। पर इसका प्रभाव यह पड़ा कि निर्मित माल की न्यूनता बढ़ गयी और सरकार नोट छाप कर यथार्थ सम्पत्ति एवम् साधन (real property and resources) न प्राप्त कर सकी। जैसे-जैसे मूल्य में वृद्धि हुई वैसे-वैसे सरकार ने यथार्थ सम्पत्ति को संचित करने के दृष्टिकोण से नयी नोट छापी, जिससे वास्तविक मुद्रा चलन में काफी वृद्धि हो गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रय शक्ति (purchasing power) या कुल मुद्रा प्रचलन (aggregate currency circulation) का वास्तविक मूल्य (real value) घट गया तथा मुद्रा स्फीति द्वारा सरकार की वास्तविक साधनों की संग्रह करने की शक्ति उत्तरोत्तर घटती गयी।

इस प्रकार सोवियट सरकार के सम्मुख निम्नलिखित महान आर्थिक समस्याएँ थीं, जिनका सुलभाना कोई सरल बात न थी।

(क) श्रमिकों ने समितियों को अधिक से अधिक स्थानीय अधिकार दिलाने की चेष्टा की। पिछले अध्याय में बतलाया गया है कि श्रमिकों ने अवैधानिक रूप से बराबर व्यवसायों को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। कारखानों के राष्ट्रीयकरण की माँग दिन प्रति दिन बढ़ती गयी। यही कारण था कि 'राज्य पूँजीवाद' के समय औद्योगिक राष्ट्रीयकरण की गति आवश्यकता से अधिक तेज थी और सोवियट सरकार इस घटना से प्रसन्न न थी। लेनिन ने बराबर शान्ति रखने का आग्रह किया और अवैधानिक राष्ट्रीयकरण पर बराबर खेद प्रकट किया।

(ख) पिछले अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि जून १९१८ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बड़ा गंभीर था। सोवियट रूस की विदेशी सम्पत्ति को अपहरण करने की नीति ने विदेशियों से ईर्ष्या तथा द्वेष उत्पन्न कर लिया था। यह भी बतलाया जा चुका है कि जब लेनिन को यह गुप्त सूचना मिली कि जर्मन राजदूत शीघ्र ही ऐसे कारखानों तथा व्यवसायों के नाम का सूचीपत्र उनके सम्मुख प्रस्तुत करने वाला है, जिसको सोवियट सरकार हड़प नहीं कर सकती है क्योंकि उसमें अधिकतर पूँजी जर्मन नागरिकों की है, 'वैसान्खा' की एक विशेष बैठक ने उसी दिन यह निर्णय किया कि रूस के तमाम उद्योग-धंधे सरकार द्वारा ले लिये जावें और उनका तत्कालीन राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे।

(ग) ईंधन, उत्पत्ति साधन सामग्री, खनिजपदार्थ तथा कच्चा माल इत्यादि की कमी ने यह आवश्यक कर दिया कि राजकीय प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण बढ़ाया जावे। केवल नोट छाप कर अगर सरकार चाहती कि आर्थिक व्यवस्था को संतुलित रखे और हर सामग्री की पूर्ति सुविधापूर्वक होती रहे, तो यह असम्भव था। उसने यह समझ लिया था कि आवश्यक सामग्रियों तथा साधनों की पूर्ति राजकीय हस्तक्षेप द्वारा ही हो सकती है और जनता में उसका वितरण केन्द्रीय नियन्त्रण तथा राशनिंग द्वारा ही किया जा सकता है।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है कि मुद्रा प्रसार ने क्रय शक्ति का वास्तविक मूल्य इतना घटा दिया था कि सरकार को उत्पत्ति साधनों को संग्रह करने की नीति असफल हो गयी। जून १९१८ से मार्च १९२१ तक का समय युद्धकालीन साम्यवाद युग था। इस काल में प्रहयुद्ध, विदेशी आक्रमण तथा देश की अस्त-व्यस्त अर्थव्यवस्था ने सोवियट सरकार को राष्ट्रीयकरण तथा आर्थिक प्रशासन एवम् औद्योगिक प्रबन्ध में अत्याधिक केन्द्रीयकरण नीति अपनाने में शीघ्रता करनी पड़ी।

युद्धकालीन साम्यवाद की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थीं :

- (क) लगभग सारे औद्योगिक तथा व्यवसायिक संगठनों का राष्ट्रीयकरण;
- (ख) कृषक वर्ग से खाद्यान्न अनिवार्य अधिग्रहण;
- (ग) आन्तरिक व्यापार पर राज्य-एकाधिकार, तथा
- (घ) सर्वहारा वर्ग प्रशासन की स्थापना

(क) औद्योगिक एवम् व्यवसायिक संगठनों का राष्ट्रीयकरण :

उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण निरन्तर चलता रहा। देश के सारे विशाल एवम् लघु उद्योग-धन्धे सरकार के अधिकार में पहुँच गये। १९२० में एक निर्णय-पत्र प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार सारे ऐसे व्यवसाय जिसमें पाँच या पाँच से अधिक श्रमिक काम करते थे और यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होता था

अथवा ऐसे सारे उद्योग-धन्धे जिनमें दस या दस से अधिक श्रमिक कार्य करते थे और यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता था, सरकार द्वारा ले लिये जाने का आयोजन किया गया। १९२० के अन्त तक देश के लगभग ३७,००० व्यवसाय राजकीय स्वामित्व के अन्तर्गत आ गये।

औद्योगिक प्रबन्ध के दृष्टिकोण से उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया :

(क) वृहत् उद्योगों को उचित 'ग्लैवकी' के निर्देशन तथा प्रबन्ध में रखा गया। 'ग्लैवकी', 'वेसान्खा' के ऐसे उप-विभाग (sub-departments) थे जो अपने उद्योग के किसी अङ्ग में प्रवीण थे। 'ग्लैवकी' जैसे विशिष्ट मंडलों (specialised bodies) का जन्म यों तो क्रान्ति के उपरान्त ही हो चुका था, पर उनका महत्त्व एवम् उनकी संख्या में वृद्धि १९१६ के बाद हुई, जब राष्ट्रीयकरण उद्योगों की संख्या बढ़ी। कुछ उद्योगों में 'सेन्टर्स' नामक मण्डलियाँ बनायी गईं पर वे प्रायः 'ग्लैवकी' की ही तरह विशिष्ट मण्डल थे और अन्तर केवल इतना था कि 'सेन्टर्स' में विशिष्टता (specialisation) अधिक थी।

यद्यपि 'ग्लैवकी' और 'सेन्टर्स' को अपने कार्य संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता थी, तथापि राष्ट्रीय कार्यों के लिये एवम् दूसरे विभागों से समन्वय प्राप्त करने के लिये वे 'वेसान्खा' के अधीन थे। प्रारम्भ में वे उत्पत्ति साधन एवम् कच्चे पदार्थों की पूर्ति का अपना स्वयम् प्रबन्ध करते थे, पर वस्तु न्यूनता की वृद्धि के साथ-साथ 'ग्लैवकी' का यह अधिकार जाता रहा और उन्हें राष्ट्रीय उपयोगिता आयोग (Supreme Utilization Commission) के अधीन कर दिया गया। यह आयोग 'वेसान्खा' से सम्बन्धित था। सामग्री वितरण, उत्पत्ति साधन विभाजन, पूर्ति प्राथमिकता (supply priority) इत्यादि महान समस्याओं को सुलभाने का भार इस आयोग पर था।

कारखानों के नित्य संचालन के लिये तीन, पाँच, सात, अथवा दस की संख्या में संचालकों (directors) की नियुक्ति 'वेसान्खा' करती थी। अधिकतर अवसरों पर संचालकों की नियुक्ति ट्रेड यूनियन नेताओं के परामर्श से की जाती थी।

प्रारम्भ में तो संचालकों की समिति बनाई गई, पर धीरे-धीरे प्रबन्ध एक ही संचालक या कम से कम संख्या में संचालकों के हाँथ में रखा गया। यही नहीं 'वेसान्खा' के नियन्त्रण परिषद् (controlling board) के सदस्यों की संख्या पचास से घटा कर १०-१५ कर दी गयी थी, जिसमें ट्रेडयूनियन, राजकीय अधिकारी एवम् स्थानीय आर्थिक समितियों के प्रतिनिधि थे।

विशाल उद्योगों को केन्द्रीय नियन्त्रण में रखा गया, जो राष्ट्रीय नीति के आधार पर प्रशासित किये गये थे ।

(ख) माध्य तथा लघु उद्योगों पर स्थानीय अधिकार अधिक था । यद्यपि केन्द्र से उनके प्रबन्ध सम्बन्धी निर्देश आते रहते थे, पर उनका प्रत्यक्ष संचालन स्थानीय मण्डलों द्वारा ही होता था । संचालन में विकेन्द्रीयकरण नियमों का अनुकरण किया जाता था । स्थानीय औद्योगिक विभाग (Local Industrial Sections जिन्हें Gubsovnaarhozy कहते थे) उद्योगों का प्रबन्ध एवम् निरीक्षण, उनमें समन्वय तथा सहयोग वे उसी प्रकार प्रदान करते थे जैसे केन्द्र में 'ग्लैवकी' स्थानीय विभागों को व्यवहार में वही कार्य करने पड़ते थे जो 'ग्लैवकी' द्वारा निर्धारित किये गये थे । उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता शून्य थी । वे किसी कार्य को अपने नेतृत्व में नहीं कर सकते थे । उनका तो केवल यही कार्य था कि वे 'ग्लैवकी' द्वारा जो निर्णय किसी समस्या के विषय में किया गया है उसको कार्यान्वित करते रहें तथा नित्य के प्रबन्ध एवम् संचालन को ओर भली प्रकार ध्यान दें । वैधानिक तौर से तो अवश्य उनका व्यक्तिगत रूप था, पर वास्तव में उनमें तथा 'ग्लैवकी' में कार्य प्रबन्ध के दृष्टिकोण से कोई विशेष अन्तर न था ।

(ग) इसके अतिरिक्त लघु उद्योग-धन्वे थे, जिनका केवल स्थानीय महत्त्व था । वास्तविक रूप में उनमें विकेन्द्रीयकरण लाया गया । उनका संचालन पूर्ण रूप से स्थानीय समिति द्वारा किया जाता था ।

इस प्रकार वृहत् उद्योगों का संचालन 'ग्लैवकी' तथा मध्य एवम् लघु उद्योगों का संचालन, स्थानीय औद्योगिक विभागों द्वारा होता था । स्थानीय औद्योगिक विभाग केवल वही कार्य कर सकते थे, जिसकी आज्ञा उन्हें 'ग्लैवकी' से प्राप्त होती थी । 'ग्लैवकी' के पास कार्य की अधिकता थी । लघु उद्योगों के स्थानीय विभागों का यह कर्तव्य था कि वे कारखाने की आर्थिक दशा तथा संचालन के विषय में समय-समय पर सम्पूर्ण कार्य विवरण 'ग्लैवकी' के पास भेजते रहें, क्योंकि ऐसा करने पर ही 'ग्लैवकी' उचित परामर्श किसी अमुक व्यवसाय को दे सकेंगे । लगभग सभी उद्योगों में यह शिकायत थी कि 'ग्लैवकी' को उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नियमानुसार तथा समयानुसार प्राप्त न हो पाता था और स्थानीय औद्योगिक विभाग संचालन सम्बन्धी स्वतः निर्णय कर लेते थे । प्रायः कुछ स्थानों पर 'ग्लैवकी' इन विषयों पर अनभिज्ञ रहता था । कहीं कहीं वृहत् उद्योगों में भी यही अवगुण पाया गया । १९२० में एक अन्वेषण समिति ने (committee of investigation) यह उल्लेख किया कि बहुत से उद्योगों में 'ग्लैवकी' को केवल यह ही ज्ञान न था कि किन गोदामों में कितना सामान संचित

है पर वे इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि कुल कितने गोदाम थे। जाँच-पड़ताल करने पर यह पता चला कि उद्योगों पर केन्द्रीयकरण का संचालन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है तथा सारा शासन प्रबन्ध अस्त-व्यस्त है।

औद्योगिक संचालन में गोलमाल तथा सामग्री वितरण में विलम्ब एवम् असावधानी उत्पन्न होने के कारण युद्धकालीन रूस की अर्थव्यवस्था को महान कष्ट उठाना पड़ा। कुछ ऐसे उद्योग थे जिनका स्वस्थ रहना युद्ध के लिये अनिवार्य समझा गया, और जिस पर राष्ट्रीय प्रगति भी अवलम्बित थी। ईंधन तथा अन्य उत्पादन शक्तियों को उचित मात्रा में प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था। ये ऐसे उद्योग थे जिनकी उत्पादन सामग्री में न्यूनता, अनेक जटिल एवम् क्लिष्ट समस्याएँ उत्पन्न किये थीं। 'ग्लैवकी' अथवा राष्ट्रीय उपयोगता आयोग (Supreme Utilization Commission) का यह प्रथम कर्तव्य था कि इन उद्योगों में आवश्यक खनिज पदार्थ कच्चा माल ईंधन एवम् शक्ति आदि की पूर्ति में प्राथमिकता दें। ऐसे उद्योगों को जिनके सम्मुख अनेक दुःसहाय एवम् कठिन कार्य थे तथा जिनका स्थान सारे उद्योग-धंधों में सर्वोच्च था, "शाक" व्यवसाय कहा गया। ये ऐसे व्यवसाय थे जो युद्ध के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये थे और जो अधिकतर युद्ध सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन करते थे। इन व्यवसायों को धन तथा दूसरी साधन सामग्री प्रदान करने में उच्चकोटि की प्राथमिकता दी गई; इनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को खाद्य सामग्री सर्वप्रथम प्रदान की गई तथा इन उद्योगों के संचालन के लिये श्रेष्ठ एवम् कुशल संचालक नियुक्त किये गये। आरम्भ में उच्चकोटि की प्राथमिकता सिद्धान्त के अन्तर्गत आने वाले विशेष उद्योगों की संख्या थोड़ी थी। धीरे-धीरे "शाक" उद्योग श्रेणी में उनकी संख्या बढ़ने लगी। सब की आवश्यकताएँ अपना-अपना स्थान रखती थीं, जिससे प्राथमिकता निर्णय में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। इस पद्धति में यह त्रुटि थी कि व्यक्तिगत उद्योगों की प्राथमिकता को माप कर उनका महत्त्व निश्चित करना सरल न था। साधन-सामग्री की इतनी अधिक न्यूनता थी कि "शाक" उद्योगों के प्राथमिकता पाने के बाद अन्य उद्योगों को फाँके करने पड़ते थे। इस कारण वे तमाम उद्योग जिनका स्थान प्राथमिकता पैमाने पर काफी नीचे था, उत्तेजित थे, आन्दोलन करने को तत्पर रहते थे और अशान्ति उत्पन्न कर रहे थे। इसका प्रभाव उत्तरोत्तर बुरा पड़ता गया। प्राथमिकता सूची में उलट-फेर अथवा "शाक" उद्योगों की सूची को अति विस्तृत करने के कारण ऐसे उद्योगों की दशा और शोचनीय हो गयी, जिनकी प्राथमिकता सूची में कोई स्थान ही न उपलब्ध हो सका था। चारों ओर इस कारण से अशान्ति, निराशा तथा विफलता दृष्टिगोचर हो रही थी।

सोवियट संघ के प्रत्येक उद्योगों में वस्तु की केवल न्यूनता ही नहीं, बल्कि उनका समुचित वितरण भी न था। इसके कारण अनेक कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं। इस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिये सोवियट सरकार ने उद्योग-धन्वों पर विविध प्रकार के नियन्त्रणों का जाल बिछा दिया था। देश में ऐसी अवस्था थी कि न्यूनतम लागत पर किसी पदार्थ का उत्पन्न होना असम्भव था। इस समय तो सरकार एवम् औद्योगिक संचालक केवल उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता में थे—चाहे जिस लागत पर उत्पादन हो; चाहे जितनी विवेकरहित रीतियों को उन्हें अपनाना पड़े। राजकीय विभागों में कोई कुशल सांख्यिकी संकलन रीति भी प्रयोग में न थी, जिससे समय-समय पर सरकार उचित अवस्था की जानकारी कर सकती और पुनः सुधार का प्रबन्ध करती। किसी कारखाने में ईंधन की कमी थी और कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में था; किसी दूसरे कारखाने में कच्चे माल का अभाव था और ईंधन बहुतायत मात्रा में मिल रही थी तथा किसी तीसरे कारखाने की ऐसी अवस्था थी कि दोनों पदार्थ पर्याप्त मात्रा में थे, पर वहाँ के श्रमिकों के पास खाने का सामान न था।

(ख) कृषक वर्ग से खाद्यान्न अनिवार्य अधिग्रहण :

खाद्यान्न की इतनी अधिक कमी थी कि सोवियट सरकार के सम्मुख उसका अनिवार्य अधिग्रहण के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था। दशा इतनी गंभीर तथा चिन्ताजनक थी कि बिना अनुचित दबाव डाले या बिना बल उपयोग के सरकार को केवल सैनिकों के लिये भी गल्ला एकत्रित करना असम्भव था। केन्द्रीय नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप अति आवश्यक था। गल्ले के वितरण में भी सरकार को सारा प्रबन्ध स्वयम् करना पड़ता था। इसी उद्देश्य से खाद्यान्न का कृषकों से अधिग्रहण अनिवार्य रूप से किया गया।

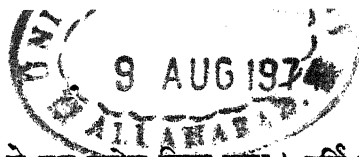
प्रत्येक कृषक से, अपने उपभोग तथा निजी आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त, उत्पत्ति-अतिरेक को अनिवार्य रूप से, सरकार ने ग्रहण करने की योजना बनाई। इसका संचय और इसका उद्योग तथा सेना में वितरण पूर्ति मंत्रिमण्डल द्वारा (commissariate of supplies) सुव्यवस्थित किया गया। सम्पूर्ण खाद्य सामग्री का केन्द्रीय संचय एवम् वितरण रूस के युद्धकालीन साम्यवाद में एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर यह प्रथा ग्रहण न की जाती, तो सम्भवतः दुर्भिक्ष, मृत्यु एवम् गृह-कलह आदि घटनायें अति भयंकर रूप धारण कर लेतीं। कल-स्वरूप सम्पूर्ण सेना भी व्यर्थ एवम् निष्काम हो जाती, क्योंकि युद्ध काल में सेना के लिये भोजन पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलना अत्यन्त आवश्यक था। खाद्यान्न अनिवार्य

अधिग्रहण तथा केन्द्रीय सुसंगठित विभाजन प्रथा, जो कृषि में अपनायी गयी थी, युद्धकालीन साम्यवाद की सार एवम् तत्त्व कही जा सकती है। सोवियट सरकार ने इस नीति को वाद्य होकर ग्रहण किया और यह भी कहना अनुचित न होगा कि खाद्यान्न अनिवार्य अधिग्रहण नीति केवल एक अस्थायी उपाय था, क्योंकि यह निश्चय था कि इसको ग्रहण करने से कृषक एवम् श्रमिक वर्ग का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता यद्यपि क्रान्ति काल से ही उनमें सन्धि हो चुकी थी। उत्पत्ति-अतिरेक को उपलब्ध करने के लिये नगरों से सेना बुलाई गई थी, जिससे राजनैतिक अशान्ति उत्पन्न हो गई। उत्पादन एवम् सस्य क्षेत्र में सामान्य रूप से तो हास हुआ ही, पर कृषकों ने इसको और अधिक प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इस प्रथा के अन्तर्गत वे खाद्यान्न पदार्थ का स्वयम् संचय एवम् विक्रय नहीं कर सकते थे। विस्तृत सस्य क्षेत्र युद्ध में विनिष्ट हो गये थे। इसके अतिरिक्त कृषक वर्ग को उत्पादन के प्रति कोई उत्तेजना एवम् सहानभूति भी न रह गयी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उपभोग एवम् बीज की आवश्यकता से अधिक सम्पूर्ण उत्पादन सरकार द्वारा अपहरण कर लिया जावेगा। साइबेरिया में लगभग आधा तथा वाल्गा और काकेसस में एक चौथाई भाग घट गया था। उपज और क्षेत्रफल — दोनों में काफी कमी हो गयी थी। अनिवार्य अपहरण नीति को सरकार ने दिन प्रति दिन, अधिक से अधिक, नियम निष्ठता द्वारा प्रयोग किया। मई १४, १९१८ को एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (Central Executive Committee) ने एक निर्णयपत्र द्वारा घोषणा की कि प्रत्येक जिले में साहसी कृषकों को चाहिये कि वे उत्पत्ति-अतिरेक निश्चित मूल्य पर सरकार को सौंप दें और जो लोग ऐसा न करेंगे, वे जनता के शत्रु कहलावेंगे और वे नागरिक अधिकार से वंचित करके क्रान्तिकारी पंच मण्डल के सम्मुख लाये जावेंगे।

(ग) आन्तरिक व्यापार पर राज्य-एकाधिकार :

जब औद्योगिक तथा खाद्य उत्पादन पर जटिल प्रतिबन्ध लगाया जा चुका था, तो स्पष्ट है कि स्वतंत्र व्यापार तथा वस्तु विनिमय भी स्थगित हो गया होगा। स्वतंत्र बाजार ऐसी कोई व्यवस्था न रह गयी थी। लगभग सभी पदार्थों का विनिमय सरकार द्वारा एकाधिकार रूप में होने लगा था। निजी व्यापार शून्य था और केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि उत्पत्ति साधन तथा निर्मित माल भी सरकार ने उपभोक्ताओं के मध्य सरकारी दूकानों द्वारा वितरण किया था।

बाजार विनिमय का, जो पूँजीवाद प्रथा का एक सर्वोत्तम गुण है, युद्ध-काल में सोवियट रूस की साम्यवाद अर्थव्यवस्था में कोई स्थान न था। द्रव्य



भी माध्य विनिमय के रूप में कम से कम प्रयोग किया गया। पूर्ति मंत्रिमण्डल (commissariat of supplies) का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उपयोग की सामग्रियों को नागरिकों तथा सैनिकों के मध्य उनकी आवश्यकतानुसार बाँटना था। आरम्भ में कृषि-पदार्थों के व्यापार को तीन प्रकार सुसंगठित किया गया :

(क) ऐसे पदार्थ जो अनिवार्य अधिग्रहण (compulsory requisition) प्रथा के अन्तर्गत आते थे ;

(ख) ऐसे पदार्थ जो अनिवार्य अधिग्रहण प्रथा के अन्तर न थे, पर उनका सारा क्रय सरकार द्वारा एकाधिकार रूप से होता था ;

(ग) ऐसे पदार्थ जिनके क्रय पर राजकीय एकाधिकार न था और वे स्वतंत्रतापूर्वक बाजार में निजी व्यक्तियों द्वारा या सहकारी समितियों (cooperative societies) द्वारा क्रय-विक्रय या विनिमय किये जा सकते थे। सूची में राजकीय एकाधिकार के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। एक वस्तु के क्रय पर नियन्त्रण लगाने के उपरान्त दूसरी वस्तुओं पर नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार एक के बाद एक करके सम्पूर्ण पदार्थ पर राजकीय एकाधिकार कर लिया गया। सहकारी समितियों को भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। पर वे बिना मंत्रिमण्डल से अनुमत लिये हुए, स्वतंत्रतापूर्वक कोई क्रय-विक्रय तथा विनिमय सम्बन्धित कार्य नहीं कर सकते थे। ऐसे पदार्थ जिनका क्रय-विक्रय व्यक्तिगत संस्थाओं या सहकारी समितियों द्वारा होता था, नाममात्र के थे और जो अवशेष थे भी, उनका व्यापार में साधारण महत्त्व था। जब सम्पूर्ण सामग्रियों के क्रय-विक्रय तथा विनिमय पर राजकीय एकाधिकार था, तब यह स्पष्ट है कि बिना द्रव्य प्रयोग के भी सामग्री विनिमय का लेखा राजकीय विभागों द्वारा किया जा सकता था। क्योंकि निजी व्यापार केवल नाममात्र शेष रह गये थे, इसलिये मुद्रा प्रचलन भी यत्र-तत्र थी। केवल परिमाण में सामग्री के आवागमन का लेखा ही मिलता था। अगस्त १९१८ में "वैसान्खा" के एक निर्णयपत्र से पता चला कि वस्तु विनिमय ही राजकीय प्रचलित प्रथा है। उसने घोषित किया :

"उत्पादन के बाद वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा वितरण का बन्दोबस्त बिना द्रव्य प्रयोग के, जहाँ तक सम्भव हो सके, केवल लिखा-पढ़ी द्वारा ही किया जावे।" २१ नवम्बर को राजकीय-निर्णय द्वारा निजी व्यापार बिल्कुल स्थगित कर दिया गया और उपभोग के पदार्थों की पूर्ति के लिये पूर्ति मंत्रिमण्डल को (जिसे Narcomprod कहते थे) सम्पूर्ण एकाधिकार दिये गये। मार्च १९१९

को एक दूसरे प्रादेश द्वारा सहकारी समितियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जाती रही। औद्योगिक पदार्थों में भी “ग्लैवकी” ऊपर ही सारा उत्तरदायित्व था। उनका विनिमय तथा वितरण, राजकीय समितियों के मध्य, द्रव का न्यूनतम प्रयोग करके, लिखा पढ़ी द्वारा ही किया जाता था।

(घ) सर्वहारा वर्ग सत्ता की स्थापना :

सोवियट संघ का विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग सत्ता की आवश्यकता उस समय तक रहेगी जब तक कि सामाजिक वर्गीकरण विनिष्ट नहीं कर दिया जाता। जब देश में एक ही वर्ग रहने लगेंगे, सत्ता की आवश्यकता जाती रहेगी। लेनिन ने कहा था : “समाजवाद से तात्पर्य है—वर्गों का विनाश : वर्तमान काल में कई सामाजिक वर्ग हैं और इसीलिये सर्वहारा वर्ग सत्ता की आवश्यकता है। जब वर्गों की समाप्ति हो जावेगी ; सत्ता की आवश्यकता न रहेगी। बिना सर्वहारा वर्ग सत्ता की स्थापना किये हुए, समाज से वर्ग न हट सकेंगे।”^१

‘युद्धकालीन साम्यवाद’ नीति से देश को अत्यन्त क्षति पहुँची, पर उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि किसी दूसरी नीति को ग्रहण करना राष्ट्रीय-स्वतंत्रता एवम् समाजवाद के लिये हितकर न था। जो नियम अपनाये गये थे, उनके पक्ष में केवल यह कहा जा सकता है कि वे युद्धकालीन परिस्थिति को देखते हुए अनिवार्य थे। रूस ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों ने भी साम्यवाद समकक्ष नीति अपनाया, क्योंकि वे भी लगभग उसी प्रकार की समस्याओं तथा संकटों से पीड़ित थे, जिनका विवेचन रूस के सम्बन्ध में उपर्युक्त किया जा चुका है।

अल्प काल के दृष्टिकोण से साम्यवाद नीति ही ऐसा उपाय था जो रूस को अत्याधिक पतन से बचा सका था। पर दीर्घ काल को ध्यान में रखते हुए इस नीति के विरोध में यह कहा जा सकता है कि इसने रूस की स्थायी उत्पादन शक्ति, और श्रमिकों की कुशलता, एवम् कार्यक्षमता को अत्यन्त हानि पहुँचायी। इसमें सन्देह नहीं कि क्रान्ति के समय से ही दशा निरन्तर बिगड़ती जा रही थी; उत्पादन में दिन-प्रति-दिन ह्रास हो रहा था तथा औद्योगिक संगठन अव्यवस्थित

१ “Socialism means abolition of classes ; classes remain and will remain in the era of dictatorship of proletariat. When classes disappear, the dictatorship will become unnecessary. Without dictatorship of the proletariat, classes in society will not disappear.” Lenin : Collected Works.

हो चला था। इस युग में भी यह प्रवृत्तियाँ जारी रहीं और इस निरन्तर हास को रोकना न जा सका, जिसके फलस्वरूप उत्पादन-हास अति बढ़ता गया तथा औद्योगिक प्रबन्ध छिन्न-भिन्न हो गया। कृषि में उर्वरा शक्ति, श्रमिकों में कार्य-क्षमता, यातायात साधनों में निपुणता और वितरण पद्धति में समानता का काफी हनन हुआ। प्रत्येक क्षेत्र में दशा बिगड़ गयी थी और सारा देश निर्धनता, कपट, कलंक तथा असन्तोष से पीड़ित था। अपने कटु अनुभव द्वारा सोवियत सरकार स्वयम् विचार कर रही थी कि साम्यवाद नीति से देश को जो संकट पहुँचा है उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। बालशेविक पार्टी ने जब सत्ता प्राप्त की थी, इसने जनता को आश्वासन दिया था कि सब के लिये भोजन, कृषकों के लिये भूमि, सर्वहारा वर्ग सत्ता की स्थापना एवम् शान्ति का पूरा प्रबन्ध वे शीघ्र से शीघ्र करेंगे। कई वर्षों के उपरान्त भी खाद्यान्न की कमी थी; शान्ति केवल उच्च पदाधिकारियों को थी; भूमि से सम्बन्धित जितने भी प्रादेश प्रकाशित हुए, वे स्थायी रूप से कोई सुधार का आयोजन न कर पाये थे और इस प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक एवम् राजनैतिक संकट की अग्नि से जल रहा था।

विश्व में रूसी साम्यवाद असफलता की चर्चा थी। विश्व के अनेक राष्ट्र रूसी साम्यवाद नीति को कलंकित एवम् दोषित ठहराते हुए यही आलोचना कर रहे थे कि साम्यवाद का आगमन रूस की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर देगा। परन्तु प्रथम एवम् द्वितीय महायुद्धों के अनुभव के पश्चात् आलोचकों को यह ज्ञात हुआ कि युद्धकाल में प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वस्तु न्यूनता के प्रभाव को कम करने के लिये सामान वितरण, राशनिंग तथा राजकीय नियन्त्रण प्रथाएँ ही देश को समयानुकूल सुसंगठित कर सकती हैं। युद्ध के पश्चात् इन प्रथाओं का महत्त्व स्वतः कम होता जाता है। ठीक इसी प्रकार साम्यवाद की समालोचना लेनिन ने की थी। इसीलिए इसको “युद्धकालीन साम्यवाद नीति” की संज्ञा दी गयी थी। लेनिन को यह दृढ़ विश्वास था कि जो पद्धतियाँ युद्धकाल में एकाएक अपनायी गयी हैं, वे अस्थायी हैं, केवल युद्ध कालीन हैं और उनका ग्रहण करना पूँजीवाद सामाजवाद परिवर्तन क्रिया से विचलित होना है। समाजवाद की स्थापना रूस का अग्रिम लक्ष्य था और एकाएक साम्यवाद की स्थापना उस मार्ग से विचलित होना था। यह विचलन युद्ध के कारण अनिवार्य था, यद्यपि उसका स्थान अस्थायी था। लेनिन का कथन था कि युद्ध के उपरान्त हम पुनः उसी लक्ष्य को ग्रहण करने की ओर अग्रसर होवेंगे। अप्रैल २१, १९२१ को लेनिन ने यह स्पष्ट कहा :

“युद्ध कालीन साम्यवाद हमारे ऊपर युद्ध तथा विनाश द्वारा आरोपित

कर दिया गया था। न तो यह ऐसी नीति थी और न ऐसी हो ही सकती थी, जो सर्वहारा वर्ग के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह एक अस्थायी कार्यवाही थी।”^१ युद्ध के पश्चात जब लेनिन ने रूसवासियों को नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य समझाया, उसने पुनः कहा : “हम लोगों ने अनेक कार्य परिस्थिति बाध हो कर किये..... अधिकतर कार्य भ्रामक तथा अनुचित थे..... राजनैतिक एवम् सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से भी हम लोग पथ विचलित हो गये थे।”^२ १९२१ में एक बार व्याख्यान देते समय लेनिन ने यह स्वीकार भी किया : “जो कुछ गत वर्षों में किया गया अनुचित था। एक ऐसी भगदौड़ हुई जिसमें सोवियट रूस को बड़ा आघात पहुँचा।”

१ “War communism was thrust upon us by war and ruin. It was not nor could it be a policy what corresponded to the economic tasks of the proletariat. It was a temporary measure.” *Lenin : Selected Works.*

२. “Some of the things we were compelled to do by necessity... We did much that was wrong..... We went further than was necessary theoretically and politically.” *Lenin : Selected Works, Volume XI, p. 178.*

पाँचवाँ अध्याय
नवीन आर्थिक नीति
(१९२१-१९२८)

जिस दिशा की ओर सोवियट सरकार क्रान्ति के उपरान्त आठ मास तक चल रही थी, उसका वर्णन तीसरे अध्याय में किया जा चुका है। पूँजीवाद त्याग कर समाजवाद की स्थापना ही एक स्थायी मार्ग था। साम्यवाद तो केवल अस्थायी तथा अत्यावश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण अपना ली गयी थी। सोवियट रूस के अनेक लेखकों का भी यहीं दृष्टिकोण था। एक ने लिखा :

“युद्धकालीन साम्यवाद में परिवर्तन एक वाध्य निर्णय था, जो जर्मन साम्राज्यवाद और तत्पश्चात् परस्पर विनाशकारी विरोधी क्रान्ति द्वारा आरोपित किया गया था। यद्यपि युद्धकालीन साम्यवाद एक सामान्य आर्थिक नीति न थी, फिर भी ऐतिहासिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से वह एक समयानुकूल अत्यन्त आवश्यक नीति थी।”

अन्य लेखकों तथा राजनैतिक नेताओं का भी यही मत था कि साम्यवाद की नीति अगर निरन्तर अपनायी जावेगी तो यह सोवियट सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत इस नीति को ग्रहण किया गया था, वे अधिकतर युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थीं। युद्ध समाप्त होने के उपरान्त सोवियट रूस को पुनः प्राचीन मार्ग का अनुकरण करना चाहिये था, जिस मार्ग पर क्रान्ति के उपरान्त सोवियट सरकार चन्द महीनों चल पाई थी। ऐसा विश्वास किया गया कि वही एक स्वाभाविक तथा प्रसामान्य गति सिद्ध होगी, जो रूस की समाजवाद स्थापना में सहायक हो सकेगी। साम्यवाद का प्रथम अनुभव तो

असफल एवम् कष्टमय था और इसीलिये इसका पुनः परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक था। इस नवीन नीति को केवल कूटनीति के दृष्टिकोण से “नवीन आर्थिक नीति” की संज्ञा दी गयी थी। वास्तव में यह वही नीति थी जो रूस की सरकार ने नवम्बर १९१७ से जून १९१८ तक अपनायी थी और जिसकी लेनिन ने उस समय भी प्रशंसा की थी। क्रान्ति के बाद सर्वहारा वर्ग के हित की यही एक ऐसी नीति थी जो साधारण एवम् स्वाभाविक आर्थिक नीति कही जा सकती थी। ऐसा विश्वास किया गया कि अगर इस पथ का सोवियट रूस कुछ समय तक अनुकरण करता रहेगा तो समाजवाद अवश्य शीघ्र ही स्थापित हो सकेगा। इसी उद्देश्य से सोवियट संघ ने इस नीति को पुनः ग्रहण किया था।

लेनिन ने इसको “प्रवैगक (dynamic) मिश्रित अर्थव्यवस्था” की संज्ञा दी, जिसमें पूँजीवाद तथा समाजवाद दोनों को उचित स्थान दिया गया था। इस पद्धति को, जैसा तीसरे अध्याय में बताया जा चुका है, राज्य-पूँजीवाद (state capitalism) या नियंत्रित पूँजीवाद (directed capitalism) कहा गया। शिक्षार्थियों को यह स्मरण होगा कि इस पद्धति का लेनिन ने क्रान्ति उपरान्त भी अत्याधिक पक्षपात तथा अन्य पद्धतियों की अपेक्षा इसको अधिक उच्च स्थान प्रदान किया था।

“नवीन अर्थव्यवस्था” (N.E.P.) कोई नयी एकाएक, तथा आश्चर्यजनक नीति न थी। प्राचीन “राज्य पूँजीवाद” को ही यह नवीन संज्ञा दी गई थी ताकि लोग इसको श्रेष्ठ तथा उच्च स्थान दे सकें; इस नीति के प्रति उनका विश्वास बढ़े और उन पर आध्यात्मिक प्रभाव द्वारा भी कुछ सुधार हो सके। “नवीन आर्थिक नीति” समाजवाद अर्थव्यवस्था की प्रारम्भिक क्रिया थी। समाजवाद अर्थव्यवस्था से लेनिन का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उत्पादन की सामूहिक रीति प्रचलित हो तथा जिसका आधार उत्पत्ति साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व हो। ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में अनेक परिस्थितियों को पार करना पड़ेगा। “नवीन आर्थिक नीति” उनमें से एक प्रारम्भिक परिस्थिति थी।

आन्तरिक व्यापार एवम् नवीन आर्थिक नीति

युद्धकालीन साम्यवाद के समय स्वतंत्र व्यापार पर प्रतिबन्ध था। अनेक प्रतिबन्ध धीरे-धीरे हटाये जा रहे थे और साधारण व्यापारिक सम्बन्ध का पुनरुत्थान हो चला था। निजी व्यापारियों, राजकीय विभागों, एवम् निजी व्यापारी और राजकीय विभागों के मध्य पारस्परिक विनिमय पुनः आरम्भ हुआ। यह

प्रथा केवल खाद्यान्न में ही नहीं, बल्कि निर्मित सामग्री के व्यापार में भी प्रचलित की गयी। गत साम्यवाद युग में ग्राम एवम् नगरों के मध्य व्यापार न होने का बहुत बड़ा कारण गल्ले की अनिवार्य अधिग्रहण प्रथा थी। उपभोग के अतिरिक्त सम्पूर्ण खाद्यान्न राज्य को अर्पित करना पड़ता था, जिसका मूल्य निश्चित था, तथा उनमें प्रतिस्पर्धा, मूल्य ह्रास तथा विवेचन का कोई विशेष स्थान न रह गया था। सम्पूर्ण व्यापारिक क्रियायें समाप्त हो चुकी थीं। “नवीन अर्थव्यवस्था” नीति के अन्तर्गत यह सम्भव न था, क्योंकि कृषकों को आवश्यक व्यापारिक सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये थीं। परन्तु अगर उन्हें गल्ला विक्रय अधिकार प्राप्त हो जाता तो श्रमिकों का अनहित होता, क्योंकि देश में खाद्यान्न न्यूनता अत्यधिक थी। कृषकों को व्यापारिक स्वतंत्रता प्राप्त होना, मूल्य में महान वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन देना था। इस समस्या को हल करने के लिये सोवियट सरकार ने एक नयी सूक्ष्म निकाली। प्रत्येक कृषक सम्पूर्ण उत्पत्ति का एक अंश सरकार को उत्पत्ति कर के रूप में प्रदान करने लगा। इसको कृषि कर (agricultural tax) कहा गया। इसका भुक्तान मुद्रा में न होकर उत्पत्ति में ही हुआ। प्रत्येक कृषक को कर भुक्तान करने के उपरान्त यह पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वह अवशेष उत्पत्ति को बाजार में अपनी इच्छानुसार विक्रय कर सके। सरकार को सैनिकों, उद्योगों एवम् नागरिकों के हितार्थ खाद्य सामग्री एवम् कच्चा माल की प्राप्ति के लिये उच्च कर दर निर्धारित करना आवश्यक था। कृषि उत्पादन कर इस अनुपात से निश्चित किया गया कि सरकार कम से कम इतना गल्ला प्राप्त कर सके जो सेना तथा उद्योग के लिये आवश्यक हो। जितना गल्ला सरकार गत अधिग्रहण योजना के अन्तर्गत संग्रहित कर पाती थी, उसका लगभग आधा भाग प्रत्येक कृषक से सरकार ने कर द्वारा उपलब्ध किया जो सेना तथा उद्योग के मध्य वितरित किया जाता था। लेनिन ने इस नीति की समालोचना करते हुए लिखा: “अधिग्रहण नीति के स्थान पर कृषि उत्पत्ति कर का स्थानापन्न एक राजनैतिक महत्त्व रखता है। इसका अस्तित्व श्रमिक एवम् कृषक के सम्बन्ध से है।”^१

वास्तव में कृषकों को यह माँग थी कि अधिग्रहण नीति को तिलान्जलि दे दी जाये और अबाध व्यापार नीति ग्रहण की जावे। इसके प्रतिकूल औद्योगिक श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य पर ही था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेनिन ने कृषि उत्पा-

१ “The question of substituting a tax in kind for requisitioning is primarily a political one. Its essence lies in the relations between the workers and the peasants.” : *Lenin in Pravda* on June 21, 1921.

दन कर लगाया और दोनों पक्षों के विचारों का समन्वय करने की पूर्ण चेष्टा की। उसने स्पष्ट कर दिया कि कृषि उत्पादन कर का निर्धारण समयानुकूल परिस्थिति वश किया गया है। उसने उल्लेख किया :

“विचित्र युद्ध कालीन साम्यवाद नीति को त्यागने में कृषि उत्पादन कर का बहुत बड़ा हाथ था। हम अब भी विनाश की अवस्था से दूर नहीं हैं। युद्ध ने हमारी दशा बड़ी दुर्बल कर दी है। कृषि उत्पत्ति के विनिमय के लिये हमारे पास निर्मित सामान उस अनुपात से नहीं है। इस गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम कृषि उत्पादन कर प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात् हम न्यूनतम परिमाण में कर द्वारा खाद्यान्न संग्रहित करेंगे और शेष पदार्थ के लिये कृषकों को खुले बाजार में विक्रय का पूर्ण अधिकार देंगे। कृषकों के पास केवल उतना गल्ला शेष बचेगा जिसे वे बेचकर धनोपार्जन कर सकें और आवश्यक निर्मित सामग्रियों की सीमित मात्रा में खरीद सकें।”

नवीन आर्थिक नीति के तमाम परिवर्तनों में कृषि-कर का स्थान सर्व प्रमुख है। इसका प्रभाव अनेक दिशा में भिन्न-भिन्न प्रकार से पड़ा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये।

(क) कृषक वर्ग को उत्पादन अंश बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया जिसके फलस्वरूप कृषि पदार्थों के विक्रय में स्वतंत्र निजी व्यापार तथा मुद्रा प्रचलन का पुनः उत्थान हुआ। पहले कृषक अपनी उत्पत्ति अंश को केवल स्थानीय बाजार में बेचता था, पर शीघ्र ही प्रतिबन्ध उठा लिया गया और उत्पादक क्षेत्र के बाहर भी विक्रय होने लगा।

(ख) युद्धकालीन साम्यवाद नीति के अन्तर्गत ‘नारकमप्राड’ (Narcomprod) अर्थात् पूर्ति मंत्रि-मण्डल (Commissariat of Supplies) को कृषि पदार्थ में क्रय-विक्रय तथा वितरण करने का एकाधिकार था। स्वतंत्र व्यापार होने के कारण राज्य-एकाधिकार जाता रहा और सहकारी समितियों (cooperative societies) को पुनः अधिकार प्राप्त हुए कि वे अपना व्यापार स्वयम् कर सकें।

(ग) युद्धकाल में कच्चे माल तथा साधन सामग्रियों का वितरण, “ग्लैवकी” के केन्द्रीय नियन्त्रण के आधार पर था। अब औद्योगिक व्यवसायियों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे स्वेच्छानुसार कच्चे माल के क्रय तथा निर्मित माल के विक्रय का उचित प्रबन्ध करें। क्रमानुसार ये परिवर्तन १९२१-२२ में होता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य संगठनों (state organisations) को यह अधिकार दिया गया कि वे क्रय तथा विक्रय स्वयम् कर सकते हैं, क्योंकि

कि केन्द्र से उन्हें निर्धारित 'कोटा' मिलना बन्द हो गया था। अगस्त १९२१ से बहुत से उद्योगों को अपना लगभग आधे से अधिक निर्मित सामान बाजार में विक्रय करने का अधिकार दिया गया और शेष आधा सरकार कच्चा माल तथा ईंधन के विनिमय में, पूर्वानुसार सिद्धान्त द्वारा, प्राप्त करती रही।

(घ) दी मास उपरान्त इन व्यवसायों को ईंधन तथा कच्चा माल इत्यादि के क्रय एवम् निर्मित सामान के विक्रय करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई।

(ङ) कुछ समय पश्चात् कारखानों ने प्रत्यक्ष रूप से वस्तु विनिमय करना प्रारम्भ किया और कृषकों ने भी इस रीति को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा की। इससे अनेक नई समस्याएँ उत्पन्न हुई और शीघ्र ही द्रव्य को माध्य मान कर क्रय-विक्रय होने लगा।

सोवियट रूस का विदेशी व्यापार प्रारम्भ से ही राज्य के अन्तर्गत था। निजी व्यापार को कभी भी इस क्षेत्र में अनुमति न मिल पायी। कई दल के व्यक्तियों ने विदेशी व्यापार में निजी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहा पर सरकार ने उसे स्वीकार न किया। साम्यवाद पार्टी में कई ऐसे दल थे जो विदेशी व्यापार को सरकार के प्रतिबन्ध से मुक्त कराना चाहते थे, पर सरकार द्वारा यह हमेशा अमान्य रहा।

उद्योग-धन्धे तथा नवीन आर्थिक नीति

गत साम्यवाद युग में उद्योग-धन्धों में केन्द्रीयकरण की अधिकता थी। अधिकतर उद्योग-धन्धे "ग्लैवकी" के अधिकार में थे। इस क्षेत्र में अब अनेक परिवर्तन किये गये। २७ अक्टूबर, १९२१ के प्रादेशानुसार व्यवसायों को दो भागों में विभाजित किया गया।

(क) वे जो केन्द्रीय राज्य द्वारा प्रबंधित किये जावेंगे, जिनको सारी उत्पादन सामग्री राज्य द्वारा प्राप्त होगी और जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र न थे।

(ख) ऐसे उद्योग जिन्हें सम्पूर्ण वित्तीय एवम् व्यवसायिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इन व्यवसायों के प्रबन्ध के लिये एक नयी संस्था बनायी गयी जिसे "राष्ट्रीय ट्रस्ट" की संज्ञा दी गयी। इनके द्वारा अनेक कारखानों का प्रबन्ध तथा संचालन किया गया। इनको अनेक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनमें अधिक से अधिक विकेन्द्रीयकरण करने की चेष्टा की गयी। इन "ट्रस्टों" में "वेसान्ला" द्वारा अनेक परिषद् (board) बनाये गये। इन परिषद्ओं के कार्य निजी कम्पनी के संचालक-परिषद् के कार्य के समान थे। इनमें विशेषता यह थी कि परिषद् के प्रत्येक सदस्य के नेतृत्व में एक विशिष्ट निभाग था जिनको व्यवसाय सम्बन्धी अनेक स्वतंत्रताएँ प्राप्त थीं। अप्रैल १०, १९२३ के प्रादेश की

धारा दो और तीन के अनुसार राजकीय विभाग तथा राजकीय कम्पनियाँ “ट्रस्टों” की किसी सम्पत्ति को बिना उनसे समझौता या संविदा (contract) किये हुये नहीं ले सकती थीं और “ट्रस्टों” को स्वतः निर्णय करने का पूर्ण अधिकार था। धारा २९ के अनुसार “वेसान्खा” ट्रस्ट परिषद् के प्रचलित प्रशासन तथा प्रबन्ध-कार्यों में हस्तक्षेप न करेगा। धारा ४७ के अनुसार “ट्रस्टों” पर आया कर, सम्पत्ति कर इत्यादि आरोपित किया गया और वह निश्चय किया गया कि इनके मुकतान का उत्तरदायित्व निजी कम्पनियों के कर-भार के तुल्य होगा।

व्यवसायों का संघबद्ध “ट्रस्ट” के आधार पर अनेक प्रकार से हुआ। कहीं-कहीं उत्पादन के दृष्टिकोण से, कहीं जिलों के आधार पर और कहीं-कहीं राष्ट्रीय ढंग से “ट्रस्ट” बनाये गये।

(क) रबर तथा चीनी के उद्योगों में “राष्ट्रीय-ट्रस्ट” बनाये गये क्योंकि उनका संगठन राष्ट्रीय आधार पर होना सरल तथा लाभजनक था।

(ख) कहीं-कहीं उद्योग धन्वे स्थानीय महत्त्व के आधार पर सुसंगठित किये गये। उदाहरणार्थ, कोयले की खाने जो डानटूज (Dontez) क्षेत्र में थी, एक “स्थानीय ट्रस्ट” (Donugol) के प्रबन्ध में रक्खी गयी तथा मास्को के आसपास कोयले की खानों को मास्को में एक “ट्रस्ट” (Moscugol) बना कर रक्खा गया।

(ग) उद्गम संयोग द्वारा अनेक समान उद्योगों को एक “ट्रस्ट” के अधीन सुसंगठित किया गया। उदाहरणार्थ यूगोस्टल (Yugostal) “ट्रस्ट” के प्रबन्ध में दक्षिणी प्रांत के यन्त्रकला उद्योग, कोयले की खाने, तथा उसके गौण उद्योगों को उद्गम रूप से संयोजित किया गया।

(घ) बहुत से उद्योगों का क्षैतिज संयोग (horizontal combination) एवम् उद्गम संयोग (vertical combination) एक साथ हुआ। कुछ कारखानों को दूसरे प्रकार के कारखानों के साथ उद्गम रूप से मिला कर एक “ट्रस्ट” के अधिकार में किया गया और कुछ को क्षैतिज संयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न “ट्रस्टों” के अधीन प्रबन्धित किया गया।

“ट्रस्ट” एक स्वायत्त मण्डल (autonomous body) था, जिसको अनेक राजकीय सुविधायें प्राप्त थीं।

श्रम एवम् नवीन आर्थिक नीति

नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत श्रम सम्बन्धित नियमों में महान परिवर्तन की आवश्यकता थी। अनिवार्य श्रम-सेवा (compulsory labour ser-

vice) तथा सामान्य पारिश्रमिक (equal wage) नियमों का परित्याग कर दिया गया और श्रमिक-संघ यां ट्रेड-यूनियन तथा संचालकों के मध्य एक नया सम्बन्ध स्थापित हुआ । एक ऐसी समस्या (जिसको फलित करने में वाद-विवाद हुआ था) उत्पन्न हुई जिसका मूल आधार यह था कि श्रमिक-संघों तथा राज्य उद्योगों के मध्य कैसा सम्बन्ध होना चाहिये । अग्रिम समाजवाद व्यवस्था में श्रमिक संघों को कैसा स्थान दिया जाए, उनके अधिकार तथा कर्तव्य किस प्रकार निर्माणित किये जावें और वे औद्योगीकरण आन्दोलन में किस प्रकार सहकारी बनें । ट्राट्स्की का विचार था (जो १९२० में यातायात तथा संचादवाहन मंत्री थे) “कि श्रम-सेना के संघों को सेनादल में संगठित किया जावे और इसके अध्यक्षों (brigadier) की नियुक्त सरकार द्वारा हो ।” श्रमिकों के ऊपर एक बड़ा भार था । उन्हें उसी प्रकार काम करना था जिस प्रकार सेना के सिपाही युद्ध में करते हैं । उनमें उसी कोटि का अनुशासन होना चाहिये था । यही कारण था कि ट्रेड-यूनियन अथवा श्रमिक-संघों को राज्य की सेना-दल माना गया । इस विचार-धारा का विरोध रूस में अधिकतर लोगों ने किया । ट्राट्स्की के इन विचारों को “कर्मचारी निरंकुश शासन”, “सरकारी दम्तरो में नौकरशाही,” तथा “ताना-शाही कड़ाई” इत्यादि विश्लेषणों से कलंकित किया गया ।

“अधः पतित तथा दुर्दशित केन्द्रीकरण” के नाम से सोवियट शासन व्यवस्था की अवहेलना की गयी । ट्राट्स्की ने अपने वक्तव्य में प्रचलित ट्रेड-यूनियन अवस्था को व्यवसायिक लकीर के फकीर कहा जो परिवर्तन विरोधी थे, जिनमें समामेलित भावना का अपवर्जन (spirit of corporative exclusiveness) था । उसने सरकार से श्रमिक-संघों में क्रान्ति उत्पन्न करने का अनुग्रह किया, ताकि उनमें जागृति हो और वे सरकार द्वारा आयोजित क्रियायों को कार्यान्वित करें । प्रचलन में श्रमिक-संघों को अनेक अधिकार भी प्राप्त थे, जिन्हें दूसरे पक्ष के कुछ जननेता (जिनमें सर्वप्रमुख लेनिन, स्टैलिन तथा ट्राट्स्की थे) सबल बनाना चाहते थे । इसी दृष्टिकोण से वे श्रमिक-संघों को सुसंगठित करने का आयोजन कर रहे थे । इन नेताओं ने एक सम्मिलित रिपोर्ट “दस व्यक्तियों के दल का कार्यक्रम” (“Platform of The Ten”) प्रकाशित की । सम्पूर्ण देश में ट्रेड-यूनियन व्यावस्था के विषय पर बड़ा मतभेद था ।

(क) ट्राट्स्की पक्ष के अनुयायियों का विचार था कि ट्रेड-यूनियनों को राज्य में मिला दिया जावे ।

(ख) कुछ लोगों का विचार था कि सम्पूर्ण औद्योगिक प्रबन्ध ट्रेड-यूनियन

के हाँथ में हो; वे ही उद्योगों के स्वामी हों और उन्हीं पर औद्योगिक संचालन का उत्तर दायित्व हो।

(ग) कुछ मध्यवर्ती विचारधारा के लोग थे ("Buffer" group) जिन्होंने अपनी नीति उपर्युक्त दोनों विचारों के संयोग से बनायी थी। उनका विचार था कि न तो राजकीय विभागों की भाँति ट्रेड-यूनियन संगठित किया जावे और न सारा औद्योगिक प्रबन्ध ही उनके ऊपर आभारित किया जावे।

(घ) इन तीनों मतों से भिन्न लेनिन की विचारधारा थी। उसने ट्रेड यूनियन को एक स्वाधीन संस्था माना, जिसके ऊपर श्रमिक उत्पादन शक्ति तथा कार्य क्षमता में वृद्धि उत्पन्न करने का पूर्ण भार था। उनका कर्तव्य था कि वे यह ध्यान दें कि श्रमिक असावधान हो जावें, उनमें कार्य निपुणता बनी रहे और वे उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें। औद्योगिक संगठन संबंधी अनेक कार्यों का उत्तर-दायित्व ट्रेड-यूनियन पर होना चाहिए।

"दस व्यक्तियों का कार्यक्रम" ("Platform of the Ten") के यही विचार थे। यूनियन का यह भी एक ध्येय था कि पार्टी में न सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों से भी सहयोग प्राप्त करें। उनको चाहिये कि वे अपने हित को "राजकीय अत्याचार निरंकुश तथा कर्मचारी शासन" से सुरक्षित करें। साथ ही साथ श्रमिकों को चाहिये कि वे आपस में सहयोग बढ़ा कर अपने प्रतिनिधि को राज्य पदों के निर्वाचन में खड़ा करें और आर्थिक संगठन तथा प्रबन्ध में पूर्ण रूप से हाँथ बटावें।

१९२२ के श्रम विधान संग्रह (Labour Code) ने बहुत से नवीन परिवर्तन किये। इस विधान द्वारा प्रौढ़ पुरुषों को आठ घन्टा, १६—१८ वर्ष के युवकों को छः घन्टा, तथा खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को छः घन्टा काम करने की व्यवस्था की गई। श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये और भी अनेक कार्य किये गये। सामाजिक सुरक्षा की योजना भी सरकार ने चलाई। सामाजिक बीमा कोष (Social Insurance Fund) केवल मिल मालिक अथवा सरकार के अंशदान से संचित किया गया। श्रमिकों को कोई अंशदान स्वयम् न करना पड़ा।

कृषि तथा नवीन आर्थिक नीति

नवीन आर्थिक नीति का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सब क्षेत्रों में उत्पादन गति को बढ़ाना था। कृषि-उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक थी क्योंकि समाजवाद स्थापना का उद्देश्य बिना इस लक्ष्य को प्राप्त किये असम्भव था। यह सत्य था कि उत्पादन में वृद्धि तब ही हो सकती थी जब किसानों को

व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया जावे। इसका प्रबन्ध सोवियट संघ ने इस नवीन नीति द्वारा किया। साम्यवाद युग में केवल उत्पादन साधनों पर ही नहीं बल्कि उत्पादन पर भी सरकार ने अधिकार कर लिया था, जिससे कृषकों को हतोत्साहित होना पड़ता था। इसके फलस्वरूप केवल सस्य-क्षेत्र (crop area) में ही कमी नहीं, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति में भी काफी क्षति पहुँची थी। नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत अनेक प्रतिबन्धों को हटा कर इस बात की पूर्ण चेष्टा की गयी कि कृषकों के लिये काम करने का उचित वातावरण हो तथा उन्हें दूसरी अनेक सुविधाएँ प्राप्त हों ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकें।

कृषि कर, जिसके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है, सोवियट सरकार की महत्त्वपूर्ण सूझ थी। उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिये था। कर अदा करने के बाद, जो अतिरिक्त उत्पत्ति कृषकों के पास रह जाती थी, उसे उन्हें पूरा अधिकार था जहाँ, जिस प्रकार चाहें, बेंचे। इसका प्रभाव यह पड़ा कि वे निरन्तर इस बात का प्रयास करते रहे कि उत्पादन इतना अधिक बढ़े कि कर अदा करने के पश्चात् उत्पादन-अतिरिक्त अधिकतम हो। वे इस नयी व्यवस्था से पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसको एक विशेषता और थी कि अनुपात में धनी कृषकों पर कर अधिक दर से लगाया जाता था, जब कि निर्धन किसानों पर कम था। यह एक प्रगतिशील कर (progressive tax) था, और इसका प्रभाव भी लाभप्रद था। सरकार ने इस बात पर अधिक ध्यान दिया कि निर्धन कृषकों को इस नीति से उत्तेजना मिले; वे उन्नति कर सकें; और अपने खेत की दशा को सुधार सकें। ऐसा होने से सम्पूर्ण देश का हित होगा। इस कर की प्रशंसा करते हुए एक राजकीय पदाधिकारी ने कहा : “कृषक को पूरा अधिकार था कि कर अदा करने के बाद अतिरिक्त उत्पत्ति को जिस प्रकार चाहे बेंचे।^१.....हर एक कृषक को विदित होना चाहिये कि अगर वह अधिक भूमि पर खेती करेगा तो अधिक उत्पत्ति होगी और अधिक अंश में अतिरिक्त उत्पादन संचय हो सकेगा। कर की दर निश्चित तथा स्थायी थी। उद्देश्य यह था कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो अधिक

^१ The decree reads : “After the tax has been paid, what remains with the peasant is left at his full disposal.....Every peasant must now realise and remember that the more land he plants, the greater will be the surplus of grain which will remain in his complete possession.”

Dobb : Soviet Economic Development Since 1917.

अनुपात में अतिरेक हो सकेगा और इसमें केवल कृषक का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश का हित होगा ।”

सहकारी समितियों (cooperative societies) को भी प्रोत्साहन दिया गया । सरकार ने कृषकों को आकर्षित एवम् प्रोत्साहित करने के लिये इस क्षेत्र में अनेक कार्य किये और इस बात पर अधिक जोर दिया कि सहकारी समितियाँ ही उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो सकती हैं, जो निर्धन कृषकों के मध्य अधिक लोक प्रिय थीं । इन समितियों को अनेक राजकीय सुविधाएँ प्रदान की गईं । इनमें धनी कृषकों को सम्मिलित नहीं किया गया । प्रारम्भ में सहकारी समितियाँ खाद्यान्न विक्रय के लिये ही बनायी गईं थीं, परन्तु बाद में उत्पादन सम्बन्धी सहकारी समितियाँ भी बनीं । २६ अक्टूबर १९२१ को कृषक सहकारी समितियों को एक विधान द्वारा प्रमाणित किया गया । घरेलू उद्योगों को भी सहकारी समिति द्वारा सुसंगठित करने का आयोजन किया गया । इन सहकारी समितियों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे संघबद्ध मण्डल (federating body) बनावें, जिस उद्देश्य से “सेल्सकोसोयस” (Selskosoyus) नामक संघीय समिति की स्थापना हुई ।^१

कृषि साख तथा ऋण संघों (agricultural credit and loan associations) को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिन्होंने कृषि को वित्त सहायता प्रदान किया ।

सहकारी समितियाँ तथा नवीन आर्थिक नीति

नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत बाजार का पुनर्जन्म हो चुका था, जिसमें यह आवश्यकता हुई कि सहकारी समितियों का उत्थान हो तथा उन्हें वित्तीय एवम् व्यवसायिक स्वतंत्रता दी जावे । इसके फलस्वरूप यह हुआ कि पूति मंत्रि मण्डल तथा सहकारी समितियाँ (Narcomprod तथा Ceutrosoyus) के मध्य मई २५, १९२१ को एक सामान्य समझौता हुआ कि सहकारी समितियाँ सरकार को निश्चित मूल्य पर खाद्य पदार्थ प्रदान करेंगी । इसके विनिमय में पूति मन्त्रिमण्डल (Narcomprod) ने यह प्रतिज्ञा की कि सहकारी समितियों को सारा निर्मित सामान जो उनके पास संचित था निश्चित अनुपात में देगी । उस प्रकार सरकार ने खाद्यान्न क्रय का प्रबन्ध समितियों द्वारा किया । उन्हें आश्वासन भी दिया कि निर्मित सामान बराबर संविदानुसार प्राप्त होता रहेगा । इसमें संदेह नहीं कि सहकारी समितियाँ अपना स्वयं व्यक्तित्व रखती थीं; तथा वे सरकार के

आधीन न थीं, फिर भी सामग्री के क्रय-विक्रय में समितियों को अधिकतर प्रारम्भ में हानि हुई, जिसका कारण यह था कि “निश्चित अनुरूप” (fixed equivalent) सिद्धान्त पर सामग्री क्रय-विक्रय होती थी। १९२१ की सस्य (crop) नष्ट हो जाने के कारण कृषि पदार्थों का मूल्य बाजार में काफी बढ़ गया था पर “निश्चित अनुरूप” के संविदानुसार जिस अनुपात में कृषि पदार्थ तथा निर्मित सामान का विनिमय निश्चित हो चुका था, उसी अनुपात में क्रय-विक्रय होने से कृषकों को हानि हो रही थी, जिसके कारण उन लोगों ने अपने सामान को खुले बाजार में बेचना अच्छा समझा। २६ अक्टूबर १९२१ को सरकार ने इस कानून को हटा कर एक नया निर्णयपत्र निकाला जिसके अनुसार समितियों को सम्पूर्ण व्यवसायिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। संघीय सहकारी समिति (Centrosoyus) पर से “निश्चित अनुरूप” (fixed equivalent) जैसी अनिवार्य शर्तें हटा ली गयीं। सहकारी समितियों को सरकार ने अनेक और भी सुविधायें प्रदान कीं। घरेलू उद्योग, कृषि उत्पादन, कृषि-पदार्थ विक्रय तथा वित्त प्रबन्ध इत्यादि क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ाया गया, क्योंकि राज्य पूँजीवाद प्रथा में इनको एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये। निजी व्यापार को सम्पूर्ण रूप से तिलांजलि देना हितकर न था।

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक वर्ष तथा कैंची-रूपी संकट

‘नवीन आर्थिक नीति’ के समय एक अनोखी घटना घटी, जिसे “कैंची-रूपी संकट” (“scissors” crisis) कहते हैं और जिसका सम्बन्ध कृषि तथा उद्योग मूल्य स्तर से था। १९२० में देश की दशा अच्छी न थी। पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि कच्चे माल की न्यूनता, ईंधन की कमी तथा पूँजी का अभाव आदि ऐसी समस्याएँ थीं जो उद्योग-धन्यों को क्षति पहुँचा रही थीं। सहकारी समितियों का निर्माण हुआ, तथा निजी व्यापार प्रोत्साहित किया गया, ताकि निर्मित माल सुविधापूर्वक विक्रि सके और पूँजी का अभाव, जो उद्योग-धन्यों की महान समस्या थी, उन्हें अधिक न पीड़ित कर सके। कार्यशील पूँजी (working capital) की अत्यधिक आवश्यकता थी। व्यवसायों का सर्वप्रमुख कार्य था कि माल का विक्रय शीघ्र से शीघ्र हो और आवश्यक पूँजी उन्हें प्राप्त हो सके जिससे वे अपने उत्तरदायित्व का भुक्तान तुरन्त कर सकें। पूर्व स्थापित ट्रस्टों का भी यह कार्य था कि वे औद्योगिक परिस्थिति अनुकूल बनाये रखें। इसके फलस्वरूप औद्योगिक सामग्रियाँ शीघ्र से शीघ्र बेचने का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि कार्यशील पूँजी की अत्यन्त आवश्यकता थी।

उद्योगों की यह निरन्तर चेष्टा रही कि निर्मित सामान को शीघ्र बेचकर वे कच्चा माल तथा ईंधन प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकें। इसके अतिरिक्त, इस समय श्रमिकों को पर्याप्त भोजन भी मिलना दुष्वार था। कई स्थानों पर तो ऐसा हुआ कि कारखानों से मिली हुई विक्रय ‘डिपो’ स्थापित की गयीं, जिनका कार्य केवल निर्मित सामान का खाद्यान्न से विनिमय करना था। ग्रामों में भी

इसी प्रकार के संगठन बनाये गये। स्पष्ट है कि औद्योगिक सामग्रियों का मूल्य-स्तर दिन प्रति दिन गिर रहा था, जब कि कृषि-पदार्थों की न्यूनता के कारण उनके मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही थी।

इस दशा ने “कैची रुपी संकट” की एक महान समस्या सोवियट सरकार के सम्मुख उपस्थिति कर दी। यह सब उस समय हुआ जब कि खाद्यान्न तथा ईंधन की अत्यन्त कमी थी। समय पर औद्योगिक सामग्रियों का न विक्रय होना ही सारे संकट का कारण था। उनके सम्मुख “विक्रय संकट” (sales crisis) एक विशेष समस्या थी क्योंकि उसी की लोच पर पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति भी निर्भर थी। एक सुसंगठित तथा स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक तथा खाद्य सामग्रों का मूल्य-स्तर समान हो। अगर कृषि-मूल्य में ह्रास अथवा वृद्धि हो तो उद्योग-मूल्य भी उसी ओर अभिसरित होना चाहिये और इसी प्रकार अगर उद्योग-मूल्य में ह्रास अथवा वृद्धि हो तो कृषि मूल्य भी उसी प्रकार चलना चाहिये, परन्तु सोवियट रूस इस समय इस प्रकार की संतुलित व्यवस्था से वंचित रहा।

कृषि-उत्पाद का मूल्य बढ़ रहा था, क्योंकि कृषि पदार्थों की अत्यधिक माँग थी जब कि पूर्ति उस अनुपात में न थी। इसके प्रतिकूल, निर्मित सामग्रियों का मूल्य निरन्तर कम होता जा रहा था, क्योंकि उद्योगों की पूँजी की आवश्यकता थी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि निर्मित सामान की अधिकता थी। कदापि नहीं। उत्पादन केवल कृषि में ही नहीं, बल्कि उद्योगों में भी बहुत कम था। पर समस्या यह थी कि उत्पादन को कमा होते हुये भी, जितनी उत्पत्ति उद्योगों के पास थी, उसका विक्रय भी न हो पा रहा था। रूसी अर्थव्यवस्था में यह एक “विरोधाभास” (paradoxical) घटना थी।

१९१४ को अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन इस समय एक चौथाई कम था। पर इसके विक्रय के लिये भी क्रयताओं का मिलना कठिन था। कृषि तथा उद्योग मूल्य में जा अनुपात युद्ध के पूर्व था, वह अब असंतुलित हो गया। परिस्थिति ऐसी थी कि औद्योगिक-सामान के विनिमय में ६५ प्रतिशत से अधिक कृषि-पदार्थ उपलब्ध नहीं हो सकता था।

कृषि-पदार्थ में मूल्य-वृद्धि होने पर भी कृषकों की परिस्थिति में अधिक सुधार न हो सका, क्योंकि उत्पादन का एक बड़ा अंश कृषि-कर के रूप में सरकार को चला जाता था और जो अतिरिक्त शेष था, उससे वे औद्योगिक सामान न खरीद कर मुद्रा ही संचित करते थे। औद्योगिक सामान के मूल्य में ह्रास होने के कारण, कृषकों का विश्वास उन्हें खरीदने में न था और कृषकों की इस प्रवृत्ति

तथा शक्ति के उद्योगों में लगाई गयी और यातायात सुविधायें भी प्रदान की गयीं। अनेक प्रकार से समस्या सुलझाने का प्रयास किया गया। शीघ्र ही परिस्थिति में सुधार दिखाया पड़ा। मई मास के बाद उद्योग तथा कृषि मूल्यों के अनुपात में अन्तर कम होना प्रारम्भ हुआ और अगस्त मास में दशा इतनी सुधर गयी कि यह अन्तर शून्य हो गया। नयी सस्य (crop) बाजार में आ गयी। उत्पत्ति में कुछ वृद्धि भी हुई। चतुर्दिशोन्मुख सुधार होने के कारण कृषि तथा उद्योग मूल्यों में अन्तर कम होता गया, जो निम्नलिखित सूचकांक एवम् विन्दुरेखीय निरूपण (graphic representation) से स्पष्ट है :

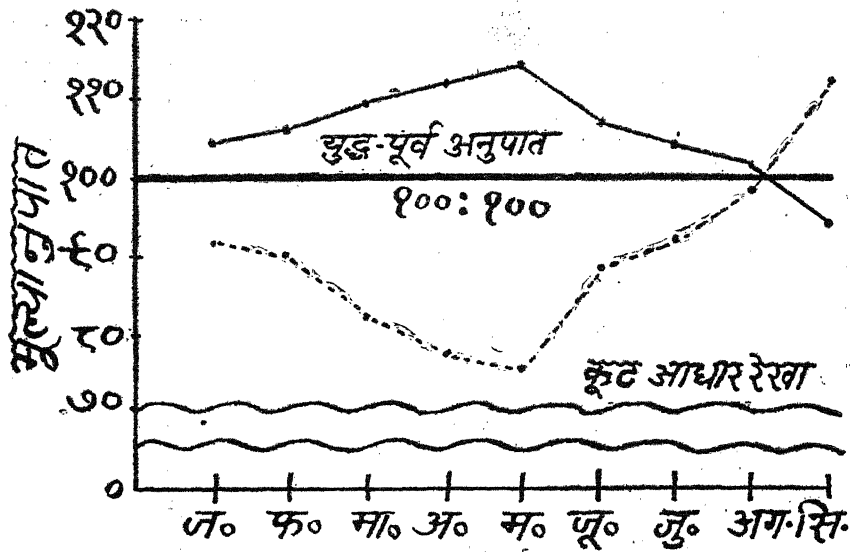
उद्योग तथा कृषि मूल्यों का सूचकांक

वर्ष	कृषि-पदार्थ	उद्योग-पदार्थ
१९१३	१००	१००
जनवरी १९२२	१०४	९२
फरवरी "	१०५	९०
मार्च "	१०६	८२
अप्रैल "	१११	७७
मई "	११३	७४
जून "	१०६	८६
जुलाई "	१०४	९२
अगस्त "	१००.५	९६
सितम्बर "	९४	११२

अगस्त १९२२ के उपरान्त मूल्य-विचलन में पुनः वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थ के मूल्य में उत्तरोत्तर हास तथा औद्योगिक पदार्थों के मूल्य में वृद्धि प्रारम्भ हुई। "कैचरेपी संकट" विपरीत दिशा में पुनः दृष्टिगोचर होने लगा।

निम्नलिखित सारणी से उपर्युक्त कथन स्पष्ट है। इस बार समस्या अधिक जटिल थी और इसको नियन्त्रित करना सरल न था।

मूल्य का सापेक्ष परिवर्तन



—१९२२—

संकेत

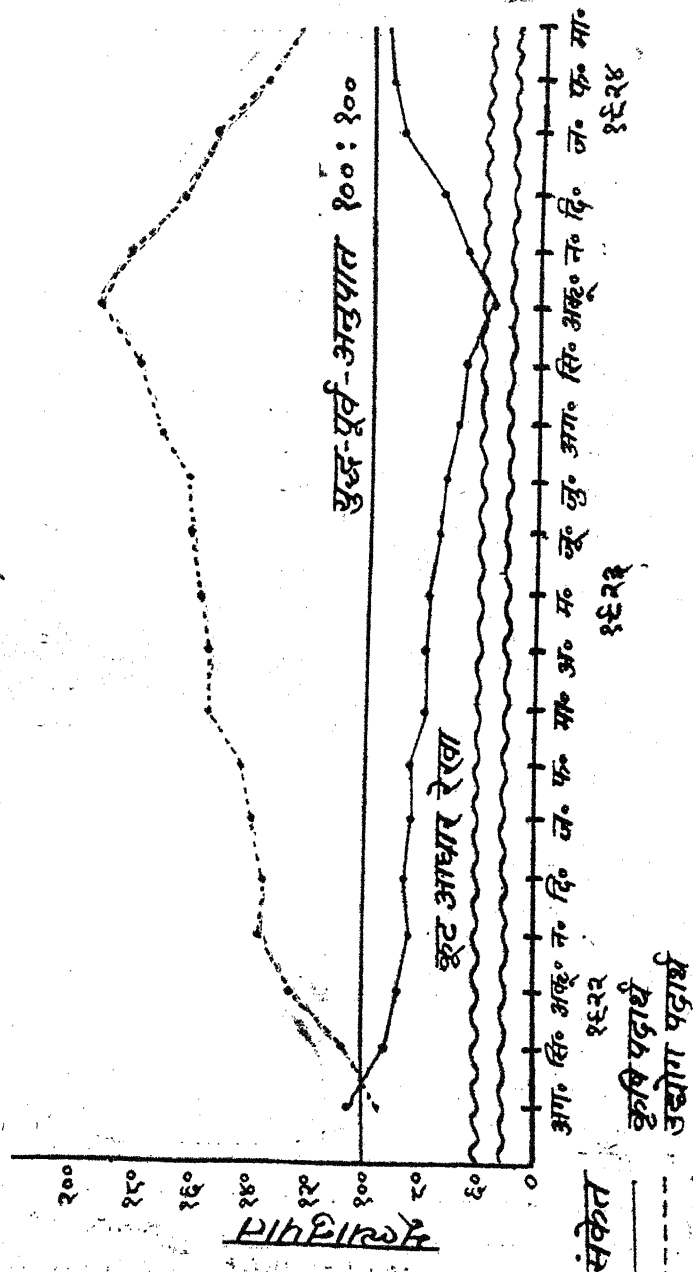
———— कृषि पदार्थ
----- उद्योग पदार्थ

कैची के दो फलों (blades) की भाँति कृषि एवम् उद्योग मूल्य विपरीत दिशाओं में जा रहा था। यह गति अगस्त १९२२ से पुनः प्रारम्भ हुई और अक्टूबर १९२३ तक निरन्तर जारी रही। अक्टूबर-नवम्बर १९२३ से मूल्यों में सामान्य स्तर पर पहुँचने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई जो मार्च १९२४ में पूर्ण हुई।

‘कैची रूपी संकट’ के कारण, प्रभाव तथा सुभाव पर अलग-अलग मत थे, जो दो विस्तृत भागों में विभाजित किये जा सकते हैं :

(क) एक मत तो यह था कि मूल्यों में विरोधाजनक प्रवृत्ति मौद्रिक कारणों से प्रभावित हुई है। जनवरी-जुलाई के मध्य में जो उद्योग-मूल्य में वृद्धि हुई, उसका सम्बन्ध मुद्रा प्रचलन से था। कार्यशील पूँजी के अभाव के कारण उद्योग धन्यों के प्रति राजकीय वित्तीय उदारता थी, जिससे मुद्रा स्फीति को प्रोत्साहन मिला।

मूल्य का सापेक्ष परिवर्तन (१९२२ - १९२४)



उद्योग तथा कृषि मूल्यों का सूचकांक

वर्ष	कृषि-पदार्थ	उद्योग-पदार्थ
१९१३	१००	१००
१९२२ अगस्त	१००.५	९९
" सितम्बर	९४	११२
" अक्टूबर	८८	१२३
" नवम्बर	८२	१३५
" दिसम्बर	८३	१३१
१९२३ जनवरी	८१	१३९
" फरवरी	८१	१४०
" मार्च	७९	१५०
" अप्रैल	७६	१५०
" मई	७८	१५२
" जून	७५	१५८
" जुलाई	७१	१६०
" अगस्त	६९	१६६
" सितम्बर	६५	१७४
" अक्टूबर	५९	१८९
" नवम्बर	६६	१८०
" दिसम्बर	७२	१६०
१९२४ जनवरी	६१	१५०
" फरवरी	६	१३२
" मार्च	६७	१२४

इसमें सन्देह नहीं कि मुद्रा प्रचलन बढ़ने के कारण मुद्रा स्फीति प्रगतिशील हुई, पर इससे "कैची-रूपी संकट" की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाती। "कैची रूपी संकट" का तात्पर्य उद्योग-मूल्य में वृद्धि तथा कृषि-मूल्य में ह्रास था। इस गति का पूर्ण स्पष्टीकरण उपर्युक्त मत द्वारा नहीं हो पाता।

(ख) इस संकट की प्रातिद्वन्दी व्याख्या यह थी कि १९२२-२४ में उत्पादन क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुये, जिनके प्रभाव से "कैची-रूपी समस्या" उत्पन्न हुई। इस मत के मानने वालों का विश्वास था कि कच्चे माल की वृद्धि लागत

ने ही उद्योग-सामग्री के मूल्य में वृद्धि उत्पन्न की है। अप्रैल १९२३ से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न हुई थी उसका कारण मुद्रा प्रचलन में वृद्धि न थी, बल्कि उत्पादन तथा मुद्रा प्रचलन का अव्यवस्थित सम्बन्ध था, जिसके अन्तर्गत मुद्रा प्रचलन के समान विनियोजित सामग्री न थी। मार्च से पूर्व विक्रय-सामग्री अधिक परिमाण में थी, परन्तु अप्रैल से विक्रय घट गया था, क्योंकि उत्पादन लागत अधिक था। अतः इस मतानुसार परिस्थिति अनुकूल करने के लिये यह आवश्यक था कि कम लागत पर उत्पादन बढ़ाया जावे और उत्पत्ति का अधिक से अधिक सामान बाजार में विक्रय के लिये लाया जाय।

दोनों मतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उद्योग-मूल्य को घटाने तथा कृषि-मूल्य को बढ़ाने की पूर्ण चेष्टा की। कृषि-पदार्थों का मूल्य काफी गिर गया था। उपर्युक्त विन्दुरेखीय निरूपण एवम् सूचकांक से स्पष्ट है कि कृषि पदार्थों के मूल्य के गिरने की प्रवृत्ति जो अगस्त १९२२ से प्रारम्भ हुई थी, अक्टूबर १९२३ तक निरन्तर जारी रही। सरकार ने अन्न क्रय समितियों (grain purchasing societies) को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वे कृषकों से उचित मूल्य पर अन्न खरीदें। निर्यात को भी प्रोत्साहित करके मूल्य-हास पर रोक-थाम की गयी। निर्मित वस्तुओं के मूल्य को घटाने की निम्न-लिखित कार्यवाही की गई :

(क) साख पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इसके पूर्व राज्य बैंक द्वारा उद्योगों को साख सरलतापूर्वक मिल जाता था, पर अब उस पर नियन्त्रण कर दिया गया। परिणामस्वरूप उद्योगों ने कार्यशील पूँजी की आवश्यकता से विवश होकर कम मूल्य पर विक्रय किया।

(ख) कई स्थानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य को निश्चित कर दिया गया, जिसके लिये एक समिति की भी स्थापना हुई।

(ग) कुछ असाधारण उद्योगों में आयात वस्तुओं द्वारा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की गयी। कम मूल्य पर विदेशी निर्मित वस्तुओं को आयात करके, देशीय मूल्यों को बढ़ने से रोका गया।

“वस्तु हस्तक्षेप नीति” द्वारा अनेक उद्योगों को सफलता प्राप्त हुई। परन्तु यह नीति व्यापक रूप से न अपनाई जा सकी, जिसके निम्नलिखित कारण थे।

(क) सोवियट सरकार आयात को प्रोत्साहित करके अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दायित्व को बढ़ाना नहीं चाहती थी।

(ख) सीमित साधनों के कारण मशीन, भारी सामान, तथा यन्त्रों के अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं का आयात असम्भव था।

(ग) अधिक उत्पादन लागत के कारण उद्योग-मूल्य अधिक था, जिसका घटना अत्यन्त आवश्यक था। सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट हुआ। संचालन तथा सामान्य व्यय प्रत्येक क्षेत्र में बहुत थे, जिनमें आर्थिक बचत करने की व्यवस्था की गयी।

(घ) केन्द्रीयकरण एवम् एकत्रीकरण नियमों पर भी सरकार का ध्यान गया। उत्पादन सकेन्द्रण, कम लागत तथा अधिक उत्पत्ति की ओर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। ट्रस्टों में संचालन व्यवस्था सुधारने का आयोजन किया गया।

अक्टूबर १९२३ से उद्योग-मूल्य में कमी होना प्रारम्भ हुई। मार्च-अप्रैल १९२४ तक अवस्था काफी सुधर गयी थी। उद्योग तथा कृषक मूल्यों के सूचकांक का अनुपात जो अक्टूबर १९२३ में ३:१ था, वर्ष के अन्त काल तक २:१ तथा अक्टूबर १९२४ तक १.५ : १ हो गया। कैंची-फल रूपी विन्दुरेखायें जो विपरीत दिशा की ओर अग्रसर थी, धीरे धीरे अनुकूल तथा सामान्य स्थित पर पहुँच गयीं।

नवीन आर्थिक नीति की प्रतिक्रिया

इस नीति के अन्तर्गत देश ने प्रशंसनीय प्रगति की। प्रति व्यक्ति आय जो १९२१ में ११७ अन्तराष्ट्रीय इकाई थी, १९२३ में १८५ तथा १९२५ में २८० हो गई। इस प्रगति ने देश को १९१४ के स्तर तक पहुँचा दिया। गत चार वर्षों में ही लगभग १५० प्रतिशत वृद्धि हुई। युद्ध काल में जो कृषि क्षेत्र नष्ट हो गये थे पुनः कृषि योग्य कर लिये गये। गोहूँ, ज्वार तथा राई का उत्पादन बढ़ा तो अवश्य, पर १९१३ स्तर तक न पहुँच सका। पशुपालन उद्योग जो युद्ध तथा क्रान्ति काल के समय नष्ट हो गया था, पुनः उत्थान के पथ पर अग्रसित था। डान तथा क्यूबान क्षेत्रों में घोड़ों के पालने का उद्योग प्रगतिशील था। १९१६ में लगभग ३,००० निजी अस्तबल थे और घोड़ों की संख्या लगभग ३५० लाख थी। क्रान्ति एवम् गृह युद्ध में लगभग ५० प्रतिशत घोड़े मारे गये। इस नीति के अन्तर्गत पशुपालन उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। गृह-युद्ध काल में रेलवे लाइने, स्टेशन, डिब्बे, इंजन आदि बनाने के कारखाने जो नष्ट हो गये थे, पुनः निर्माण किये गये। ऐसा अनुमान किया जाता है कि केवल युद्ध काल में सम्पूर्ण नाश ३० लाख स्वर्ण-रुबल का था।

१९२८ में १७,००० लोकोमोटिव देश में थे जो लगभग सभी जीर्ण थे। गाड़ियों द्वारा यातायात लगभग ४० प्रतिशत बढ़ गया था। अनेक उद्योगों में

भी उत्पादन वृद्धि हुई थी। १९२६ तक उत्पादन १-१३ के स्तर पहुँच गया था। वचत क्षमता एवम् विनियोग-दर में भी वृद्धि हुई। १९२२ में सूती वस्त्र उद्योग की दशा ९२१ की अपेक्षा तिगुनी अच्छी थी, यद्यपि १९१३ की अपेक्षा केवल ३ थी। ऊनी एवम् रेशमी वस्त्र उत्पादन २७ तथा ३६ प्रतिशत क्रमशः उन्नति कर पाया था।

मूल सुविधाओं का समंक (१९१३-१९२८)

(आधार वर्ष १९१३)

	१९१३	१९२८
सम्पूर्ण मूल सुविधायें	१००	१२०
मूल उत्पादन सुविधायें	१००	१३६
जिसमें:—		
उद्योग एवम् निर्माण	१००	१३२
कृषि	१००	१४१
यातायात और संवाद वाहन	१००	१३१
मूल अनुत्पादन सुविधायें	१००	१११

१९१३-१९२८ के मध्य प्रगति का मूल समंक:

(आधार वर्ष १९१३)	१९१३	१९२८
कैक्टरी एवम् दस्तरो में श्रमिकों की संख्या	१००	९५
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सारे विभागों में मूल उत्पादन सुविधायें.....	१००	१३६
राष्ट्रीय आय.....	१००	११९
सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पत्ति...	१००	३२
विशेष औद्योगिक व्यवस्थाओं की उत्पत्ति	१००	१५२
सम्पूर्ण यातायात साधनों द्वारा किया गया व्यापार.....	००	१०४
रेल द्वारा व्यापार भाड़ा ...	१००	१४२
रेलवे पर प्रति दिन सामान लादने का काम.....	१००	११८

इसमें संदेह नहीं कि नवीन अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता मान्य थी और युद्ध कालीन साम्यवाद पर यह एक महत्त्वपूर्ण सुधार था, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह एक स्थायी आदर्शवादी आर्थिक नीति थी। जैसा कि प्रारम्भ में लिखा जा चुका है कि यह नीति तो केवल अल्पकाल के लिये ही मान्य थी।

ऐसी आशा की गई थी कि नवीन आर्थिक नीति काल में, जो समाजवाद का बीज छिंटा गया था, वह अग्रिम वर्षों में एक विशाल वृत्त का रूप धारण करके पल्लवित एवम् फलित होकर सम्पूर्ण देश को अपनी छात्र-छाया में रक्खेगा। १९२५ के उपरान्त राजकीय नीति की प्रवृत्ति प्रतिबन्धों की ओर अधिक थी तथा निजी व्यापार पर कुठाराघात किया जा रहा था। सोवियट सरकार का यही उद्देश्य था कि समाजवाद की स्थापना की जावे; निजी पूँजीपतियों से सारे महत्त्वपूर्ण कार्य ले लिये जावें और सरकार स्वयम् सारे उद्योग-धन्धों का योजनात्मक संचालन करे। सामूहिक कृषि हो, सामूहिक उत्पादन हो और सामूहिक ढंग से निर्मित सामान की उत्पत्ति का संगठन तथा संचालन हो।

समाजवाद का लक्ष्य निजी लाभ के उद्देश्य को हटाकर समाजवाद सेवा के उद्देश्य को प्रातिष्ठित करना था। समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त था, जिसका लक्ष्य सोवियट राज्य द्वारा अच्छे वितरण तथा उत्पत्ति की अच्छी व्यवस्था करना था। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों का पालन किया गया :

- (क) उत्पत्ति के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाये;
- (ख) उद्योग का संचालन लामार्जन के उद्देश्य से न होकर, समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जावे, और
- (ग) व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज सेवा उद्देश्य होना चाहिये।

सातवाँ अध्याय

सोवियट रूस में प्रारम्भिक नियोजन

‘कैची-रूपी संकट’ के समाप्त होने के बाद बालशेविक पार्टी का प्रस्तुत विषय औद्योगीकरण था, जो अग्रिम युग का एक प्रधान सिद्धान्त समझा गया। ऐसा विचार था कि देश का शीघ्र से शीघ्र औद्योगीकरण होने से समाजवाद स्थापना कार्य सरल हो जावेगा। औद्योगीकरण उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये देश को किस मार्ग पर चलना चाहिये, एक तर्क का विषय था और सम्पूर्ण पार्टी गंभीरतापूर्वक इस पहलू पर विचार कर रही थी। सब से कठिन तो यह समस्या थी कि किस प्रकार वित्तीय साधनों का निर्माण किया जावे। वित्त प्रबन्ध के तीन साधन मार्ग थे :

(क) विदेशी पूँजी आयात की जाये, अथवा

(ख) मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार मान कर प्रगति की जाये। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों, यातायात साधनों तथा राजकीय विनियोग एवम् साख प्रणालियों का संगठन किया जाये और कृषि में निजी व्यवसाय, तथा स्वतंत्र व्यापार पद्धति प्रचलन में होने के कारण, उनसे पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय स्थापित किया जाये, अथवा

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में राजकीय व्यवस्था की स्थापना की जाये तथा निजी व्यापार को पूर्ण रूप से त्याग दिया जावे। राजकीय व्यवसायों तथा उद्योगों में जो लाभ होगा, उसका पुनः विनियोग किया जावे। स्टैलिन पक्ष के अनुयायियों ने इसी पथ पर चलने का मत प्रकट किया। उनका विश्वास था कि समाजवाद में प्रबलता एवम् दृढ़ता इसी पर आधारित है। उद्योगों का राजकीय संचालन एवम् समाजवाद की उन्नति ने एक सामान्य योजना की आवश्यकता उत्पन्न कर दी। स्तेलिन ने सोचा कि अगर सम्पूर्ण उद्योग राजकीय आधिपत्य में रहेंगे और

निजी व्यवसाय अगर सम्पूर्ण रूप से स्थगित कर दिये जावेंगे, तो उनका प्रबन्ध तथा संरक्षण योजनात्मक होना चाहिये। योजना द्वारा उत्पादन तथा वितरण का कोई पूर्वानुमान न किया, पर जैसे-जैसे लेनिन तथा उनके अनुयायियों ने शासन सम्बन्धी अनुभव किये, उनका विश्वास बढ़ता गया कि समाजवाद का कार्य बिना योजना के असम्भव है और इसलिये सारा उत्पादन कार्य योजनात्मक होना चाहिये। जैसे-जैसे समय व्यतीत हुआ, यद्यपि नाना प्रकार की आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तथापि योजना की रचना होती गयी और एक नवीन चित्र सामने दृष्टिगोचर होने लगा। वर्तमान काल की प्रस्तुत अवस्था लगभग चालीस वर्ष के कठिन परिश्रम तथा अनुभव के उपरान्त स्थापित हो पायी है। प्रारम्भिक वर्षों में योजना के विषय पर केवल साधारण चर्चा थी और कोई वास्तविक रचना न हो पाई थी। योजना का कोई नामकरण भी न था और न यह कोई 'आर्थिक शक्ति' (economic force) के रूप से ही सम्बोधित की गयी थी। इसको बालशेविक पार्टी का केवल एक प्रचारक समझा गया था।

सिडनी तथा वेब (Sydney and Webb) ने ठीक लिखा है :

“वर्ष-प्रति-वर्ष इसका (नियोजन का) धीरे-धीरे विकास होता गया। प्रारम्भ में तो “विचार-विभ्रम” (trial and error) की मौलिक प्रक्रिया (primitive process) द्वारा “विचार व्यवस्था” (order of thought) तथा “विषय-व्यवस्था” (order of things) का निरन्तर तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जो कि निरीक्षण (observation), अनुभव (experience), प्रयोग (experiment), युक्ति तर्क, विवाद आदि रीतियों पर आधारित था। इनका विस्तारपूर्वक समंक संग्रह किया गया, ताकि वे भविष्य में प्रयोगात्मक हो सकें। इस प्रकार योजनात्मक रीतियों का जन्म हुआ।”

जब बालशेविक पार्टी शासन-सत्ता में आयी, सामाजिक परिवर्तन (social change) इसका अटल उद्देश्य था। इस उद्देश्य की उसने स्वयम् समालोचना को आरम्भ कि यह “एकवर्गीय व्यवस्था” है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे वर्ग से है जिसके अन्तर्गत श्रमिक अपने श्रम का स्वयम् सदुपयोग करेंगे और दूसरा कोई वर्ग ऐसा न होगा जो उनका किसी प्रकार शोषण कर सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूँजीवाद की विनिष्टता तथा समाजवाद का संस्थापन बालशेविक पार्टी का प्रधान उद्देश्य था। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्य-क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तथा वितरण में भी समानता होगी। इस निश्चित उद्देश्य के होते हुये भी, सोवियट सरकार को अभी यह

अनुभव न हो पाया था कि समाजवाद निर्माण किस प्रकार किया जावे । इसके लिये सुत्रवसर की आवश्यकता थी ।

१९१७ के बाद से ही, हम देख सकते हैं, कि तमाम लेखों, निबन्धों तथा पुस्तकों में लेनिन ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि समाजवाद की रूपरेखा चित्रित करने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होगा, वे किस प्रकार प्राप्त होंगी, तथा उन्हें किस प्रकार सम्मिलित करके प्रयोग किया जावेगा । इसी उद्देश्य से नवीन आर्थिक नीति अपनायी गयी थी और इसके कुछ वर्ष तक कार्यान्वित होने के बाद, अनेक अनुभव किये जा चुके थे । किस प्रकार १४ नवम्बर १९१७ को श्रमिक-समितियों को अधिकार तथा उद्योग संचालन स्वतंत्रता प्राप्त हुई ; किस प्रकार उन्होंने अवैधानिक कार्य किये ; किस तरह लेनिन ने लोगों को समझाया और किस प्रकार नवीन आर्थिक नीति से लाभजनक अनुभव प्राप्त हुये, आदि एक रांचक इतिहास है, जिसका आगे आने वाली व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा ।

युद्धकालीन साम्यवाद के समय से ही, लेनिन ने अनुभव किया था कि उद्योगों का संचालन करने के लिये योजना की आवश्यकता थी । पुनः निर्माण के लिये, सामान्य योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है । जब मई, १९१८ में ट्रेड-यूनियन सामिति को अखिल यूनियन कांग्रेस (All Union Congress of Council of Trade Union) के सदस्यों की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि राष्ट्रीय उत्थान के लिये योजनात्मक कार्य करना ही उचित मार्ग होगा, साम्यवाद पार्टी का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य योजना के महत्त्व का प्रचार भी करना था । मार्च १९१९ में सम्पूर्ण देश को योजनात्मक प्रगति के उद्देश्य की नीति प्रकाशित हुई, जिसमें यह निश्चय किया गया कि एक सामान्य योजना तैयार की जावे, जो कि राष्ट्रीय दार्घ-कालीन नीति होगी । इसी मत से प्रभावित होकर गोयलरो (Goelro) नामक एक विद्युत् नियोजन आयोग स्थापित किया गया । इसका कार्य था कि सम्पूर्ण देश के लिये एक विद्युत्-योजना बनाई जाये ताकि देश की सम्पूर्ण राजनैतिक एवम् आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो सके । विद्युत् शक्ति की आवश्यकता देश के प्रत्येक भाग में थी ।

लेनिन का बुलन्द नारा था : “सोवियट + विद्युत् = साम्यवाद” । विद्युत् नियोजन द्वारा प्रत्येक क्षेत्र को संगठित किया जा सकता है । एक योजना बन कर तैयार हुई; श्रम-सुरक्षा समिति (council of labour and defence) द्वारा इसका संचालन, निर्देशन तथा समपदीकरण किया गया । पर इस योजना की गति से लोग असन्तुष्ट थे । सरकार का ध्यान चतुर्दिशा में होने के कारण विद्युत्

नियोजन की ओर यथेष्ट रूप में न दिया जा सका। आलोचकों ने यह आलोचना की कि “यह विद्युत् (‘‘electrification’’, नियोजन नहीं है, बल्कि विद्युत्-कथा है—कल्पना है (‘‘electric fiction’’) मिथ्या है—कविता है—वास्तविकता से बहुत दूर।”

विद्युत् योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य निश्चित किया गया कि विद्युत् शक्ति उत्पादन; जो १९०१ में ५,००० लाख किलो घन्टा थी, ८८,००० लाख किलो घन्टा हो जावे। इस लक्ष्य ने रूसियों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि वे इसका सफल होना असम्भव समझते थे। इस युग में सोवियट रूस अनेक आर्थिक एवम् राष्ट्रीय समस्याओं में भी व्यस्त था, विशेषतौर से कैची-रूपी संकट, जो सरकार के लिये उर वेदना थी। यच० जी० वेल्स, प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक का इस सम्बन्ध में एक हास्यप्रद कथन है कि विद्युत् योजना की सफलता “सामाजिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच जाना होगा जो काल्पनिक एवम् मिथ्यावाद है।”

इस पर आक्षेप करते हुए एक जर्मन पत्रकार ने भी यह प्रकाशित किया कि: “गोयलरों की विज्ञप्ति में कल्पना रूपी फल (fruits of imagination) के अतिरिक्त कुछ और उपलब्ध करना, एक असम्भव कार्य है। वर्तमान अवस्था में सम्पूर्ण विद्युत् नियोजन एक मिथ्या एवम् क्षतियुक्त वचन है।”

विद्युत् योजना के अन्तर्गत ३० नये स्टेशन, जिनकी शक्ति १५ लाख किलो घन्टा तथा स्थापित कारखानों की शक्ति, दो लाख पचास हजार किलो घन्टा थी, बढ़ने का आयोजन किया गया। सम्पूर्ण शक्ति १७ लाख ५० हजार किलो घन्टा बढ़ने का लक्ष्य था। इस प्रकार १९१३ की अपेक्षा विद्युत् शक्ति में ३४० प्रतिशत तथा विद्युत् स्टेशन की संख्या में १७५ प्रतिशत उन्नति होने का प्रबन्ध किया गया।

मार्च १९२१ में एक राष्ट्रीय नियोजन आयोग (National Planning Commission, अथवा गॉसप्लान (Gosplan) बनाया गया और गोयलरों को उसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस नवीन आयोग का कार्य केवल योजना निर्माण एवम् सुझाव प्रस्तुत करना था। इसके अतिरिक्त इसका शासन सम्बन्धी कोई अधिकार प्राप्त न थे। श्रम एवम् सुरक्षा समिति (Council of Labour and Defence) को योजना के कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया। प्रारम्भ में गॉसप्लान का कार्य निम्नलिखित शब्दों में प्रकाशित हुआ: “सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये एक समरूप आर्थिक योजना की रचना करना, जिसका आधार विद्युत् होगी और जो आठवीं सोवियट कांग्रेस के पास स्वीकृत के लिये भेजी जावेगी।” प्रारम्भिक वर्षों में नियोजन आयोग के कोई विशेष कार्य न थे। जो थे भी वे प्रत्याशा से नीचे थे। इसके कार्यों को ६ भागों में विभक्त किया गया।

आर्थिक जीवन का एक विशेष अंग प्रत्येक विभाग के अधीन था। दस उप-आयोग स्थापित किये गये और प्रत्येक के अधीन एक मंत्रिमण्डल (Commissariat) था। इनका सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें पारस्परिक सहयोग का अभाव था और सब अपने को एक दूसरे से विलग एवम् स्वतंत्र समझते थे। इनका दृष्टिकोण विभाजित एवम् सूक्ष्म था।

अनुभव द्वारा यह शिक्षा मिली कि यह विभागीय, सूक्ष्म एवम् निम्न विचारधारा देश के लिये हिंसात्मक है। १९२१ के उपरान्त इन उप-आयोगों ने अपनी-अपनी विभिन्न-योजनायें कार्यान्वित कीं। एक योजना ईंधन उद्योग के लिये, दूसरे ने यातायात योजना, तीसरे ने भोजन-पदार्थ योजना, चौथे ने विदेशी व्यापार योजना-इस प्रकार अनेक योजनायें बनायी गयीं जिनमें सहयोग, संयोग एवम् समन्वय नाममात्र को भी न था।

दुःसह अनुभव द्वारा अनेक त्रुटियों का ज्ञान हुआ, जिनका निवारण शनैः शनैः किया गया। सब विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं की रचना कर के योजना आयोग के सम्मुख समन्वय तथा स्वीकृत के लिये भेजी जहाँ सीमित साधनों का ध्यान में रखते हुए, उनमें परिवर्तन किये गये और उन्हें एक रूप दिया गया। यद्यपि इसे विस्तृत, एवम् व्यापक योजना कहना उचित न होगा, पर जो कुछ भी इस दिशा में हुआ, एक महत्त्वपूर्ण सुधार था।

गासप्लान ने १९२५-२६ के 'नियन्त्रित अंक' (control figures) प्रकाशित किये। यह एक उल्लेखनीय बात थी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिये योजना इसी के आधार पर बनाई गयी। ये 'नियन्त्रित अंक' भिन्न-भिन्न मंत्रिमण्डलों द्वारा रचे गये, जो योजना के पथ-प्रदर्शक थे। प्रारम्भ में इनका उद्देश्य केवल यह था कि ये वास्तविक योजना के बनने में सहायता पहुँचावें तथा इन्हीं के आधार पर मन्त्रिमण्डल एक व्यापक राष्ट्रीय योजना का निर्माण करे।

एक दिव्य महल के निर्माण के लिये जो मचान बनाये जाते हैं, वही ठीक रूप इन नियन्त्रित अंकों का था, जिन पर एक राष्ट्रीय योजना आधारित थी। एक लेखक ने लिखा था : "ये ऐसे चौखट थे, जिन पर योजना अबलम्बित थी ऐसा स्तर जिसके चारों ओर वास्तविकता घूम रही थी, और जिस पर चातुर्यपूर्ण योजना संचालन गति आधारित थी।"

संक्षेप में, योजना निर्माण इस प्रकार हुआ :

(क) गासप्लान ने 'नियन्त्रित अंकों' को प्रत्येक से सम्बन्धित मन्त्रिमण्डल के सम्मुख उपस्थिति किया।

(ख) इसके उपरान्त प्रत्येक मन्त्रिमण्डल आलोचना सहित अपने विभाग के कार्यक्रम को ग्रासप्लान के सम्मुख पुनः प्रस्तुत करते थे ।

(ग) तत्पश्चात् ग्रासप्लान प्रत्येक विभाग द्वारा भेजे गये कार्यक्रमों का समन्वय करके उन्हें एक व्यापक एवम् विस्तृत सामान्य योजना—रूप प्रदान करता था ।

(घ) तथा अन्त में श्रम एवम् सुरक्षा-समिति उसे स्वीकार करती थी ।

प्रारम्भ में ग्रासप्लान को सांख्यिकी की कमी अनुभव हुई, पर कुछ ही वर्षों में दशा बहुत ही सुधर गयी । १९२५-२६ में 'नियन्त्रित अंक' प्रकाशित हुये थे, जिन पर प्रत्येक विभाग ने अलग-अलग विचार किया था । ग्रासप्लान के सम्मुख उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे । पुनः ग्रासप्लान ने सामान्य योजना तैयार करके श्रम एवम् सुरक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया था । इसी प्रकार १९२६-२७ तथा १९२७-२८ के भी 'नियन्त्रित अंक' प्रकाशित किये गये, जिससे सांख्यिकी-अवस्था में काफी और सुधार हुआ । अब यह सम्भव हो गया कि नियोजन आयोग, जो 'नियन्त्रित अंक' प्रकाशित करें, वे इतने पूर्ण हों कि इसी प्रकार उन्हें अक्षरशः स्वीकार कर लिया जावे ।

१९२७-२८ तक प्रकाशित 'नियन्त्रित अंकों' का परिमाण तथा स्वरूप विस्तृत हो गया, जिनके निर्माण में प्रारम्भ से ही आवश्यक ध्यान दिया गया था ।

१९२८-२९ तक ऐसी उन्नति हुई कि अन्तिम योजना के निर्माण करने के नियन्त्रित-अंकों में कोई विशेष परिवर्तन न करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें वैधानिक तौर से वार्षिक-योजना (annual plan) की संज्ञा भी दे दी गयी ।

तत्पश्चात् पाँच वर्षों के 'नियन्त्रित अंकों' को मिलाकर पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी । सोवियट रूस ने वर्तमान काल तक जितनी भी उन्नति की है, उसका श्रेय उन्हीं योजनाओं को है, जिनमें से एक का जन्म १९२८ में हुआ था । १९२८ से जो योजनायें विविध युगों में बनी हैं, वे अधोलिखित हैं :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-१९३२) ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९३३-१९३८) ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९३८-१९४२) ।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९४६-१९५१) ।

(ङ) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (१९५१-१९५५) ।

(च) छठी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६०) एवम् सप्तवर्षीय योजना (१९६१-१९६५) ।

आठवाँ अध्याय प्रथम पंचवर्षीय योजना

(१९२८-१९३२)

१९२८ से सोवियट रूस ने अपने आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को नियोजन द्वारा आयोजित किया है। नियोजन का तात्पर्य यथेष्ट लक्ष्यों को पूर्वा-नुमान द्वारा कार्यान्वित करना है। सोवियट संविधान (Soviet Constitution) के अनुसार: “सोवियट संघ में आर्थिक जीवन को राष्ट्रीय नियोजन द्वारा नियन्त्रित किया जावेगा, जिसका उद्देश्य सामाजिक सम्पत्ति में वृद्धि, भौतिक एवम् सांस्कृतिक जीवन स्तर का उत्थान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की दृढ़ता तथा सुरक्षा क्षमता की प्रबलता है।”

पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय नियोजन आयोग अथवा गासप्लान द्वारा किया जाता था। १९२८ के उपरान्त यह एक स्थायी आयोग हो गया, जिसमें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ११ सदस्य थे, जिनका निर्वाचन औद्योगिक श्रमिकों, वैज्ञानिकों एवम् विशेषज्ञों में से किया जाता था। गासप्लान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे :

(क) त्रै-मासिक, अर्द्ध-वार्षिक, वार्षिक एवम् पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा मंत्रिमण्डल समिति के सम्मुख उन्हें स्वीकृत के लिये प्रस्तुत करना;

(ख) योजना की सफलता का निरीक्षण करना, तथा

(ग) आर्थिक नियोजन सम्बन्ध व्यवहारिक एवम् सैद्धान्तिक समस्याओं पर सुझाव देना।

योजना के उद्देश्य : १९२८-१९३२, प्रथम पंचवर्षीय योजना का “मशीन-युग” कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मशीन निर्माण की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया। यही कारण है कि इसे “मशीन रश” युग भी कहा गया।

स्टैलिन ने अपनी आर्थिक नीति सूचना-पत्र में इस विषय पर विशेष जोर दिया था और कहा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मशीनों का निर्माण होगा, ताकि सोवियट रूस, जो उस समय मशीन आयात करता था, शीघ्र ही मशीन का उत्पादन करने लगे और एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जावे। योजना का सर्व-प्रमुख उद्देश्य सोवियट संघ की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करना था, जो औद्योगीकरण एवम् समाजवाद-तत्त्व की सफलता एवम् सबलता पर निर्भर था। इसके अतिरिक्त योजना का यह भी उद्देश्य था कि “सोवियट संघ पूँजीवाद देशों के आर्थिक एवम् यंत्रकला स्तर के समकक्ष पहुँच कर, विश्व के सम्मुख एक ज्वलंत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर दे कि समाजवाद व्यवस्था ने पूँजीवाद व्यवस्था पर विजय प्राप्त कर ली है”। औद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान इसलिये दिया गया कि :

(क) सोवियट संघ में समाजवाद की नींव प्रबल हो जावे और यह पूँजीवाद देशों से सुरक्षित रहे, तथा

(ख) सोवियट संघ के नागरिकों का जीवन-स्तर उच्च हो सके।

योजना के लक्ष्य : इन पाँच वर्षों में योजना का लक्ष्य कुल औद्योगिक उत्पादन को दुगुना करना था, जिसके अन्तर्गत प्रथम स्थान भारी उद्योगों को, द्वितीय स्थान उपभोक्ता सामग्री उद्योगों को तथा तृतीय स्थान कृषि को देने का आयोजन किया गया। विद्युतशक्ति का उत्पादन ५ गुना, कोयले का उत्पादन दुगुना से अधिक, कच्चे लोहे का उत्पादन दुगुना तथा इस्पात का उत्पादन भारी परिमाण में बढ़ने का आयोजन किया गया। सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय को दुगुना बढ़ाना था। लोहे तथा इस्पात का उत्पादन स्तर १०० लाख टन के लगभग होने का लक्ष्य निश्चित किया गया। कोयले का उत्पादन ७५० लाख टन होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त योजना ने दूसरे नवीन उद्योगों की ओर भी पूरा ध्यान दिया, जो आधुनिक विज्ञान से सम्बन्धित हैं, जैसे सिन्थेटिक रबर, प्लास्टिक, नकली रेशम, वायुयान तथा रेलवे के सामान आदि।

पूँजी विनियोग में भी उपभोक्ता सामग्री उद्योगों को, भारी उद्योगों की अपेक्षा, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। सोवियट रूस का ध्यान भारी उद्योगों की ओर कम हो गया, क्योंकि वित्त साधन सीमित थे। उत्पादन लागत में ह्रास, श्रम-उत्पादन शक्ति में वृद्धि, एवम् कार्य क्षमता में प्रगति आदि ऐसे उद्देश्य थे, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। श्रमिकों का जीवन निर्वाह, निवास-स्थान सुविधा तथा उत्तम वातावरण आदि बातों पर भी उचित ध्यान देने का प्रयास किया गया।

विनियोग का न्यूनतम अंश कृषि क्षेत्र में लगाया गया जो योजना की सबसे बड़ी त्रुटि समझी गयी। कृषि में सामूहिक खेती (collective farming) पर अत्यधिक ध्यान दिया गया, जिसका यह उद्देश्य था कि पाँच वर्षों के अन्दर सामूहिक खेती की भी उन्नति की जाये तथा ऐसी परिस्थिति एवम् वातावरण उत्पन्न किया जावे कि लोग स्वेच्छानुसार सामूहिक कृषि में सम्मिलित हो सकें। राज्य कृषि (state farming) एवम् सामूहिक कृषि द्वारा सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पत्ति का $\frac{1}{3}$ अंश तथा सम्पूर्ण विक्रय अतिरेक (marketed surplus) का $\frac{2}{3}$ अंश उपलब्ध होने का आयोजन किया गया। स्टैलिन ने कहा : “प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त काल तक “अन्न ट्रस्ट” (“grain trust”) के अधीन अन्न उत्पादन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो जावेगा, जितना अर्जनटाइना का क्षेत्रफल उस समय था। केवल राज्य कृषि के अन्तर्गत लगभग दस लाख हैक्टेयर्स कैनेडा की अपेक्षा अधिक भूमि होगी।” यद्यपि योजना के अन्दर राज्य-कृषि पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य बनाया गया था, तथापि योजना कार्यान्वित होने पर सामूहिक कृषि ने अधिक प्रगति की। नियोजन आयोग का विश्वास था कि कृषि में उन्नति ट्रैक्टर, कृत्रिम खाद (artificial manure), मशीन, बीज आदि से ही सम्भव है। इन उत्पत्ति साधनों पर कृषि की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इन्हीं उद्योगों की उन्नति पर कृषि उन्नति निर्भर है। इसी कारण विनियोग का अधिक अंश उत्पत्ति साधनों के उद्योगों में विनिमय किया गया।

१९२८ में स्टैलिन ने अपने वक्तव्य में कहा : “हम रूसी अपनी पिछड़ी हुई स्थिति की अवहेलना करते हुए, अब औद्योगिक पथ पर साम्यवाद की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहे हैं, तथा धातु (metal), मोटरगाड़ी (automobile) एवम् ट्रैक्टर सम्पन्न एक देश का निर्माण कर रहे हैं।”

योजना की कल्पनायें (assumptions) : प्रारूप योजना में जो लक्ष्य निश्चित किये गये थे, वे वर्गान्तर (class-intervals) थे, जिनकी न्यूनतम-अधिकतम सीमायें थीं। वर्गान्तर की न्यूनतम सीमा इस बात पर आधारित थी कि बहुत सी सन्देहयुक्त एवम् अनिश्चित घटनायें पाँच वर्षों में उत्पन्न हो सकती हैं। अतः यह निश्चित किया गया कि लक्ष्यों को न्यूनतम स्तर पर रक्खा जावे। इसके विपरीत अधिकतम सीमा निश्चित करने में यह धारणा अथवा कल्पना थी कि कोई अनिश्चित अथवा सन्देहयुक्त बाधा इस युग में उत्पन्न न होगी। १९२९ में जो निर्णीत योजना (final plan) सरकार ने कार्यान्वित की, उसमें वर्गान्तर की अधिकतम सीमा के लक्ष्य निश्चित किये थे। उनकी कल्पनायें निम्नलिखित थीं :

(क) सस्य (crop) सामान्य रूप से अच्छी रहेगी ।

(ख) सोवियट रूस का वित्तीय एवम् व्यापारिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय देशों के साथ बढ़ेगा । उसके निर्यात में वृद्धि होगी और विदेशी ऋण उपलब्ध होगा ।

(ग) परिमाण में वृद्धि तो होगी ही, पर यह भी धारणा थी कि गुणात्मक सुधार (qualitative improvement) जैसे उत्पत्ति में वृद्धि, लागत में ह्रास आदि सामान्य रूप से हो सकेगी ।

(घ) अग्रिम वर्षों में सुरक्षा व्यय में भी कमी होगी ।

खेद तो इस बात का है कि उपर्युक्त लिखित सारी कल्पनायें निर्मूल निकलीं । प्रारम्भिक आगणन (preliminary estimates) के अनुसार योजना फलित न हो सकी । विनियोग का जो रूप लक्ष्य किया गया था, वह भी असफल रहा ।

योजना की सर्वप्रथम कल्पना यह थी कि पाँच वर्षों में सस्य सामान्य रूप से अच्छी रहेगी । पर ऐसा न हुआ । यह बिल्कुल अज्ञात था कि पशु हत्या इतनी अधिक संख्या में होगी, जिसके प्रभाव से कृषि उद्योग अस्त-व्यस्त हो जावेगा । इसके अतिरिक्त सामूहिक कृषि आन्दोलन भी तीव्र गति से चलाया गया, जो मांस एवम् दुग्धशाला पदार्थों (dairy products) के उत्पादन के लिये विनाशकारी हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि १९३० की सस्य अच्छी थी, जिसके कारण कुछ निर्यात भी हो सका था । पर १९३१ तथा १९३२ में उत्पादन आशाजनक न था ।

योजना की दूसरी कल्पना यह थी कि पाँच वर्षों में सोवियट रूस अपना निर्यात बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक व्यापारिक महत्त्व स्थापित करेगा । पर यह कल्पना भी अधूरी रही । १९२९—१९३१ में कच्चे माल का मूल्य २० से ३० प्रतिशत घट गया था, जब कि निर्मित सामान का मूल्य केवल १०—२० प्रतिशत कम था । १९२८—१९३१ में गेहूँ और राई का मूल्य लगभग ६० प्रतिशत कम हो गया था । सोवियट रूस के विदेशी व्यापार की दशा और अधिक खराब हो जाती, यदि १९३१ में अधिकतर आयात धातु एवम् कच्चा माल न होता, जिसका मूल्य निर्मित माल के मूल्य से अधिक घट गया था ।

योजना की तीसरी कल्पना थी कि उद्योग-धन्धों में गुणात्मक सुधार सामान्य रूप से होता रहेगा । पर वास्तविकता यह थी कि नए-नए उद्योग-धन्धे जो स्थापित किये गये थे उनमें भी अधिकतम कार्य क्षमता तथा न्यूनतम उत्पत्ति लागत आदि ऐसी कल्पनाओं का कार्यान्वित होना असंभव न था । उदाहरणार्थ उद्योगों में श्रमिक कार्य क्षमता तथा उत्पादन शक्ति, जिनमें १०० प्रतिशत वृद्धि का आयोजन किया गया था, केवल ४१ प्रतिशत सफल हो सकी । सम्पूर्ण निर्माण

कार्यक्रम (construction programme), १०० प्रतिशत कार्य क्षमता वृद्धि पर आधारित था। अगर यह कल्पना सत्य होती तो उत्पादन लागत भी ४० प्रतिशत घट जाती और इससे संलग्न अन्य उद्योगों के भी निश्चित लक्ष्य परिपूर्ण हो जाते। पर कार्य क्षमता में यथेष्ट काल्पनिक लक्ष्य पूर्ण न होने के कारण, उत्पादन लागत केवल २०—२५ प्रतिशत घट सकी। ऐसी असंतोषजनक गति से अनुभव प्राप्त कर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में ही स्टैलिन ने यह संकेत किया था कि : “नवीन निर्माण के लिये प्रस्तुत उत्साह असंतोषजनक है। नवीन यन्त्रकला एवम् नवीन निर्माणशालाओं पर विजय प्राप्त करने के लिये हमें तीव्र गति एवम् प्रचण्ड उत्साह से कार्य क्षमता परिशिष्ट करना है।”^१

योजना की चौथी कल्पना कि सुरक्षा-व्यय घट जावेगा, मिथ्या सिद्ध हुई। युद्ध संशय ने इस कल्पना पर तुषारापात कर दिया। इसके फलस्वरूप सुरक्षा-व्यय अधिक परिमाण में बढ़ गया।^२ साथ ही साथ समाजवादी रूस के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व से उसकी आर्थिक एवम् राजनैतिक व्यवस्था विभिन्न थी। उपर्युक्त कथित कल्पनाओं की मिथ्या गणना (wrong calculation) के कारण, योजना की अनेक सफलतायें लक्ष्य विचलित हो गयीं।

योजना की सफलता एवम् विफलता : योजना के कार्यान्वित होते ही सोवियट रूस को, जापान के, आक्रमण का भय लगने लगा। अकस्मात् नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसकी कि कल्पना भी सोवियट सरकार ने १९२८ में न की थी। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि सोवियट योजना की यह एक कल्पना थी कि युद्ध की कोई आशंका न होने के कारण, सुरक्षा-व्यय निरन्तर कम होता जावेगा। १९३२ में हिटलर की साम्राज्यवाद सत्ता बढ़ने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध-भय बढ़ गया। निर्धारित लक्ष्यों का सम्पूर्ण रूप से सफल होना असम्भव प्रतीत होने लगा। राजकीय घोषणा की गई कि “पंचवर्षीय योजना को चार वर्षों में ही पूर्ण किया जावे।” और वार्षिक अंकों को भी सापेक्ष अनुपात में बढ़ा दिया गया। अतः योजना जो वैधानिक तौर से १९३३ तक संचालित होने वाली थी, १९३२ की शरद् ऋतु में ही स्थगित कर दी गयी थी।

१. Report to Joint Plenum of C. C. and Control Comm. Of C. P. S. U., Jan. 7, 1933.

२. Summary of the Fulfilment of the First Five Year Plan (Gosplan) p. 8.

योजना की सफलता एवम् विफलता का अध्ययन करते समय पाठकों को चाहिये कि वे इस बात की उपेक्षा न करें कि तमाम सफलतायें पाँच के स्थान पर चार वर्षों में ही प्राप्त हुई थीं, जब कि समय का अभाव था, अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध संशय था, सुरक्षा-व्यय अधिक था तथा अन्य कल्पनायें भी मिथ्या सिद्ध हो गयी थीं। समय, साधन एवम् परिस्थिति को देखते हुए, यह कहना अनुचित न होगा कि जो सफलता प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध हुई है, वह प्रसंशनीय है।

यद्यपि भारी उद्योगों की प्रधानता पहले से ही प्राप्त थी, फिर भी योजना के कार्यान्वित होने में इस क्षेत्र में विनियोग गति लक्ष्य से भी अधिक तीव्र हो गयी थी और हल्के उद्योगों के अंश का बहुत सा विनिमय भारी उद्योगों में ही लगा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार सामूहिक कृषि पर भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक महत्त्व दिया गया था।

भारी उद्योगों में नियोजित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त हुई। मूल वस्तु उद्योगों (basic goods industries) में वृद्धि २½ गुना हुई जो कि नियोजित लक्ष्य से कुछ अधिक थी। अनेक प्रकार की मशीनों का उत्पादन चार गुना बढ़ गया और तेल का उत्पादन भी दूना हो गया। विद्युत-सामान २½ गुने से अधिक बढ़ गया। यह प्रगति निम्नलिखित सारणीयों से स्पष्ट है :

तेल तथा शक्ति का उत्पादन

वर्ष	लाख टन	किलो० वा०
१९१३	१०३	२०
१९२८	११६	५०
१९२९	१३७	६२
१९३०	१८५	८४
१९३१	२२४	१०७
१९३२	२१४	१३५

मशीन निर्माण एवम् धातु उद्योगों में उत्पत्ति १९१३ एवम् १९२८ की

अपेक्षा १९३२ में, ७ गुना एवम् ४ गुना क्रमशः बढ़ गई, जो निम्नलिखित सारणी से सिद्ध है :

मशीन-निर्माण और धातु उद्योगों की उत्पत्ति

वर्ष	इकाई	वर्ष	इकाई
१९१३	१०	१९२८	१०
१९२८	१८	१९३२	४०
१९३२	७०		

मशीन निर्माण उद्योगों में ट्रैक्टर का उत्पादन चार-पाँच वर्षों के अन्दर गई गुना बढ़ गया। सामूहिक खेती की प्रगति ट्रैक्टरों पर आधारित थी। आगे चलकर बतलाया जावेगा कि स्थान-स्थान पर मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन स्थापित किये गये थे, जो ट्रैक्टर तथा दूसरे यन्त्र, सामूहिक खेतों को किराये पर देते थे।

ट्रैक्टर का उत्पादन

वर्ष	हजार इकाई
१९२५	०.६
१९२६	०.६
१९२८	१.३
१९२९	३.३
१९३०	६.१
१९३१	३७.६
१९३२	४८.६

व्यापारिक लकड़ी तथा सीमेन्ट के उत्पादन की दशा निम्नलिखित सारणियों में प्रस्तुत की गयी है :

व्यापारिक लकड़ी का उत्पादन

वर्ष	लाख घ० म०
१९१३	३०५
१९२८	३६०
१९२९	६००
१९३०	९६७
१९३१	१,०४१
१९३२	९६४

सीमेन्ट का उत्पादन

वर्ष	हजार टन
१९१३	१,७७७
१९२८	१,८५०
१९२९	२,२३२
१९३०	३,००६
१९३१	३,३३६
१९३२	३,४७८

कृषि की उन्नति के दृष्टिकोण से खनिज-खाद का उत्पादन १३५ हजार टन से ६३१ हजार टन प्राप्त हुआ जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

खनिज-खाद का उत्पादन

वर्ष	हजार टन
१९१३	६६
१९२८	१३५
१९२९	२०८
१९३०	४०४
१९३१	७०१
१९३२	६२१

१९३२ में सोवियट संघ की राष्ट्रीय आय १९१३ की अपेक्षा लगभग दूने से अधिक थी, जैसा निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है :

सोवियट संघ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
१९१३	१००
१९२८	११६
१९३२	२१७

यद्यपि सापेक्ष प्रगति का उल्लेख सोवियट सांख्यिकी द्वारा अधिक उपलब्ध है, तथापि कुछ क्षेत्रों में परिमाणिक उत्पादन समंक भी प्राप्त हैं, जो निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं :

औद्योगिक उत्पादन में परिमाणिक वृद्धि

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	वृहत् उद्योग
१९१३	१००	१००
१९१७	७१	६३
१९२१	३१	२१
१९२५	७३	७५
१९२६	८८	१०८
१९२७	१११	१२२
१९२८	१३२	१५८
१९२९	१५८	१६०
१९३०	१६३	२४६
१९३१	२३३	३०७
१९३२	२७०	३५२

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन जो १०० लाख टन प्रत्येक का लक्ष्य था, अनेक विरोधी कारणवश केवल ६२ लाख तथा ९९ लाख टन क्रमशः पूर्ण हो पाया। फिर भी लोहे का उत्पादन पाँच वर्षों में ८८ प्रतिशत तथा इस्पात का उत्पादन लगभग ४० प्रतिशत की दर से बढ़ गया था। कोयला ८१ प्रतिशत, मिट्टी

का तेल ८४ प्रतिशत, शक्ति २७० प्रतिशत तथा खनिज खाद का उत्पादन ५८० प्रतिशत की दर से बढ़ा था ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

पद	पाँच वर्षों में प्रगति १९२८=१००
सम्पूर्ण उद्योगों का उत्पादन	२०२
उत्पत्ति साधन सामग्री...	२७३
उपभोक्ता सामग्री.....	१५६
कच्चा लोहा	१८८
इस्पात	१३६
रोल्ड धातु	१२६
कोयला	१८१
मिट्टी का तेल	१८४
शक्ति	१७०
खनिज खाद	१८०
औसत योग	१६६

भारी उद्योगों में उपभोक्ता पदार्थ उद्योग की अपेक्षा उत्पादन अधिक हुआ । विनियोग प्रतिशत भी उस क्षेत्र में नियोजित लक्ष्य से अधिक थी । उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादन अधिक न बढ़ा । सम्पूर्ण उद्योगों को सम्मिलित कर पाँच वर्षों में उत्पादन केवल ५६ प्रतिशत था, जो लक्ष्य से कम था । यों तो उत्पादन एवम् विनियोग प्रतिशत का लक्ष्य भी इस क्षेत्र में अधिक न था, फिर भी जो कुछ उन्नति हुई थी वह लक्ष्य से भी कम थी और यह प्रथम योजना की सब से बड़ी असफलता रही ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	भारी उद्योग	उपभोक्ता पदार्थ उद्योग
१९२८	१००	१००	१००
१९२९	१२०	१२६	११४
१९३०	१४६	१७८	१३६
१९३१	१७६	२२६	१४२
१९३२	२०२	२७३	१५६

सूती वस्त्र उद्योग में भी यथेष्ट उन्नति न हो पायी थी। १९२८ के स्तर पर ही उत्पादन स्थगित रहा। १९२९ में कुछ वृद्धि अवश्य हुई, पर १९३० और १९३१ में तो उत्पादन १९२८ से भी कम हो गया। यह गति निम्न सारणी से दृष्टिगोचर होती है :

वस्त्र-उत्पादन

वर्ष	लाख मीटर्स
१९१३	२६,७२०
१९२८	२६,७८०
१९२९	२८,६६०
१९३०	२३,५१०
१९३१	२२,४२०
१९३२	२६,६४०

ऊन के भी उद्योग में लगभग ऐसी ही अवस्था थी, जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है। १९३२ १९१३ के उत्पादन से बहुत ही कम था।

ऊनी वस्त्र उद्योग में उत्पादन वृद्धि

वर्ष	लाख मीटर्स
१९१३	१,०७७
१९२८	८६८
१९२९	१,००६
१९३०	१,१४५
१९३१	१,०७६
१९३२	८८७

रेशमी वस्त्र की दशा और अधिक शोचनीय थी, जैसा कि अधोलिखित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं :

रेशमी वस्त्र उद्योग में उत्पादन

वर्ष	लाख मीटर्स
१९१३	४२६
१९२८	६६
१९२९	१३०
१९३०	१७८
१९३१	१६५
१९३२	२१५

चमड़े के जूतों की भी अवस्था में कोई सुधार न हो पाया था। उत्पादन १९१३ या १९२८ की अपेक्षा अवश्य अधिक था, पर कोई विशेष उन्नति न हो पायी थी।

जूता उद्योग में उत्पादन

वर्ष	लाख जोड़े
१९१३	६००
१९२८	५८०
१९२९	७७०
१९३०	७५४
१९३१	८६७
१९३२	८६६

कागज के उत्पादन की दशा अन्य उपभोक्ता पदार्थों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी।

कागज उद्योग में उत्पादन

वर्ष	हजार टन
१९१३	२६६
१९२८	२८४
१९२९	३८५
१९३०	४६५
१९३१	५०५
१९३२	४७१

मछली उत्पादन में वृद्धि निम्नकोटि की थी। मक्खन तथा अन्य दुग्ध-शाला पदार्थों में वृद्धि कदापि न हो पायी थी, क्योंकि पशुओं की हत्या इन वर्षों में काफी संख्या में हुई। दूध उत्पादन में अवस्था शोचनीय थी। १९३२ में १९२८ की अपेक्षा उत्पादन स्थिर रहा।

दूध-उत्पादन

वर्ष	लाख टन
१९१३	२३
१९२८	१६
१९२९	१८
१९३०	१०
१९३१	२०
१९३२	१६

मक्खन के उत्पादन की दशा और खराब थी, जो योजना की एक भयानक असफलता थी। निम्नलिखित तालिका में वास्तविक दशा प्रदर्शित की गयी है :

मक्खन उद्योग में उत्पादन

वर्ष	हजार टन
१९१३	१०४
१९२८	८२
१९२९	७८
१९३०	४१
१९३१	८३
१९३२	७२

लगभग ऐसी ही दशा चीनी के उत्पादन में भी थी। १९३२ में १९१३ या १९२८ की अपेक्षा उत्पादन बहुत ही कम था। निम्नलिखित सारणी से यह स्पष्ट है। १९२८ में उत्पादन १९३२ की अपेक्षा अधिक था।

चीनी उद्योग में उत्पादन

वर्ष	हजार टन
१९१३	१,३५८
१९२८	१,२८३
१९२९	८२३
१९३०	१,५०७
१९३१	१,४८६
१९३२	८२८

इस युग में कुशल एवम् विशिष्ट श्रमिकों की बहुत कमी थी। एक आन्दोलन चलाया गया कि विश्वविद्यालयों में उच्च विशिष्टशिक्षा दी जाये; यन्त्रकला शिक्षा में लोग निपुण किये जावें तथा प्रयोगशालाओं में वे अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजे जावें। अनेक प्रयोगशालायें तथा प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये। योजना के अन्त तक लगभग कई लाख विद्यार्थी माध्यमिक एवम् विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

पाँच वर्षों में निम्नलिखित संख्या में विशेषज्ञों ने विश्वविद्यालय डिग्रीयाँ प्राप्त कीं।

विशेषज्ञों की कुल संख्या जिन्होंने डिग्री प्राप्त की : (१९२९-१९३२)	विशेषज्ञों की वार्षिक औसत संख्या (१९२९-१९३२)
उच्च शिक्षा (विद्यालयों से)..... १,७०,०००	४२,५००
माध्यमिक शिक्षा (विद्यालयों तथा यन्त्रकला केन्द्रों से)... २,९१,०००	७८,८००

निरक्षरता दूर करने के लिये एक प्रभावशाली आन्दोलन चलाया गया। १९३४ की सांख्यिकी उपलब्ध न होने पर भी १९२६ तथा १९३९ के समकों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि इस दिशा में बहुत अधिक प्रगति हुई है।

१९२६ में शिक्षा विस्तार ५१ प्रतिशत था जो कि १९३६ में ८१ प्रतिशत हो गया। १९३२ में १,५५,००० डाक्टर देश में थे। 'गासप्लान' द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, १९३६ में कुल ६५ लाख शिक्षित प्राणी थे।

सामूहिक कृषि में प्रथम पंचवर्षीय योजना ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किये। इस क्षेत्र में उन्नति अनुमान से अधिक हुई। यद्यपि इस समय इसके अस्थायी प्रभाव अत्यन्त कष्टमय थे, फिर भी निश्चित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त हुई। सोवियट सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत कृषि (individual farming) के स्थान पर सामूहिक कृषि (collective farming) तथा राज्य कृषि (state farming) पर जोर दिया। उसका लक्ष्य था कि यह परिवर्तन धीरे-धीरे किया जावे, क्योंकि कृषकों को प्रारम्भिक वर्षों में नये समाज तथा नयी पद्धतियों के अन्तर्गत कार्य करने में असुविधा हो सकती है, जिसके कारण वे इसका विरोध भी कर सकते हैं। स्टैलिन का कहना था :

“यह एक यथेष्ट मार्ग होगा कि छोटे तथा बिखरे खेतों को सम्मिलित कर, तथा उन्हें बृहत् सामूहिक रूप देकर सार्वलौकिक कृषि की जावे, जिसका तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है, जिसके अन्तर्गत नवीन एवम् उच्चकोटि के यान्त्रिक साधनों का समावेश होता है। छोटे एवम् बिखरे खेतों का समन्वय बिना किसी राजकीय अनुचित प्रभाव के, विश्वास, अनुभव तथा उदाहरण द्वारा किया जावे। यह पद्धति सामान्य सहकारी कृषि के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टरों का प्रयोग एवम् वैज्ञानिक ढंग की गहन कृषि सम्मिलित है। प्रगति हेतु यही एक मार्ग सम्भव है।”

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, इसमें सन्देह नहीं, कि सामूहिक खेती ने उन्नति की, पर प्रारम्भ में केवल ६०,००,००० कृषक कुटुम्ब तथा १५ प्रतिशत भूमि-क्षेत्र को सामूहिक कृषि में परिवर्तित करने का आयोजन किया गया था। नियोजन आयोग ने फूँक-फूँक कर कदम रखने का निश्चय किया था और लिखा : “यह बात निष्कपटता से स्वीकार करनी पड़ेगी कि हममें यह एक महान् त्रुटि है, जो हम सामूहिक कृषि के महत्त्वपूर्ण यन्त्रकला सम्बन्धी सिद्धान्तों से अभी तक अनभिज्ञ हैं। वास्तव में सामूहिक कृषि, मध्यवर्ग का एक दीर्घकालीन उपकरण है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रगतिशील उद्योगों को खाद्यान्न, एवम् कच्चा माल प्रदान करना है।”^१ सरकार ने सामूहिक कृषि के अतिरिक्त राज्य-कृषि की ओर भी ध्यान दिया। राज्य खेतों को ‘अन्न कारखानों’ (grain factories)

१. Soviet Union looks Ahead, p. 85.

के रूप में रक्खा गया, जिनका मुख्य उद्देश्य नये क्षेत्रों को खेती योग्य बनाना तथा उन्हें अपने साथ मिलाना था। एक 'अन्न ट्रस्ट' स्थापित किया गया। लगभग १५० विस्तृत अन्न खेत जिनमें कुछ का क्षेत्रफल कई सैकड़-हजार एकड़ था, योजना के लक्ष्य बनाये गये। १९३३ तक अन्न फसल का पाँचवा भाग तथा विक्रय-अतिरेक का $\frac{2}{3}$ भाग सामूहिक एवम् राज्य खेतों द्वारा उपलब्ध होना चाहिये था। प्रथम दो तीन वर्षों में सफलता आशा से अधिक थी। १९२९-३० में अन्न के विक्रय-अतिरेक की पूर्ति, जो राज्य-खेतों से प्राप्त हुई थी, १९३३ के निश्चित लक्ष्य से अधिक हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी ने एक प्रस्ताव (resolution) द्वारा निश्चित लक्ष्य को दूना कर दिया। इस परिमाण में विक्रय-अतिरेक प्राप्त करने के लिये राज्य-कृषि का क्षेत्रफल ८०० प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया। यह कार्य कितना विस्तृत तथा बड़े आकार का था, स्टैलिन के १९३२ के वक्तव्य से पता चलता है : " 'अन्न-ट्रस्ट' के आधीन अब इतना विस्तृत कृषि-क्षेत्र हो गया है, जितना कि कुल अर्जनटाइना ।" कैनाडा के कृषि-क्षेत्रों से तुलना करते हुये स्टैलिन ने पुनः कहा : "रूसी राज्य-कृषि के अन्तर्गत दस लाख हैक्टेयर्स अन्न-भूमि कैनाडा से अधिक है ।" यह स्थिति प्रथम पंच-वर्षीय योजना के कृषि सफलता की पुष्टि तो करती है, पर यह इस विषय पर बिल्कुल प्रकाश नहीं डालती कि किस लागत पर इतना सारा परिवर्तन चार वर्षों में सम्भव हो सका था।

सामूहिक कृषि आन्दोलन की प्रगति आशा से अधिक होने के कारण सोवियट रूस के पशुपालन उद्योग पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यह उद्योग सम्पूर्णतः विनष्ट हो गया। इस घटना को प्रोत्साहित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन धनी कृषकों पर था, जिनसे अतिरेक-भूमि ले ली गयी थी और जिन्हें निर्धन कृषकों का शोषण करने से वंचित कर दिया गया था। १९३१ तक पशुओं की संख्या १९२६ की अपेक्षा एक तिहायी से अधिक कम हो गई। बकरी तथा भेड़ों की संख्या लगभग आधी रह गयी तथा १९३३ तक पशुओं के नाश की गति उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते इस अवस्था पर पहुँच गई कि उसको सुन्यवस्थित करने के लिये अनेक वर्षों की आवश्यकता थी। १९३९ तक भी पशुओं तथा भेड़-बकरियों की संख्या १९२६ की अपेक्षा पूरी न हो पायी थी। घोड़ों की संख्या भी १९३२ में १९२६ की अपेक्षा आधी से अधिक न थी। पशुओं की संख्या घटने के कारण मांस तथा दुग्धशाला पदार्थों में कमी अनेक वर्षों तक रही। कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यों के लिये (जैसे हल चलाना आदि) पशुओं की आवश्यकता प्रतीत हुई। कृषि में ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनों का प्रयोग एकाएक तो हो नहीं सकता था,

क्योंकि उनके निर्माण करने में कुछ समय अवश्य लगेगा। दूसरे, कितनी भी तीव्र गति से उनका निर्माण क्यों न किया जावे, पशुओं की न्यूनता के कारण अनेक गौण समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं, जिनका सुलभना कोई सरल कार्य न था। प्रारम्भ के कुछ वर्षों में सामूहिक कृषि की प्रगति के कारण कृषक वर्ग को बहुत अधिक क्षति पहुँची और कृषि में निश्चित उर्वरता भी, जो नियोजित की गयी थी, अपूर्ण रही। जैसे-जैसे सामूहिक खेती में प्रगति हुई, वैसे-वैसे पशु-हत्या में भी वृद्धि हुई। सामूहिक खेतों में प्रगति निश्चित लक्ष्य से अधिक थी, जिसके प्रभाव भी अधिक कष्टदायक थे। फलस्वरूप कुछ काल तक सारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त रही। देश निवासियों का कष्ट अवर्णनीय हो गया था। सिद्धान्त के अनुसार तो सामूहिक कृषि की प्रगति स्वेच्छानुसार होनी चाहिये थी। प्रत्येक व्यक्ति को इस पद्धति के स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। पर वास्तवमें हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। यही कारण था कि स्टैलिन ने मार्च २, १९३० को उन व्यक्तियों के इस कार्य की घोर निन्दा की जो जबरजस्ती सामूहिक कृषि को बढ़ा रहे थे और “स्वेच्छाकृत सिद्धान्त” का गला घोट रहे थे। इस आन्दोलन को कृषकों की इच्छानुसार, तथा स्थानीय विशेषताओं पर उचित ध्यान देते हुये, संचालित करने का आयोजन किया गया था। परन्तु कार्यान्वित होते समय इन सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी, जो उच्च पदाधिकारियों के लिये एक खेदप्रद एवम् असंतोषजनक बात थी। निम्नलिखित समंको से सामूहिक कृषि प्रगति का विस्तारपूर्वक लेखा प्राप्त है :

सामूहिक कृषि

वर्ष	कृषक-कुटुम्ब प्रतिशत	सस्य-क्षेत्र प्रतिशत
१९१८	०.१	—
१९२७	०.८	—
१९२८	१.७	२.३
१९२९	३.६	४.६
१९३०	२३.६	३३.६
१९३१	५२.७	६७.८
१९३२	६१.५	७७.७
१९३७	६३.०	६६.१
१९४०	६६.६	६६.६

राज्य-कृषि, मशीन तथा ट्रैक्टर स्टेशन एवम् सामूहिक कृषि

(१९२८-१९३३)

पद	१९२८	१९३३
कुल राज्य-कृषि का योग	१,४८७	४,३३७
मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन की संख्या...	६	२,४४६
सामूहिक-कृषि की संख्या	०'४	२११.७
सामूहिक कृषि में सम्मिलित कुटुम्ब की संख्या	३३'३	१४'७
प्रति सामूहिक कृषि की औसत संख्या...	१३	७१

योजना का वित्त-प्रबन्ध : अधिकांश वित्त-प्रबन्ध राज्य-आय से किया गया, जो औद्योगिक लाभ से संग्रहित की गई थी। इसके अतिरिक्त अनेक व्यवसायों तथा संस्थाओं से भी राज्य-ऋण संग्रह किया गया। १९३० के उपरान्त अधिकतर पूँजी विक्रय-कर (turnover tax) से एकत्रित की गई। १९३० के कर व्यवस्था सुधारक विधान (Taxation Reform of 1930) द्वारा विक्रय-कर को सुसंगठित किया गया, जिसके द्वारा बहुत बड़ी धन-राशि संग्रहित होने लगी। इसके अतिरिक्त जितना वेतन तथा पारिश्रमिक परिमाण में बढ़ गया था, उसी अनुपात में मुद्रा प्रचलन भी बढ़ा दिया गया था तथा यह भी योजना को वित्त प्रदान करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन था। नियन्त्रणों द्वारा मुद्रा-स्फीति को प्रतिबन्धित किया गया तथा राशन की दूकानों ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया।

आलोचना : आलोचकों ने अनेक त्रुटियाँ इस महान योजना में बतलाई। उनका कथन था कि इसकी धारणा एवम् इसका विचार सूक्ष्म तथा सीमित था, जिसके कार्यान्वित करने में अत्यधिक व्यय हुआ और इसके कार्य, विवेक एवम् चेतना रहित थे। कुछ आलोचकों ने इसकी असफलताओं की ओर भी संकेत किया और इसी दृष्टिकोण से इसको बहुत ही दूषित ठहराया। अक्टूबर ७, १९३० को 'टाइम्स' नामक समाचारपत्र ने अपने सम्पादक-अग्रलेख (editorial) में लिखा: "योजना ने अपने विनाश के लक्षण संकेत किये हैं" और 'न्यूयार्क टाइम्स' ने इसको "योजना" न कह कर एक "घूत" ("gamble") कहा, "जिस ओर सोवियट सरकार अपने को एक महान् जोखिम में डाल रही थी।" यह भी

आक्षेप किया गया कि पंचवर्षीय योजना में वास्तविकता कम है, जिसके कारण उद्योगों में एक महान संकट किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है। सोवियट रूस की सब से बड़ी विफलता खाद्यान्न की विशेष कमी थी। एक ने उल्लेख किया “सोवियट रूस, विशाल उद्योगों के निर्माण हेतु मदान्ध हो गया है जिसने बहुत सी व्यय-साध्य व्यर्थ वस्तुओं को (“a race of white elephant”) जन्म दिया है।” विश्व का प्रत्येक राष्ट्र यही अनुमान करता था, कि सोवियट रूस जिस गति से पाँच वर्षों में बढ़ा है, उसी गति से, आश्चर्य नहीं, इसका पतन भी हो जाये। जब भी सोवियट योजना के अन्तर्गत कोई कमी उन्हें दृष्टिगोचर होती थी, वे उसका सम्बन्ध सोवियट रूस के पतन से ही आँकते थे।

जिन कल्पनाओं के आधार पर योजना निर्माण की गयी थी, वे अपूर्ण रहीं, जिसके कारण योजना सम्पूर्ण रूप से सफल न हो सकी। यह योजना की आलोचना न होकर एक समालोचना है। योजना को अत्यधिक क्षति कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई, जो पाँच वर्षों में उत्पन्न हो गई थी और जिसका उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। ऋतु उत्तम न होने के कारण कई वर्ष फसल नष्ट हुई; अन्तराष्ट्रीय अवस्था भी असंतोषजनक होने के कारण, निर्यात में वृद्ध होने के स्थान पर हास हुआ तथा सुरक्षा-व्यय निरन्तर बढ़ता गया। परिणाम यह हुआ कि योजना के कार्यान्वित होने में बहुत से ऐसे परिस्थितिवश परिवर्तन हुए, जिनका कोई भी आयोजन नहीं किया गया था। वास्तव में इस आधार पर योजना की आलोचना नहीं की जा सकती। कुछ विद्वानों ने सच कहा है कि अनेक राजनैतिक एवम् आर्थिक संकटजाल के अन्तर्गत रह कर भी, जिस प्रकार सोवियट सरकार ने अपनी परिस्थिति समझाली है, एक प्रशंसात्मक एवम् आश्चर्यजनक बात है।

योजना से सम्बन्धित बहुत ही गंभीर आलोचना उस सामूहिक कृषि के प्रति है, जिसके कारण सोवियट रूस की आधी से अधिक पशुसंख्या नष्ट हो गयी थी। परिणामस्वरूप : (क) देश को मांस तथा दुग्धशाला पदार्थों की कमी अनुभव हुई;

(ख) खेतों को जोतने के लिये पशुओं की न्यूनता एक बहुत बड़ी समस्या थी;

(ग) कृषि उत्पत्ति में भी असाधारण हास थी ; और

(घ) सोवियट योजना की यह कल्पना, कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा कर निर्यात में वृद्धि करके विदेशों से पूँजी प्राप्त की जावेगी, मिथ्या हो गई।

योजना के विरुद्ध यह भी आलोचना थी कि इसने अत्यधिक महत्त्व कोयले, लोहे, इस्पात, विद्युत्, मशीन और ट्रैक्टर के उत्पादन को दिया तथा उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन की उपेक्षा की गयी। इसमें सन्देह नहीं कि उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में १९१३ के उत्पादन की

अपेक्षा बहुत ही कम था, जो योजना की महान असफलता थी, जैसा कि पिछले पृष्ठों में उल्लेख किया गया है ।

यह भी कहना अनुचित न होगा कि मुद्रास्फीति का सर्वप्रथम कारण मुद्रा प्रचलन में वृद्धि था । मुद्रा प्रचलन को बढ़ाकर योजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गयी थी और इसका प्रभाव वहाँ की जनता के जीवन-स्तर पर घातक सिद्ध हुआ । सोवियट सरकार ने राशनिंग तथा मूल्य का नियन्त्रण तो अवश्य किया, पर इसका सुव्यवस्थित प्रबन्ध न हो सका । योजना को इस बात पर दोषित किया गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य अपूर्ण रहें :

- (१) जिन कल्पनाओं पर योजना आधारित थी, वे अपूर्ण रहीं ।
- (२) कृषि उत्पादन में वृद्धि निश्चित लक्ष्य के अनुसार न हो सकी ।
- (३) वित्तीय पद्धति दोषपूर्ण थी ; मुद्रास्फीति को उत्तेजित करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था ।

(४) उपभोक्ता सामग्री उद्योगों में भी उत्पादन अधिक न बढ़ सका । यद्यपि लक्ष्य का परिमाण अधिक न था, फिर भी सफलता असंतोषजनक थी । उपभोक्ता सामग्री उद्योगों में विनियोग प्रतिशत भी भारी उद्योगों की अपेक्षा बहुत ही कम था ।

(५) पशु-संहार तथा पशुपालन आयोग का विनाश योजना की प्रमुख विफलता थी ।

(६) यातायात साधनों में आवश्यकतानुसार ध्यान न दिया गया था ।

यह कहना अनुचित न होगा कि समाजवादी रूस ने चतुर्दिशाओं में पूँजीवाद राष्ट्रों से प्रसित होकर, तमाम विफलताओं तथा आलोचनाओं का अनुभव करते हुये, पाँच वर्षों में जो प्रगति की है, वह प्रशंसनीय है । प्रथम पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण नाटक का प्रथम अङ्क था, जिसके पूर्ण होने पर दूसरा अङ्क प्रारम्भ एवम् प्रदर्शित किया गया । सम्पूर्ण नाटक को बिना देखे हुये, किसी विशेष अङ्क की आलोचना-समालोचना करना न्याय संगत नहीं है ।

१९३२ तक अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित हो गयी थी । निःसन्देह उपभोक्ता सामग्री की न्यूनता अधिक थी, फिर भी परिस्थिति अच्छी थी । गिने-चुने उद्योगों को छोड़ कर, प्रगति चतुर्मुखी थी । ऐसी आशा प्रतीत होने लगी थी कि समाजवादी रूस उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, योजनात्मक नाटक खेल कर अपनी रङ्ग भूमि को सम्पूर्ण जगत के सम्मुख ऐसा प्रदर्शित करेगा कि विश्व के लिये यह एक रहस्यात्मक तथा आश्चर्यजनक घटना होगी और पूँजीवाद देशों के समकक्ष वह एक प्रभावशाली राष्ट्र हो सकेगा । जीवन-स्तर निम्नकोटि का होते हुये भी, योजना की सफलता इतना तीव्र प्रकाश प्रदान कर रही थी, कि ऐसा प्रतीत होता था कि एक साधारण रूसी कह रहा है: “कामरेड ! जीवन सुधर रहा है ।”

नवाँ अध्याय

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(१९३३-१९३७)

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सोवियट सरकार ने जो कटु अनुभव किये, तथा जिन त्रुटियों के द्वारा उसे महान क्षति पहुँची, उनका विशेष ध्यान रखते हुये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। नियोजन आयोग की यह घोषणा थी कि : “यन्त्र कला का पूर्णज्ञान करके (“master technique”) प्राप्त लाभों को सुदृढ़ बनाया जावे।” प्रथम पंचवर्षीय योजना में गुणात्मक सुधार को कल्पना आधार मान लिया गया था, जिन पर अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी थी। प्रस्तुत योजना में उन तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण थे, तथा जिन्हें प्रथम योजना में काल्पनिक तथ्य माना गया था।

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सस्य विनाश अधिक हुआ था, जब कि यह योजना की कल्पना थी कि सस्य को किसी प्रकार क्षति न पहुँचेगी और सामान्य सस्य उत्तम होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस तथ्य को आधार अथवा कल्पना न मान कर, इसका समुचित आयोजन किया गया।

(ख) प्रथम योजना की यह भी कल्पना थी कि सोवियट सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एवम् व्यापार व्यवस्था निरन्तर सुधरेगी। द्वितीय योजना में इस अपूर्ण तथ्य का समुचित आयोजन तथा प्रबन्ध किया गया।

(ग) प्रथम योजना की यह धारणा थी कि समाजवाद व्यवस्था में आर्थिक गुणात्मक सुधार स्वतः होना चाहिये। अनुभव द्वारा सरकार का विश्वास दृढ़ हो गया था कि बिना पूर्ण चेष्टा किये, इस क्षेत्र में स्वतः उन्नति असम्भव है, जो सम्पूर्ण योजना की विफलता का कारण हो सकती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने कार्यक्षमता, उर्वरता तथा अन्य गुणात्मक सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया

तथा विनियोग का बहुत बड़ा अंश इस ओर लगाया, ताकि जितनी भी अब तक उन्नति हुई थी, उसे वे अति प्रबल तथा दृढ़ बना सकें।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी प्रथम योजना की तरह सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो पाई, क्योंकि युद्ध-भय दिन प्रति दिन बढ़ रहा था।

योजना के लक्ष्य : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारी उद्योगों के निर्माण कार्य में प्रधानता दी गई तथा सम्पूर्ण विनियोग का अधिकांश इस उद्योग में लगाया गया। यद्यपि प्रतिशत दर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम थी, तथापि निरपेक्ष रूप से (absolute sense) विनियोग का परिमाण हल्के उद्योगों की अपेक्षा भारी उद्योगों में अत्यधिक था। निःसन्देह उपभोक्ता सामग्री तथा हल्के उद्योगों को प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया, फिर भी विनियोग का अधिक अंश भारी उद्योगों में लगाया गया, जिस ओर सोवियट सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित था। निर्मिति यन्त्रों को, जो प्रथम योजना के समय तैयार किये गये थे, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मित किये जाने को थे, हल्के उद्योगों में प्रयोग किये जाने की योजना में सम्मिलित किये गये। उदाहरणार्थ, जूता बनाने की मशीनें, वस्त्र उद्योग की मशीनें और सूत कातने की मशीनें आदि।

सूत कातने की मशीनों तथा करघों के उत्पादन में दस गुना वृद्धि लक्ष्य किया गया, जिससे उनकी सूत तथा वस्त्र उत्पादन करने की क्षमता में कम से कम पाँच वर्षों में ४० प्रतिशत वृद्धि हो सके। चमड़े तथा जूते के उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनों का उत्पादन ४०० प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत योजना में भारी उद्योगों की मशीनों के निर्माण को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया। उपभोक्ता पदार्थों की उत्पत्ति में वृद्धि भारी उद्योगों की अपेक्षा अधिक थी। औसत वार्षिक वृद्धि-दर १८½ प्रतिशत थी, जो पाँच वर्षों में १३३ प्रतिशत गणना की गयी। इसके विपरीत भारी उद्योगों में १४½ प्रतिशत तथा सम्पूर्ण उद्योगों में १६½ प्रतिशत प्रगति करने का लक्ष्य किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र का उत्पादन दूना, ऊनी वस्त्र तथा जूतों का दुगुना से कुछ अधिक, स्कूल तथा दफ्तर की सामग्री तिगुनी, लिनन (linen) तथा मोजा-बनियाइन, बाइसकिल, घड़ियाँ तथा संगीत सामग्री का उत्पादन चौगुना होना लक्षित किया गया। नागरिक श्रमिकों की उपभोग-सामग्री में वृद्धि दुगुना करने का लक्ष्य किया गया। इसके अतिरिक्त नगर तथा नगरपालिकाओं के निर्माण कार्य में सुधार करने का पूर्ण प्रबन्ध किया गया। गृह निर्माण में ३३ प्रतिशत वृद्धि, अस्पताल-विस्तरों में ४४ प्रतिशत वृद्धि,

बीस नगरों में 'ग्रामवे' तथा चालीस नगरों में 'बस' सेवाओं का पूर्ण प्रबन्ध किया जाने का आयोजन किया गया। उन नगरों में जहाँ की जनसंख्या ५०,००० से अधिक थी, मल प्रणाल (sewer) और उन नगरों में जहाँ जनसंख्या १०,००० से अधिक थी, जल-नल सेवा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। परन्तु यह सम्पूर्ण हितकारी एवम् कल्याणकारी प्रबन्ध करते हुये भी, विनियोग की तीन चौथाई भाग से अधिक राशि भारी उद्योगों में लगायी गयी, क्योंकि सोवियट रूस का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को प्रबल एवम् शक्तिशाली बनाना था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नवीन कार्यालय स्थापित किये गये थे तथा जिन मशीनों तथा यन्त्रों को प्रयोग किया गया था, उनका समुचित सदुपयोग होने का आयोजन किया गया। "समाजवाद अर्थव्यवस्था में यान्त्रिक पुनर्निर्माण कार्य को पूर्ण करो", द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम एवम् असन्दिग्ध आर्थिक उद्देश्य था। प्रथम एवम् द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जिन नवीन उद्योगों का जन्म हुआ था, उनका अधिकतम उपयोग जनकल्याण हित के दृष्टिकोण से कालान्तर तक हो जाना चाहिये था। प्रस्तुत योजना का प्रमुख कर्तव्य नवीन यन्त्रकलात्मक प्रयोग की पूर्ण व्यवस्था पर नैपुण्य एवम् विद्वता स्थापित करना था : ताकि

(क) श्रम उत्पत्ति में वृद्धि,

(ख) उत्पत्ति लागत में ह्रास तथा

(ग) उत्पत्ति में गुणात्मक सुधार सम्भव हो सकें।^१

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य उच्चतम सीमा (upper limit) पर निश्चित थे। इसके प्रतिकूल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वे न्यूनतम सीमा (lower limit) पर लक्षित किये गये। इसका विशेष कारण यह था कि योजना के प्रथम वर्ष के उपरान्त जब निर्णीत योजना (final plan) मान्यता प्राप्ति हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अनेक पदार्थों का उत्पादन आशा हीन था, और ऐसा प्रतीत होता था कि यदि लक्ष्य उच्चतम सीमा पर निर्धारित किये जायेंगे, तो अव्यवस्थित आर्थिक कारणवश वे अपूर्ण रह जायेंगे।

यद्यपि स्थापित मशीनों में अधिक सुधार तो किया ही जाने का लक्ष्य था तथापि नयी कम्पनियाँ एवम् नये व्यवसायों के निर्माण की ओर भी सोवियट सरकार का यथेष्ट ध्यान था। नवीन निर्माण विस्तृत परिमाण में संचालित करने का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत ४५ नयी ब्लास्ट भट्टी, १६४ खुली

भट्टियाँ तथा १०७ 'रोलिंग मिलें' स्थापित होनी चाहिये थीं। १९३७ में लोहा उत्पादन १६० लाख टन तथा इस्पात १७० लाख टन हो जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया। ऐसा होने से अनुमान किया गया कि १९३३ की अपेक्षा इनका उत्पादन २५० प्रतिशत अधिक हो जावेगा। प्रथम योजना के अन्तर्गत उत्पादन १०० प्रतिशत बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी अपेक्षा द्वितीय योजना में, ऐसा अनुमान किया गया, कि ६३ प्रतिशत वृद्धि आयोजित करने से उत्पादन लागत २६ प्रतिशत घट जावेगी तथा सम्पूर्ण श्रम-शक्ति में २८ प्रतिशत वृद्धि होगी। निम्नांकित तीन ऐसे भारी उद्योग थे, जिनको द्वितीय योजना में अत्यधिक महत्त्व दिया गया :

(क) लोहे तथा इस्पात का उद्योग, जिसका वर्णन उपर्युक्त हो चुका है।

(ख) मशीन निर्माण उद्योग, जिसकी स्थापना प्रथम योजना में दृढ़ हो चुकी थी।

(ग) लोहा-धातु (ferrous metal) के अतिरिक्त अन्य-धातु (non-ferrous metal) को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके पूर्व प्रथम योजना में इन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। अधिकतर धातुयें जैसे तांबा, पीतल, टिन, आलमोनियम, निकल, तथा जस्ता की माँग विद्युत् उद्योग में थी। रेडियो सम्बन्धी तथा युद्धसामग्री निर्माण में इन धातुओं की अधिकता से प्रयोग किया गया। प्रथम योजनाकाल में इन धातुओं को प्रायः आयात किया जाता था, परन्तु द्वितीय योजना में इनके उत्पादन पर विशिष्ट ध्यान आकर्षित किया गया। ताँबे का उत्पादन यूराल पर्वत तथा बाल्कस भील, शीशे का उत्पादन शिमकेन्ट, अल्टाई, उत्तरी काकेशस तथा सुदूर पूर्व प्रदेश एवम् जस्ता का उत्पादन यूराल तथा साइबेरिया प्रदेश में बढ़ाने का आयोजन किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में आलमोनियम का उत्पादन दो ऐसे केन्द्रों में हो रहा था जहाँ विद्युत् सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। मध्य यूराल प्रदेश में आलमोनियम निर्माण का आयोजन किया गया, जो भविष्य के लिये बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में जर्मन आक्रमण असम्भव था। यह ऐसा विशिष्ट पदार्थ था, जिसकी समता एवम् तुलना फ्रान्स के प्रसिद्ध गुणी धातु से की गयी थी।

प्रस्तुत तीव्र प्रगति असुविधाजनक यातायात के कारण सम्भव न थी। निःसन्देह, नवीन आर्थिक नीति तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में यातायात साधन, विशेषतः रेलों, पर अत्यधिक भार पड़ा, जब कि उनमें गुणात्मक सुधार

अथवा नवीन निर्माण शून्य था। कुछ आलोचकों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की इस दृष्टिकोण से कटु आलोचना की। ऐसा अनुभव किया गया कि औद्योगिक उत्थान के लिये सुविधाजनक एवम् सस्ता यातायात प्राप्त होना अत्यन्त आवश्यक था। वास्तव में जल-थल यातायात असंतोषजनक थे। १९३२-३७ के मध्य रेलवे यातायात में ७५ प्रतिशत वृद्धि करने की आयोजना की गयी थी जिसका तात्पर्य यह था कि १९१३ की अपेक्षा १९३७ में यातायात भार ५०० प्रतिशत अधिक था। रेलवे यातायात भार पर यह वृद्धि औद्योगीकरण की तीव्र गति प्रदर्शित करती है, जिसका प्रारम्भ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। ग्रामीणों का ग्रामीण उद्योग-धन्धों का त्यागना तथा नगरों में स्थायी निवास करना, इस विषय की पुष्टि करता है कि नगरों में खाद्यान्न समस्या अत्यधिक बढ़ गयी थी और सरकार के सम्मुख यह एक उत्कृष्ट विषय था कि किस प्रकार सस्ते अन्न की पूर्ति की जावे। यातायात उन्नति औद्योगीकरण के साथ-साथ होनी चाहिये, क्योंकि औद्योगिक उन्नति की सर्वप्रथम आवश्यकता सस्ता यातायात है। कोयले तथा लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, निर्मित सामग्रियों को बाजार पहुँचाना तथा खाद्यान्न को शहरों में लाना आदि ऐसे कार्य थे, जिनके कारण आधुनिक यातायात पर उत्तरोत्तर भार बढ़ रहा था। ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे अधिकतम क्षमता युक्त संचालित थी। खाद्यान्न आयात घट जाने के कारण, आन्तरिक रूस में सुदूर पूर्व से पश्चिम में खाद्यान्न पहुँचाना पड़ता था। जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी थी, प्रायः मध्य भाग से भेजा जाता था। साइबेरिया की उत्पत्ति यूराल पर्वत को पार कर पश्चिम में ही नहीं किन्तु दक्षिणी भागों में भी भेजना पड़ता था, क्योंकि उन प्रान्तों में कपास की कृषि इसी आशा पर बढ़ाई गई थी, कि सोवियट सरकार उनको खाद्यान्न उनकी आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों से प्रदान करेगी।

जब तक कि आन्तरिक लोहे एवम् इस्पात के उद्योगों की उत्पत्ति-क्षमता न बढ़े, यातायात उत्थान असम्भव था। रेलवे, निर्माण धातुओं का, अति लोलुप उपभोक्ता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग तथा रेलवे निर्माण हेतु लोहे की माँगों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण, औद्योगिक माँगों को प्रधानता दी गई। इसके विपरीत, द्वितीय योजना में सीमित साधनों के होते हुये भी, रेलवे-माँगों की ओर अधिक ध्यान आकृष्टि किया गया। इसके फलस्वरूप प्रथम योजना की अपेक्षा प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत धातुओं को रेलवे निर्माण में ३०० प्रतिशत अधिक परिमाण में लगाने का आयोजन किया गया। नवीन रेलवे निर्माण की अपेक्षा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्राचीन रेलवे की दशा सुधारने पर अधिक ध्यान

दिया गया। सम्पूर्ण रेलवे व्यवस्था में विनियोजित पूँजी का ६ अंश केवल नवीन रेलवे लाइन निर्माण में तथा ६ अंश प्राचीन रेलवे सुधार में व्यय करने का आयोजन किया गया। दोहरी लाइन (double line) बनाना, विद्युत् द्वारा इंजन संचालन करना, अधिक शक्तिशाली इंजनों तथा गाड़ियों का चलना, स्वतः दो डिब्बों की संयुक्तता, स्वतः सिगनल, तथा रेलवे पटरियों पर बालू के स्थान पर कीयले का उपयोग आदि सुधार इस योजना काल में किये गये। लगभग ३००० मील लम्बी लाइनों पर विद्युत् की व्यवस्था करना योजना का एक महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य था। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी इतनी लम्बी लाइन १९३१ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी न थी। नहर निर्माण योजना में भी पूर्ण प्रबन्ध किया गया। नदियों पर उचित बन्दरगाह-सुविधायें तथा नदी-बेड़ों (river fleet) का आयोजन किया गया। मास्को-वाल्गा के मध्य एक नहर निर्माण का आयोजन किया गया। मास्को को लेनिनग्रेड, मिन्स्क, खारकाव, क्रीमिया, काकेशस तथा यूराल आदि स्थानों से मिलाने के दृष्टिकोण से अनेक विस्तृत सड़कें बनवाई गयीं। मास्को को कीवि तथा ओडेसा से भी मिला दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान गुणात्मक सुधार की ओर दिया गया और इसी कारण इसे “गुणात्मक योजना” (“qualitative plan”) की संज्ञा दी गयी। सामूहिक कृषि को, जिसका जन्म प्रथम योजना में हुआ था, प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत और दृढ़ तथा प्रबल बनाया गया।

योजना की सफलता : प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा, प्रस्तुत योजना को कार्यान्वित करने में कम बाधाएँ उत्पन्न हुईं। उसने बड़ी निर्विघ्नता से प्रगति की। १९३०, १९३१ तथा १९३२ ऐसे वर्ष थे, जिनके सम्मुख अनेक विघ्न-बाधाएँ उत्पन्न हुई थीं, अर्थात् द्वितीय योजना में १९३२ एक प्रथम तथा अन्तिम बाधा-प्रसित वर्ष था। अग्रिम वर्षों में लक्ष्यानुसार अनेक दिशाओं में प्रगति हुई, यद्यपि उपभोक्ता सामग्री उद्योगों में योजना सम्पूर्ण सफलता न प्राप्त कर सकी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय खाद्यान्न की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो १९३२ के उपरान्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काफी सुव्यवस्थित हो गयी। सामूहिक कृषि विधान आरोप करने में, जितनी अधिक कठिनाई प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में उत्पन्न हुई थी, द्वितीय योजना के सम्य नाम-मात्र थी और १९३७ तक तो दशा अत्यधिक सुधर गयी थी। जिन लोगों ने इस पद्धति को अपना लिया था, वे अब सामूहिक कृषि की ओर से ध्यान विचलित कर कृषि उर्बरता, गुणात्मक सुधार एवम् कार्यक्षमता की ओर उन्मुख थे।

१९३५ में खाद्यान्न स्थिति काफी अच्छी थी, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि खाद्यान्न से राशनिंग हटा लिया। १९३३-३५ का काल 'राशनिंग तथा खाद्यान्न न्यूनता युग' है। १९३५ के उपरान्त १९३८ तक ऐसा काल था, जिसमें गुणात्मक सुधारों पर अधिक ध्यान गया और उर्वरता में वृद्धि भी की गई। खाद्यान्न न्यूनता काफी कम हो चुकी थी और सम्पूर्ण परिस्थित पहले से अधिक सुव्यवस्थित थी।

इस युग में भारी उद्योगों में प्रगति, हल्के उद्योगों की अपेक्षा, शीघ्र एवम् अधिक हुई, जिसका विशेष कारण यह था कि योजना के कार्यान्वित होते समय बहुत से परिवर्तन योजना की प्रकृति में ऐसे हुये, जिन्होंने भारी उद्योगों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया और जिसका प्रभाव उनके उत्थान पर बड़ा लाभजनक हुआ। जैसा कि प्रथम योजना सम्बन्ध में भी लिखा जा चुका है कि सुरक्षा-व्यय दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार यह प्रवृत्ति द्वितीय योजना में भी प्रचलित रही तथा युद्ध सामग्री उत्पादन हेतु विनियोग परिमाण एवम् प्रतिशत दिन-प्रति-दिन बढ़ता गया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि भारी उद्योगों की आवश्यकता और अधिक बढ़ने पर, हल्के उद्योगों को पुनः क्षति पहुँची। विशेषतः वस्त्र उद्योग पुनः निश्चित उन्नति न कर सका। सूती वस्त्र तथा उन के उत्पादन में केवल ४० तथा २२ प्रतिशत क्रमशः वृद्धि हुई। हल्के उद्योगों में उत्पादन वृद्धि १०० प्रतिशत हुई, यद्यपि योजना लक्ष्यानुसार २५० प्रतिशत होनी चाहिये थी। जूते, चमड़े तथा चीनी के उद्योगों में उत्पादन लक्ष्य से कुछ ही कम था, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :

सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन परिमाण में प्रगति

(१९१३-१९३७)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	विशाल उद्योग
१९१३	१००	१००
१९३३	२८१	३८१
१९३४	३५३	४५७
१९३५	४११	५६३
१९६६	५२६	७३३
१९३७	५८८	८१६

सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन परिमाण में प्रगति

(१९२८-१९३७)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	भारी उद्योग	उपभोक्ता पदार्थ
१९२८	१००	१००	१००
१९३३	२१३	२६०	१६३
१९३४	२५४	२६२	१८३
१९३५	३१२	४२६	२१५
१९३६	४०१	६०१	२७०
१९३७	४४६	६५२	३११

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि भारी उद्योगों में उन्नति हल्के उद्योगों की अपेक्षा अधिक थी। सम्पूर्ण उद्योगों में १९१३ की अपेक्षा १९३३ में उन्नति १८१ प्रतिशत अधिक थी, जो १९३७ में ४८८ प्रतिशत हो गयी। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारी उद्योगों में १९२८ को आधार मानकर वृद्धि १६० प्रतिशत थी, जब कि हल्के उद्योगों में केवल ६३ प्रतिशत। १९३७ में संख्यायें क्रमशः ५५२ तथा २११ थीं। १९३२ की अपेक्षा १९३७ में कितना उत्पादन बढ़ा, निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

उत्पत्ति वृद्धि का सूचकांक

पद	(१९३२ = १००)	सूचकांक
सम्पूर्ण उत्पादन...		२२०
उत्पत्ति साधन का उत्पादन...		२३६
उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन...		१६६
कच्चा लोहा...		२३५
इस्पात...		२६६
पिटी हुई धातु...		२६३
कोयला...		१६६
मिट्टी का तेल...		१३३
शक्ति...		२६७

खनिज-खाद...	३५२
मशीन निर्माण एवम् धातु सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्पादन...	२८३
सीमेन्ट...	१५७
सूती वस्त्र ..	१२८
रेशम...	२७५
घड़ियाँ...	११३
घी तथा दुग्धशाला पदार्थ...	२५८
वनस्पति तेल...	११०
बेंत का सामान...	१४२
दानेदार चीनी...	२६२

भारी उद्योगों में लोहे के उत्पादन में आसाधारण उन्नति हुई । १९३७ में उत्पादन १६३२ की अपेक्षा दुगने से अधिक था । इस्पात का उत्पादन भी निश्चित लक्ष्य से अधिक हुआ । १९३२ में ६९ लाख टन से बढ़ कर, १९३७ में १७७ लाख टन हो गया । पूर्ण विवरण निम्नलिखित सारणी से प्राप्त है :

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन

वर्ष	लोहा (लाख टन)	इस्पात (लाख टन)
१९३३	७१	६९
१९३४	१०४	९७
१९३५	१२५	१२६
१९३६	१४४	१६४
१९३७	१४५	१७७

मिट्टी का तेल ही एक ऐसा पदार्थ था जिसमें अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी और उत्पादन, लक्ष्य से बहुत ही कम रहा । योजना में निर्धारित लक्ष्य ४६८ लाख टन था, जब कि १९३७ में उत्पादन केवल २८५ लाख टन गणना किया गया । इसी प्रकार कोयले का उत्पादन यद्यपि १९३७ में १९३२ की अपेक्षा दुगना हो गया था, फिर भी केवल १२८० लाख टन था, जब कि लक्ष्य १५२० लाख टन निश्चित किया गया था । मिट्टी के तेल तथा कोयले की दशा निम्नलिखित है :

मिट्टी का तेल तथा कोयले का उत्पादन

वर्ष	मिट्टी का तेल	कोयला
१९३३	२१५ (लाख टन)	७३३ (लाख टन)
१९३४	२४२ "	६४२ "
१९३५	२५२ "	१,०६६ "
१९३६	२७४ "	१,२६८ "
१९३७	२८५ "	१,२८० "

इसके प्रतिकूल मशीन निर्माण उद्योग में सफलता अद्वितीय थी। सम्पूर्ण उद्योग में प्रगति ३०० प्रतिशत हुई, जब कि लक्ष्य में केवल २०० प्रतिशत निश्चित किया गया था। १९१३ की अपेक्षा उत्पादन लगभग २० गुना बढ़ गया था। संक्षेप में दशा इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है :

मशीन निर्माण उत्पादन तथा धातु सम्बन्धी उद्योग में प्रगति

१९१३=१

वर्ष	इकाइयाँ	टिप्पणी
१९१३	१०	
१९२८	१८	प्रथम पंचवर्षीय योजना
१९३२	७०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१९३७	२००	

मोटर-गाड़ी उत्पादन निश्चित लक्ष्य के समान ८ गुना बढ़ा। ट्रैक्टर पार्कों की संख्या दुगुने से अधिक हो गई और मोटरकार पार्कों की संख्या ८ गुना हो गई। शक्ति उत्पादन का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है, जिसमें भी उत्पादन दुगुने से अधिक था।

शक्ति तथा खनिज खाद का उत्पादन

वर्ष	हजार लाख किलो०	हजार टन
१९३३	१६४	१,०३४
१९३४	२१०	१,३६८
१९३५	२६३	२,३२३
१९३६	३२८	२,८३६
१९३७	३६२	३,२४०

ट्रैक्टर निर्माण १९३३-१९३५ में तीव्र गति से हुआ। १९३५-१९३८ में उत्पादन बहुत घट गया, क्योंकि सम्पूर्ण उत्पादन शक्ति युद्ध सामग्री उत्पादन में लग गयी थी। सीमेन्ट का उत्पादन काफी बढ़ गया था। १९३७ में अवश्य १९३६ की अपेक्षा कम था, पर १९३८ में पुनः वृद्धि हुई थी।

ट्रैक्टर निर्माण तथा सीमेन्ट उत्पादन

वर्ष	हजार	हजार टन
१९३३	७३.७	२,७०६
१९३४	६४.०	३,५३६
१९३५	११२.६	४,४८८
१९३६	११२.६	५,८७२
१९३७	५१.०	५,४५४

भोजन तथा उपभोग पदार्थों के भी उत्पादन में वृद्धि हुई, पर भारी उद्योगों की अपेक्षा उन्हें प्रधानता न मिली। वस्त्र उद्योग की अवस्था अवश्य पहले से सुधरी थी, पर उन्नति और अधिक होनी चाहिये थी। ऊनी वस्त्र में भी दशा लगभग इसी प्रकार थी। रेशमी वस्त्र में अवश्य अपेक्षाकृत दशा अच्छी थी। चमड़े के जूतों का भी उत्पादन लगभग दुगुना हो गया था, यद्यपि सम्पूर्ण देश के लिये पर्याप्त न था।

सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र तथा जूते का उत्पादन

वर्ष	वस्त्र उद्योग	ऊन उद्योग	रेशम उद्योग	जूता
	लाख मीटर	लाख मीटर	लाख मीटर	लाख जोड़े
१९३३	२७,३२०	८६१	२६०	६०३
१९३४	२७,३३०	७७६	३१४	८५४
१९३५	२६,४००	८४०	३८२	१,०३६
१९३६	३२,७००	१,०१५	५१७	१,४३२
१९३७	३४,४८०	१,०८३	५८६	१,०६६

कागज के उत्पादन में भी उन्नति अधिक न हो पाई थी। मक्खन तथा दुग्धशाला पदार्थों के उत्पादन में भी प्रगति उस प्रकार न थी, जैसी अन्य उद्योगों

में। पाँच वर्षों में लगभग ६० प्रतिशत उन्नति हुई थी। अन्य उपभोक्ता पदार्थों की अपेक्षा चीनी में उत्पत्ति अधिक हुई, यद्यपि स्थिति बड़ी अस्थायी एवम् असंतुलित थी। निम्नलिखित सारणी इन विषयों पर कुछ प्रकाश डालती है :

वर्ष	कागज	मक्खन तथा दुग्ध- शाला पदार्थ	चीनी
	(हजार टन)	(लाख टन)	(हजार टन)
१९३३	५०६	३५	६९५
१९३४	५६६	३८	१,४०४
१९३५	६४१	४२	२,०३२
१९३६	७६३	५१	१,९९८
१९३७	८३२	५०	२,४२१

सामूहिक कृषि (collective farming) की दशा १९३३-१९३७ में बहुत सुधर गयी थी। ९३ प्रतिशत कृषक कुटुम्ब सामूहिक कृषि में सम्मिलित हो चुके थे तथा उनकी ६६.१ प्रतिशत सस्य भूमि सामूहिक कृषि के अन्तर्गत थी। दशा निम्नांकित है :

सामूहिक कृषि की प्रतिशत प्रगति

वर्ष	कृषक कुटुम्ब	सस्य भूमि
१९३३	०.१	—
१९३२	६१.५	५७.७
१९३७	६३.०	६६.१

मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन तथा सामूहिक कृषि में उन्नति द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक बहुत बड़ी सफलता थी। राज्य-कृषि में कमी का प्रमुख कारण सामूहिक कृषि के अन्तर्गत भूमि तथा कुटुम्ब में वृद्धि थी, जो निम्नांकित तालिका प्रदर्शित करती है :

मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन तथा सामूहिक कृषि

	१९३२	१९३७
राज्य-खेतों की संख्या...	४,३३७	३,९९२
मशीन-ट्रैक्टर		
स्टेशन की संख्या...	२,४४६	५,८१८
सामूहिक कृषि की संख्या	२११.७	२४३.५
सामूहिक खेतों के अन्त- र्गत कुदुम्बों की संख्या...	१४.७	१८.१
प्रति खेत पर औसत कुदुम्बों की संख्या...	७१	७६

ग्रामीण व्यवस्था में काफी सुधार दृष्टिगोचर हो रहा था। गुणात्मक सुधार की ओर विशेष ध्यान देने के कारण जीवन-साधन सुधर गये थे। ग्रामों की अवस्था, जितनी पहले शोचनीय थी, राजकीय विज्ञप्तों द्वारा, उतनी ही सुधरी प्रकाशित की गई। किसी लेखक ने अपने विचार प्रकट करते हुये कहा :

“प्राचीन भोपड़ियाँ जिनकी भित्त कोरी मिट्टी से पुती थी, जिनमें न तो चिमनी थी और न शयन करने के लिये, केवल एक पटरे के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान था, और जिनकी खिड़कियाँ बहुत ही संकीर्ण थीं, आदि न्यूनता ग्रामों से विलुप्त हो चुकी थीं। इनका स्थानापन्न नवीन गृहों द्वारा किया गया था, जिनमें प्रकाश का सुव्यवस्थित प्रबन्ध, और शयन आदि का अधिक स्थान उपलब्ध था। गृह का आन्तरिक भाग स्वस्थ एवम् स्वच्छ था। और चीनी-मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, तथा लिनन आदि प्रथम बार अवलोकित किये गये।”

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महत्त्व रूस के आर्थिक विकास में बहुत अधिक है, क्योंकि :

(क) भृत्ति प्रणाली में (wage system) अनेक सुधार किये गये। यह अनुभव किया गया कि सामान्य कार्य के लिये सामान्य पारिश्रमिक अनीति तथा अपव्यय है, जो श्रमिकों की कुशलता, योग्यता एवम् कार्यक्षमता के लिये बाधक है। इस प्रणाली द्वारा अयोग्य एवम् अकर्मण्य श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी कारणवश द्वितीय योजना में प्रगतिशील अनुक्रम भृत्ति-प्रणाली (progressive piece-wage system) ग्रहण की गयी।

(ख) १९३५ में खाद्यान्न पर से राशनिंग प्रतिबन्ध मुक्त कर दिया गया। राशनिंग में इतने दोष आ गये थे, जिनका उन्मूलन नितान्त आवश्यक था। इसका तात्पर्य यह नहीं कि नियन्त्रणों की अवहेलना की गई, बल्कि खाद्यान्न अवस्था सुव्यवस्थित हो जाने के कारण, राशनिंग उन्मूलन आवश्यक समझा गया।

(ग) १९३५ में 'कृषि-आर्टेल' के आदर्श ('Model of Agricultural Artel') का प्रवर्तन किया गया। इनके संचालन हेतु अनेक सिद्धान्त निर्मित किये गये, जिससे सामूहिक कृषि में गुणात्मक सुधार सम्भव हुये।

(घ) इस योजना का महत्त्व गुणात्मक सुधारों के कारण अत्यधिक हो गया। इसका ध्यान परिमाण की अपेक्षा गुण की ओर अधिक गया। श्रमिकों की कार्यक्षमता, उत्पत्ति लागत में ह्रास, जीवन निर्वाह में सुधार आदि ऐसी समस्याएँ थीं जिन पर द्वितीय योजना में अत्यधिक ध्यान दिया गया। इन्हीं कारणों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील एवम् प्रशंसनीय थी जिसके फलीभूत होने पर लोगों की सहानभूति एवम् विश्वास, योजना एवम् सरकार के प्रति, अधिक हो गया। समाजवाद की प्रबलतम अत्यधिक बढ़ गयी थी। अधिकतर उत्पादन राजकीय व्यवसायों द्वारा ही होता था। अधिकतर राष्ट्रीय आय समाजवादी क्षेत्र (socialised sector) द्वारा ही संग्रहित की जाने लगी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त काल तक ही समाजवाद काफी दृढ़ हो चुका था, जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी क्षेत्र का अंश

(प्रतिशत में)

पद	१९२४	१९२८	१९३७
राष्ट्रीय आय	३५.०	४४.०	६६.१
कुल औद्योगिक उत्पादन	७६.३	८२.४	६६.८
कुल कृषि-उत्पादन	१.५	३.३	८.५
फुटकर विक्रय	४७.३	७६.४	१००.०

तृतीय पंचवर्षीय योजना

(१९३८-१९४२)

जिस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, युद्ध का आभास हो चला था, जिसका प्रभाव उसके निर्माण तथा कार्यान्वित होने पर अत्यधिक पड़ा। प्रारम्भ में ही नियोजन आयोग ने यह उल्लेख किया कि सोवियट संघ, ग्रेट ब्रिटेन अथवा अमेरिका की तुलना में अब भी एक पिछड़ा हुआ देश है। प्रस्तुत योजना का यही मुख्य लक्ष्य था कि प्रगतिशील पूँजीवाद देशों को भारी पदार्थों के उत्पादन में पीछे कर दिया जाये। पूँजी का विनियोग, युद्ध सामग्री उत्पादन आदि में किस अनुपात से लगाया गया था, यह बात पूर्णतः अज्ञात है। परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि १९३८ के पूर्व सुरक्षा-व्यय अथवा युद्ध-सामग्री व्यय अधिक न था। १९३८ की अपेक्षा १९४० में सुरक्षा-व्यय पर बजट में दुगुना आयोजन किया गया था और राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक अंश युद्ध-सामग्री उत्पादन में विनियोजित था। भारी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। भारी उद्योगों में भी युद्ध सामग्री, जैसे सैनिकों का सामान, गोला-बारूद तथा शस्त्र आदि, को प्रधानता दी गई। जितनी पूँजी भारी उद्योगों में विनियोग की गई, उसका केवल १५ प्रतिशत उपभोक्ता पदार्थ उत्पादन में लगाया गया और शेष ८५ प्रतिशत पूँजी भारी उद्योग में सज्जित थी। पुनः इस बार भारी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, उपभोक्ता पदार्थ के उत्पादन से अधिक थी। भारी उद्योगों में उत्पादन १०३ प्रतिशत तथा हल्के उद्योगों में ६९ प्रतिशत बढ़ाने का आयोजन किया गया। वस्त्र, चमड़ा तथा चीनी के उद्योगों पर सरकार का ध्यान पुनः अधिक आकृष्ट न हो सका, क्योंकि युद्ध की तत्परता समाजवादी देश रूस की एक गंभीर समस्या थी।

सूती-ऊनी वस्त्र का उत्पादन ५०-६० प्रतिशत, चमड़े का ४३ प्रतिशत तथा चीनी का ४४ प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया। मशीन यन्त्रों का सामान सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के १९२६ के उत्पादन स्तर से अधिक निर्मित किया जाये, योजना का एक सर्वप्रमुख लक्ष्य था। विशेष ध्यान यातायात, लोहा, इस्पात, रसायनिक पदार्थ तथा अन्य धातुओं के उत्पादन की ओर था। मालोटोव का प्रधान नारा था : "तृतीय पंचवर्षीय योजना को 'रसायनिक योजना' बनाया जाये।" मशीन-निर्माण, अलमोनियम, जस्ता (zinc), शीशा (lead) तथा निकल उत्पादन पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। राजनैतिक एवम सैनिक उद्देश्यों को दृष्टिकोण में रखते हुये यह निर्णय किया गया कि भविष्य में नवीन उद्योग-धन्धे पूर्वी क्षेत्रों में ही स्थापित किये जायें।

प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन १९३७ से १९४२ तक ६,५५,००० लाख रुबल से १८,४०,००० लाख रुबल का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कृषि उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ना चाहिये था। रेलवे भाड़ा व्यापार ३५,५०,००० लाख टन किलोमीटर से ५१,००,००० लाख किलोमीटर होने का आयोजन किया गया। पूँजी निर्माण १८,२०,००० लाख रुबल बढ़ने का लक्ष्य किया, जब कि द्वितीय योजना काल में वह केवल ११,४७,००० लाख रुबल हो सकी थी।

इसके अन्तर्गत पूर्वी प्रदेशों में धातु निकालने तथा शोधन करने के विशाल उद्योग, यंत्रकला उद्योग तथा विद्युत् शक्ति केन्द्र के निर्माण का पूर्ण प्रबन्ध किया गया। वाल्गा तथा यूराल के मध्य मिट्टी का तेल निकालने का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र 'द्वितीय बाकू' के नाम से विख्यात है।

योजना की सफलता : प्रथम तीन वर्षों में लगभग सम्पूर्ण वार्षिक लक्ष्य पूर्ण हुए। औद्योगिक उत्पादन १३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ा। प्रथम तीन वर्षों में उत्पत्ति साधनों की उन्नति ५० प्रतिशत हुई और मशीन-निर्माण उद्योग की प्रगति ७५ प्रतिशत गणना की गई। पूर्वी भागों में उद्योगों का अधिक संस्थापन हुआ तथा एक विशाल अन्नोत्पादक प्रदेश का भी जन्म हुआ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रथम ३½ वर्षों में १३,००,००० लाख रुबल का विनियोग किया गया, जिसका लगभग ३ अंश केवल पूर्वी प्रदेशों में ही विनियोजित किया गया। स्टैलिन ने अपने वक्तव्य में कहा : "उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति, जिसने रूस को अत्यन्त पिछड़ी हुई दशा से एक उन्नतिशाली राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया है, कोई साधारण सामान्य बात नहीं है। यह एक ऐसी छलांग (leap) है जिसने मातृ-भूमि को देखते ही देखते एक पिछड़े हुये देश से एक प्रगतिशील देश में परिणित

कर दिया है तथा एक कृषक देश को एक आदर्शवादी औद्योगिक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया है।^१

१९३८-१९४० के मध्य सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का परिमाण निम्नांकित है :

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	विशाल उद्योग
१९१३	१००	१००
१९३८	६५७	६११
१९३९	७६३	१,०५१
१९४०	८५२	१,१७२

उत्पत्ति-साधन तथा उपभोक्ता पदार्थ का उत्पादन १९३८-१९४० के मध्य अधोलिखित है। इस उत्पादन परिमाण की तुलना १९२८ से की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वर्षों से भी उन्नति की प्रवृत्ति भारी उद्योगों में अधिक थी।

औद्योगिक उत्पादन में सापेक्ष प्रगति

(१९२८ = १००)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	उत्पादन सामग्री उद्योग	उपभोक्ता उद्योग
१९२८	१००	१००	१००
१९३८	४६८	७३२	३४५
१९३९	५५८	८७१	३८७
१९४०	६४६	१,०००	४१५

निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रथम तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में प्रगति १९३७ की अपेक्षा विभिन्न दिशाओं में कैसी थी, प्रदर्शित किया गया है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि लोहा, इस्पात, रोल्ड धातु, कोयला, मशीन-निर्माण

१ A. Kursky : The Planning of the National Economy of the U. S. S. R., p. 80 : "This unprecedented growth of production cannot be regarded as the simple and ordinary development of a country from backwardness to progress. It was a leap by which our Motherland became transformed from a backward country into a progressive country, from an agrarian into an industrial country."

आदि उद्योग प्रगतिशील थे। इसके विपरीत चीनी तथा घड़ी उद्योगों में अवनति हुई। वनस्पति तेल तथा वस्त्र का उत्पादन बढ़ा तो अवश्य, पर उन्नति अधिक प्रशंसनीय न थी।

विभिन्न सामग्रियों में औद्योगिक उत्पादन की सापेक्ष प्रगति^१

पद	तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक तीन वर्ष (युद्ध के पूर्व) १९३७=१०० (१९३७-१९४०)
सम्पूर्ण उद्योगों का उत्पादन ...	१४५
उत्पत्ति साधनों का उत्पादन...	१५३
उपभोग सामग्री का उत्पादन...	१३३
लोहा खनिज	१०३
इस्पात	१०३
रोल्ड धातु	१०१
कोयला	१३०
मिट्टी का तेल	१०६
शक्ति	१३३
खनिज खाद	६३
मशीन-निर्माण तथा धातु-सामग्री	१७६
सीमेन्ट	१०४
सूती वस्त्र	११५
रेशमी वस्त्र	१३०
घड़ियाँ	६६
मक्खन तथा अन्य दुग्धशाला पदार्थ	१२६
वनस्पति तेल	१४८
दानेदार चीनी	८६

भारी उद्योगों के अन्तर्गत लोहा उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि न हुई थी। १९३८ में उत्पादन १४७ लाख टन था, जो १९४० में केवल १४६ लाख टन हो पाया। इस्पात की भी दशा कोई विशेष अच्छी न थी।

^१ National Economy of the U.S.S.R. : Statistical Returns, p. 45

लोहा तथा इस्पात का उत्पादन

वर्ष	लोहा	इस्पात
	(लाख टन)	(लाख टन)
१९३८	१४७	१८१
१९३९	१४५	१७६
१९४०	१४९	१८३

लोहा तथा इस्पात में १९३९ में उत्पादन १९३८ की अपेक्षा कम हो गया था और १९४० में १९३८ की अपेक्षा वृद्धि नाम-मात्र की थी। मिट्टी के तेल का उत्पादन इन वर्षों में घट गया था। कोयले में भी कोई विशेष वृद्धि न हो पाई थी।

कोयला तथा मिट्टी के तेल का उत्पादन

वर्ष	मिट्टी का तेल	कोयला
	(लाख टन)	(लाख टन)
१९३८	३२२	१३३३
१९३९	३०३	१,४६२
१९४०	३११	१,६५६

अत्यधिक सफलता शक्ति-निर्माण को प्राप्त हुई, जिसकी दशा निम्न-लिखित सारणी में प्रस्तुत है। इससे भी अधिक उन्नति मशीन-निर्माण तथा धातु-सामग्री में हुई।

शक्ति निर्माण

वर्ष	हजार लाख कि० वा०
१९३८	३६४
१९३९	४३२
१९४०	४८३

निम्नलिखित सारणी^१ से औद्योगिक प्रगति की एक झलक १९४० तक प्रदर्शित की गई है :

^१ A. Kursky : The Planning of the National Economy of the U.S.S.R., p. 80.

औद्योगिक प्रगति

पद	इकाई	१९१३	१९४०	१९१३ को आधार मानकर १९४० की दशा
राष्ट्रीय आय	हजार लाख			
	रुबल	२१०	१,२८३	६.००
सम्पूर्ण उद्योगों का उत्पादन...	"	१६२	१,३८५	८.५०
उत्पत्ति साधन का उत्पादन...	"	५४	८४८	१५.५०
उपभोग पदार्थ का उत्पादन...	"	१०८	४३७	४.००
कच्चा लोहा	लाख टन	४२	१५०	३.६०
इस्पात	"	४२	१८३	४.४०
कोयला	"	२६०	१,६६०	६.३०
मिट्टी का तेल	"	६०	३१०	३.४०
विद्युत् शक्ति	हजार लाख किलोवाट	१६	४८३	२६.००
मशीन निर्माण तथा धातु-सामग्री...	हजार लाख रुबल	१५	५०२	३३.००
विक्रय-अतिरिक्त खाद्यान्न	लाख टन	२१६	३८३	१.८०
कपास	"	७.४	२७	३.६०

इस प्रकार हम देखते हैं कि कपास तथा खाद्यान्न के अतिरिक्त औद्योगिक उन्नति अन्य क्षेत्रों में तीव्र थी। उत्पत्ति-साधन सामग्री उत्पादन १९३३ की अपेक्षा लगभग १५-१६ गुना अधिक था। इसी प्रकार मशीन-निर्माण तथा धातु-सामग्री लगभग ३३ गुना और विद्युत् शक्ति की उत्पत्ति लगभग २६ गुना अधिक थी। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य उद्योगों में भी उत्पादन दुगुना, तिगुना, चौगुना तथा कहीं-कहीं पाँचगुना अथवा छः गुना पहुँच गया था। समाजवादी रूस भारी उद्योगों में इस प्रकार दिन-प्रति-दिन शक्तिशाली होता जा रहा था।

द्वितीय महायुद्ध कालीन नियोजन

यह उपर्युक्त कहा जा चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष शान्तिमय थे। औसत राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही थी तथा योजना लक्ष्यानुसार प्रगति कर रही थी। इसी मध्य में २२ जून, १९४१ को तानाशाही हिटलर ने बिना पूर्व घोषणा किये सोवियट रूस पर आक्रमण कर, उसकी प्रगति पर एक असहनीय कुठाराघात किया। युद्ध ने सारी योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया और सम्पूर्ण देश अपनी पूर्ण शक्ति सहित तानाशाही जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-कुण्ड में कूद पड़ा। यह एक असाधारण युद्ध था। रूसियों का यह अनुमान था कि हिटलर का युद्ध केवल सोवियट संघ से नहीं है, बल्कि उसकी समाजवादी प्रथा से है।

इस युद्ध ने सोवियट अर्थव्यवस्था में महान् परिवर्तन किये। सम्पूर्ण व्यवस्था तथा प्रशासन में क्रान्तिकारी उलट-पलट होने लगा। सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति युद्ध कालीन आवश्यक कार्यों में संलग्न की गई। सोवियट संघ का यह जीवन-मरण प्रश्न था। अपनी राजनैतिक एवम् आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उसके समस्त प्रत्येक बलिदान और त्याग इस समय नाममात्र थे। स्टैलिन ने अपने वक्तव्य में कहा :

“युद्ध ने हम लोगों को युद्ध-आधार पर कार्य करने के लिये विवश कर दिया है। इसने सर्वसम्पन्न सोवियट रूस को युद्ध पृष्ठभूमि में परिणित कर, इसके अग्रभाग को लाल तथा नैविक सेना से सुसज्जित किया है।

“शान्तिमय निर्माण युग का अब अंत हो रहा है, तथा जर्मन आक्रमण-कारियों से मुक्त पाने हेतु क्रान्तिकारी युग का प्रवेश हुआ है।”^१

१, J. V. Stalin : On the Great Patriotic War of the Soviet Union, 1946, p. 19.

द्वितीय महायुद्ध काल तक सोवियट संघ जर्मनी के सम्मुख एक दुर्बल देश था। इसकी अपेक्षा सम्पूर्ण जर्मनी अति प्रबल शक्तिशाली राष्ट्र था। भारी उद्योगों में उसकी अवस्था सोवियट संघ से अधिक बढ़-चढ़ कर थी। निःसन्देह सोवियट राष्ट्र ने गत १२-१५ वर्षों में भारी उद्योगों को प्रधानता दी थी, पर यह कहना अनुचित न होगा कि सोवियट रूस का योजनात्मक आर्थिक विकास १९२८ से ही प्रारम्भ हुआ था, जब कि वह एक अत्यन्त निर्धन एवम् निर्बल देश था। कोयला, लोहा तथा इस्पात में जर्मनी, रूस की अपेक्षा, अधिक सम्पन्न था। सोवियट रूस को ऐसी आशा प्रतीत हो रही थी कि यह भयंकर युद्ध पश्चिमी भाग में होगा और वह पूर्वी प्रदेशों में विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ायेगा। सोवियट संघ के सम्मुख केवल यही एक आकस्मिक युद्ध कालीन साधन सम्भव था, जो लाभप्रद सिद्ध हो सकता था। इस समय जर्मनी, कोयला १८६० लाख टन, लोहा १८० लाख टन, तथा इस्पात २३० लाख टन उत्पादन कर रहा था, जब कि सोवियट रूस में उत्पादन क्रमशः १,३३० लाख टन, १४६ लाख टन, तथा १८० लाख टन था। इस प्रकार जर्मनी की स्थिति सोवियट रूस की अपेक्षा उत्तम थी। यही नहीं अगर जर्मनी के मैत्रिक राज्यों को उसके साथ सम्मिलित कर उसकी अवस्था का अनुमान किया जावे, तो यह प्रतीत होगा कि जर्मन राष्ट्र के सम्पूर्ण साधन सोवियट संघ की अपेक्षा लगभग दूने थे, जैसे कोयले का उत्पादन २,८०० लाख टन से अधिक, लोहा ३०० लाख टन से अधिक तथा इस्पात ४०० लाख टन से अधिक था।

इसके विपरीत कुछ विशेष पदार्थों में सोवियट रूस की अवस्था अच्छी थी। इसके पास खनिज लोहा (iron ore) काफी मात्रा में था। १९३८ में विश्व का $\frac{1}{2}$ भाग केवल सोवियट संघ में पाया जाता था तथा तेल का उत्पादन जर्मनी की अपेक्षा चार गुना अधिक था। ताँबे का उत्पादन भी जर्मनी से अधिक था। परन्तु अगर प्रति इकाई राष्ट्रीय आय आँकी जावे तो ज्ञात होगा कि जर्मनी की अवस्था सोवियट संघ की अपेक्षा उच्च थी। सोवियट संघ में प्रति इकाई राष्ट्रीय आय जर्मनी की तुलना में आधी थी। इससे प्रतीत होता है कि सोवियट संघ के सम्मुख युद्ध एक महान समस्या थी, क्योंकि प्रबल जर्मन राष्ट्र को पराजित करना कोई सरल कार्य न था।

युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में सोवियट संघ को बहुत अधिक क्षति पहुँची। अचानक आक्रमण के कारण जर्मन सैनिकों को पूर्व के अनेक औद्योगिक भागों पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई थी। यूक्रेन, क्रीमिया, डान-डेज़ डान तथा उत्तरी काकेसस प्रदेश शत्रुओं के अधिकार में हो गये थे, जिससे

रूस की दशा और अधिक सोचनीय हो गयी थी। ऐसी गणना की गई है कि सोवियट संघ के आधिपत्य से १६४१-४२ में कोयले के क्षेत्र का आधे से अधिक, लोहे तथा इस्पात का ६० प्रतिशत तथा यन्त्रकला का २०-२५ प्रतिशत क्षेत्र निकल जाने के कारण, जर्मन राष्ट्र अत्यधिक प्रबल बन गया। पश्चिमी भाग के मुख्य विशाल खेत भी जर्मनी के आधिपत्य में आ गये थे।

युद्ध कालीन एवम् शान्ति कालीन नियोजनों में महान विभिन्नता थी, जैसे:-

(क) सोवियट सरकार के पास जो कुछ भी खाने-पहनने की सामग्री उपलब्ध थी, उसमें सैनिकों को प्रथमता दी गई। यह कार्य संगठन अधिक से अधिक केन्द्रीयकरण द्वारा किया गया था।

(ख) केवल वार्षिक योजना ही नहीं, बल्कि अनेक मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक योजनायें भी निर्मित की गयीं, जिनको कार्यान्वित करने में युद्ध कालीन परिस्थितियों पर यथेष्ट ध्यान दिया गया।

(ग) पूर्वी प्रान्तों के नवीन उद्योगों के निर्माण में सोवियट सरकार संलग्न हो गई तथा पश्चिमी प्रान्तों से बहुत से व्यवसाय पूर्वी प्रान्तों में स्थान्तरित कर दिये गये। सोवियट पृष्ठ भूमि को यथेष्ट संपन्न तथा प्रबल बनाने के लिये सोवियट सरकार ने पूर्ण चेष्टा की, जिसके आधार पर योजना संचालित की गयी। पूर्वी प्रान्तों में उद्योग-धन्धे इतनी शीघ्रतापूर्वक स्थापित हो कर उत्पत्ति दे रहे थे कि जिसे देखकर अन्य प्रगतिशील देशों ने भी सोवियट रूस की बड़ी प्रशंसा की। पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि सोवियट रूस में युद्ध के पूर्व से ही इस बात का प्रयास किया गया था कि नवीन उद्योग-धन्धे भविष्य में पूर्वी क्षेत्रों में ही स्थापित किये जावें। तृतीय योजना को निर्मित एवम् कार्यान्वित करने में इस लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। जैसे-जैसे जर्मन फौजें पश्चिम की ओर से सोवियट रूस में प्रवेश कर रही थी, वैसे-वैसे उद्योग-धन्धे पश्चिम भाग त्याग कर यूराल तथा साइबेरिया में अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। अनेक स्थानों पर परिस्थितिबश, शीघ्रतापूर्वक, काष्ठ-गृह निर्माण कर दिये गये थे, एवम् युद्ध-सामग्री उत्पादन प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार युद्ध सम्बन्धी अस्थायी सम्पूर्ण कार्य सुचारु रूप से होने लगा था। यह कार्य इतनी शीघ्रता एवम् उदंडता से किये गये कि यथेष्ट रूप से उत्पादन साधनों को अनेक सुविधायें उपलब्ध करना असम्भव था। प्रारम्भिक काल में इन प्रदेशों में जीवन निर्वाह कष्टमय था, क्योंकि आवश्यक पदार्थों का अभाव, अव्यवस्थित निवास स्थान दूषित जलवायु तथा आसमयिक परिवर्तनों के उपस्थित होने के कारण छिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धे, आदि ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर असहनीय प्रभाव डाला।

कुछ भागों में निवास करने का उचित-अनुचित स्थान ही न था। निर्माण के लिये सामग्री की न्यूनता थी तथा आवश्यक यातायात सुविधायें भी शून्य थीं जिसके कारण अन्य स्थानों से समुचित प्रबन्ध असम्भव था। स्थानीय अशिक्षितों को नये ढंग से शिक्षा दी गयी तथा नये साधनों से युद्ध सामग्री का उत्पादन करना सिखलाया गया। वालगा क्षेत्र में अधिकतर हल्के उद्योगों को स्थापित किया गया। तोप के गोले, बम, बारूद तथा रसायनिक पदार्थयुक्त अनेक सामग्रियाँ मास्को के निकट निर्माण की गयीं। अनेक प्रकार की मशीनों के निर्माण करने का कार्य अधिक से अधिक पूर्वी भागों में उत्पन्न करने का आयोजन किया गया तथा १९४२-४३ में कज़नेट्सक (kuznetsk) की घाटी में कोयला तथा युद्ध सामग्री निर्माण का विशाल केन्द्र समझा जाने लगा। पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर जाने की प्रवृत्ति १९४१-४२ में तीव्र थी। इसका अनुमान कीव तथा खारकोव की आधी से अधिक जनसंख्या पूर्वी प्रान्तों में बसने तथा लेनिनग्रेड के अनेक विशाल उद्योगों में विनिर्मित पूँजी का ७० प्रतिशत से अधिक अंश हटा लिये जाने से लगता है। सोवियट संघ का यह एक प्रशंसनीय कार्य था, कि पूर्वी भागों में निष्क्रमण (evacuation) गति तीव्र होते हुये भी, कार्यक्षमता में कोई विरुद्ध प्रभाव न पड़ा। अनेक संकटों से ग्रसित होते हुये भी, सोवियट संघ ने इस कार्य को बड़ी चातुर्यता एवम् कुशलता से किया। फलस्वरूप युद्ध काल में उत्पादन प्रगति बड़ी प्रभावशाली थी।

१९४३ तक कुछ पदार्थों में सोवियट संघ ने जर्मनी की अपेक्षा उत्पादन अधिक कर लिया जैसे टैंक तथा वायुयान का निर्माण विद्युत् शक्ति स्टेशनों की स्थापना यूराल, साइबेरिया, मध्य एशिया तथा वालगा प्रान्तों में दुगुने से अधिक थी। पूर्वी प्रान्त में स्थापित इस्पात की एक नवीन निर्माणशाला विश्व की तुलना में सर्वोच्च थी। इसके अतिरिक्त दस और नवीन भट्टियाँ स्थापित की गयी थीं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता पचास लाख टन से अधिक थी। १९४५ तक इस्पात का उत्पादन केवल पूर्वी प्रान्तों में ५० प्रतिशत से अधिक था। टैंकटर के निर्माण के लिये पूर्वी प्रान्तों में कई नयी विशाल कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थी। १९४२ में ही सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि “युद्धकालीन अनेक संकटों के होते हुए भी, हमने युद्ध-सामग्री अस्त्र-शस्त्र प्रारम्भिक वर्ष में ही १९४० की अपेक्षा अधिक पारमाण्य में निर्माण कर लिया है।”^१

सम्पूर्ण उत्पादन “केवल युद्ध अग्रभाग हेतु” (“all for the fronts”) उपलब्ध किया जाये, एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया गया। इस युद्ध में सोवि-

यट रूस विजेता हुआ तथा इसका सम्पूर्ण श्रेय वहाँ के निवासियों की बलिदान शक्ति को है। रूस की आर्थिक व्यवस्था जो गत १५ वर्षों में योजनात्मक सुसज्जित की गयी थी, इससे प्राप्त अनुभव ने रूसियों में सहनशीलता तथा बलिदान-प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी थी। अनेक संकटों का धैर्य एवम् अनुशासन सहित सामना किया गया था। निःसन्देह रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था, जर्मनी की 'नाज़ी' अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक कुशल तथा कार्यक्षम थी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के अतिरिक्त, १९१७ की अक्टूबर क्रान्ति ने भी रूसियों में राष्ट्रीय कल्याण हेतु, बलिदान एवम् सहनशीलता आदि प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कर दी थीं।^१ इसका प्रभाव प्रस्तुत "स्वदेशाभिमान युद्ध" ("Patriotic War") पर लाभप्रद सिद्ध हुआ। योजना द्वारा पूर्व निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जावे, इसका अनुभव सोवियट सरकार की गत तीन योजनाओं के अन्तर्गत भली प्रकार प्राप्त हो चुका था। स्टैलिनग्रेड पर जर्मन फौज को रोक कर, उस पर शक्तिशाली आक्रमण करना तथा युद्ध विजेता बनना, इस वैज्ञानिक युग में, एक अवर्णनीय चमत्कार है। इसी कारणवश रूसियों की राष्ट्रीयता, साहस, शक्ति एवम् देशभक्ति विश्व के इतिहास में एक अमूल्य एवम् अद्वितीय स्थान रखती है।

यों तो उपभोग पदार्थों की न्यूनता पहिले से विद्यमान थी, युद्ध के कारण इसने और भयंकर रूप धारण कर लिया। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि युद्ध के पूर्व तो भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी, किन्तु युद्ध काल में यह रीति संभावाद के सहश तीव्र हो गयी। यही नहीं जर्मन फौज भी इनके उत्पादन साधन तथा उद्योगों को विकट रूप से विध्वंस करते हुये पीछे हटते गये थे। गोले तथा

१ N. A. Voznesensky : Report made at the First Session of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. on March 1946 :

"One distinguishing feature of the Soviet system is its ability in a crisis to mobilise immense reserves and by the heroic labour of its people to supply the needs of war by domestic production. The working of the people of the Soviet rear, primarily the working class of the Soviet Union, as well as the Soviet peasantry and intelligentsia, our devoted women and young people, performed heroic deeds and gained the economic victory over the enemy. The guiding force of the Soviet people, of the State System was the Communist Party, the Bolsheviks, the party of Lenin and Stalin under whose leadership the whole multi-national Soviet Union was consolidated into a single armed camp."

बारूद द्वारा रेलवे पटरियाँ विनिष्ट की गयीं, नगरों को फूक दिया गया, तथा ग्रामों में हजारों मील तक सम्पूर्ण व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी गयी। खानों की सुरंगें, यातायात साधन, लोहे के कारखाने, इस्पात की भट्टियाँ तथा विद्युत् शक्ति के विशाल बाँध विध्वंस कर दिये गये। जिन मार्गों से जर्मन फौजें भागी थीं वे स्थान हजारों मील तक श्मशान भूमि हो गये, तथा चर-अचर, एवम् कृषि-उद्योग आदि सम्पूर्णतः अदृश्य हो गये। इस प्रकार रूस में २००० से अधिक नगर, ६५-७० हजार ग्राम तथा असंख्य कारखाने, जिनमें प्रायः ४० लाख से अधिक श्रमिक कार्य करते थे, युद्ध द्वारा किसी न किसी प्रकार त्रसित किये गये तथा राजकीय गणना के अनुसार लगभग २५० लाख मनुष्य गृहहीन हो गये।

इस वृहत् एवम् विशाल विनाश का पुनर्निर्माण कोई सरल कार्य न था। दक्षिणी तथा पश्चिमी रूस के प्रान्तों में सामान्य आर्थिक जीवन की पुनः स्थापना करने से पूर्व अनेक विशाल कार्य करने को अवशेष थे। सोवियट सैनिकों ने इस पुनर्निर्माण तथा पुनर्निवेशन के विशाल कार्य में अनेक प्रभावशाली कार्य किये जिनका प्रारम्भ १९४३ से ही हो गया था। शान्ति कालीन उद्योगों का पुनः संचालन बड़ा उत्साह तथा वेगता से प्रारम्भ हुआ। कृषि-व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिये सोवियट सरकार ने इस और विशेष ध्यान दिया। यातायात साधनों के पुनः उत्थान हेतु एक नवीन योजना निर्माण की गई तथा शीघ्र ही उसे कार्यान्वित की जाने का आयोजन किया गया। ट्रान्स-वालगा प्रान्त में नयी भूमि पर कृषि की गयी तथा साइबेरिया के अनेक क्षेत्रों में भी, जहाँ-जहाँ सम्भव हो सका, कृषि की सुव्यवस्था की गई। पश्चिमी भाग में जो विनाश हुआ था, उस क्षति को पूर्ण करने के दृष्टिकोण से पूर्वी भाग में निर्माण कार्य युद्ध काल से ही संचालित था; युद्ध उपरान्त इसी कार्य को और अधिक प्रोत्साहित किया गया। कुछ हल्के उद्योग थे जिनमें केवल सैनिकों के लिये उत्पादन हो रहा था, अचानक युद्ध उपरान्त नागरिकों के लिये उन्हें सुसंगठित करना पड़ा। सूती वस्त्र, जूता तथा मोजा-बनियाइन के उत्पादन को सरकार ने प्रधानता दी। युद्धकालीन उद्योगों को शान्तिकालीन उद्योगों में परिणित करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई। वस्त्र तथा चमड़े के अनेक युद्ध-व्यस्त उद्योग भी अब नागरिक हेतु उत्पादन में संचालित किये गये। शीघ्र ही यूक्रेन का तीन चौथाई क्षेत्र पुनः कृषि योग्य बनाया गया। युद्ध के उपरान्त सोवियट सरकार ने यह पुनः निश्चय किया कि एक पंचवर्षीय योजना पुनर्निर्माण तथा पुनर्निवेशन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाये।

सोवियट अर्थव्यवस्था, द्वितीय महायुद्ध काल में, प्रथम युद्ध की अपेक्षा

अधिक सुचारु थी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि जो योजनात्मक विकास हुआ था, साधारणतः अन्य किसी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सम्भव न था। अगर हम सम्पूर्ण उत्पादन के सम्बन्ध में प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध की तुलना करें तो हमें अनुभव होगा कि द्वितीय युद्ध काल में सोवियट संघ की व्यवस्था अधिक शक्तिशाली एवम् उच्चतर थी। समाजवाद व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पत्ति साधन तथा इसका नवीन आधार पर, नवीन दिशा की ओर, संचालन करने की पद्धतियाँ अनेक थीं, जिनको सोवियट सरकार ने कुशलता पूर्वक द्वितीय महायुद्ध के समय कार्यान्वित किया था। १९१५-१७ के समय रूस के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य लगभग ३,३०,००० लाख रूबल था तथा १९४२-४४ में (उसी मूल्य स्तर पर) उत्पादन ३६,१०,००० लाख रूबल हो जाने के कारण ११ गुना अधिक बढ़ गया। उसी प्रकार बाजार अतिरेक (marketed surplus) ढाई गुना अधिक और रेल का औसत वार्षिक भाड़ा ३.४ गुना अधिक हो गया। यही नहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में टंकी तथा वायुयान का सम्भवतः कोई निर्माण हुआ हो, जब कि इसके प्रतिकूल १९४०-४० के मध्य लगभग ३०,००० टंकी तथा ४०,००० वायुयान प्रतिवर्ष की दर से युद्धकाल में निर्माण किये गये थे। प्रथम युद्ध के अन्तिम तीन वर्षों में रूस ने लगभग ३,६०० तोपें वार्षिक उत्पादन किया था, जिनका उत्पादन द्वितीय महायुद्ध काल में ३० गुना अधिक हो गया। इसी प्रकार प्रथम युद्ध के अन्तिम तीन वर्षों में केवल ८,६०० मशीन-तोपें तथा हल्की मोटरें प्रति वर्ष की दर से निर्माण की गयी थीं, जब कि द्वितीय महायुद्ध काल में इनकी संख्या ४,५०,००० तक पहुँच गई थी, जो ५० गुना अधिक थी। राइफल का उत्पादन प्रथम महायुद्ध काल में, १०,५०,००० प्रति वर्ष था, जब कि द्वितीय महायुद्ध के समय इनकी संख्या ५,०००,००० (लगभग ५ गुना अधिक) पहुँच गयी थी। इस तरह युद्ध की अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी द्वितीय महायुद्ध के समय कहीं अधिक था और समाजवाद रूस की योजनात्मक प्रगति ने सोवियट अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया था।

बारहवाँ अध्याय चौथी पंचवर्षीय योजना

(१९४६-१९५०)

चौथी पंचवर्षीय योजना का आर्थिक एवम् राजनैतिक कार्य युद्ध में विध्वंस क्षेत्रों का पुनर्निवेशन करना था। उद्योग तथा कृषि उत्पादन में प्रगति ऐसी होनी चाहिये थी कि शीघ्राशीघ्र उत्पादन १९१३ के स्तर तक पहुँच जावे।^१ योजना का निम्नलिखित प्रधान उद्देश्य था :

- (क) युद्ध-विध्वंस क्षेत्रों तथा प्रान्तों का पुनर्निवेशन किया जाये।
- (ख) उद्योग तथा कृषि उत्पादन स्तर १९१३ के तुल्य शीघ्राशीघ्र पहुँच कर,
- (ग) १९१३ के स्तर को अतिक्रमण कर सके।

उपर्युक्त निश्चित उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्यों का आयोजन किया गया :

(क) सर्वप्रथम भारी उद्योगों को प्रधानता दी गयी। ऐसा विचार किया गया कि रेलवे यातायात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। सोवियट संघ का विश्वास था कि जब तक कि भारी उद्योगों का पुनः निर्माण नहीं किया जावेगा, १९३९-४० के पूर्व जिस उच्च अवस्था पर सोवियट राष्ट्र पहुँचा था, वह स्थिति पुनः प्राप्त न हो सकेगी।

(ख) कृषि तथा उपभोग पदार्थों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह आन्दोलन चलाया गया कि अधिकाधिक प्रयास इस बात का होना चाहिये कि उपभोग पदार्थ भारी मात्रा में सोवियट नागरिकों को प्राप्त हो सकें। युद्ध-पूर्व जो प्रगति थी, उतना तो प्रस्तुत युग में पुनः प्राप्त होना आवश्यक था ही। वस्तुतः खाद्यान्न

^१ Law of the Five Year Plan : For the Rehabilitation and Development of the National Economy of the U. S. S. R. 1946-50, Published by 'Soviet New's, London, 1946.

इतना उपलब्ध होना चाहिये था कि राशनिंग पद्धति रहित, राज्य-व्यापार स्थापित हो सके। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वस्तु-मूल्य में हास तथा जीवन में सुधार होना सोवियट सामान्य जीवन स्तर के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

(ग) तृतीय आयोजन कार्य यन्त्रकला प्रगति से सम्बन्धित था। श्रम-उत्पत्ति में वृद्धि करने का आयोजन किया गया था। यह आवश्यक था कि योजना में विज्ञान सम्बन्धी उन्नति का यथेष्ट प्रबन्ध किया जावे, क्योंकि ऐसी विचारधारा थी कि भविष्य में सोवियट राष्ट्र का सम्पूर्ण उत्थान वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर था। राष्ट्रीय नियोजन आयोग के मंत्री वोझनेसेन्सकी (Voznesensky) ने १९४३ में प्रकाशित किया : “यदि रूसी वैज्ञानिकों को यथेष्ट राजकीय सहयोग प्रदान किया जावे, तो शीघ्र ही सोवियट विज्ञान अन्य देशों की अपेक्षा अधिक प्रवैगिक तथा प्रगतिशील हो जावेगा।”^१

(घ) प्रस्तुत योजना का महत्त्वपूर्ण कार्य समाजवाद पूँजी संचयन में अत्यधिक वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य था कि पाँच वर्षों में सरकार द्वारा २४,००,००० लाख रूबल का संचय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उत्थान हेतु किया जावेगा तथा २३,४०,००० लाख रूबल का निर्माण नवीन उद्योगों के रूप में होगा। फलस्वरूप सम्पूर्ण पूँजी निर्माण का योग १,१०,३०,००० लाख रूबल हो जायेगा, जो युद्ध-पूर्व स्तर से आठ प्रतिशत अधिक था। पूँजी निर्माण की प्रगति में प्रतिवर्ष १२ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन किया गया।

१ Report of the Five Year Plan of the U. S. S. R. (1946-50), Soviet News, London, 1946, p. 9.

नियोजन आयोग के अध्यक्ष ने लिखा : “हमारे देश का इतिहास शिल्प कला विज्ञान सम्बन्धी अनेक नव-नता-प्रवर्तकों तथा क्रान्तिकारियों के विश्व-व्यापक सहस्वपूर्ण अन्वेषणों से परिपूर्ण है, जैसे पोपाव (Popov) भौतिक विज्ञान-वेत्ता तथा रेडियो प्रवर्तक जिसके अनेक अन्वेषण ‘राडार’ पर आधारित हैं तथा वैज्ञानिक क्रान्ति एवम् पुनः अन्वेषण करने में सहायक सिद्ध हुये हैं; मेन्डेलेयेव (Mendeleev) जो विश्व के प्रधान रसायन-शास्त्रियों में से एक हैं, जिन्होंने “नियतकालिक सिद्धान्त” (Periodic Law) का अन्वेषण किया—रसायन शास्त्र का वह प्रसिद्ध सिद्धान्त जो आज भी वैज्ञानिकों को अणुशक्ति सम्बन्धी गुप्त विषयों के अन्वेषण में सहायगी है; जूकोवस्की (Zhukovsky), विश्व का सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने आधुनिक वायुगतिक शास्त्र (aerodynamics) तथा वायुयान द्वारा यात्रा (aviation) सम्बन्धी सिद्धान्त प्रमाणित किये हैं; जिओब्रॉक्स्की (Tsiolkovsky), प्रमुख आविष्कारक एवम् वैज्ञानिक, जिसने राकेट सिद्धान्त को विकसित कर आधुनिक ‘जेट’ (Jet) ‘प्रोपल्शन’ यन्त्रकला को प्रोत्साहित करते हुये समान विदेशी अन्वेषणों पर पूर्व अनुसन्धान कर लिया है। यदि हमारे वैज्ञानिकों को सुचित सहयोग प्रदान किया जावे तो सोवियट विज्ञान अन्य देशों के वैज्ञानिक आविष्कारों को अतिक्रमण कर देगा।”

(ङ) युद्ध से सुरक्षित रहने के लिये सोवियट सरकार ने सुरक्षा-साधनों पर भी व्यय करने का आयोजन किया। “नवीन शास्त्रों के निर्माण, राष्ट्र की शक्ति-शाली तथा अन्तर्देशीय शान्ति को प्रोत्साहित करने हेतु सोवियट सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। स्टैलिन का मत था : “जब तक देश स्वतः स्वावलम्बी नहीं होता, विदेशी आक्रमणकारियों के भय से त्रासित रहेगा। अस्तु सुरक्षा साधनों पर विशिष्ट ध्यान देना अति आवश्यक है।” प्रस्तुत योजना में भारी उद्योगों की प्रधानता इस उद्देश्य से भी दी गई थी।

इन उद्देश्यों के पूर्णार्थ लोहे तथा इस्पात के उद्योग में उत्पादन १९४० की अपेक्षा ३५ प्रतिशत अधिक होने का आयोजन किया गया। कच्चे लोहे का उत्पादन १,६५,००,००० टन तथा इस्पात का २५४,००,०००, टन हो जाने का लक्ष्य किया गया। लोहे तथा इस्पात की ४५ ‘ब्लास्ट’ भट्टी, १८ ‘खुली’ भट्टी, ६० विद्युत् भट्टियाँ तथा १०४ ‘रोलिंग मिलें’ स्थापित होने का आयोजन किया गया। १९५० की अपेक्षा ताँबे का उत्पादन १.६ गुना, अलमोनियम २ गुना, मैगनेसियम २.७ गुना, निकल १.९ गुना, शीशा २.६ गुना, जस्ता २.५ गुना, टंगस्टन ४.४ गुना, ‘मोलिब्डेनम’ २.१ गुना तथा टिन २.७ गुना बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

धातुओं के अतिरिक्त कोयले का उत्पादन १९५० में २,५०० लाख टन हो जावेगा, जो १९४० की अपेक्षा ५१ प्रतिशत अधिक था। कोयले के उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनों तथा यन्त्रों का उत्पादन तीन-चार गुना बढ़ेगा। नये प्रकार की ईंधन तथा शक्तियों का निर्माण किया गया, जैसे सिन्थेटिक द्रव-ईंधन का वार्षिक उत्पादन नौ लाख टन, और गैस का १,१२,००० लाख घ० मी०। मिट्टी के तेल का उत्पादन, जो १९१३ की अपेक्षा १४ प्रतिशत अधिक था, ३५४ लाख टन करने का लक्ष्य किया गया। पूर्वी भागों में मिट्टी के तेल का उत्पादन सम्पूर्ण उत्पादन का १२ प्रतिशत से ३६ प्रतिशत बढ़ाने का आयोजन किया गया।

विद्युत् की ओर भी सरकार का विशेष ध्यान गया। ८,००,००० लाख किलोवाट घण्टा उत्पादन होने का था जो १९१३ की अपेक्षा ७० प्रतिशत अधिक था। जल-विद्युत् का अंश १०.५ प्रतिशत से १५.२ प्रतिशत वृद्धि हो जाने का निश्चय किया गया। मशीन-निर्माण उद्योग पर सम्पूर्ण प्रगति आधारित थी, जिसका लक्ष्य शत-प्रतिशत वृद्धि होने का आयोजन किया गया था। लोहे तथा इस्पात बनाने की मशीनों का उत्पादन ३.७ गुना, मोटर ३.४ गुना, रेलवे इंजन २.४ गुना, ट्रैक्टर ३.६ गुना तथा विद्युत् सामग्री २.५ गुना बढ़ने का लक्ष्य किया गया। रसायनिक उद्योग में भी उत्पादन १९१३ की अपेक्षा १.५ गुना बढ़ना चाहिये

था। खनिज-खादों में फास्फेट का उत्पादन दूना, नाइट्रेट का १. गुना पोटाश का १.३ गुना लक्षित किया गया। सिन्थेटिक रबर का उत्पादन दूना होना चाहिये था। कागज का उत्पादन, ६५ प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया था। गृह निर्माण हेतु अन्य पदार्थों की आवश्यकता थी जैसे काठ-कबाड़ (lumber) का उत्पादन २,८०,०००,००० घ० मी० होना चाहिये था, जो ५६ प्रतिशत वृद्धि का समर्थन करता है। सीमेन्ट तथा शीशे की प्लेटों का उत्पादन १.८ गुना बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहित किया गया।

उपभोग सामग्री उत्पादन के लक्ष्य अधिक प्रभावशाली न थे। खाद्यान्न में भी यही त्रुटि थी। सम्पूर्ण उपभोक्ता पदार्थों में १७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का आयोजन किया गया। सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग, जूते और मोजे-बनियाइन के उत्पादन में भिन्न-भिन्न लक्ष्य निश्चित किये गये थे। सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन ४६,८६० लाख मीटर, ऊनी वस्त्र उद्योग में १,५६० लाख मीटर, रेशमी वस्त्र में १,४१० लाख मीटर, जूते का उत्पादन २,४०० लाख तथा बनियाइन का उत्पादन ५,००० लाख मीटर निर्धारित किया गया। सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रेशम का था, जिसमें ४.६ गुना उत्पादन बढ़ने का आयोजन किया गया। भोजन के अन्य पदार्थों में भी उत्पादन बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

पूँजी निर्माण तथा नवोन उत्पादन साधनों पर सरकार को अधिक ध्यान देना था। निर्माण कार्य में भी यन्त्रों के उपभोग पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। खानों में मशीनों का प्रयोग ६० प्रतिशत, पत्थर तोड़ने की मशीनों में ६० प्रतिशत, चूने तथा सीमेन्ट आदि को मिलाने की मशीनों में ६५ प्रतिशत, गारा तथा चूने आदि को उलटने के उद्योग में ६० प्रतिशत तथा चित्रकार कला में ५० प्रतिशत मशीनों का प्रयोग बढ़ाने का आयोजन किया गया। युद्धकाल में अनुशासन अन्तर्गत शीघ्रतापूर्वक काम करने में श्रमिक पूर्ण दत्त हो गये थे, जिसका प्रभाव युद्ध के उपरान्त भी अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुआ। निर्माण उद्योग में तीन विशेष बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता समझी गई :

- (क) आवश्यक शिल्प-कार्यों में अधिक समय न नष्ट होना चाहिये।
- (ख) क्षति रहित न्यूनतम लागत पर निर्माण कार्य होना चाहिये।
- (ग) निर्माण सामग्री एवम् श्रमिक समुदाय तथा कर्मचारीगण इस विभाग में स्थायी रहेंगे, जिनका केवल निर्माण कार्य ही न होगा, वरन् मरम्मत आदि के भी कार्य में वे निरन्तर सहायता पहुँचावेंगे।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य

प्रतिशत निर्धारित किया गया। श्रमिकों में कार्य क्षमता वृद्धि तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी यन्त्रों का प्रयोग अत्यधिक होना चाहिये। श्रमिक संघों की सुव्यवस्था, भोजनालय में सुधार, यन्त्रों का प्रयोग, तथा 'जीवन-निर्वाह' में सुधार आदि रीतियों द्वारा श्रम उत्पादकता १.५ गुना बढ़नी चाहिये थी और इस प्रकार सम्पूर्ण औद्योगिक संगठन में भी गुणात्मक सुधार होने के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे।

कृषि क्षेत्र में भी लक्ष्य निर्धारण निम्नलिखित किये गये :

(१९३२=१००)

वर्ष	सूचकांक
१९३०	१००
१९३७	१५३ द्वितीय योजना के अन्त में
१९४०	१७७ तृतीय " " " "
१९४०	२२५ चौथी " " " "

विविध पदार्थों में विभिन्न लक्ष्य निश्चित किये गये और ऐसा अनुमान लगाया गया कि भविष्य में प्रगति लक्ष्यानुसार होगी। सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि १९४० की अपेक्षा केवल सात प्रतिशत होने का आयोजन किया गया। चुकन्दर में २२ प्रतिशत, कपास में २५ प्रतिशत, सन में ३६ प्रतिशत, सूर्यमुखी बीज में ११ प्रतिशत, उत्पादन-वृद्धि लक्ष्य निश्चित किये गये। सस्य आवर्तन (rotation of crop), वैज्ञानिक ढंग से बीज बोना, ट्रैक्टरों का प्रयोग, तथा जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि रीतियों पर अधिक जोर दिया गया। 'गुणात्मक सुधार होना चाहिये', एक राजकीय आन्दोलन था। पशुपालन की ओर भी सरकार का विशेष ध्यान गया तथा इसका निश्चित प्रबन्ध किया गया। घोड़े ४६ प्रतिशत, कुल चौपाये २६ प्रतिशत, भेड़-बकरी ७५ प्रतिशत, तथा सुअर की संख्या २०० प्रतिशत बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सामूहिक खेतों पर, १९४० की अपेक्षा, चौपाये २६ प्रतिशत, भेड़-बकरी ६२ प्रतिशत तथा सुअर ३५ प्रतिशत अधिक हो जाने का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर, अन्य कृषि मशीन तथा खनिज-खाद के उत्पादन बढ़ाने का पूर्ण चेष्टा की गई। ऐसा आयोजन किया गया कि पाँच वर्षों में ७,२०,००० ट्रैक्टर प्रदान किये जावेंगे, जब कि द्वितीय योजना के समय केवल

५,१२,००० हैक्टर उत्पन्न किये गये थे। सामूहिक तथा राज्य कृषि एवम् हैक्टर स्टेशनों में विद्युत् का प्रयोग विस्तृत आकार में किया जावेगा। ग्रामीणों को भी विद्युत् अत्यधिक परिमाण में उपलब्ध होनी चाहिये, ताकि हैक्टर स्टेशनों तथा सामूहिक खेतों के गोदामों को विद्युत् पर्याप्त मात्रा में सस्ते मूल्य पर प्रदान की जा सके। ऐसा होने पर उर्वरता बढ़ेगी तथा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो सकेंगे। सामूहिक कृषि की सामान्य दशा सुधारने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विषयों पर पूर्ण विचार किया गया :

(क) सामूहिक खेतों की सर्वसाधारण सम्पत्ति बढ़ायी जाये तथा उत्तम पशुओं की संख्या बढ़े ताकि सामाजिक सम्पत्ति अधिक मात्रा में संग्रहित की जा सके।

(ख) सामूहिक खेतों में भूति-प्रथा कार्य-दिवस इकाई (work-day unit) के आधार पर, इस प्रकार संचालित की जावे कि कृषकों को अधिकतम धन प्राप्त हो सके और साथ ही साथ कार्य को प्रोत्साहन भी मिले।

(ग) कृषकों को बोनस तथा अन्य आर्थिक हित प्रदान किये जावें।

(घ) राज्य कृषि दशा सुधारने के लिये श्रमिकों को अनेक सुविधायें प्रदान की जावें ; उनके निवास स्थान सुव्यवस्थित किये जावें तथा सरकार से उन्हें व्यक्तिगत गृह तथा पशु रखने का अधिकार प्राप्त हो सके।

इस विषय पर भी योजना आयोग का ध्यान आकृष्ट हुआ कि सामूहिक तथा राज्य कृषि के अतिरिक्त सहकारी कृषि के प्रति भी सरकार को कुछ ध्यान अवश्य देना चाहिये।

भौतिक निर्माण हेतु यातायात तथा संवादवाहन सुविधा होना अत्यन्त आवश्यक है। रेल, जल तथा मोटर यातायात वृद्धि का उचित आयोजन होना स्वीकार किया गया। १९३२ में कुल यातायात भाड़ा २,१५० हजार लाख टन किलोमीटर से १९३७ में ४,३०० हजार लाख किलोमीटर तथा १९४० में ४,८३० हजार लाख किलोमीटर हो जाने के उपरान्त १९५० में ६५,७५,००० लाख टन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस क्षेत्र में १९४०-१९५० में प्रगति ३६ प्रतिशत से अधिक थी। यूराल तथा साइबेरिया में नवीन रेलवे लाइन के निर्माण में अधिक ध्यान दिया गया था। विद्युत् तथा डीजल (diesel) इंजन अधिक मात्रा में बनाये गये और अनेक प्रकार से गुणात्मक सुधार करने का आयोजन किया गया। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु पंचवर्षीय योजना में ६,१६५ वाष्प, ५५५ विद्युत् तथा ८६५ डीजल इंजन निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और ५,७२,००० भाड़ा गाड़ी निर्माण होने का प्रबन्ध

किया गया। अस्त-व्यस्त तथा विध्वंस रेलवे लाइनों को पुनर्जीवन प्रदान करने के अतिरिक्त ७,२३० किलोमीटर नई रेलवे पटरियाँ निर्मित करने का आयोजन हुआ, जिसमें केवल साइबेरिया में ३,५५० किलोमीटर पटरियाँ बननी थीं। ५,३२५ किलोमीटर विद्युत् रेलवे संचालन की जाने को थी। इस उत्थान के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४,५०० हजार टन रेल तथा १८,५०,००० ००० लाख 'स्लीप्स' की आवश्यकता थी। योजना के ये निश्चित लक्ष्य थे।

रेलवे यातायात पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४,००,१०० लाख रुबल पूँजी निर्माण करना निश्चय किया गया। जल यातायात पर भी योजना ने यथेष्ट ध्यान दिया। नदी द्वारा यातायात में ३० प्रतिशत वृद्धि और समुद्र द्वारा यातायात में २.२ गुना वृद्धि होने का प्रबन्ध किया गया। जहाज निर्माणशालाओं पर अधिक ध्यान देकर, १६५० तक सामुद्रिक जहाजों में २.५ गुना, तथा नदी के जहाजों में ४ गुना निर्माण बढ़ाने की योजना बनी और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ऐसा करने से सोवियट रूस की सामुद्रिक युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जावेगी। मोटर-गाड़ी यातायात तथा सड़कों के निर्माण के लिये भी विभिन्न लक्ष्य निश्चित किये गये। वायुयानवाहन की ओर भी योजना में पूर्ण ध्यान दिया गया। रेडियो, टेलीफोन, संवादवाहन का भी पूर्ण प्रबन्ध योजना में किया गया और अनेक प्रान्तीय, जिला तथा स्थानीय संचालन केन्द्र निर्मित किये गये।

उत्पादन लागत ह्रास पर सोवियट योजना का अत्यधिक ध्यान था। उद्योगों में १७ प्रतिशत, ट्रेक्टरों में १६ प्रतिशत और रेल यातायात में १८ प्रतिशत लागत ह्रास उत्पन्न करने का आयोजन किया गया। निर्मित सामग्री में गुणात्मक सुधार तथा कृषि पदार्थ में उच्चकोटि का उत्पादन लक्षित किया गया। जनकल्याण तथा जन-सेवा हेतु प्रत्येक क्षेत्र में सुविधायें प्रदान की गईं।

ऐसा विचार किया गया कि समाजवादी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये भौतिक उन्नति अत्यन्त आवश्यक थी ताकि

(क) उत्पादन प्रगतिशील रहे,

(ख) राष्ट्रीय पूँजी निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, तथा

(ग) जीवन निर्वाह और शिल्पकला में निरन्तर प्रगति होती रहे।

सर्वसाधारण शिक्षा में यथेष्ट वृद्धि अत्यन्त आवश्यक समझा गया। स्कूल, कालेज तथा संस्थाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु योजना निर्मित की गई। श्रमिक दशा सुव्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजना ने निम्नलिखित साधनों को कार्यान्वित करने का प्रबन्ध किया :

(क) सोवियट मुद्रा को प्रबल तथा स्थिर बनाने हेतु, यह आवश्यक था कि वस्तुओं का मूल्य कम किया जावे ।

(ख) निवास स्थान निर्माण में निरन्तर प्रगति होनी चाहिये और नागरिकों को सम्पूर्ण सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये ।

(ग) जैसे-जैसे श्रम कुशलता एवम् कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उसी अनुपात में पारिश्रमिक भी बढ़ना चाहिये ।

(घ) सामूहिक कृषकों की सामान्य आय बढ़नी चाहिये तथा कार्यानुसार भुक्ति देना चाहिये ।

(ङ) वैज्ञानिक अनुसन्धान, यन्त्रकला तथा योजना की सफलता हेतु प्रगतिशील बोनस प्रदान करना चाहिये ।

निम्नलिखित सारणी द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक विकास स्तर जो १९५० तक प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया था, प्रदर्शित किया गया है :

आर्थिक विकास (१९४०-१९५०)

पद	इकाई	१९४०	१९५०	१९५० में (१९४० का प्रतिशत)
राष्ट्रीय आय	हजार-दसलाख रुबल (१९२६-२७ मूल्य के आधार पर)	१२८.३	१७७.०	१३८
ल औद्योगिक उत्पादन...	"	१३८.५	२०५.०	१४८
कुल कृषि-उत्पादन	"	२३.२	२९.५	१२७
रेल, जल व मोटर भाड़ा यातायात...	हजार-दसलाख टन किलोमीटर	४८३.०	६५७.५	१३६
राज्य व सहकारी फुटकर व्यापार...	हजार-दसलाख रुबल (फुटकर मूल्य)	१७५.१	२७५.०	१२८
औद्योगिक श्रम उर्वरता	प्रतिशत	—	—	१३६
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पारिश्रमिक कोष...	हजार-दसलाख रुबल	१६२.०	२५२.०	१५६

योजना की सफलताएँ : राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्य से अधिक हुई। दफ्तर एवम् कारखानों में श्रमिकों की संख्या २५ प्रतिशत अधिक हो गयी। मौलिक क्षेत्रों में उत्पादन सुविधायें ३४ प्रतिशत अधिक थीं और राष्ट्रीय आय में ६४ प्रतिशत उन्नति हुई। पाँच वर्षों में सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन ७३ प्रतिशत अधिक हो गया। उत्पादन साधनों की उत्पत्ति १०५ प्रतिशत और उपभोग पदार्थों का उत्पादन २३ प्रतिशत बढ़ा। उपभोग पदार्थों में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण न थी। सम्पूर्ण विशाल उद्योगों में उत्पादन वृद्धि ७६ प्रतिशत हुई और यातायात साधनों में उन्नति केवल ४६ प्रतिशत ही रही। रेल यातायात ने ४५ प्रतिशत प्रगति की और सम्पूर्ण पूँजी विनियोग में ११० प्रतिशत वृद्धि हुई। निम्नलिखित सारणी इस तथ्य की पुष्टि करती है :

१९४०—१९५० में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रगति के मौलिक अंक

पद	१९४०	१९५०
कारखाने, दफ्तर तथा अन्य स्थानों में श्रमिकों की संख्या...	१००	१२५
सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में मौलिक उत्पादन सुविधाएँ...	१००	१३४
राष्ट्रीय आय...	१००	१६४
सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन : जिसमें...	१००	१७३
उत्पादन साधनों की उत्पत्ति...	१००	२०५
उपभोग पदार्थों का उत्पादन...	१००	१२३
विशाल उद्योगों में सम्पूर्ण उत्पादन...	१००	१७६
सम्पूर्ण यातायात साधनों में भाड़ा वृद्धि...	१००	१४६
रेलगाड़ी सम्बन्धी भाड़ा...	१००	१४५
रेलगाड़ी पर सामग्री चढ़ाने की औसत प्रति दिन क्रिया...	१००	१२१
सम्पूर्ण पूँजी विनियोग...	१००	२१०

यह योजना रूसी समाजवाद हेतु अत्यन्त सहयोगी सिद्ध हुई। इसकी प्रबलता एवम् शक्ति तो बड़ी ही, परन्तु अधिक से अधिक क्षेत्र सरकार के आधिपत्य में आ गये। १९५० तक ६६.८ प्रतिशत, समाजवादी क्षेत्र राष्ट्रीय आय प्रदान करने लगा। शत-प्रतिशत उद्योग-उत्पादन, ६८.१ प्रतिशत कृषि-उत्पादन और शत-प्रतिशत फुटकर व्यापार ने समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आकर, इस क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

समाजवादी क्षेत्र का अंश

पद	१९२८	१९३७	१९५०
राष्ट्रीय आय	४४.०	६६.१	६६.८
उद्योग उत्पादन	८२.४	६६.८	१००.०
कृषि-उत्पादन	३.३	६८.५	६८.१
फुटकर व्यापार	७६.४	१००.०	१००.०

सोवियट संघ के मौलिक साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और १९८० की अपेक्षा अवस्था निम्नलिखित प्रदर्शित की गई है :

पद	१९४०	१९५०
सम्पूर्ण मौलिक साधन (पशुओं के अतिरिक्त)	१००	१२३
मौलिक उत्पादन साधन	१००	१३४
उद्योग तथा निर्माण	१००	१५८
कृषि	१००	१०५
यातायात एवम् संवादवाहन	१००	११७
अनुत्पादी साधन	१००	१११

श्रम उत्पादकता में सफलता प्रशंसनीय थी। १९५० में १९२८ की अपेक्षा ३७० प्रतिशत और १९४० की अपेक्षा ३७ प्रतिशत श्रम-दक्षता में अधिक वृद्धि हुई। निर्माण उद्योगों में भी इसी माप पर क्रमशः २०७ प्रतिशत तथा २३ प्रतिशत और रेलवे में १६५ तथा १० प्रतिशत क्रमशः वृद्धि हुई, जैसा कि अधोलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

अम-उत्पादकता में वृद्धि

(१९२८=१००)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	निर्माण उद्योग	रेलवे
१९२८	१००	१००	१००
१९४०	३४३	२५०	२६६
१९५०	४७०	३०७	२९५

(१९४०=१००) .

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	निर्माण उद्योग	रेलवे
१९४०	१००	१००	१००
१९५०	१३७	१२३	११०

राष्ट्रीय आय में भी १९१३ की अपेक्षा १९५० में कई गुना तथा १९४० की अपेक्षा ६४ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सफलता सोवियट रूस के आर्थिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

सोवियट संघ की राष्ट्रीय आय की प्रगति

वर्ष	१९१३=१००
१९१३	१००
१९२८	११९
१९३२	२१७
१९३७	४५९
१९४०	६१
१९५०	१,००३
वर्ष	१९४०=१००
१९४०	१००
१९५०	१६४

१९२८ को आधार वर्ष मान कर अगर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की तुलना की जावे तो उन्नति बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है, जो निम्नांकों से स्पष्ट है :

सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन की सापेक्ष माप

(१९२८ = १००)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	उत्पादक साधन (भारी उद्योग)	उपभोग पदार्थ
१९२८	१००	१००	१००
१९४५	५९३	१,१२२	२४६
१९४६	४९५	८२४	२७९
१९४७	६०३	१,००८	३३८
१९४८	७६१	१,२९६	४०९
१९४९	९१२	१,४२६	४४२
१९५०	१,११९	२,०४९	५१०

अगर १९४० को आधार मानकर १९५० के उत्पादन की सापेक्ष तुलना की जावे तो अधोलिखित अवस्था दृष्टिगोचर होगी :

सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन की सापेक्ष माप

(१९४० = १००)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	उत्पादन-साधन (भारी उद्योग)	उपभोग पदार्थ
१९४०	१००	१००	१००
१९४५	९२	११२	५३
१९४६	७७	८२	६७
१९४७	९३	१०१	८२
१९४८	११०	१३०	९९
१९४९	१४१	१६३	१०७
१९५०	१७३	२०५	१२३

१९४५ में जब युद्ध समाप्त हुआ, १९४० की अपेक्षा सम्पूर्ण उद्योग तथा

उपभोग पदार्थ उद्योगों में उत्पादन सूचकांक ९२ तथा ५६ हो गया था। केवल भारी उद्योगों में अवस्था १९४० की अपेक्षा ११२ सूचकांक थी।

१९४७ तथा १९४८ तक उपभोग पदार्थों की अवस्था निरन्तर सोचनीय थी। सूचकांक १९४५ को आधार मान कर ८२ था। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण उद्योगों का सूचकांक केवल ९३ तक पहुँच सका। १९४६ में उपभोग उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई। भारी उद्योगों में अवश्य उत्पादन १९४५ की अपेक्षा दुगुने से अधिक हो गया। क्षेत्र में योजना केवल सफल ही नहीं, किन्तु सफलता की सीमा भी लंघन कर गयी थी। निम्नलिखित समंक, इस दशा की पुष्टि हेतु प्रदर्शित किये गये हैं :

चौथी योजना की सफलता

पद	(१९४५=१००)	(१९४०=१००)
सम्पूर्ण उद्योग में उत्पादन	१८९	१७३
भारी उद्योगों में उत्पादन	१८३	२०५
उपभोग पदार्थों में उत्पादन	१०७	१२३
कच्चा लोहा	२१८	१२६
इस्पात	२२३	१४६
पिटी-धातु	२४६	१५६
कोयला	१७५	१५७
मिट्टी का तेल	१६५	१८२
शक्ति	२११	१८६
खनिज-खाद	४३१	१८१
मशीन-निर्माण आदि	१६७	२१५
सीमेन्ट	५५३	१८०
सूती वस्त्र	२४१	६६
रेशम	३५८	१६६
बड़ियाँ	२३ गुना	२७१
मकखन तथा दुग्धशाला पदार्थ	२६०	१३१
वनस्पति तेल	२८०	१०३
बैत का सामान	२७५	१३८
दानेदार चीनी	५४३	११७

यदि प्रमुख विभिन्न साधनों के उत्पादन का समुचित विवेचन किया जाये तो प्रगति की सफलता स्पष्ट दर्शित होती है। कच्चे लोहे का उत्पादन १९६ में ६६ लाख टन था जो १९५० में १६२ लाख टन हो गया, अर्थात् दुगुने से अधिक। इस्पात उत्पादन में भी लगभग इसी प्रकार सफलता प्राप्त हुई। कोयले का उत्पादन भी ५५ प्रतिशत के लगभग बढ़ा। मिट्टी का तेल एवम् शक्ति में भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति हुई :

प्रमुख भारी उद्योग का वास्तविक उत्पादन

वर्ष	कच्चा लोहा (लाख टन)	इस्पात (लाख टन)	कोयला (लाख टन)	मिट्टी का तेल (लाख टन)	शक्ति दस लाख कि० वा०
१९४६	६६	१३३	१,६४१	२१७	४८.३
१९४७	११२	१४५	१,८३२	२६०	५६.५
१९४८	१२७	१८६	२,०८०	२६२	६६.३
१९४९	१६४	२३३	२,३५५	३३१	८८.३
१९५०	१६२	२७३	२,६११	३७६	९१.२

मशीन निर्माण उद्योग में उन्नति अद्वितीय थी। यदि १९२८ के उत्पादन को इकाई मना जाये तो १९५० में उत्पादन ४३ होगा, जैसे :

मशीन निर्माण उद्योग

वर्ष	१९२८=१
१९४०	२०
१९४६	१७
१९५०	४३

ट्रैक्टर उत्पादन में भी १९४६-१९५० में कई गुना वृद्धि हुई। १९४६ में उत्पादन १२.३ हजार था, जो १९५० में १०८.८ हजार हो गया, जैसा कि निम्न-लिखित सारणी द्वारा प्रतीत होता है :

१४४]

[सो वयट रूप का आर्थिक विकास

वर्ष	उत्पादन हजार इकाई
१९४६	१३.३
१९४७	२७.८
१९४८	५६.६
१९४९	८८.२
१९५०	१०८.८

युद्ध काल में अनेक नगर, गृह, फैक्टरी तथा भवन आदि नष्ट होने के कारण सीमेन्ट के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। खनिज-खाद का भी उत्पादन ३ गुना से अधिक बढ़ गया था जो निम्नांकित है :

सीमेन्ट तथा खनिज-खाद उत्पादन

वर्ष	सीमेन्ट (हजार टन)	खनिज-खाद (हजार टन)
१९४६	३,३५३	१,५०६
१९४७	४,५१८	२,३५५
१९४८	६,४५५	३,४६८
१९४९	८,१४७	४,५८५
१९५०	१०,१६४	५,४६२

यों तो वस्त्र उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी, पर इससे रुस की वस्त्र-न्यूनता समस्या किसी प्रकार न सुलभ सकी। ऊन उद्योग में प्रगति महत्त्वपूर्ण थी। रेशम का भी उत्पादन चार-गुना बढ़ गया था। जूते भी लक्ष्य से कई लाख अधिक निर्मित किये गये थे। कागज के उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त प्रभावशाली थी। निम्नलिखित सारणी से दशा का पूर्ण ज्ञान होता है :

उपभोक्ता पदार्थ उद्योग में उत्पादन

वर्ष	सूता वस्त्र (दस लाख मीटर)	ऊन (दस लाख मीटर)	रेशम (दस लाख मीटर)	जूता (दस लाख जोड़े)	कागज (हजार टन)
१९४६	१,६०१	७०.६	४८.७	८१.२	५१७
१९४७	२,५५१	९५.०	६५.४	११२.८	६४८
१९४८	३,१५०	१२३.७	८१.७	१३४.०	७७६
१९४९	३,६०१	१४८.३	१०५.०	१६३.६	९९५
१९५०	३,८६६	१५५.२	१०६.७	२०३.४	१,१६३

चीनी का उत्पादन भी लगभग चार गुना से अधिक बढ़ गया था। १९४६ में ४६६ हजार टन उत्पादन था जो १९५० में २,५२३ हजार टन हो गया। औद्योगिक लागत पर भी सुधार आश्चर्यजनक हुआ। ट्रेड यूनियन ने सराहनीय सहायता प्रदान की। सामूहिक कृषि संगठन में भी अनेक सुधार हुये और सफलता प्रत्येक दिशा में निश्चित लक्ष्य से अधिक थी। पशुपालन उद्योग में भी उन्नति हुई और खाद्यान्न का उत्पादन भी लक्ष्यानुसार हुआ। खाद्यान्न समस्या जो युद्ध काल में बड़ी विकट थी, उत्पादन वृद्धि के कारण काफी सुव्यवस्थित हो गई। कच्चे पदार्थ का भी उत्पादन उन्नति-पथ पर अग्रसर था। मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों के प्रबन्ध में अनेक सुधार हुये, जिनके आधार पर सामूहिक कृषि भी सुव्यवस्थित की गई।

योजनात्मक प्रगति (१९४०-१९५०)

पद	१९४०	१९५०	
		योजना-लक्ष्य	पूर्णाता
(१) राष्ट्रीय आय—१९२६-२७ के मूल्य स्तर पर (हजार-दसलाख रुबल) प्रतिशत में.....	१२८.३ १००	१७७ १३८	२१० १६४
(२) श्रमिकों की संख्या (दस लाख) प्रतिशत में.....	३१.५ १७०	३६.८ १२६
(३) औद्योगिक उत्पादन (हजार दस लाख रुबल) प्रतिशत में.....	१३८.५ १००	२०५ १४८	२४० १७३
(४) रेलगाड़ी व्यापार (हजार-दसलाख टन) प्रतिशत में.....	४१५ १००	५३२ १२८	६०५ १४६
(५) औद्योगिक श्रम-उत्पत्ति प्रतिशत में.....	१००	१३६	१३७
(६) विद्युत् शक्ति का उत्पादन (हजार-दसलाख कि० वा०) प्रतिशत में	४८.३ १००	८२ १७०	६१.२ १८६

जो उन्नति १९४६-१९५० में हुई, उसमें पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेश अधिकांश थे। १९५० के अन्तकाल तक पूर्वी प्रान्त में एक अत्यन्त शक्तिशाली औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो चुका था। वाल्गा, यूराल, साइबेरिया, केन्द्रीय एशिया का संघ तथा सुदूर पूर्व के प्रदेशों में आश्चर्यजनक प्रगति हो रही थी। विशाल औद्योगिक केन्द्र बढ़ तो हो ही गये थे। केवल पुनर्निवेशन अथवा पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि नवीन निर्माण भी अधिक थे। भारी उद्योगों को विशेष प्रधानता देकर सोवियट रूस ने अपने राष्ट्र को अत्यधिक प्रबल बना लिया था और यह आशा की गई कि यदि इसी प्रकार सोवियट समाजवाद निरन्तर प्रगति करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आवेगा जब साम्यवाद स्थापित करने का लक्ष्य पूर्ण हो जावेगा। चौथी योजना की पूर्णता (fulfilment) का विवरण पिछले पृष्ठ में दिये गये अंकों से प्राप्त है^१।

चौथी योजना की सफलता ने सोवियट रूस को पूर्ण सहयोग प्रदान कर अति अधिक प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप पाँचवी योजना के निर्माण कार्य में सम्पूर्ण देश संलग्न हो गया।

^१ Planned Economy, 1951, No. 2, "Results of the Fulfilment of the Fourth Five Year Plan of the U.S.S.R.", pp. 3—13; National Economy of the U.S.S.R. 1956, pp. 71, 189; S. G. Strumilin : Planning in the Soviet Union, pp. 52.

तेरहवाँ अध्याय

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

(१९५१-१९५५)

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सोवियट रूस ने अपने को प्रबल एवम् सम्पन्न करने को पूर्ण चेष्टा की थी। यद्यपि युद्ध में अर्थव्यवस्था को अधिक क्षति पहुँची तथापि चौथी योजना के अन्तर्गत पुनर्निवेशन तथा पुनर्निर्माण कार्य इतनी शीघ्रतापूर्वक हुआ कि रूस केवल युद्ध से पूर्व अवस्था समकक्ष ही नहीं बरन् उससे भी अधिक सम्पन्न एवम् शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। कितनी भी गंभीर एवम् विशाल समस्याएँ क्यों न उत्पन्न हो जावें, सोवियट रूस का यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त न होकर एक सुन्दर एवम् सुडौल रूप धारण करेगी। नींव दृढ़ होने के उपरान्त सोवियट सरकार ने प्रस्तुत योजना में समाजवाद की प्रभावशाली बनाने तथा दीर्घ काल में साम्यवाद को ग्रहण करने हेतु अनेक लक्ष्य निर्धारित किये। साम्यवाद को स्थापित करने में सामाजवाद दृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक था और सोवियट सरकार का विश्वास था कि गत योजना काल में उसने समाजवाद पूर्ण रूप से स्थापित कर, उसे यथेष्ट शक्ति प्रदान किया है। जिससे फल-स्वरूप वे साम्यवाद की ओर एक पग और आगे बढ़ सकते हैं। अतः प्रस्तुत योजना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ साम्यवाद निर्माण की ओर झुकी थीं। उसी उद्देश्य के आधार पर योजना निर्माण की गई।

योजना के लक्ष्य : पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन ७० प्रतिशत बढ़ने का लक्ष्य था। भारी उद्योगों में वार्षिक औसत उत्पादन १३ प्रतिशत, हल्के उद्योगों में ११ प्रतिशत तथा औसत सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन १२ प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का आयोजन किया गया। यद्यपि भारी उद्योगों को पुनः अधिक

महत्त्व दिया गया था, फिर भी उपभोग-पदार्थों के उत्पादन की ओर गत योजनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया। कच्चा लोहा ७६ प्रतिशत, इस्पात ६२ प्रतिशत, अलौहमय धातु (nonferrous metal) ६४ प्रतिशत, मिट्टी का तेल ८५ प्रतिशत, कोयला ४३ प्रतिशत, विद्युत् ८० प्रतिशत, वाष्प इंजन १३० प्रतिशत, जल विद्युत् इंजन ६८० प्रतिशत, वाष्प-यन्त्र १७० प्रतिशत, उत्पादन वृद्धि का आयोजन किया गया। मोटर-गाड़ी २० प्रतिशत, ट्रैक्टर १६ प्रतिशत, सोडा भस्म ८४ प्रतिशत, कास्टिक सोडा ७६ प्रतिशत, खनिज-खाद ८८ प्रतिशत, सेन्थेटिक रबर ८२ प्रतिशत, सीमेन्ट १२० प्रतिशत, लकड़ी ५६ प्रतिशत, कागज ४६ प्रतिशत, सूती वस्त्र ६१ प्रतिशत, ऊनी वस्त्र ५४ प्रतिशत, जूते ५५ प्रतिशत, चीनी ७८ प्रतिशत, मांस ६२ प्रतिशत, मछली ५८ प्रतिशत तथा मक्खन ७२ प्रतिशत की दर से बढ़ने के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये, १९५०-१९५५ में भारी उद्योगों में गत योजना की अपेक्षा १०० प्रतिशत अधिक विनियोग करने का आयोजन किया गया। भारी उद्योगों को प्रधानता इसलिये दी गयी कि अन्य अनेक उद्योग न पर आधारित थे। लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं में उत्पादन बढ़ने का पूर्ण आयोजन किया गया। पाँच वर्षों में ताँबे का उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ना चाहिये था, शीशा १७० प्रतिशत, अलमोनियम १६० प्रतिशत, जस्ता १५० प्रतिशत, निकल ५३ प्रतिशत और टिन ८० प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया।

विद्युत् क्षेत्र में भी योजना ने विशेष ध्यान दिया। विद्युत् स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने का भी पूर्ण प्रयास किया गया। पाँच वर्षों में सम्पूर्ण विद्युत् शक्ति क्षमता १०० प्रतिशत बढ़ने का आयोजन किया गया। जल विद्युत् पर विशेष ध्यान देकर उत्पादन २०० प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अनेक शक्ति स्टेशनों में गुणात्मक सुधार भी किये गये। कुछ नवीन शक्ति-स्टेशनों का निर्माण करने का आयोजन किया गया, जैसे क्विबिशेव (Kuibyshev) शक्ति स्टेशन, जिसकी क्षमता २,१००,००० कि० वा० थी और कामा (Kama), गॉर्की (Gorky), मिंगचौर (Mingechaur), उस्त कामेनोगोर्स्क (Ust-Kamenogorsk) आदि स्टेशन जिनकी शक्ति १,९१६,००० कि० वा० थी। दक्षिणी प्रान्तों में, यूराल, तथा कुजनेत्स्क (Kuznetsk basin) की खाड़ी में विद्युत् शक्ति का निर्माण अधिक परिमाण में होने का प्रबन्ध किया गया।

मिट्टी के तेल उद्योग की ओर भी योजना का पूर्ण ध्यान आकृष्ट हुआ। सामुद्रिक भागों में तेल निकालने का पूर्ण प्रबन्ध इस योजना के अन्तर्गत किया

गया। सिन्थेटिक द्रव ईंधन (synthetic liquid fuel) तथा गैस की उद्योग में भी योजना ने निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये थे, जिनको पाँच वर्ष में उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक था। कोयले के उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त गुणात्मक सुधार का यथेष्ट प्रबन्ध किया गया, जैसे न्यूनतम लागत पर कोयला निकालना तथा साफ करना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा लगभग ३० प्रतिशत अधिक कोयला शक्ति वृद्धि का आयोजन किया गया था।

इन भारी उद्योगों के अतिरिक्त, मशीन निर्माण तथा धातु कार्यों में १०० प्रतिशत उत्पात्ति बढ़ने का आयोजन किया गया। ऐसा अनुमान था कि लोहे, विद्युत्, तेल, इस्पात, मोटरगाड़ी तथा अन्य उद्योगों में निश्चित सुधार तब ही सम्भव है जब इस कोण से योजना यथेष्ट ध्यान दे। भाग्यवश प्रस्तुत योजना ने इसी आधार पर मशीन का निर्माण किया। पाँच वर्षों में 'रोलिंग' सामग्री १०० प्रतिशत, वृहत् चक्रयन्त्र आदि १०० प्रतिशत तथा वृहत् धातु गढ़न-कुचलन यंत्र में ७०० प्रतिशत वृद्धि आयोजन किया गया। रसायनिक मशीनों का २३० प्रतिशत तथा वृहत् डीजल गैस-निर्माण यन्त्रों का उत्पादन भी बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण की योजना निर्मित की गई, क्योंकि अन्य उद्योगों की निश्चित उन्नति पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित थी। रसायनिक उद्योग में सब से अधिक महत्त्व खनिज-खाद को दिया गया। सोडा, सिन्थेटिक रबर तथा तेल की गैसों के निर्माण का आयोजन किया गया। अमोनिया, सल्फरिक ऐसेड, सिन्थेटिक अल्काहोल तथा सोडा आदि के भिन्न-भिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गये।

अन्य योजनायों के प्रतिकूल उपभोग पदार्थ उद्योगों में इस बार लक्ष्य अधिक उच्च थे तथा उनमें विनियोग प्रतिशत भी अधिक था। खाद्यान्न तथा हल्के उद्योगों का उत्पादन पाँच वर्षों में ७० प्रतिशत से कम न बढ़ना चाहिये था। १९५५ तक सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन ३२ प्रतिशत, कृत्रिम वस्त्र उत्पादन ३७० प्रतिशत, जूता ३४ प्रतिशत, चीनी २५ प्रतिशत, चाय ८० प्रतिशत, मिट्टी का तेल १५० प्रतिशत तथा सूखी सब्जी २५० प्रतिशत, मछली, हरी साग-सब्जी तथा फल आदि ४० प्रतिशत, एवम् शर्करा यंत्र में सुरक्षित मत्स्य ३५ प्रतिशत, पनीर १०० प्रतिशत, सूखा दूध १०० प्रतिशत, तथा अन्य दुग्ध पदार्थ ६० प्रतिशत बढ़ने चाहिये थे। फल, दूध, मत्स्य, मौस आदि क्षतिशील पदार्थों को यन्त्रों द्वारा सुरक्षित रखा जाने का प्रबन्ध किया जाये, ताकि वे शीघ्र नष्ट न हो सकें और अधिक समय तक संचित की जा सकें।

स्थानीय उद्योग तथा उत्पादक सहकारी समितियों में उत्पादन ६० प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये उपभोग पदार्थ सम्बन्धी उद्योग थे तथा ऐसा आयोजन किया गया कि इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ उच्च गुण का उत्पादन होगा। श्रमिकों का स्थानीय उद्योगों के संचालन तथा प्रबन्ध में अत्यधिक आधिपत्य रहेगा। गृह तथा कारखाने निर्माण के विभिन्न पदार्थों की उत्पादन शक्ति में सुधार होना आवश्यक था, क्योंकि वे अन्य क्षेत्रों के सुधारक थे। मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग की व्यवस्था की गई। गृह तथा यंत्रशालाओं के निर्माण कार्य में सम्पूर्ण क्रियाओं को मशीन द्वारा संचालन करने का आयोजन किया गया और साधक यन्त्रों के उत्पादन में वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किये गये। सगुण पदार्थों तथा उत्तम सामग्रियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। अलमोनियम, तेल, कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेन्ट चूना, पत्थर आदि सामग्रियों का अधिक से अधिक तथा अच्छे गुण तथा विशाल परिमाण में उत्पादन एवम् वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग आदि ऐसी क्रियायें थीं जिनकी प्रधानता प्राप्त हुई।

कृषि क्षेत्र में : (क) प्रति हेक्टेयर उर्वरता वृद्धि ; (ख) पशु-रक्षा, उनकी उर्वरता तथा क्षमता पर विशेष ध्यान, (ग) खाद्यान्न तथा दुग्धशाला पदार्थों के सम्पूर्ण विक्रय उत्पादन अंश में वृद्धि, (घ) सामूहिक खेतों पर सामान्य पशुपालन व्यवस्था में सुधार, (ङ) राज्य खेतों में गुणात्मक सुधार और यन्त्रों तथा ट्रैक्टर स्टेशनों में उत्तम यन्त्रों का प्रयोग, आदि ऐसी समस्यायें थीं, जिन पर प्रस्तुत योजना में विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न उत्तम वैज्ञानिक साधनों की स्वीकृत, कृषि में गुणात्मक सुधार, सस्य आवर्तन (rotation of crop), उत्तम बीज, यन्त्रों का प्रयोग तथा उद्योग पदार्थों के उच्च उत्पादन लक्ष्य आदि कृषि सम्बन्धी प्रधान विषय थे, जिनकी राजकीय प्रधानता प्राप्त थी। पशुओं के लिये चारा आदि उत्पादन के लक्ष्य भी निश्चित किये गये। प्रस्तुत पाँच वर्षों में कृषि पदार्थों की उत्पादन वृद्धि सम्बन्धित निम्नलिखित आयोजित तथ्य थे :

(१) कृषि पदार्थों में विशेष ध्यान खाद्यान्न को दिया गया, जिसमें गेहूँ उत्पादन प्रमुख था।

(२) औद्योगिक पदार्थों में विशेष ध्यान कपास, चुकन्दर, सन आदि पर दिया गया, जिनके निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये गये।

(३) आलू, सूर्यमुखी बीज, अंगूर, तम्बाकू, चाय आदि पदार्थों की औसत उत्पादन वृद्धि ६०-६५ प्रतिशत आयोजित की गई।

(४) पशुओं के चारे में भूसा उत्पादन ८०-९० प्रतिशत तथा जड़दार सस्य

में वृद्धि २००-३०० प्रतिशत एवम् हरी घास को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रबन्ध किया गया ।

(५) साग-सब्जी, दुग्धशाला पदार्थ, तथा मांस आदि में उत्पादन अधिक होने की योजना बनाई गई और मास्को, लेनिनग्रेड, यूराल, डानट्रेज तथा कुजनेत्स्क की घाटियाँ आदि स्थानों पर इनके वृद्धि का पूर्ण प्रबन्ध किया गया ।

(६) हरे-भरे वनों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जावे, पाँचवी योजना की एक विशेष समस्या थी और उस पर अत्यधिक ध्यान दिया गया । वनों की लकड़ी, वृक्ष, खाद एवम् मिट्टी आदि को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक समझा गया ।

(७) सिंचित भूमि (irrigated land) का क्षेत्र विस्तृत किया जाये तथा वैज्ञानिक ढंग पर कृषि की जाये । कुलन्दा के घास के मैदानों पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हेतु सरकार को बहुत धन व्यय करना चाहिये था । मध्य के काले क्षेत्र तथा कुरा (Kura) के निचले भाग में अनेक नहर तथा बाँध (dam) बनवाने की योजना बनाई गयी ।

(८) गाथों को दुग्धशील बनाने हेतु पशुपालन व्यवस्था में अनेक सुधार किये जाने का आयोजन किया गया । उत्तम चरागाह तथा वैज्ञानिक पशु-पालन विद्या पर अधिक महत्त्व दिया गया ।

(९) सामूहिक कृषि में सस्य काटने, सफाई, गुड़ाई तथा अन्य कार्यों में अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । फल उत्पादन में भी यन्त्रों का प्रयोग करने का प्रबन्ध किया गया । खाद्यान्न तथा उत्पत्ति वितरण हेतु यातायात सुविधायें अधिक से अधिक प्रदान की गई और मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों को भी सुसंगठित करने का आयोजन किया गया । मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों से यह आशा की गई कि वे अपने कार्य करने की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार करके श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे । कृषि उर्वरता वृद्धि का पूर्ण भार उन्हीं पर था और ऐसा विश्वास किया गया कि उनके द्वारा श्रम क्षमता क्षेत्र में महान प्रगति एवम् उन्नति हो सकती है । सम्पूर्ण लक्ष्य कृषि सुधार हेतु निर्धारण किये गये थे और इसी कोण में योजना कार्य अग्रसर थे ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन से व्यापार तथा यातायात सुविधाओं को भी सम्बन्धित करना अत्यन्त आवश्यक था । फुटकर व्यापार पाँच वर्षों में लगभग ७० प्रतिशत बढ़ने का आयोजन हुआ । १९५० की अपेक्षा १९५५ में मुख्य पदार्थों के विक्रय में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये :

पद	लक्ष्य
मांस आदि	६० प्रतिशत
मछली पदार्थ	७० "
मक्खन	७० "
पनीर	१०० "
वनस्पति तेल	१०० "
साग-सब्जी, फल तथा दूध	१५०-२०० "
चीनी	१०० "
चाय	१०० "
अंगूर की शराब (wine)	१०० "
जब की शराब (beer)	७० "
सिले हुए वस्त्र	८० "
ऊनी, सूती, सन तथा रेशमी वस्त्र	७० "
जूते	८० "
मोजा-बनियाइन	१०० "
बिनी हुई सामग्री	१२० "
फर्नीचर	२०० "
बर्तन	१५० "
बाइसकिल	२५० "
वस्त्र सीने की मशीन	१४० "
रेडियो तथा टेलीविजन	१०० "
घड़ियाँ	१२० "
शीतल यन्त्र तथा वस्त्र धोने की मशीन आदि.....	१०० "

अत्यधिक परिमाण में फुटकर व्यापार बढ़ने के लिये नवीन विक्रय-शालाओं का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक था। सहयोगी समितियों को अधिक संख्या में संचालित होने का प्रबन्ध किया गया। नवीन भोजनालय, होटल, चाय की दूकानें, आदि स्थापित की गई तथा आस्थापित विक्रयशालाओं को विस्तृत किया गया। प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट दूकान स्थापित की गई थी। शीतल यन्त्र योजना संचालित कर कमरों को तप्त एवम् शीतल करने की पूर्ण

व्यवस्था की गई। १९५५ तक व्यापार भाड़ा निम्नलिखित दर से बढ़ने का आयोजन हुआ :

यातायात-व्यापार वृद्धि

रेल यातायात	३०-४० प्रतिशत
नदी "	७५-८० "
समुद्री "	५५-६० "
मोटरगाड़ी "	८०-८५ "
वायु "	१०० "
पाइप लाइन "	४०० "

रेल यातायात में सर्व प्रथम कार्य उनकी क्षमता तथा शक्ति वृद्धि हेतु थी, जिसके लिये आवश्यक था कि :

(क) १९४६-१९५० की अपेक्षा दोहरी लाइने ६० प्रतिशत और विद्युत् रेल ३०० प्रतिशत निर्माण की जावें,

(ख) १९४६-१९५० की अपेक्षा नवीन रेल १५० प्रतिशत अधिक निर्माण की जावें ;

(ग) पाँच वर्षों में स्वतः अवरोध क्रिया (automatic blocking) में ८० प्रतिशत, स्वतः गतिरोध (autostop) में १५० प्रतिशत वृद्धि १९४६-१९५० की अपेक्षा होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त विद्युत् की पारस्परिक-संलग्न-रेल की पटरी को बदलने के यन्त्र की संख्या १३० प्रतिशत बढ़ायी जावे ;

(घ) पाँच वर्षों में १९४६-१९५० की अपेक्षा ८५ प्रतिशत अधिक कार्य क्षमता वृद्धि होनी चाहिये ;

(ङ) विद्युत् इंजन, डीजल इंजन, भाड़ा गाड़ी, शीतल यन्त्र संयुक्त गाड़ी तथा 'पैसन्जर' गाड़ी में आवश्यक वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया ।

नदी तटस्थ बन्दरगाहों (river port) की भाड़ा शक्ति को १०० प्रतिशत बढ़ाने का आयोजन किया गया । विशाल बन्दरगाहों पर सम्पूर्ण यान्त्रिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये । बाल्गा-बाल्तिक जल यातायात का पुनर्निर्माण, कामा नदी को यातायात योग्य बनाना, तथा अन्य अनेक स्थानों पर उचित सुविधायें प्रदान करने का आयोजन किया गया । विदेशी बन्दरगाह हेतु जहाज निर्माण तथा बन्दरगाहों पर पूर्ण यान्त्रिक प्रबन्ध आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया । मोटरगाड़ी तथा सड़क यातायात सम्बन्धी अनेक सुधार किये गये । टेलीफोन तथा तार की लम्बाई १०० प्रतिशत अधिक बढ़ा कर उन्हें सुव्यवस्थित किया

गया। डाकघर के अनेक कार्यों में अधिक क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया।

भौतिक जीवन निर्वाह, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक स्तर में सुधार करने का पूर्ण आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत :

(१) समाजवादी उद्योगों में उत्पादन वृद्धि होने के कारण सामान्य जीवन-स्तर पर अति लाभप्रद प्रभाव पड़ा ; तथा राष्ट्रीय आय वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या में लगभग १५ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन किया गया।

(२) उपभोग पदार्थों के मूल्य में ह्रास होना चाहिये। यथार्थ शारिर्श्रमिक में ३५ प्रतिशत वृद्धि केवल मूल्य ह्रास होने से ही सम्भव थी। अतः ऐसा आयोजित किया गया कि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा योजना में कम से कम ३० प्रतिशत आर्थिक हित अधिक प्रदान किये जावें।

(३) निवास स्थान में सुधार करने के दृष्टिकोण से नवीन गृहों का निर्माण तथा प्राचीन गृहों में समुचित सुविधायें प्रदान करने का आयोजन किया गया। गृह निर्माण में गत पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा १०० प्रतिशत अधिक पूँजी विनियोग का आयोजन किया गया। नगरपालिका तथा अन्य सेवा संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

(४) राज्य स्वास्थ्य सेवायें बढ़ाने हेतु अस्पताल, चिकित्सालय, 'सैनीटोरियम', 'किण्डरगार्टेन', 'क्रेश' (creche) आदि की संख्या बढ़ायी जावें। अस्पतालों में २० प्रतिशत अधिक विस्तर, 'सैनीटोरियम' में १५ प्रतिशत, विश्रामगृहों में ३० प्रतिशत, 'क्रेश' में २० प्रतिशत तथा 'किण्डरगार्टेन' में ४० प्रतिशत अधिक अवस्थान का प्रबन्ध किया गया।

(५) अनेक नगरों में सप्तवर्षीय माध्यमिक शिक्षा को दशमवर्षीय विश्व-विद्यालय शिक्षा में परिणित करने का पूर्ण प्रबन्ध किया गया, ताकि सम्पूर्ण देश में अत्यधिक संख्या में केवल माध्यमिक शिक्षा ही न प्राप्त हो, बल्कि विश्वविद्यालय में भी उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके। अधिक से अधिक संख्या में स्कूल कालेज, तथा विश्वविद्यालय संचालन के लक्ष्य निश्चित किये गये।

(६) विशिष्ट शिक्षा की ओर भी योजना में विशेष ध्यान दिया गया। ३०-३५ प्रतिशत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को व्यवसाय के किसे। मुख्य अङ्ग में प्रवीण करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। रिसर्च तथा विश्वविद्यालय में विशिष्टता तथा शस्त्र के मुख्य अङ्गों के अध्ययन पर अधिक महत्त्व दिया गया।

(७) कालेज तथा स्कूल के अतिरिक्त श्रमिकों में विशिष्टता बनाने के उद्देश्य

से 'दल प्रशिक्षण' (team-training) तथा 'राज्य श्रम संचित प्रथा' (state labour reserve system) को प्रोत्साहित करने हेतु पूर्ण आयोजन किया गया।

(८) सिनेमा तथा टेलीविजन में प्रगति हुई। सिनेमा-गृहों की संख्या लगभग २५ प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य किया गया, और अधिक स्वच्छ फिल्मों के निर्माण की ओर भी सरकार का विशेष ध्यान गया।

योजना का सफलता : पूर्ण फलीभूत होकर प्रस्तुत योजना ने भी विश्व के समस्त एक अद्भुत, प्रवैगिक तथा प्रगतिशील दृश्य प्रदर्शित किया है। इसकी प्रगति प्रशंसनीय थी। सम्पूर्ण विश्व रूस की आश्चर्यजनक समाजवाद प्रगति देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ। पूँजीवाद देशों में से किसी ने भी इतनी प्रभावशाली प्रगति कहीं नहीं की थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के समय भी इस गति से उन्नति न हो पायी थी। रूस का समाजवाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूँजीवाद पर उत्तरोत्तर उच्चता की छाप लगा रहा था और इस योजना के सफल होने के उपरान्त रूस की उच्चता सर्व-मान्य समझी गई। इस योजना द्वारा रूस ने सर्वोत्तम उन्नति की। सम्पूर्ण क्षेत्रों में कार्य क्षमता में वृद्धि हुई तथा केवल उत्पादन में ही प्रगति न हुई, बल्कि समाजवादी रूस के पग इतने दृढ़ हो गये थे कि साम्यवाद पथ पर वह अत्यन्त तत्परतायुक्त अप्रसर था। फलस्वरूप साम्यवाद निर्माण की ओर सोवियट संघ अधिक उत्सुकता से प्रवीण होकर समाजवाद के बृहत् कार्य में संलग्न हो गया था। सम्पूर्ण क्षेत्र, कृषि, उद्योग तथा फुटकर व्यापार, सरकार द्वारा स्वामित्व तथा संचालित थे और इस प्रकार समाजवाद प्रबलतापूर्वक स्थापित हो गया था। निम्नलिखित सारणी से यह स्पष्ट है कि १९५० तक लगभग सब ही क्षेत्रों में समाजवाद स्थापित हो चुका था और इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि अग्रिम पाँच वर्षों में उनमें गुणात्मक सुधार अवश्य हुये होंगे। समाजवाद संस्थापना तो १९२८ अथवा १९३७ तक भली-भाँति हो चुकी थी। गत वर्षों में जो समाजवादी विशाल गृह-निर्माण किया गया था, पाँचवीं योजना के अन्तर्गत उसमें अनेक गुणात्मक सुधार किये गये।

रूस की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में समाजवाद

(प्रतिशत में)

पद	१९५०	१९५४	१९५५
राष्ट्रीय आय	६६.८	६६.६८	६६.६६
उद्योग-उत्पादन	१००.००	१००.००	१००.००
कृषि-उत्पादन	६८.१०	६६.८७	६६.७८
फुटकर व्यापार	१००.००	१००.००	१००.००

रूस की राष्ट्रीय आय १९५५ में ९६.९९ प्रतिशत समाजवादी क्षेत्र से उपलब्ध थी। स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का कोई स्थान शेष न रह गया था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि १९५०-१९५१ में १२ प्रतिशत, १९५२ तक २५ प्रतिशत, १९५३ तक ३६ प्रतिशत, १९५४ तक ५३ प्रतिशत तथा १९५५ तक ६८ प्रतिशत हुई। औद्योगिक उत्पादन में भी १९५० की अपेक्षा १९५१ में १६ प्रतिशत, १९५२ तक ३० प्रतिशत, १९५३ तक ४५ प्रतिशत, १९५४ तक ६५ प्रतिशत तथा १९५५ तक ८५ प्रतिशत वृद्धि हुई। भारी उद्योगों में प्रगति अधिक प्रभावशाली थी। १९५० की अपेक्षा १९५१ तक १७ प्रतिशत, १९५२ तक ३१ प्रतिशत, १९५३ तक ४६ प्रतिशत, १९५४ तक ६० प्रतिशत तथा १९५५ तक ६१ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९५० की अपेक्षा १९५५ में उपभोग पदार्थों में उत्पादन ७६ प्रतिशत अधिक हुआ। भारी उद्योगों में भी उत्पादन वृद्धि ८६ प्रतिशत हुई। सम्पूर्ण यातायात साधनों

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रगति के मूल सूचकांक^१

(१९५०-१९५५)

पद	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
फैक्टरी एवम् दफ्तरों में श्रमिकों की संख्या...	१००	१०५	१०९	११२	१२२	१२४
सम्पूर्ण मूल उत्पादन सुविधायें...	१००	११०	१२१	१३३	१४७	१६४
राष्ट्रीय आय...	१००	११२	१२५	१३६	१५३	१६८
सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पत्ति जिसमें :	१००	११६	१३०	१४५	१६५	१८५
भारी उद्योग में उत्पादन...	१००	११७	१३१	१४६	१६६	१९१
उपभोग पदार्थ उद्योग में उत्पादन...	१००	११६	१२८	१४४	१६३	१७६
विशाल उद्योगों में उत्पादन	१००	११७	१३१	१४८	१६८	१८९
सम्पूर्ण यातायात व्यापार.	१००	११२	१२३	१३२	१४४	१६३
रेलगाड़ी द्वारा यातायात.	१००	११२	१२३	१३२	१४०	१६१
सम्पूर्ण पूँजी निर्माण...	१००	११२	१२५	१३१	१५४	१८५

में भाड़ा व्यापार ६३ प्रतिशत अधिक हुआ। रेलगाड़ी द्वारा व्यापार में ६१ प्रतिशत वृद्धि हुई। पूँजी विनियोग भी १९५० की अपेक्षा १९५१ में १२ प्रतिशत, १९५२ तक २५ प्रतिशत, १९५३ तक ३१ प्रतिशत, १९५४ तक ५४ प्रतिशत तथा १९५५ तक ६५ प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले पृष्ठ में दी गई सूची इस प्रगति को विस्तारपूर्वक प्रदर्शित करती है।

१९५० की अपेक्षा १९५५ में औद्योगिक श्रम उत्पादन लगभग ४४ प्रतिशत अधिक था। १९५१ में १० प्रतिशत, १९५२ तक १७ प्रतिशत, १९५३ तक २५ प्रतिशत, १९५४ तक ३३ प्रतिशत, और १९५५ तक ४४ प्रतिशत वृद्धि हुई। निर्माण उद्योगों में भी लगभग इसी गति से श्रम-उत्पादकता बढ़ी। रेल याता-यात में अवश्य इतनी अधिक वृद्धि न हुई। पर जितनी भी उन्नति हुई, अत्यन्त आश्चर्यजनक है। निम्नलिखित सारणी से कथित वृद्धि का समर्थन किया जा सकता है :

श्रम-उत्पादकता में वृद्धि^१

(१९५०=१००)

वर्ष	(उद्योगों में)	(निर्माण में)	(रेल में)
१९५०	१००	१००	१००
१९५१	११०	११०	१०६
१९५२	११७	११७	११३
१९५३	१२५	१२२	१२०
१९५४	१३३	१३२	१२४
१९५५	१४४	१४५	१३६

विविध प्रकार के औद्योगिक उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जैसा उपर्युक्त कहा जा चुका है, सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन में ८१ प्रतिशत वृद्धि हुई। भारी उद्योगों में ८१ प्रतिशत, उपभोग सामग्री में ७६ प्रतिशत, लोहा ७४ प्रतिशत, इस्पात ६६ प्रतिशत, कोयला ५० प्रतिशत, तेल ८७ प्रतिशत, शक्ति ८७ प्रतिशत तथा खनिज-खाद में ७५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुई। सब से अधिक वृद्धि मशीन निर्माण तथा सीमेंट के उद्योग में १२१ प्रतिशत थी। उपभोग सामग्री

१५८]

[सोवियट रूस का आर्थिक विकास]

में सबसे अधिक वृद्धि रेशम तथा घड़ियों के उद्योगों में हुई। निम्नलिखित तालिका औद्योगिक वृद्धि की विस्तार पूर्वक विवेचना करती है :

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि^१

पद	(१९५०=१००)
उद्योगों में सम्पूर्ण उत्पादन	१८५
भारी उद्योग में उत्पादन	१९१
उपभोग सामग्री में उत्पादन	१७६
कच्चा लोहा	१७४
इस्पात	१६६
रोल्ड-धातु	१६६
कोयला	१५०
तेल	१८७
शक्ति	१८७
खनिज-खाद	१७५
मशीन निर्माण तथा धातु सम्बन्धी कार्यों में उत्पादन...	२२१
सीमेन्ट	२२१
सूती वस्त्र	१५१
रेशम	४०५
घड़ियाँ	२६०
मक्खन	१५६
वनस्पति तेल	४१
बेंत की सामग्री	२१०
दानेदार चीनी	१३६

लोहे, इस्पात तथा अन्य धातुओं में उत्पादन, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित किया जा चुका है, क्रमशः ७४, ६६ तथा ६६ प्रतिशत बढ़ा था। वास्तविक परिमाण में उत्पादन वृद्धि अधोलिखित है :

वर्ष	लोहा (दस लाख टन)	इस्पात (दस लाख टन)	अलौहमय धातु (दस लाख टन)	काँचला (दस लाख टन)	तेल (दस लाख टन)	शक्ति (हजार कि० वा०)
१९५१	२१'६	३१'४	२४'०	२८१'६	४२'३	१३'७
१९५२	२५'१	३४'५	२६'८	३००'६	४७'३	१४'६
१९५३	२७'४	३८'१	२९'४	३२०'४	५२'८	१६'२
१९५४	३०'०	४१'४	३२'१	३४७'१	५९'३	१८'६
१९५५	३३'३	४५'३	३५'३	३६१'०	७०'८	२३'१

ट्रैक्टर निर्माण की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई। १९५१ में ६१.८ हजार, १९५२ में ६६ हजार के लगभग, १९५३ में १११, १९५४ में १३५ तथा १९५५ में १६३ हजार से अधिक ट्रैक्टर निर्माण किये गये।

दुग्धशाला पदार्थों में भी उत्पादन वृद्धि आई। १९५० की अपेक्षा १९५१ में मांस का उत्पादन अवश्य कुछ कम था (४ प्रतिशत) परन्तु १९५२ में ६ प्रतिशत अधिक, १९५३ में २० प्रतिशत, १९५४ में २९ प्रतिशत और १९५५ में ३० प्रतिशत अधिक हुआ। इसी प्रकार दूध तथा अण्डे के उत्पादन में भी १९ तथा ५४ प्रतिशत क्रमशः वृद्धि हुई जो निम्नलिखित सारणी से प्रतीत होती है :

पशु-पालन पदार्थ का उत्पादन^१

पद	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
मांस	१००	६६	१०६	१२०	१२६	१३०
दूध	१००	१०२	१०१	१०३	१०८	११६
ऊन (भेंड़ से)	१००	११७	१२२	१३०	१२८	१४२
अण्डे	१००	११३	१२३	१३७	१४७	१५१

खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थ का उत्पादन भी १९५०-१९५५ में अधिक मात्रा में बढ़ा। इसमें लक्ष्य से अधिक सफलता तथा पूर्णता प्राप्त हुई और विशेषकर कच्चे पदार्थ के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। औसत सम्पूर्ण अन्न उत्पादन १९५५ में १९५० की अपेक्षा केवल २६ प्रतिशत अधिक था। कपास की उत्पत्ति अधिक न हो पाई थी। निम्नलिखित सांख्यिकी इस वास्तविकता को सिद्ध करती है :

खाद्यान्न तथा कच्ची सामग्री का उत्पादन

पद	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
खाद्यान्न...	१००	६७	११३	१०१	१०५	१२६
जिसमें :						
गेहूँ...	१००	१०४	१४१	१३१	१३६	१५१
ज्वार...	१००	७२	८८	५६	५६	२०१
सूर्यमुखी बीज...	१००	६७	१२३	१४६	१०६	२०७
चुकन्दर...	१००	११४	१०७	१११	६५	१४७
कपास...	१००	१०५	१०६	१०८	११८	१०६
सन-सूत्र...	१००	७६	८३	७४	८५	१४६

यातायात साधनों में भी अधिक प्रगति हुई। १९५० में १९१३ की अपेक्षा सम्पूर्ण यातायात भाड़ा में ६२ गुना वृद्धि हुई। १९५४ में यह उन्नति ८६ गुना हो गई जो १९५५ में १०३ गुना हुई। रेल यातायात में सापेक्ष अनुपात और अधिक था। १९५० में वृद्धि १९१३ की अपेक्षा ६२ गुना, १९५४ में १३ गुना और १९५५ में १४.८ गुना हो गई। मोटरगाड़ी यातायात रूस का इतना अधिक पिछड़ा क्षेत्र था, कि जो थोड़ी प्रगति हुई वह भी अधिक परिणाम में प्रतीत हुई। निम्नलिखित सारणी से यह गति स्पष्ट है :

सम्पूर्ण यातायात भाड़ा वृद्धि^१
(१९१३-१९६०)

वर्ष	सम्पूर्ण याता- यात साधन	रेलवे	जल	मोटरगाड़ी	पाइपलाइन
१९१३	१००	१००	१००	१०	१.०
१९२८	१०४	१४२	५२	२ गुना	२.१ गुना
१९४०	४.३ गुना	६.३ गुना	१२३	८६ गुना	१२ गुना
१९५०	६.२ गुना	६.२ गुना	१७७	२०.१ गुना	१६ गुना
१९५४	८ गुना	१.३ गुना	२४६	३७.५ गुना	३२ गुना
१९५५	१०.२ गुना	१४.८ गुना	२८२	४०.५ गुना	४४ गुना

१९५५-५६ में लगभग ५०० लाख शिक्षार्थी थे, जिनमें से ३५० लाख प्रारम्भिक एवम् सप्तवर्षीय माध्यमिक शिक्षा तथा शिल्पकला में विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सिनेमा तथा टेलीविजन के स्टेशनों में भी अत्यधिक निर्माण तथा प्रगति हुई। योजना सर्वदिश सकल रही। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हुये, जिनकी सफलता से सोवियट रूस स्वतः अत्यधिक प्रबल एवम् शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। भारी उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ता पदार्थ के उद्योग में भी प्रभावशाली उन्नति होने के कारण सोवियट संघ ने यह संकल्प किया कि अग्रिम योजना में इसी दिशा की ओर अधिक ध्यान दिया जावेगा ताकि दीर्घ कालीन साम्यवाद स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु समुचित आयोजन किया जा सके। अग्रिम सोवियट नियोजन का सामान्य उद्देश्य समाजवाद को साम्यवाद में परिवर्तित करना लक्षित किया गया है।

चौदहवाँ अध्याय

छठी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६०) तथा सप्तवर्षीय योजना (१९५६-१९६५)

छठी पंचवर्षीय योजना

पाँचवी योजना के पूर्णतः सफल होने पर सोवियट रूस की आर्थिक अवस्था अत्यधिक सबल हो गई; समाजवादी व्यवस्था अधिक सुसंगठित हो गयी; भौतिक तथा सांस्कृतिक स्तर उच्च प्रतीत होने लगा एवम् सोवियट संघ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रभावशाली एवम् शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाने लगा, जहाँ समाजवाद स्थिर एवम् ठोस शिला सदृश प्रतीत होता था। भारी उद्योगों की उत्पत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने से सोवियट संघ विश्व का औद्योगिक उत्पादन में द्वितीय तथा योरप का प्रथम देश हो गया। विशाल उत्पादन होने के कारण सोवियट संघ अब उपभोग उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दे सकता था, स्वतः जीवन स्तर में सुधार कर सकता था तथा साम्यवाद स्थापना पथ पर एक पग आगे बढ़ सकता था। उत्पत्ति साधनों की उन्नति तथा मशीन-निर्माण उद्योगों की उत्तरोत्तर वृद्धि से सोवियट संघ ने साम्यवाद स्थापना हेतु एक दृढ़ तथा प्रबल आधार स्थापित कर लिया था। अब यह सम्भव था कि अग्रिम योजना ऐसी निर्माण की जाये, जिसमें नागरिकों के जीवन-स्तर को उच्च करने हेतु तथा साम्यवाद के निकट पहुँचने के लक्ष्य को सोवियट राष्ट्र उचित एवम् यथेष्ट महत्त्व प्रदान कर सके।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना की भाँति छठी योजना का सामान्य उद्देश्य साम्यवाद निर्माण के अग्रभाग की ओर उन्नति करना था। इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक था कि प्रधानतानुसार निम्नलिखित क्षेत्रों पर आवश्यक ध्यान दिया जा सके^१ :

(क) भारी उद्योगों की उन्नति;

^१ Directives of the XX Congress of the C.P.S.U. For the Sixth Five Year Plan for the Development of the National Economy of the U.S.S.R. in 1956-1960.

- (ख) श्रम उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि;
- (ग) उद्योग में विशिष्टीकरण एवम् सहकारिता उन्नति;
- (घ) कृषि उत्पादन में तीव्र प्रगति; तथा
- (ङ) भौतिक एवम् सांस्कृतिक स्तर में प्रगति ।

औद्योगिक उत्पादन पाँच वर्षों में लगभग ६५ प्रतिशत बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उत्पत्ति साधनों के निर्माण में ७० प्रतिशत और उपभोग पदार्थों में ६० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि होने का आयोजन किया गया। छठी योजना में भी प्रधान स्थान उद्योग-धन्यों को दिया गया। पाँच वर्षों के अन्तर्गत भारी उद्योगों में निम्नलिखित प्रतिशतक वृद्धि उत्पन्न करने का आयोजन किया गया :

भारी उद्योगों में उत्पादन वृद्धि

पद	१९६० में वृद्धि (१९५५=१००)
इस्पात	१५१
कोयला	१५२
तेल	१९१
गैस	३८८
विद्युत् शक्ति	१८८
खनिज-खाद	२०४
धातु-शोधन यन्त्र	१६३
रसायनिक यन्त्र	१८४
तेल निकालने की मशीनें	२४८
वाष्प तथा गैस द्वारा संचालित इंजन	२५८
जल शक्ति द्वारा संचित इंजन	१७३
धातु काटने की मशीनें	१९१
छपाई के यन्त्र	१९१
मोटरगाड़ी	१४६
ट्रैक्टर	१९७
कृषि-यन्त्र	१६२
विद्युत् इंजन	२८४

(क) उपभोग पदार्थों के भी उत्पादन लक्ष्य निश्चित किये गये थे। रूसी वस्त्र उद्योग २३ प्रतिशत, ऊनी वस्त्र उद्योग ४५ प्रतिशत, लिनन ८२ प्रतिशत, रेशम उद्योग १०४ प्रतिशत, जूता ५३ प्रतिशत, घड़ी ७१ प्रतिशत, रेडियो तथा टेलीविजन १५५ प्रतिशत, शीतल यन्त्र ३२० प्रतिशत, सिलाई की मशीन १३५ प्रतिशत, मोटर साइकिल ६२ प्रतिशत, बाइसकिल ४७ प्रतिशत, दानेदार चीनी ९१ प्रतिशत, मांस ७८ प्रतिशत, मत्स्य ७८ प्रतिशत, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ ८६ प्रतिशत तथा वनस्पति तेल उद्योग में ६५ प्रतिशत की दर से उत्पादन बढ़ने का आयोजन किया गया।

(ख) प्रौद्योगिक (technical) एवम् उत्पादकता प्रगति हेतु यह आवश्यक था कि पंचवर्षीय योजना की उत्पादन क्रियाओं में यन्त्रीकरण तथा यन्त्रों के स्वयम् संचालन विधि की उत्तरोत्तर वृद्धि की जाये। सम्पूर्ण कार्यों में स्वचलन यन्त्रों का अति अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये।

(ग) सामाजिक श्रम की उत्पत्ति में वृद्धि, उत्पादन लागत में ह्रास, तथा उत्पादन पदार्थों में गुणात्मक सुधार, उत्पादन हेतु उद्योगों में अधिक से अधिक विशिष्टीकरण तथा प्रत्येक विभाग में पारस्परिक सहयोग का होना अत्यन्त-आवश्यक है। वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को मूलाधार मानकर सम्पूर्ण औद्योगिक संगठन को परिवर्तन करने का आयोजन किया गया।

(घ) कृषि में सस्य उत्पादन तथा पशुपालन उद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन १९६० में १८०० लाख टन पहुँचने का लक्ष्य

१९५५-१९६० में प्रतिशतक लक्ष्य-वृद्धि

पद	प्रतिशत (१९५०=१००)
कच्ची कपास	१५६
सन-सूत	१३५
चुकन्दर	१५४
आलू	१८५
अन्य सब्जी	२१८
मांस	२००
दूध	१९५
अण्डा	२५४
ऊन	१८२

निश्चित किया गया। उद्योग सम्बन्धी कच्चा पदार्थ, आलू तथा अन्य साग-सब्जी एवम् पशुपदार्थ का उत्पादन पाँच वर्षों में गत पृष्ठ में अंकित प्रतिशत में बढ़ने का आयोजन किया गया।

खेतों में यन्त्रों तथा ट्रैक्टरों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जावेगा। १९५६-१९६० में कृषि को १,६५० हजार विविध प्रकार के ट्रैक्टर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह निश्चित किया गया कि खेत पर विद्युत् प्रयोग अधिकता से किया जावेगा, कृषि पदार्थ के उठाने, लाने, पहुँचाने के अनेक कार्य यन्त्रों से ही किये जावेंगे तथा फसल काटने का भी पूर्ण प्रबन्ध यन्त्रों द्वारा होगा।

(ङ) यातायात तथा संवाद्वाहन क्षेत्र में भी लक्ष्य उच्च स्तर पर निर्धारित किये गये। उनका उद्देश्य था कि :

(१) जल, थल तथा वायु यातायात सेवाओं के औद्योगिक स्तर में सुधार होना चाहिये।

(२) रेल यातायात से विद्युत् वृद्धि परमाणु में उपलब्ध की जानी चाहिये, तथा

(३) प्रगतिशील एवम् नवीन वैज्ञानिक इंजनों का प्रयोग अधिकाधिक होना चाहिये।

१९५५ की अपेक्षा रेल यातायात में ४२ प्रतिशत वृद्धि उत्पन्न कर व्यापार १,३७,४००,००० लाख टन के स्तर पर पहुँचना चाहिये। विद्युत् इंजन तथा डीजल इंजन के अत्यधिक प्रयोग से सम्पूर्ण व्यापार का ४०-४५ प्रतिशत केवल रेल द्वारा ही प्राप्त होना चाहिये। ऐसा आयोजित किया गया कि पाँच वर्षों में १८६,००० 'पैसेन्जर' गाड़ियाँ तथा २५५,००० भाड़ा गाड़ियाँ निर्माण करने का लक्ष्य किया गया। गत पाँच वर्षों में योजना में जितनी विद्युत् लाइनें नियोजित की गई थीं, उनका ३.५ गुना अधिक प्रस्तुत योजना-निर्माण का लक्ष्य किया गया। वायु यातायात तथा पाइप लाइन रेल की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया।

इसके अतिरिक्त (१) पूँजी निर्माण तथा निर्माण उद्योग हेतु १९५६-१९६० में ६,६००,००० लाख रुबल (मूल्य जुलाई १, १९५५ के आधार पर) पूँजी विनियोग करने का आयोजन किया गया, जो कि ६७ प्रतिशत गत योजना की अपेक्षा अधिक था।

(२) श्रम उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करते हुये, योजना ने इस ओर भी विशेष ध्यान दिया, क्योंकि साम्यवाद में श्रम उत्पादकता उच्च-

कोटि की होनी चाहिये थी। १९५६-१९६० में श्रम उत्पादकता में वृद्धि निम्नलिखित आधार पर आयोजित की गई :

श्रम-उत्पादकता वृद्धि

उद्योग	५० प्रतिशत	से अधिक
निर्माण	५२	" " "
रेल यातायात	३४	" " "
समुद्री "	४०	" " "
नदी "	३०	" " "
राज्य कृषि	७०	" " "
सामूहिक कृषि	२००	" " "

कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी संगठनों में अनेक परिवर्तन करने की पूर्ण योजना की गयी थी जिसका अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

(३) भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन-स्तर को उच्च करने का भी लक्ष्य निश्चित किया गया। विभिन्न प्रकार का कार्यशाला आर्थिक सुविधायें प्रदान की जाने का पूर्ण आयोजन किया गया। सामाजिक बांसा तथा सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कल्याणकारा कार्य हेतु यथेष्ट व्यवस्था की गई। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वृद्धि व्यय का पूर्ण आयोजन किया और व्यय दर का बढ़ा दिया गया। साम्यवाद हेतु यह आवश्यक समझा गया कि उच्च जावन स्तर प्राप्त करने के लिये दिन प्रातादन उपभोग पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। विभिन्न उपभोग सामग्रियां के विक्रय में निश्चित लक्ष्यानुसार वृद्ध आयोजन किया गया जो निम्नलिखित है :

मांस उत्पादन ८५ प्रतिशत, मत्स्य ५६ प्रतिशत, मक्खन ५७ प्रतिशत, बनस्पति तेल ६० प्रतिशत, दूध तथा दुग्ध पदार्थ २.७ गुना, पनीर २.४ गुना, अण्डा २.६ गुना, चीनी ७० प्रतिशत, सूतों वस्त्र, ३० प्रतिशत, ऊनी वस्त्र उत्पादन दुगुना, रेशम दुगुना, लिनन ३.६ गुना, तैय्यार वस्त्र ६७ प्रतिशत, जूता ६५ प्रतिशत, फर्नीचर दुगुना, घड़ियाँ ७० प्रतिशत, बाइसकिल ४६ प्रतिशत, रेडियो २.२ गुना, टेलीविजन 'सेट' ५ गुना, शीतलयंत्र ४.७ गुना, यन्त्र शोधन यन्त्र ३.६ गुना तथा वर्सत्र शोधन यन्त्र ६ गुना।

पाँच वर्षों में कैन्टीन तथा डाइनिंग कमरों की संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये और सामाजिक भण्डार व्यवसाय द्वारा उत्पत्ति ७५ प्रतिशत बढ़ने

का आयोजन किया गया। निवास स्थानों को सुव्यवस्थित करने हेतु २०५० लाख वर्ग मील के ग्राम एवम् नगर में मोहल्ले स्थापित किये जावेंगे, जो पाँचवीं योजना के लक्ष्यों की अपेक्षा क्षेत्रफल में दुगुने थे। विभिन्न प्रकार से सांस्कृतिक प्रगति की ओर योजना में ध्यान दिया गया और उन्नतिशील एवम् प्रगतिशील रूस को सर्वोन्मुखी शक्तिशाली बनाने का आयोजन किया गया। गत योजना की अपेक्षा चिकित्सालयों में विस्तर की संख्या २.८ गुना अधिक, 'किन्डरगार्टन' में अवस्थान २.४ गुना अधिक तथा धाय-गृहों में भी २.४ गुना अधिक अवस्थान उत्पन्न करने का लक्ष्य किया गया।

पंचवर्षीय योजना का परित्याग

छठी पंचवर्षीय योजना १९५६ में प्रारम्भ हुई। इसके एक ही वर्षकार्यान्वित होने के उपरान्त अचानक सोवियट सरकार को यह पता चला कि नवीन धातुयें तथा खनिज सम्पत्ति का कई स्थानों पर अन्वेषण हुआ है। इस नवीन सम्पत्ति के सदुपयोग हेतु नवीन व्यवसाय, नवीन औद्योगिक केन्द्र तथा नवीन उद्योग-वन्धे संचालित किये गये, जिनको कोई स्थान छठी योजना में नहीं मिला था और न अब इस महान निर्माण कार्य को इस योजना में सम्मिलित ही किया जा सकता था। इनके पूर्णतः सदुपयोग हेतु कम से कम सात वर्ष लगेंगे और इसलिये सोवियट सरकार ने एक सप्तवर्षीय योजना को १९५६ से कार्यान्वित करने की घोषणा की, जिसमें अनुसंधान किये गये खनिज सम्पत्ति के शोषण का पूर्ण प्रबन्ध किया गया। एक सप्तवर्षीय योजना १९५६-१९६५ हेतु निर्माण की गई। पंचवर्षीय सिद्धान्त को अचानक तिलांजलि दे देने से विश्व के अनेक देशों को इस प्रवृत्ति से बड़ी शंका हुई और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस ने इस विषय पर विभिन्न मत प्रदान किये। जिस समय यह अन्वेषण हो रहा था तथा इस विषय पर गंभीरता पूर्वक परामर्श हो रहा था, छठी योजना के लगभग दो वर्ष पूर्ण हो चुके थे और तीसरा वर्ष (१९५८) कार्यशील था। इसमें भी सन्देह नहीं कि गत वर्षों में सोवियट रूस ने लोहे, तेल, कोयले तथा अन्य नवीन खनिज पदार्थों का अन्वेषण किया है, जिसका वास्तविक स्वरूप १९५७ में दृष्टिगोचर हुआ। सितम्बर २७, १९५७ में 'प्रवदा' के "प्रेरणात्मक अनुसंधान" ('Inspiring Prospects') नामक लेख में सप्तवर्षीय योजना की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की गई :

"गत वर्षों में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों के नवीन साधनों का अन्वेषण हुआ है।लोहे तथा औद्योगिक ईंधन आदि विशाल सम्पत्ति की खोज कुस्तनाई क्षेत्र (Kustanai) में हुई है। इसके अतिरिक्त एक विशाल

लोहे की खान का अन्वेषण कर्स्क (Kursk) प्रान्त में हुआ है जो यूक्रेन के औद्योगिक केन्द्र के निकट है। यूक्रेन प्रान्त के निकट टिटानियम (titanium) और ज़िरकोनियम (zirconium) खनिज, काजकस्तान (Kazakhstan) में टंगस्टन (tungsten) और मालेबडनम (molybdenum) की खाने, पूर्वी साइबेरिया तथा सुदूर पूर्व देशों में टिन की खाने, यूराल में अनेक अलौहमय धातुओं की खाने अणु सम्बन्धी धातु, कोयला, तेल, गैस, आदि की नयी सम्पत्ति तथा रसायनिक उद्योगों की नवीन सामग्रियाँ जिनका अभी गत वर्ष ही अन्वेषण हुआ है, सोवियट भूमि की ऐसी निधि हैं जो कि भविष्य में उसकी महान सेवा करेंगी। इस नवीन अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति के आधार पर नवीन उद्योग तथा औद्योगिक एवम् व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण की शीघ्र ही सम्भावना की जाती है, जिसका कि छठी योजना में कोई भी उल्लेख अथवा स्थान नहीं था। अवशेष तीन वर्षों में यह असम्भव है कि इस नवीन निर्माण कार्य को योजना में सम्मिलित किया जा सके। इस कार्य के कार्यान्वित हेतु पूर्ण पाँच-सात वर्षों की आवश्यकता है।”

अतः सोवियट सरकार ने घोषणा की कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सप्तवर्षीय योजना निश्चित की जावेगी, जो १९५६ से कार्यान्वित की गई। सोवियट संघ की पार्टी कांग्रेस की २१वीं बैठक में प्रस्तुत योजना के निश्चित लक्ष्यों को स्वीकार किया गया। सोवियट संघ के इस महान परिवर्तन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। आलोचकों ने सोवियट योजना के विरुद्ध तर्क करते हुये यह दोषारोपण किया कि सप्तवर्षीय योजना रूपी आडम्बर अपनी असफलता एवम् त्रुटियों का आवरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि १९५६ तथा १९५७ में उद्योग-धन्धे निश्चित वार्षिक लक्ष्य, जो छठी योजना में निर्धारित किये गये थे, अपूर्ण रहकर वास्तविकता से दूर थे। अनेक विशाल उद्योगों में निश्चित लक्ष्य पूर्ण न हुये थे और सोवियट सरकार को शंका होने लगी थी कि ‘शेष तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न हो कर उसकी विफलताओं को प्रदर्शित करते हुये सम्पूर्ण विश्व के समक्ष उसकी निन्दा करेंगे। इस अभिय आलोचना से बचने के लिये सोवियट सरकार ने सप्तवर्षीय योजना रूपी स्वांग रचा है।”

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में निर्धारित लक्ष्य अपूर्ण होने के कारण आलोचकों का यह अनुमान है कि सोवियट संघ को प्रतीत होने लगा था कि अभिसर तीन वर्षों में वह अपनी क्षति पूर्ण न कर सकेगा। एक आलोचक ने १९५५ (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पाँचवें वर्ष) को आधार मान कर निश्चित लक्ष्य तथा वास्तविक पूर्णता की तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला कि

छठी योजना की असफलतायें वृहताकार थीं, जिनके कारण यह आशंका थी कि पाँच वर्ष पश्चात् सोवियट रूस के सम्पूर्ण दोषों एवम् वृष्टियों को भली प्रकार प्रदर्शित करेंगी। इसी कारणवश सोवियट संघ ने शीघ्र ही नवीन खनिज सम्पत्ति साधनों का विडम्बना करके सप्तवर्षीय योजना द्वारा पंचवर्षीय योजना का स्थानापन्न कर दिया है और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी असफलताओं पर इस प्रकार आवरण डाल दिया है।

सोवियट संघ की २१ वीं पार्टी बैठक में जब सप्तवर्षीय योजना स्वीकार की गई, अनेक प्रकार से सोवियट संघ की प्रबलता, शक्ति तथा प्रगति का उल्लेख किया गया। औद्योगिक उत्पादन में सोवियट संघ का योग्य में प्रथम स्थान तथा विश्व में द्वितीय स्थान पहुँच गया है; १९१३ की अपेक्षा औद्योगिक उत्पत्ति ३६ गुना अधिक है जब कि भारी उद्योगों में वृद्धि ८३ गुना और यन्त्रकला एवम् धातु निर्माण उद्योगों में २४० गुना उन्नति हुई है। १९५८ में सोवियट संघ ने लगभग ४५० लाख टन इस्पात, ११३० लाख टन तेल, ४९६० लाख टन कोयला तथा २३३० हजार लाख किलोवाट विद्युत् शक्ति का निर्माण किया है। इस प्रकार सोवियट संघ की प्रगति को प्रदर्शित करते हुए नवीन योजना स्वीकार की गयी है। उपभोग पदार्थों के उत्पादन में भी १९१३ की अपेक्षा १९५८ में उत्पादन १४ गुना तथा १९४० की अपेक्षा ४.७ गुना अधिक था। १९५८ में श्रम उत्पादकता १९१३ की अपेक्षा १० गुना, तथा १९४० की अपेक्षा २.६ गुना अधिक थी, यद्यपि कार्य-अवधि कमकर दिये गये थे। १९५८ में अन्न उत्पादन ३५,००० लाख 'पूड्स' था, जो कि १९५३ की अपेक्षा १६,००० लाख अधिक था। राष्ट्रीय आय १९४० की अपेक्षा १५ गुना अधिक थी। श्रमिकों का वास्तविक पारिश्रमिक १९४० की अपेक्षा दुगुना हो गया था। सामाजिक बीमा तथा सुरक्षा हितों के अन्तर्गत बड़ी राशि में श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जीवन-स्तर में अवश्य सुधार हो रहा था। १९५६ तथा १९५७ में निरपेक्ष उत्पादन सम्बन्धी सांख्यिकी अनुपलब्ध होने के कारण योग्य के आलोचकगण यह शंका करने लगे थे कि सम्भवतः लक्ष्यानुसार उत्पत्ति नहीं हुई। अतः छठी पंचवर्षीय योजना पर उन्होंने असफलता का कलंक लगाते हुये सोवियट रूस के गोपनीय विभाग की घोर निन्दा की है।

१९५७ की दशा

१९५७ में जो सांख्यिकी प्राप्त हुई है उससे यही प्रतीत होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो आदेश-निर्देश वार्षिक योजना के रूप में निश्चित किये गये थे, अनेक क्षेत्रों में अपूर्ण रहे। नवीन आर्थिक संगठन जिस पर सोवियट

सरकार की आशा निर्भर थी, रिपोर्ट के अनुसार कोई महत्त्वपूर्ण सुधार उस वर्ष न कर सकी। गासप्लान' के अध्यक्ष बैबाकोव (Baibakov) ने जनवरी १९५८ में उल्लेख किया कि गत वर्ष (१९५७) के अन्तिम महीनों में कुछ व्यवसाय लक्ष्यानुसार यथेष्ट सफलता प्राप्त न कर सके हैं, जब कि अनेक आर्थिक समितियों ने यद्यपि पारिमाणिक लक्ष्य पूर्ण कर लिया है, फिर भी विशुद्ध एवम् गुणी पदार्थों के उत्पादन से वंचित रह गये हैं।

छठी पंच वर्षीय योजना (जैसा कि प्रत्येक योजना के अन्तर्गत होता आया है) पाँच वार्षिक योजनाओं को सम्मिलित कर निर्माण की गई थी, जिसकी प्रथम तीन वार्षिक योजनायें कार्यान्वित थीं, परन्तु अन्तिम दो वार्षिक योजनाओं को सप्तवर्षीय योजना में संयुक्त करने का आयोजन किया गया

निर्वाचित पदों के आयोजित एवम् वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन^१

(१९५७-१९५८)

पद	१९५७ के मौलिक लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (१९५७)	१९५८ के वास्तविक लक्ष्य	आयोजित लक्ष्य (१९५८)
कच्चा लोहा (दस लाख टन)	४१.१	३८.१	३७.०	३९.१
इस्पात (दस लाख टन)	५४.५	५१.५	५१.०	५३.६
रोल्ड-धातु (दस लाख टन)	४२.३	६.५३	४०.२	४१.७
कोयला (दस लाख टन)	४७२.३	४४६.२	४६३.०	५८९.०
मिट्टी का तेल (दस लाख टन)	९६.४	९७.०	९८.३	१११.८
सीमेन्ट (दस लाख टन)	३५.५	२८.५	२८.९	३३.३
विद्युत शक्ति (दस खरब किलो- वाट घण्टा ...)	२३२.२	२११.२	२०९.५	२३१.०
गैस (दस खरब घन मीटर)	२२.४	२१.०	२०.२	३१.३
सूती वस्त्र (दस खरब मीटर)	६.५	५.५	५.६	५.६
ऊनी सूत (दस खरब मीटर)	२९६.०	२७८.०	२८२.०	२८९.४
जूते (दस लाख जोड़े)	३३८.०	३०९.४	३१५.०	३४२.२
चीनी (दस लाख टन)	४.७	४.८	४.५	५.३

१ Pravda : Feb 26, 1956; Feb, 6; Dec. 20, 1957; January 27, 1958.

था। यह वार्षिक योजना प्रत्येक वर्ष सफल होनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा अनुमान लगाया गया था कि प्रथम तीन वर्षों में सम्भवतः ये पूर्णतः सफल न हुई। १९५७ तथा १९५८ के लक्ष्यों का पुनरीक्षण एवम् संशोधन किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक उद्योग में जो लक्ष्य उच्च निर्धारित किये गये थे, उनको निम्न किया गया।

लोहा जिसका मौलिक लक्ष्य ४११ लाख टन था, घटा कर ३८१ लाख टन कर दिया गया। वह भी पूर्णतः सफल न हो पाया। १९५७ में उत्पादन ३७० लाख टन था। इस्पात उत्पादन का मौलिक लक्ष्य ५४५ था जो घटा कर ५१५ किया गया; फिर भी वास्तविक उत्पादन केवल ५१० लाख टन था। कोयला उत्पादन का मौलिक लक्ष्य जो ४७२३-लाख टन था, घटा कर ४४६२ लाख टन किया गया जब कि वास्तविक उत्पादन केवल ४६३० लाख टन था। इसी प्रकार चीनी का मौलिक लक्ष्य १६५७ हेतु ४७ लाख टन से बढ़ा कर ४८ किया गया था, परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल ४५ लाख टन से अधिक न था। इसी प्रकार १९५८ का आयोजित लक्ष्य जो गत पृष्ठ में दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं, मौलिक लक्ष्य नहीं हैं। वे ह्रास संशोधित लक्ष्य हैं और यह कहना दुष्कर है कि वे सम्पूर्णतः पूर्ण हो सके हैं।

निम्नलिखित तालिका से सोवियट औद्योगिक उत्पादन में १९५५-५७ की वार्षिक वृद्धि तथा १९५८ की आयोजित वृद्धि का लेखा किया गया है :

उत्पादन में वास्तविक तथा आयोजित वृद्धि
(१९५५-५८)^१

	वास्तविक वृद्धि			आयोजित वृद्धि
	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८
लोहा (दस लाख टन)	३.३	२.५	१.२	२.१
इस्पात (दस लाख टन)	३.६	३.३	२.४	२.६
रील्ड-धातु (दस लाख टन)	३.२	२.५	२.४	१.५

^१ The National Economy of the U.S.S.R. in 1956 : (A Statistical Year Book), Moscow, 1957, p. 62-91; Pravda, December 20, 1957, and January 27, 1958.

१७२]

[सोवियट रूस का आर्थिक विकास]

कोयला (दस लाख टन)	४३.६	२८.०	१६.८	२७.०
मिट्टी का तेल (दस लाख टन)	११.५	१३.०	१४.५	१३.५
सीमेन्ट (दस लाख टन)	३.५	२.४	४.०	४.८
विद्युत् शक्ति (दस खरब किलो-वाट घन्टा...	१६.५	२१.६	१७.५	२१.५
गैस (दस खरब घन मीटर)	०.३	३.३	६.५	११.३
सूती वस्त्र (दस खरब मीटर)	०.३	०.४	०.१	०.०२
ऊनी वस्त्र (दस लाख मीटर)	६.१	१५.४	१४.३	६.४
चमड़े के जूते (दस लाख जोड़े)...	१६.५	१५.५	२५.२	२७.२
चीनी (दस लाख टन)	०.८	०.६	०.४	०.७८

सोवियट संघ द्वारा प्रकाशित सूचनाओं से यह पता चलता है कि सोवियट उद्योगों का स्थान विश्व में द्वितीय तथा योरप में प्रथम है। निम्नलिखित तालिका इसकी पुष्टि करते हुये सोवियट औद्योगिक प्रधानता पर प्रकाश डालती है :

सोवियट उद्योगों का विश्व तथा योरप में स्थान

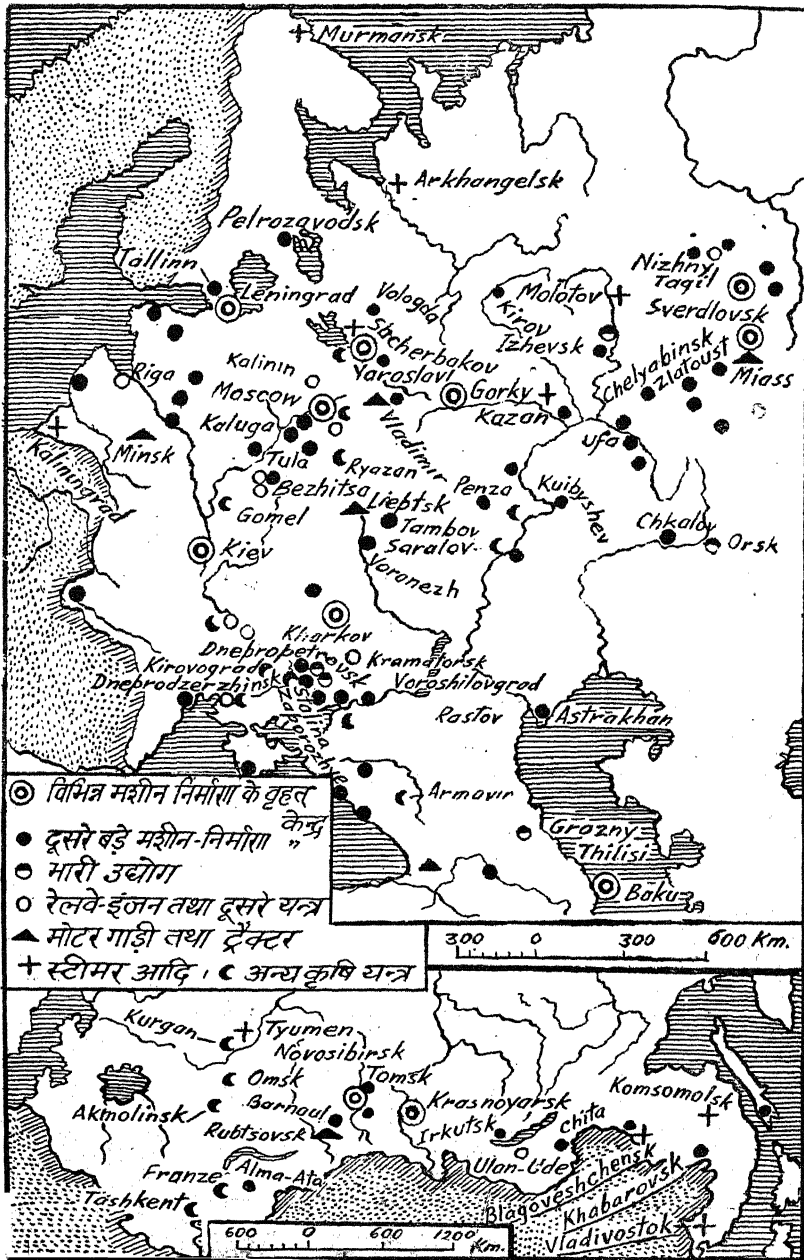
	१९१३		१९५८	
	विश्व उद्योग	योरप उद्योग	विश्व उद्योग	योरप उद्योग
औद्योगिक उत्पादन का परिमाण	५	४	५	१
इंजीनियरिंग	४	३	२	१
ट्रैक्टर	उत्पत्ति	शून्य	२	१
मोटर लारी तथा मोटर बस	”	”	२	१
विद्युत् शक्ति	८	६	२	१
कोयला	६	५	१	१
लोहा खनिज	५	४	१	१
कच्चा लोहा	५	४	२	१
इस्पात	५	४	२	१
सीमेन्ट	५	४	२	१
चीनी	४	२	२	१

यद्यपि योजनानुसार प्रगति न हुई तथापि १९५८ में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अवश्य हुई है तथा जो समंक प्रकाशित हुये हैं उनसे सापेक्ष एवम तुलनात्मक उन्नति का अध्ययन भी किया जा सकता है। १९१३ तथा १९५० से औद्योगिक प्रगति सम्बन्धी सापेक्ष सांख्यिकी उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ १९५८ में १९४१ की अपेक्षा लोहा, इस्पात, रोल्ड-धातु, कोयला, तथा तेल का उत्पादन २७, ३६, ३३, ३१ तथा ३६ लाख टन क्रमशः बढ़ा है तथा १९१३ की अपेक्षा प्रगति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :

१९५८ में मौलिक सामग्रियों का उत्पादन^१

सामग्री	इकाई-माप	१९५८ में उत्पादित की सापेक्ष वृद्धि		
		१९४०	१९१३	
कच्चा लोहा	दस लाख टन	३६.७	२.७	६.४
इस्पात	" " "	५४.६	३.६	१३.१
रोल्ड-धातु	" " "	४२.६	३.३	१२.३
कोयला	" " "	४९.६	३.०	१७.०
तेल	" " "	११३	३.६	१२.३
गैस	१००० दस लाख घ०मी०	२६.८	१८.८	१,७५६
विद्युत् शक्ति	१००० दस लाख कि०वा०	२३३	४.८	१२०
खनिज-खाद	दस लाख टन	१२.४	३.८	१८१
सलफरिक ऐसिड	" " "	४.८	३.०	४०
टर्बाइन	दस लाख कि० वा०	६.६	६.८	१,१२६
लोहा काटने की मशीन	हजार	१३८	२.५	६७
मोटरगाड़ी तथा लारी	"	५११	३.५	—
ट्रैक्टर	"	२२०	६.६	—
ट्रंक लाइन डीजल इंजन	इकाई	७१२	१४२	—
सीमेन्ट	दस लाख टन	३३.३	५.६	२१.६
विभिन्न प्रकार के सूत्र	१००० दस लाख मीटर	७.४	१.६७	२.६१
चमड़े के जूते	दस लाख जोड़े	३५६	१.६७	५.६
घड़ियाँ	दस लाख	२५	८.६	३५.४
चीनी	दस लाख टन	५.४	२.५	४

१. U.S.S.R. 1959 1965 (A Short Guide) : Soviet-Land Booklets ; New Delhi, 1959 pp. 4-5.



मशीन-निर्माण उद्योग

सोवियट रूस द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी के अनुसार १९५८ में औद्योगिक उत्पादन में १० प्रतिशत औसत दर से वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन १९१३ की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है। भारी उद्योगों में उत्पादन वृद्धि ८३ गुना तथा उपभोक्त पदार्थों में १३.७ गुना हुई है।

सम्पूर्ण औद्योगिक प्रगति
(१९१३=१)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योगों का कुल उत्पादन	उत्पत्ति साधनों का उत्पादन (श्रेणी अ)	उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन (श्रेणी ब)
१९२८	१३	१.७	१.२
१९४०	८.५	१५.५	५.०
१९५७	३३	७४.८	१३
१९५८	३६	८३	१३.७

यातायात एवम् संवादवाहन में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। यातायात लाइनों की लम्बाई-वृद्धि, सामान्य यातायात वाहन द्वारा सामग्री विक्रय, तथा संवादवाहन को प्रगति के मूल सूचक निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं :

यातायात पटरियों की लम्बाई-वृद्धि

पद	माप इकाई	१९१३	१९४०	१९५७
(१) रेलवे लाइनों की संचालित लम्बाई ..	हजार कि० मी०	५८.५	१०७.१	१२१.२
(२) अन्तर्देशीय जल यातायात लम्बाई...	"	४९.४	१०७.३	१३२.८
(३) मोटर-सड़क यातायात लम्बाई...	"	२४.३	१४३.४	२२५.७
(४) ट्रंक तेल पाइपलाइन	"	१.१	४.१	१३.२

सामान्य यातायात वाहन द्वारा सामग्री विक्रय
(१००० पुरुष कि० मी /टन में)

पद	१९१३	१९४०	१९५८
कुल यातायात साधन जिनके साथ :	११४.५	४७७.६	१,६०४.८
रेल द्वारा	६५.७	४५.०	१,३०२.०
समुद्र द्वारा	१६.६	२३.८	१०६.३
नदी द्वारा	२८.५	३६.१	८५.५
मोटरलारी द्वारा	०.१	८.६	७६.८

संवाद वाहन की प्रगति के मूल सूचकांक

पद	इकाई माप	१९१३	१९४०	१९५८
डाक, तार तथा टेलीफोन की संख्या...	हजार	८	५१	५८
जिनके साथ :				
ग्रामीण क्षेत्र	"	—	४४	४७
प्रेषित संदेश :				
पत्र	दस हजार	६१५	२,५८२	३,८८८
समाचार पत्र तथा पत्रिकायें	"	३५८	६,६६८	११,३५३
पार्सल	"	१०	४५	८२
तार	"	३६	१४१	२२७
मनीआर्डर	"	३५	६६	२८१
अन्तर-नगर टेलीफोन 'काल'	"	०.३	६२	१५२

उपर्युक्त सांख्यिकी से यह अत्यन्त अस्पष्ट है कि १९५७ की अपेक्षा १९५८ में प्रगति हुई है। आलोचकों का विचार है कि १९४० से तो अवश्य सोवियट रूस ने इस क्षेत्र में प्रगति की है, परन्तु १९५७-१९५८ में प्रगति स्तर क्या थी, स्पष्ट नहीं है, जिससे उनकी धारणा यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि के स्थान पर हास हुआ है और इस दुर्दशा को गुप्त रखने हेतु सप्तवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है।

सप्तवर्षीय योजना

सोवियट संघ की आर्थिक व्यवस्था की प्रगति हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य प्रत्येक क्षेत्र में पुनः वृद्धि उत्पन्न करना है, जिसमें भारी उद्योगों को प्रधानता देकर जनता का जीवन-स्तर उच्च बनाया जायेगा। इस योजना के सफल होने पर ऐसी आशा की गई कि साम्यवाद निर्माण हेतु एक भौतिक एवम् प्रौद्योगिक आधार स्थापित हो सकेगा और शीघ्र ही प्रति इकाई उत्पादन आय भी अमेरिका के समकक्ष पहुँच कर अतिक्रमण हो जायेगी। सोवियट संघ ने श्रमिकों की वास्तविक आय वृद्धि पर अधिक महत्त्व देकर जीवन-स्तर उच्च करने की योजना को उच्चता प्रदान की। यद्यपि भारी उद्योग-निर्माण को प्रधानता गत योजनाओं के समान इस योजना में भी दी गई है, फिर भी उपभोग पदार्थ, खाद्यान्न तथा आवश्यक निर्मित उपभोग सामग्रियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रस्तुत योजना की घोषणा, 'गुणात्मक सुधार' उत्पन्न करना है। ऐसा विश्वास किया गया है कि उत्पादन प्रति इकाई प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रतिशतक दर से बढ़ सकती है, यदि औद्योगिक व्यवस्था एवम् यातायात तथा कृषि संचालन रीतियों में सुधार करके उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। निम्नलिखित परिवर्तनों की ओर इस योजना का विशेष ध्यान है :

- (क) प्रगतिशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आवश्यक गुणात्मक सुधार;
- (ख) धातु पदार्थ एवम् अलौहमय धातुओं के उत्पादन में वृद्धि;
- (ग) रसायनिक पदार्थों के उत्पादन में सुधार;
- (घ) शक्ति सम्बन्धी तेल तथा गैस के उत्पादन में प्रधानता तथा अप-व्यय-परिहार;
- (ङ) विद्युत्-निर्माण शक्ति में तीव्र प्रगति;
- (च) विद्युत् पर अति अधिक रेल संचालन आधारित करना;
- (छ) कृषि उत्पादन तथा उसके संचालन में ऐसे सुधार, जो खद्यान्न एवम् कच्चा पदार्थ उत्पत्ति वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकें, तथा
- (ज) गृह-निर्माण में अत्यधिक वृद्धि।

इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि उद्योग-धन्वे ऐसे स्थान पर स्थापित किये जावें जहाँ ईंधन और शक्ति सस्ते मूल्य पर पर्याप्त हों। पूर्वी प्रदेशों में नवीन उद्योग-निर्माण सम्बन्धित निम्नलिखित योजना बनाई गई :

- (क) साइबेरिया और काजखस्तान (Kazakhstan) में जो लोहे का अन्वे-

षण हुआ है, उसके संशोधन हेतु एक शक्तिशाली नवीन धातु शोधन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

(ख) काजाकस्तान, मध्य एशिया, यूराल और ट्रान्स वैकल क्षेत्रों के अलौहमय धातु उद्योग में वृद्ध उत्पादन का आयोजन किया जायेगा।

(ग) साइबेरिया में गत वर्षों की अन्वेषित नवीन कोयले की खानों के आधार पर एक शक्तिशाली कोयला उद्योग स्थापित किया जायेगा।

(घ) वाल्गा तथा यूराल के मध्यवर्ती क्षेत्रों में तेल तथा गैस के उद्योगों में वृद्धि की जावेगी तथा उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) में गैस के उद्योग का एक नवीन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

(ङ) पूर्वी प्रदेशों में, जिसमें मध्य एशिया जनतंत्र राज्य मुख्य है, एक विशाल रसायनिक उद्योग का निर्माण किया जायेगा, तथा

(च) साइबेरिया और सुदूर पूर्व के अनेक जिलों में काष्ठ उद्योग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

पश्चिमी प्रदेशों की प्रगति की ओर भी योजना ने पूर्ण ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(क) दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में लोहा तथा इस्पात के उद्योग में वृद्धि हेतु यूक्रेन तथा 'कुर्स्क मैग्नेटिक एनामली' के लोहा खनिज (iron ore) साधनों का सदुपयोग किया जायेगा।

(ख) कोला द्वीप पर लोहे के अतिरिक्त अलौहमय धातु के उद्योग को बढ़ाया जायेगा।

(ग) उत्तरी काकेसस तथा यूक्रेन में लोहे तथा गैस के उद्योगों को तीव्र गति से प्रोत्साहित किया जायेगा।

(घ) रसायनिक उद्योगों की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जो तेल तथा गैस के उद्योगों की प्रगति के आधार हैं।

(ङ) बाल्टिक जनतंत्र राज्य के यूक्रेन, बाइलोरसिया आदि जिलों में कृषि योग्य भूमि का अधिकतम सदुपयोग किया जायेगा।

(च) पशुपालन उद्योग में अधिकाधिक उत्पादन एवम् खाद्यान्न उत्पत्ति में वृद्धि उत्पन्न करने की चेष्टा की जावेगी।

रूस की प्रस्तुत निर्माण योजना का प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक शक्ति में निरन्तर वृद्धि तथा आर्थिक उत्थान है। विशेष महत्त्व भारी उद्योग को पुनः दिया गया, क्योंकि सोवियट रूस का यह दृढ़ विश्वास है कि साम्यवाद निर्माण हेतु देश को प्रत्येक दृष्टिकोण से शक्तिशाली होना अत्यन्त आवश्यक है।

लक्ष्य : उपर्युक्त लिखित उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिये १९६५ में राष्ट्रीय आय ६२-६५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८० प्रतिशत, कृषि उत्पादन ६० प्रतिशत, श्रमिक संख्या २२ प्रतिशत, श्रमिकों को वास्तविक आय ४० प्रतिशत, तथा फुटकर व्यापार ६२ प्रतिशत वृद्धि-लक्ष्य निर्धारित किया गया। निम्न-लिखित तालिका विस्तारपूर्वक प्रस्तुत विषय पर सूचना प्रदर्शित करता है :

सप्तवर्षीय योजना अवधि में मौलिक आर्थिक सूचकांक

(१९६५ में १९५८ के प्रतिशत)

- (१) राष्ट्रीय आय—१६२-१६५
- (२) कुल औद्योगिक उत्पादन—१८०
- (३) कुल कृषि-उत्पादन—१७०
- (४) कुल विक्रय :
 - (क) रेलगाड़ी द्वारा—१२६-१४३
 - (ख) समुद्र द्वारा—१००
 - (ग) नदी द्वारा—१६०
 - (घ) मोटर द्वारा—१९०
- (५) फैक्टरी तथा दफ्तर के कर्मचारियों की संख्या—१२२
- (६) श्रम उत्पादकता :
 - (क) उद्योग—१४५-१५०
 - (ख) सामूहिक कृषि—२००
 - (ग) राज्य कृषि—१६०-१६५
 - (घ) निर्माण—१०-१६५
 - (ङ) रेल यातायात—१३४-१३७
- (७) जनता की वास्तविक आय—१४०
- (८) फुटकर व्यापार—१६२

सप्तवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि :

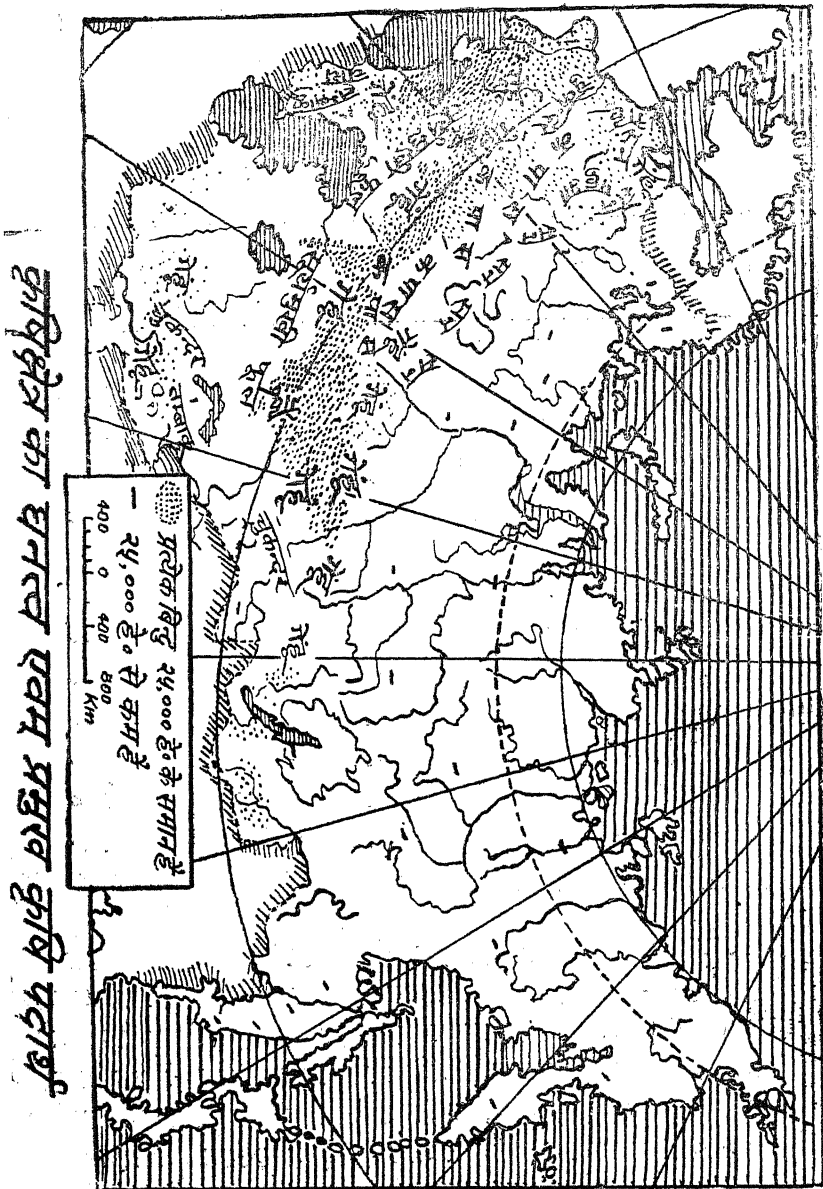
१९५८ = १००%	१९६५
कुल औद्योगिक उत्पादन	१८०
जिसके अन्तर्गत :	
उत्पत्ति-साधन उत्पादन	१८५-१८८
उपभोक्ता सामग्री उत्पादन	१६२-६५

वृद्धि आयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त फल, दूध, अण्डे, मांस तथा साग-सब्जी की उत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो अधोलिखित सारणा से स्पष्ट है :

कृषि उत्पत्ति में वृद्धि

सामग्री	माप इकाई	१९५८	१९६५	प्रतिशत वृद्धि (१९५८ = १००)
अन्न	१००० दसलाख			
	'मूड'...	८.५	१०-११	१२६
कच्ची कपास	१० लाख टन	४.४	५.७-६.१	१३६
चुकन्दर	"	५४.१	७६-८४	१५५
तिलहन	"	५.०	५.५	११०
सन	हजार टन	४४३.०	५८०	१३१
आलू	१० लाख टन	८६.१	१४७	१७०
फल-बेर आदि	—	—	—	२००
अंगूर	—	—	—	४००
मांस तथा चर्बी	१० लाख टन	७.६	१६	२०३
दूध	"	५७.८	१००-१०५	१८०
ऊन	हजार टन	३२१.०	५४८	१७०
अंडे	१००० दसलाख	२३.५	३७	१५७
साग सब्जी	१० लाख टन	१४.३	जनता की माँग के अनुसार	

योरप के प्रत्येक पूँजीवाद देशों की अपेक्षा १९६५ में सोवियट रूस की प्रति इकाई उत्पत्ति अधिक होने का आयोजन किया गया। सात वर्ष की अवधि में सोवियट रूस ने अनेक पदार्थों का पारिमाणिक उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष ही नहीं करन् उसको अतिक्रमण करके, विश्व में एक आदर्श-वादी एवम् प्रतिभाशाली राष्ट्र बनने का लक्ष्य किया है। प्रस्तुत योजना का मूल उद्देश्य १९६८-७० तक सोवियट संघ में प्रति इकाई औद्योगिक उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अधिक होना है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में यह एक अतुल्य एवम् अद्वितीय घटना होगी कि रूस एक पिछड़ा देश संयुक्त राष्ट्र



अमेरिका को जो आधुनिक युग में सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट है, अतिक्रमण कर जाये—यद्यपि विश्वास की पाराकृष्ठा से यह परे प्रतीत होता है ।

२१वीं काँग्रेस की बैठक में खुशचेव ने हृदयपूर्वक कहा : “प्रस्तुत सप्तवर्षीय योजना फलीभूत होने के उपरान्त, सोवियट संघ को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन के समकक्ष पहुँचकर, उससे अधिक प्रगति करने हेतु केवल पाँच वर्षों की और आवश्यकता होगी । तब वह विश्व में केवल पारमाण सम्बन्धी ही नहीं बरन् प्रति इकाई उत्पादन में भी प्रथम स्थान ग्रहण करेगा ।” सात वर्षों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि तीव्र गति से होगी । कुल उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि गति निम्नांकित है :

कुल उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि

(१९५६-१९ ५)

पद	प्रतिशत में
सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन	८.६
जिसमें :	
उत्पत्ति साधन	६.३
उपभोग पदार्थ	७.३

सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन ८.६ प्रतिशत वार्षिक गति से बढ़ेगा, जो गत दस वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्पादन वृद्धि की अपेक्षा चार गुना अधिक होगा । कृषि में भी औसत वार्षिक उत्पत्ति ८ प्रतिशत होगी, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दो प्रतिशत से कम वार्षिक प्रगति गत वर्षों में हुई है ।

प्रस्तुत योजना में भी भारी उद्योग को प्रधानता देकर सम्पूर्ण व्यय का ७० प्रतिशत विनियोग आयोजित किया गया है । अमेरिका की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ में उत्पादन वृद्धि कई गुना अधिक है और इस गति से सोवियट संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की समानता शीघ्राशीघ्र कर सकेगा । अगले पृष्ठ में दी गई तालिका से स्पष्ट है कि दोनों देशों में प्रगति दर अति अधिक असमान है और सोवियट रूस का उत्पादन लक्ष्य परिमाण भी असाधारण है ।

पद	माप-इकाई	१९५८	१९६५	१९५६-१९६५ में औसत वार्षिक उत्पत्ति	१९५३-१९५८ में सं० रा० आ० में औसत वार्षिक उत्पत्ति
कच्चा लोहा	दस लाख टन	३६.६	६५-७०	३.६	- ०.२
इस्पात	"	५४.६	८६-९१	४.४-५.१	- ०.७
रोल्ड-धातु	"	४२.६	६५-७०	३.२-३.६	
लोहा खनिज	"	८८.८	१५०-१६	८.७-१०.२	- ४.८

(- चिन्ह से तात्पर्य औसत वार्षिक उत्पत्ति में हास है)

१९२८ में कच्चे लोहे का उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा ६१.३ प्रतिशत तथा इस्पात का उत्पादन ६२ प्रतिशत कम था, जो ब्रिटेन अथवा जर्मनी का लगभग $\frac{१}{३}$ अथवा $\frac{१}{४}$ से अधिक न था। और आज वह ब्रिटेन, इटली तथा जर्मनी के सम्पूर्ण उत्पादन से अधिक है। १९६५ तक सोवियट संघ अनेक पदार्थों के उत्पादन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील एवम् शक्तिशाली राष्ट्र हो सकेगा। अलौहमय धातुओं (non-ferrous metal) का भी उत्पादन गई गुना बढ़ने का आयोजन किया गया, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा इस क्षेत्र में सोवियट संघ अब भी काफी पीछे रहेगा।

अलौहमय धातु के उत्पादन में वृद्धि आयोजन

पदार्थ	१९६५ में १९५८ की अपेक्षा
अलमोनियम	२.८—३.० गुना
ताँबा	१.६ गुना

यातायात क्षेत्र में लक्ष्य अधिक प्रभावशाली हैं। डीजल तथा विद्युत् द्वारा यातायात साधन संचालन करके लगभग ४,५०,००० लाख रुबल की मितव्ययता उत्पन्न करने का आयोजन किया गया है। प्रस्तुत सात वर्षों में वायुयान यात्रा में ६ गुना वृद्धि तथा मोटर बस द्वारा यात्रियों की संख्या में तिगुने से अधिक वृद्धि करने का प्रबन्ध किया गया है। अधिक संवादवाहन सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहिये। इन सात वर्षों में अन्तर्देशीय केबल लाइन दुगुनी, रेडियो लाइन ८.४ गुनी, 'टेलीविजन' स्टेशन में २.६ गुना तथा टेलीफोन विनिमय क्षमता में १.५ गुना वृद्धि होना निश्चित किया गया है।

अनेक कृषि पदार्थों में १९६५ तक सोवियट संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के केवल समकक्ष ही नहीं, किन्तु उससे अधिक उत्पादन करेगा। यही नहीं, प्रति एकड़ भूमि पर अधिक उत्पत्ति उपलब्ध करने का भी आयोजन किया गया है, जिससे जीवन-स्तर उच्च हो सके, जैसे :

सोवियट संघ तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कृषि उत्पादन
(प्रति १०० हैक्टेयर)

पदार्थ	सोवियट संघ १९६५	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका १९५७
अन्न	६२६-३६०	२८०
आलू	२६४	१६
चीनी	१८.५-२०.०	४.१
मांस	६२	२६
दूध	२००-२१०	१०१
ऊन	१.१	०.२

कृषि की दशा प्रत्येक दृष्टिकोण से सुधारने का आयोजन किया गया है। कृषि को अधिक ट्रैक्टर, अधिक विद्युत् शक्ति, अधिक खनिज खाद, तथा अन्य सुविधायें अत्यधिक मात्रा में प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया है, जो निम्न-लिखित सारणी से स्पष्ट है :

१९५९-१९६५ के अन्तर्गत कृषि में प्रौद्योगिक साधनों की उपलब्धि

(क) ट्रैक्टर	लगभग दस लाख से अधिक
(ख) अन्न-लवन-यन्त्र	लगभग चार " " "
(ग) सामूहिक कृषि में विद्युत् के प्रयोग का परिमाण	गत सात वर्षों से (१९५२-१९५८) २.५ गुना अधिक
(घ) वार्षिक खनिज खाद की प्राप्ति	तिगुनी
(ङ) विद्युत् उपभोग में वृद्धि	चौगुनी

प्रस्तुत सात वर्षों में सम्पूर्ण पूँजी विनियोग लगभग २००,००,००० लाख रुबल की जायेगी जो सोवियट शासन के निर्माण काल से आज तक सम्पूर्ण विनियोजित पूँजी से कुछ ही कम है। १९५२-१९५८ की अपेक्षा १९५९-१९६५

में पूँजी विनियोग वृद्धि निम्नलिखित प्रकार से आयोजित की गई है :

राजकीय पूँजी विनियोग

(१००० दस लाख रुबल सापेक्ष मूल्य में)

पद	१९५२-१९५८	१९५९-१९६५	वृद्धि प्रतिशत
औद्योगिक निर्माण हेतु	८२१	१४८८-१५१३	१८१-१८४
गृह निर्माण तथा जन कल्याण हेतु	२०८	३७५-३८०	१८०-१८३
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक निर्माण हेतु...	४३	७७	१७६
कुल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु	१०७२	१९४०-१९७०	१८१-१८४

पूँजी विनियोग में इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि पूर्वी प्रदेशों के प्राकृतिक साधनों का शोधन अधिकतम स्तर पर किया जाये। सम्पूर्ण पूँजी विनियोग का औसत ४० प्रतिशत इस कार्य में विनियोग किया जाने का आयोजन किया गया और यह आशा की गई कि औद्योगिक उत्पादन में पूर्वी क्षेत्रों के अंश में अग्रिम वर्षों में अत्यधिक प्रगति होगी।

औद्योगिक उत्पादन में पूर्वी क्षेत्रों के अंश में प्रगति

पद	१९६५ में पूर्वी क्षेत्रों का अंश
कच्चा लोहा	४४ प्रतिशत
इस्पात	५८ "
रोल्ड-धातु	४९ "
कोयला	५० "
मिट्टी का तेल	३० "
विद्युत्	४६ "
काष्ठ	४५ " से अधिक

१९६५ तक सोवियट श्रमिकों का श्रम उत्पादकता १९१७ की अपेक्षा १४.५-१५ गुना तथा १९४० की अपेक्षा ३.५-३.७ गुना अतिक्रमण होगा। सोवियट संघ ने उत्पादन तथा श्रम उत्पादकता में ब्रिटेन को यथेष्टतः पीछे कर दिया है; प्रस्तुत योजना में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष होने का तथा अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट होने का आयोजन किया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है

किं सात वर्षों के उपरान्त रेल यातायात में श्रम उत्पादकता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के श्रम उत्पादकता स्तर से अधिक उच्च होगा। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन लागत में लगभग ११.५ प्रतिशत, निर्माण कार्य लागत में छः प्रतिशत तथा रेल यातायात लागत में २२ प्रतिशत ह्रास होगा। सम्पूर्ण उत्पादन का $\frac{1}{3}$ भाग श्रम उत्पादकता वृद्धि पर आधारित था। इस कार्य हेतु अधिकाधिक विद्युत् प्रयोग, यान्त्रिक एवम् रसायनिक रीतियाँ, विशिष्टीकरण एवम् सहयोगिता तथा पूँजी विनियोग का दक्ष एवम् कार्यकुशल प्रयोग आदि साधनों द्वारा उच्चतर श्रम उत्पादकता निर्माण का आयोजन किया गया। अप-व्ययता पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे :

सप्तवर्षीय योजना में कुछ गुणात्मक परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव

पद	माप-इकाई	अपव्ययता (१९५५-१९६५)
(१) तेल तथा गैस के प्रतिपक्ष में ईंधन की प्रवृत्ति में परिवर्तन	१००० दसलाख रुबल	१२५
(२) विद्युत् एवम् डीजल में रेल	१००० दसलाख रुबल	४५
(३) निर्माणित थर्मल शक्ति स्टेशन की सापेक्ष वृद्धि	१००० दसलाख रुबल	२०
(४) 'केबिल' निर्माण में अलमोनियम तथा प्लास्टिक का प्रयोग	१००० दसलाख रुबल	१०
(५) नाइट्रिक खाद में प्राकृतिक गैस का प्रयोग	१००० दसलाख रुबल	४
(६) सिन्थेटिक रबर निर्माण में अलकोहल के स्थान पर 'केसिंग-हेड' गैस का प्रयोग	१००० दसलाख रुबल	१.३

अग्रिम सात वर्षों में सामान्य जीवन-स्तर भी तीव्र गति से सुधारने का पूर्ण आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आय ६२-६५ प्रतिशत, उपभोग ६०-६३ प्रतिशत, फुटकर व्यापार ६२ प्रतिशत तथा फैक्टरी तथा दफ्तर के श्रमिकों तथा कर्मचारियों की वास्तविक आय ४० प्रतिशत बढ़ाने का आयोजन किया गया। इसका पूर्ण विवरण अगले पृष्ठ में दी गई सारणी में उपलब्ध है :

जीवन-स्तर में सुधार सम्बन्धी सूचकांक
(१९५६-१९६५)

पद	तुलना योग्य काल	प्रतिशत वृद्धि
राष्ट्रीय आय	१९५८ की तुलना में १९६५ की अवस्था	६२-६५
उपभोग	" " "	६०-६३
फुटकर व्यापार	" " "	६२
फैक्टरी तथा दफ्तर के कर्मचारियों की वास्तविक आय...	" " "	४०
सामूहिक कृषकों की वास्तविक आय	" " "	४०
न्यूनतम पेन्शन 'वृद्धावस्था में'	१९५८ की तुलना में १९६६ की अवस्था	५०-७०
न्यूनतम पारिश्रमिक	१९५८ की तुलना में १९६५ की अवस्था	७१-८५
सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में वार्षिक व्यय...	" " "	६७
गृह निर्माण कार्य	१९५८-५८ की तुलना में १९५६-१९६५ की अवस्था	२.३ गुना

सोवियट सरकार ने यह घोषणा की कि कुछ वर्षों में सोवियट संघ में प्रत्येक सप्ताह तथा दिवस में कार्य घन्टे विश्व की अपेक्षा न्यूनतम रहेंगे, जिसका सामाजिक प्रभाव अत्यन्त हितकर होगा। प्रति सप्ताह काम करने की अवधि कम हो जाने से पारिश्रमिक में ह्रास न होगा, किन्तु सामान्य निम्न स्तर के श्रमिकों की भुक्ति में वृद्धि की जायेगी। सप्तावर्षीय योजना के अन्तर्गत कारखाने तथा दफ्तर के कर्मचारियों को न्यूनतम पारिश्रमिक २७०-३०० रुबल से ५००-६०० रुबल प्रति मास हो जाने का प्रबन्ध किया गया है। प्रस्तुत योजना में खाद्यान्न पदार्थों एवं उपभोग में वृद्धि होने का समुचित आयोजन किया गया है। उदाहरणार्थ वर्तमान काल में चीनी उपभोग २६ किलोग्राम प्रति पुरुष है, जो १९६५ में ४१-४४ किलोग्राम वैज्ञानिकों के मतानुसार निर्धारित किया गया है। आशा की गई है कि पर्याप्त मात्रा में वस्त्र तथा जूतों को भी उपलब्ध हो सकेगी तथा

१९६५ में विविध प्रकार के सूत्रों (fabrics) का निर्माण (११,००० दसलाख मीटर) अमेरिका के तुल्य होगा। प्रति पुरुष सूत्रों का उपभोग ५५ मीटर होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सोवियत संघ पूँजीवाद देशों की अपेक्षा गृह निर्माण कार्य अधिक कर रहा है और अग्रिम सात वर्षों में उसकी अवस्था अन्य देशों की अपेक्षा अति उत्तम हो जायेगी।

राजकीय स्वास्थ्य सेवा

पद	तुलनात्मक काल	प्रगति
राजकीय स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक सेवा, तथा चिकित्सा सम्बन्धी पूँजी विनियोग (२५,००० दस लाख रुबल)	१९५२-१९५८ की तुलना में १९५६-१९६५ की अवस्था	१.८ गुना
अतिरिक्त अस्पताल बिस्तरों की संख्या	"	दुगुना
अतिरिक्त 'किन्डरगार्टन' में अवस्थान	"	२.५ गुना
'किन्डरगार्टन' में बच्चों की व्यवस्था	"	१.८ गुना
औषधि उत्पादन	१९५८ की अपेक्षा १९६५ में	तिगुना
विटामिन उत्पादन	"	छः गुना
यन्त्र तथा साज-सामान	"	२-२.५ गुना

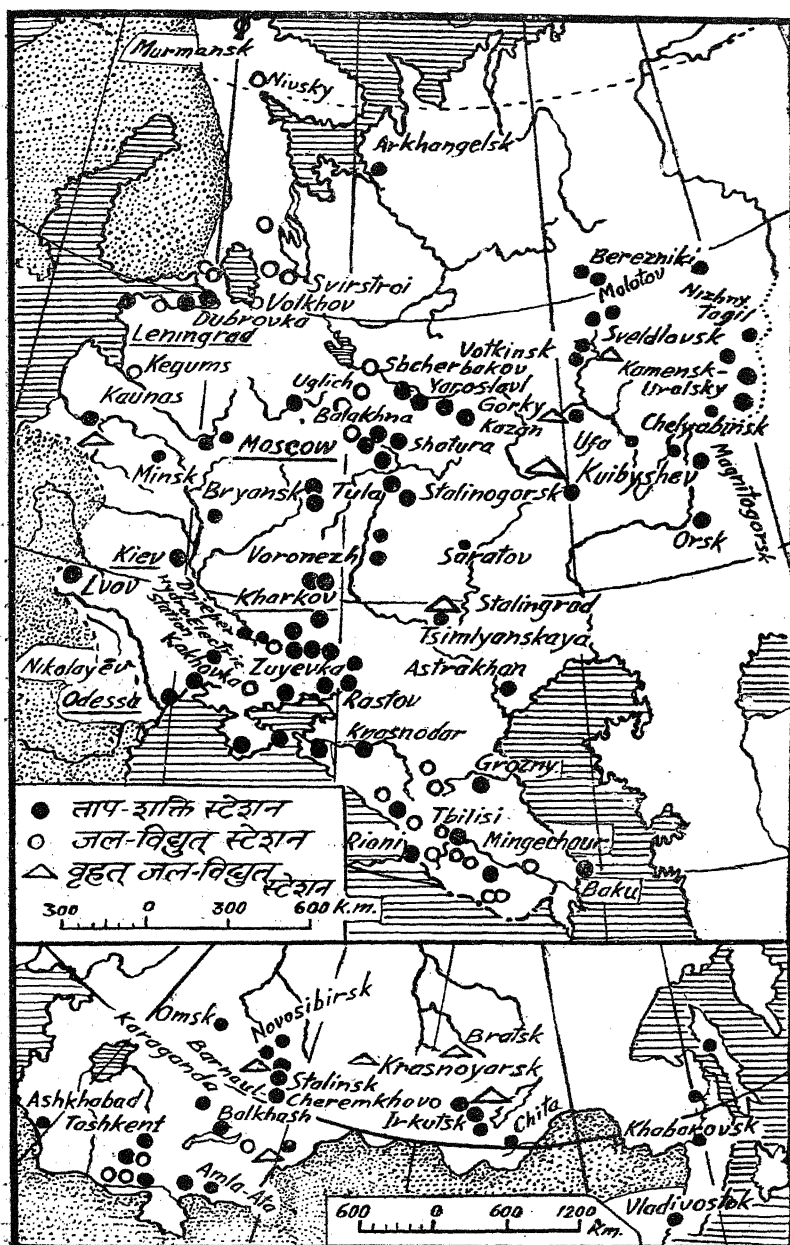
शिक्षा क्षेत्र में भी निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। १९५६-१९६५ में सात वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के स्थान पर आठवर्षीय शिक्षा का परिवर्तन-कार्य, दसवर्षीय स्कूल का सुसंगठन-कार्य, एवम् श्रमिक हेतु माध्यमिक उच्च शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया गया है। विशिष्ट एवम् शिल्प शिक्षा सम्बन्धी स्कूल, कालेज एवम् विश्वविद्यालयों के निर्माण एवम् पुनर्संगठन पर योजना ने पूर्ण ध्यान दिया है और इस क्षेत्र में प्रगति अति प्रशंसनीय है।

विशेषज्ञों की उच्च शिक्षा

पद	माप-इकाई	१९५२-१९५८	१९५९-१९६५	प्रगति
सम्पूर्ण विशेषज्ञों की संख्या	दस लाख	१.७	२.३	१.४ गुना
(क) उद्योग में	—	—	—	१.९ गुना
(ख) कृषि में	—	—	—	१.६ गुना

प्रस्तुत सप्तवर्षीय योजना दीर्घ कालीन पन्द्रह वर्षीय योजना का एक अंग है, जिसका अधिकांश १९५६-१९६५ में ही फलीभूत होने का आयोजन किया जाता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि अग्रिम पन्द्रह वर्षों में कुछ पदार्थों का उत्पादन दुगुने से अधिक और कुछ का तो तिगुना हो जावेगा। वर्तमान काल में सोवियट संघ का कुल उत्पादन परिमाण अमेरिका का ५३-५५ प्रतिशत है, जो १९६५ में अमेरिकन उत्पादन स्तर के समकक्ष हो जावेगा। कुछ पदार्थों में, जैसे लोहा खनिज, कोयला, सीमेन्ट, रसायनिक पदार्थ, मशीन, चीनी, दूध आदि, उत्पादन अमेरिका के कुल उत्पादन से अधिक होगा। पन्द्रह वर्षीय योजना का पूर्ण विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया हुआ है :

पद	माप-इकाई	१९७२ का उत्पादन-स्तर	१९५८ का स्तर	भौतिक वृद्धि १९५६-१९७०	भौतिक वृद्धि १९५६-१९६५	सप्तवर्षीय योजना के फलीभूत होने पर भौतिक वृद्धि	१९५६-१९७२ में सम्पूर्ण प्रांतीय वृद्धि
विद्युत् शक्ति	१००० दसलाख किलोवाट	८००-६००	२३३	५६७-६६७	२६७-२८७	३००-३८०	५३-५७
कोयला	दस लाख टन	६५०-७५०	४६६	१५४-२५५	१०४-११६	५०-१३८	३२-५४
तेल	"	३५०-४००	११३	२३७-२८७	११७-१२७	१२०-१६०	५१-५६
गैस	१००० दसलाख घ० मी०	२७०-३००	२६.८	२४०-२६०	१२०	१२०-१७०	५०-५६
कच्चा लोहा	दस लाख टन	७५-८५	३६.६	३५-४५	२५-३०	१०-१५	२८-३३
इस्पात	"	१००-१२०	५४.६	४५-६५	३१-३७	१४-२६	३१-४५
सीमेन्ट	"	६०-११०	३३.३	५७-७७	४२-४८	१५-२६	२७-३८
जूते	दस लाख जोड़े	६००-७००	३५६	२४४-३४४	१५६	८५-१८५	३५-५३
चीनी	दस लाख टन	६१०	५.५	३.६-४.७	३.८-४.६	—	—



सोवियट संघ मे विद्युत्

१६२]

[सोवियट रूस का आर्थिक विकास]

यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन १९५७ में १०० है, तो अनुमान किया गया है कि १९६५ में सोवियट संघ का उत्पादन निम्नांकित प्रतिशतक होगा :

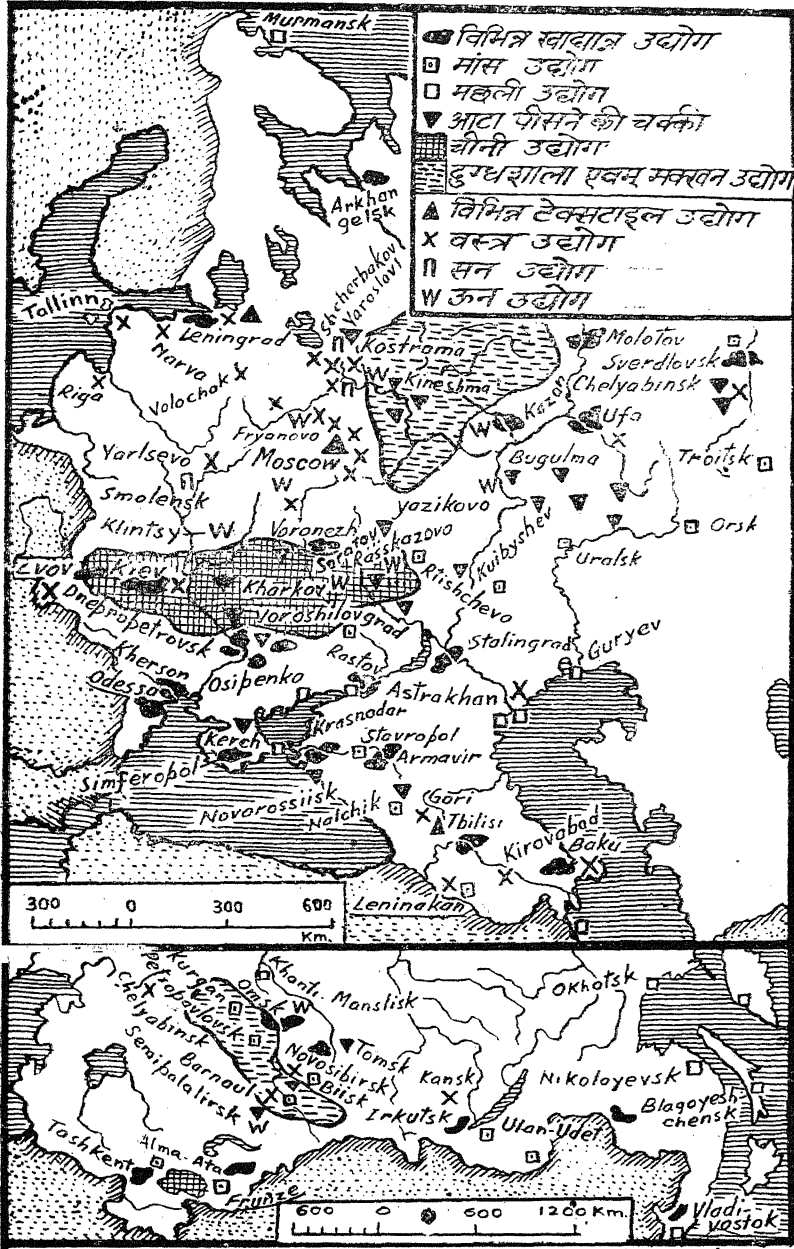
विद्युत् शक्ति	७०-७१
कोयला	११३-११५
तेल	६५-६८
गैस	५०
लोहा खनिज	१३६-१४६
इस्पात	८४-८६
कच्चा लोहा	६०-६७
सीमेन्ट	१५०-१६२
ऊनी सूत	१८७
जूते	८७

अमेरिका की अपेक्षा गत दस वर्षों में सोवियट संघ की औद्योगिक प्रगति चार गुनी तथा कृषि उन्नति सात गुनी अधिक हुई है। यदि अमेरिका के उद्योग-धन्धे वर्तमान दर से प्रगति करते रहते हैं, तो दस वर्षों में २३ प्रतिशत और इसी प्रकार कृषि में ११-११.५ प्रतिशत वृद्धि हो सकेगी। इसके प्रतिकूल सोवियट संघ में वार्षिक प्रगति ८.६ प्रतिशत दर से होगी, जो अनुमान किया गया है कि गत वर्षों की प्रगति दर से अति अधिक है।

कुल उत्पादन (कृषि क्षेत्र) की प्रगति दर

	सोवियट संघ	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
औसत वार्षिक प्रगति—गत २३ वर्षों में—युद्धपूर्व ११ वर्ष (१९३०-१९४०) तथा युद्धोत्तर १२ वर्ष (१९४६-१९५७)	४.३	१.२
औसत वार्षिक प्रगति—गत चार वर्षों में—औसत १९५४-१९५७ में	७.१	१.१

प्रति इकाई उत्पादन वृद्धि, जीवन स्तर उच्च करने हेतु, अत्यन्त आवश्यक है। सप्तवर्षीय योजना के फलीभूत होने पर प्रति इकाई उत्पादन ब्रिटेन तथा



प्रमुख खाद्यान्न एवं टेक्सटाइल उद्योग

पश्चिमी योरप के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होगा और ऐसा अनुमान किया गया है कि १९७० तक तो विश्व में प्रति इकाई उत्पादन दृष्टिकोण से सोवियट संघ का स्थान प्रथम रहेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से १९६५ की दशा के आधार पर प्रति इकाई उत्पादन में निम्नलिखित विधि से तुलना की जा सकी है :

पद	माप-इकाई	सोवियट संघ १९६५	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका १९५५
विद्युत् शक्ति	किलोवाट	२,३११	४,१८०
कच्चा लोहा	किलोग्राम	३११	४२०
इस्पात	"	४०४	५६७
तेल	"	१,०६७	२,०६७
गैस	घन मीटर	६६७	१,७६०
कोयला	किलोग्राम	२,७२०	२,७२५
सीमेन्ट	"	३६०	२६२

प्रति इकाई उपभोग पदार्थ उत्पादन में भी १९६५ तक उत्पादन स्तर को लगभग विचारयुक्त एवम् यथायोग्य स्तर के समकक्ष होने का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित सारणी द्वारा यह तथ्य सिद्ध किया गया है :

उपभोग पदार्थों की इकाई उत्पादन गति^१

पद	माप-इकाई	१९१३	१९५८	१९६५	यथायोग्य एवम् विवेकी स्तर (प्रति इकाई उत्पादन)
बस्त्र-सूत	मीटर	१६.२	२८.७	३८.१	३५-७०
ऊन	"	०.६	१.५	२.४	२-५
लिनन	"	०.७	२.४	३.०	३-६
रेशम	"	०.३	४.२	७.१	५-१२
मोजा-बनियान	जोड़े	—	४.४	६.०	१०-१६
बुने हुये जाँघिये	"	—	१.६	३.७	२-८

बुने हुये वस्त्र	जोड़े	—	०.५	०.८	१-३
जूते (चमड़े के)	जोड़े	०.४	१.७	२.४	२-४
चीनी	किलोग्राम	६.७	२६.७	४४.०	२७-३३
बनस्पति तेल	"	३.४	६.०	६.४	८-१०
दूध तथा दुग्धशाला					
पदार्थ...	"	१८४.६	८६.०	५००.०	२६२-५८५
ऊन	"	१.२	१.६	२.६	—
अण्डा	—	७४.९	१६.३	१७६.२	१८०-३५
मांस	किलोग्राम	—	—	७१.०	७३-९१
मछली	"	—	—	२०.०	७-१६
आलू	"	—	—	६३.०	५५-७१६

योरप के प्रत्येक धनी देशों में मांस का प्रति इकाई वार्षिक उपभोग ४०-८० किलोग्राम है, जैसे बेल्जियम में ४४ किलोग्राम, स्वेडन में ५०, ब्रिटेन में ६७, तथा कैनाडा में ७० किलोग्राम । १९५८ में सोवियट संघ में मांस उपभोग ३८ किलोग्राम से अधिक नहीं था, जो अन्य देशों की अपेक्षा न्यून है । आशा की जाती है कि १९६५ तक इसका उपभोग ७१ किलोग्राम हो जावेगा । इसके अतिरिक्त मत्स्य उपभोग २० किलोग्राम प्रति पुरुष होने पर १९६५ में सोवियट संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अधिक उपभोग पदार्थ सम्पन्न देश समझा जावेगा । दूध उपभोग भी १९६५ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा अधिक होगा । प्रस्तुत सप्तवर्षीय योजना का महान कार्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवम् अन्य पूँजीवाद देशों से शान्तिजनक प्रतिस्पर्धा करके समाजवाद को प्रभुता पूँजीवाद पर स्थापित करना है ।

सोवियट कृषि संगठन तथा संचालन

दूसरे अध्याय में लिखा जा चुका है कि १८६१ के पूर्व कृषि दासत्व प्रथा रूस में प्रचलित थी और अधीन कृषकों की दशा अत्यधिक चिन्ताजनक थी। भूमि तथा अधीन कृषकों के स्वामी जिन्हें 'कुलक' कहते थे, उनके पूर्ण अधिकारी थे। अधीन कृषक भूस्वामी के सम्पत्ति साधन थे। कुलक का कृषकों पर अत्याचार सम्बन्धी विवरण दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है। कृषक तथा उनके बच्चों को वे विक्रय एवम् विनिमय कर सकते थे तथा उन्हें पशुओं की तरह पाला जाता था। १८६१ के उपरान्त भी जब कृषक-मुक्त विधान निर्माण किया गया, उनकी दशा में कोई विशेष सुधार न हो सका। 'कुलक'—विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाये गये, जिन्होंने १९०५ तथा १९१७ की क्रान्ति को प्रेरणा दी। १९वीं शताब्दी के अन्त में तथा २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कृषि एवम् भूमि समस्याओं का आधार, 'कुलक' एवम् विशाल कृषकों का अत्याचार तथा दुर्बल एवम् निर्धन कृषकों की भूमि की माँग थी। 'जार' के विरुद्ध क्रान्ति तथा राजनैतिक विद्रोह का महान कारण रूसी कृषक की निर्धनता तथा क्षुधा थी, जिसका सम्बन्ध 'कुलक' के अत्याचार एवम् अनेक करों के भार से था। अक्टूबर (नवम्बर) क्रान्ति के उपरान्त सोवियट सरकार ने ३८१२ लाख एकड़ भूमि कृषकों को हस्तांतरित किया। २६ अक्टूबर (८ नवम्बर) को सोवियट कांग्रेस ने भूमि सम्बन्धी प्रादेश (Decree on the Land) पास किये। भू-स्वामित्व का बिना किसी प्रतिकर (compensation) के उन्मूलन कर, भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वह राज्य की सम्पत्ति—सम्पूर्ण जनता की सम्पत्ति मानी गई। कृषकों को केवल खेती करने का अधिकार था। वे उसे क्रय-विक्रय नहीं कर सकते थे। भू-सम्बन्धी

मूल निर्देश द्वारा भूमि सुधार के मौलिक सिद्धान्त निर्मित किये गये। उसके अनुसार : “सम्पूर्ण भूमि जनता की सम्पत्ति है। कृषकों को उसे प्रयोग करने का अधिकार है। कृषकों के मध्य उत्पत्ति वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण, स्थानीय तथा केन्द्रीय संस्थाएँ करेंगी।”

प्राचीन भू-स्वामियों ने इस नवीन अर्थव्यवस्था का घोर विरोध किया। अनेक स्थानों पर गल्ला जला दिया गया, कृषि साधन नष्ट कर दिये गये, पशुओं को बध कर दिया गया अथवा बेच डाला गया। इसके विरुद्ध निर्धन कृषक समुदाय ने सम्पत्तिवाद कृषक तथा भू-स्वामियों को बन्दी कर लिया तथा अनेक विध्वंसात्मक कार्य किये। जून १९१८ में सोवियट सरकार ने आदेश प्रकाशित किया कि निर्धन कृषकों की समितियाँ स्थापित की जायेंगी, जिनके द्वारा दासत्व प्रथा का उन्मूलन, जो कार्य १९१७ की क्रान्ति के उपरान्त प्रारम्भ हुआ था, पूर्ण किया गया। ५० लाख हैक्टेयर भूमि तथा कृषि सम्बन्धी असंख्य यन्त्र, जो ‘कुलकों’ से प्राप्त हुये, सामान्य कृषकों के मध्य वितरित किये गये। परिणाम स्वरूप १९१८-१९ में अन्तर्देशीय खाद्य संकट प्रगाढ़ हो गई। “रोटी-संवर्ष” देश की एक गम्भीर समस्या थी। युद्धकालीन साम्यवाद प्रथा में जो रीतियाँ ग्रहण की गई थीं, उनके कारण उत्पादन में हास हो गया था और खाद्य संकट में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी। नवीन आर्थिक नीति काल में भी अनेक परिवर्तन खाद्य समस्या को सुलझाने के दृष्टिकोण से किये गये तथा उनसे कुछ लाभ भी हुआ, परन्तु भू-सम्बन्धी कोई स्थायी विधान नहीं बनाया गया और क्रान्ति उपरान्त तो दस वर्षा तक कोई मौलिक निर्देश भी न पास किये गये।

शनैः शनैः इस पर अधिक प्रभाव डाला गया कि कृषि सुधार तथा ट्रैक्टर एवम् अन्य यन्त्रों के प्रयोग हेतु विस्तृत कृषि की अत्यन्त आवश्यकता है। लघु आकार के खेतों में पूँजी विनियोग तथा वैज्ञानिक कृषि निर्मूल है एवम् विस्तृत पशुपालन भी असम्भव है। ८० लाख ऐसे निर्धन कृषक एवम् कुटुम्ब थे, जिनके पास मशीन तो क्या पशु भी न थे।^१ विस्तृत कृषि समाजवादी प्रथा द्वारा ही सम्भव थी। लेनिन ने स्वतः निर्मित सहकारी योजना में कृषि पुनर्संगठन के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित की। समाजवादी प्रथा प्रचलन की दृष्टिकोण से लेनिन ने अनेक अवसरों पर कृषकों को समझाते हुए छोटे-छोटे खेतों को विस्तृत

१ D. S. Kolpakav: How the Agrarian Problem has been solved in the U. S. S. R., p. 25.

सामूहिक खेतों में परिवर्तन करने का आग्रह किया। निःसन्देह यह ऐसी व्यवस्था थी जिसकी शीघ्र स्थापना असम्भव थी, क्योंकि कृषक शताब्दियों से स्वतः छोटे छोटे खेतों पर कृषि करता चला आया था। समाजवाद प्रथा के अन्तर्गत कृषि हेतु यह आवश्यक था कि छोटे-छोटे खेतों को संगठित कर अखण्ड विशाल खेत निर्माण किए जावें तथा सहकारी कृषि में सामूहिक कार्य किये जावें, जो कृषकों के लिए एक नवीन कार्य था, क्योंकि वे अनुभवहीन थे। १९२६-२७ से ही सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस आन्दोलन का संचालन कार्य पार्टी के सदस्यों को सौंपा गया। नगरों से कर्त्तागणों को बुलाकर कृषकों को प्रोत्साहित किया गया। प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस महान् कार्य को अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। शीघ्र ही सम्पूर्ण देश में अधिकांश उत्पादन सामूहिक कृषि से प्राप्त होने लगा।

सामूहिक फार्मों को यन्त्र तथा ट्रैक्टर प्रदान करने हेतु मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन स्थापित किए गए। ट्रैक्टर तथा यंत्रों का समुचित उपयोग करने के लिए राजकीय स्वामित्व एवम् संचालित मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना हुई, जिन्होंने सामूहिक कृषि प्रगति हेतु महान् कार्य किए। केवल अनुभव द्वारा ही इन स्टेशनों की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ था। १९२७ में शेवचेन्को राज्य फार्म पर (Shevchenko State Farm)^१ स्थानीय कृषकों को सहायता पहुँचाने के दृष्टिकोण से कुछ ट्रैक्टरों को संग्रहित करके फार्मों को कृषि यंत्र सहायता प्रदान की गई थी। इस कार्य में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई। शीघ्र ही अनेक स्थानों पर मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन स्थापित किए गए, जहाँ से कृषकों को ट्रैक्टर प्राप्त होने लगे। १९३२ में लगभग २,४४७ मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन थे जो १९४० में ७,०६६, १९५० में ८,४१४, १९५२ में ८,८०७ तथा १९५५ में ६,००६ हो गए। इनकी सहायता से सस्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। १९३२ में ४९ प्रतिशत सस्य भूमि को ट्रैक्टर स्टेशन सेवा करते थे। १९४० में ९४ प्रतिशत सस्य भूमि इनके अन्तर्गत थी, जो १९५० में ९७ तथा १९५२ में ९९ प्रतिशत हो गई। अंगले पृष्ठ में प्रस्तुत सारिणी यह स्पष्ट करती है कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन सम्पूर्ण मौलिक कार्य स्वयम् करते हैं तथा रूस की सम्पूर्ण कृषि इन्हीं पर निर्भर है :

^१ Agricultural Encyclopedia : Moscow, 3rd Edition, 1953, p. 189

मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों से सम्बन्धित मौलिक सामग्री^१

	१९३०	१९४०	१९५०	१९५०	१९५३	१९५४	१९५५
मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों की (वर्ष के अन्त में) संख्या...	२,४४६	७,०६६	८,४१४	८,८०७	८,८८५	८,९९४	९,००६
मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों द्वारा सेवित सस्यक्षेत्र (प्रतिशत)...	४६	६४	६७	६६	६६	६६	६६
म० ट्रे० स्टे० द्वारा नियुक्त कर्म-चारियों की वार्षिक औसत संख्या (हजार में)...	१४४	५३७	७०५	८३३	१,१६७	३,००७	३,१२०
सम्पूर्ण ट्रैक्टरों की मात्रा (हजार इकाइयों में)...	७५	४३५	४८२	५६७	६१३	६४६	६६६
जिनमें सम्मिलित हैं : 'रोक्राप ट्रैक्टर' सम्पूर्ण ट्रैक्टरों की संख्या (१५ अश्वशक्ति इकाइयों में) हजार इकाइयों में...	०.३	७६	७५	६५	१११	१४२	१६१
जिनमें सम्मिलित हैं : सामान्य कारों के ट्रैक्टर ट्रैक्टर की कुलाई शक्ति (हजार अश्वशक्ति में)...	७२	५५७	७३६	६१५	१,००७	१,००७	१,१०६
मोटर लारी की संख्या (हजार इकाई)	७२	५८४	६८८	८४६	९२६	९६३	९७१
	१,०७७	८,३५८	११,०८०	१३,७१८	१५,१०७	१६,१५०	१६,६३५
	६	४०	५०	५१	७६	८६	९५

^१ National Economy of the U. S. S. R., Statistical Returns, p. 124.

१९३० के उपरान्त सोवियट रूस में सामूहिक कृषि की उन्नति तीव्र गति से हुई। वैयक्तिक कृषकों को हतोत्साहित करके प्रायः उन्हें बाध्य किया गया कि वे अपनी भूमि को संग्रहित करके सामूहिक कृषि को प्रेरणा दें। कुछ स्थानों पर सरकार ने राज्य फार्म स्थापित किए जहाँ कृषकों को पारिश्रमिक पर नियुक्त किया तथा कारखानों के सदस्य कृषि-उद्योग का संचालन किया जाने लगा। प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय योजना के अध्याय में बतलाया जा चुका है कि सामूहिक कृषि प्रगति प्रथम तीन योजना-अवधि में अति अधिक हुई। प्रारम्भिक काल में इसके प्रभाव हृदय विदारक एवम् कष्टमय थे। परन्तु सरकार उत्तरोत्तर इनमें वृद्धि करती गई। वर्तमान काल में शत-प्रतिशत खेत सामूहिक एवम् राज्य कृषि के अन्तर्गत हैं तथा भूमि का एक अंश भी वैयक्तिक कृषि कार्य में नहीं है। कृषक को केवल थोड़ी सी भूमि रखने का अधिकार-अवश्य प्राप्त है जिसपर वे कुछ साग-सब्जी आदि उत्पन्न करते हैं तथा निश्चित सीमित संख्या में पशु पालन भी करते हैं। परन्तु विशाल सामूहिक खेतों की तुलना में वे नाममात्र हैं। वर्तमान काल में लगभग ७०,००० सामूहिक खेत तथा ६,००० विशाल राज्य खेत हैं। इनको सम्पूर्ण आधुनिक कृषि यन्त्र भी उपलब्ध हैं। कुल उत्पादन विक्रय गत वर्षों की अपेक्षा सोवियट संघ में अत्यधिक बढ़ गया है। अन्य देशों की अपेक्षा भी सोवियट संघ में इस समय कृषि योग्य भूमि अधिक है, जो निम्न तालिका से प्रदर्शित है :

कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल

देश	वर्ष	दस लाख हैक्टेयर
सोवियट संघ	१९५४	२१६.७०
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	१९५०	१८६.००
भारतवर्ष	१९५०	१३१.३०
कैनाडा	१९५१	३६.२०
अर्जन्टाइना	१९५४	३०.००
फ्रान्स	१९५५	१६.२०

केवल कृषि योग्य भूमि ही नहीं, किन्तु सस्य एवम् खाद्यान्न सस्य क्षेत्रफल भी सोवियट संघ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा अधिक है। परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि उत्पादन क्षमता में सोवियट रूस अब भी अत्यधिक पिछड़ा हुआ देश है तथा अग्रिम वर्षों में इसके सम्मुख विशाल कार्य करने को

हैं। इन निम्न संख्याओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में सोवियट रूस का उत्पत्ति अंश विश्व के सम्पूर्ण उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगा, जब उर्वरता में भी शीघ्राशीघ्र वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

सस्य क्षेत्र (दस लाख हैक्टेयर)

देश	१९१३	१९२८	१९५०	१९५३	१९५७
	कुल सस्य क्षेत्र				
सोवियट संघ	११८.२	११३.०	१४६.३	१५७.२	१६३.७
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	१००.०	१३६.६	१३०.४	१३२.१	१२४.१
	ख. गांव सस्य क्षेत्र				
सोवियट संघ	१०४.६	९२.२	१०२.९	१०६.७	१२४.६
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	८२.०	९०.४	८४.८	८३.४	७६.९

१९५३ के उपरान्त १९५४-१९५७ में सस्य भूमि ३६० लाख हैक्टेयर बढ़ जाने का विशेष कारण, साइबेरिया का ज़ाकस्तान, वालगा क्षेत्र तथा अन्य सुदूर पूर्व के प्रदेशों में नवीन खेती योग्य भूमि का विस्तार है।

सामूहिक खेतों का औसत आकार

पद	माप-इकाई	वर्ष			
		१९३२	१९४०	१९५३	१९५७
सामूहिक खेतों की संख्या	हजार	२११.७	२३६.६	६३.३	७८.२
प्रति सामूहिक खेत :					
कुटुम्ब संख्या	इकाई	७१	८१	२२०	२४५
सस्य क्षेत्रफल	हैक्टेयर	४३४	४९२	१,४०७	१,६६६
पशुपालन	इकाई	४२	८५	२६८	३७४
जिसके अन्तर्गत :					
गाय	"	१३	२४	६३	१३७
सुअर	"	१५	३५	१४६	२५५
भेंड़-बकरी	"	५४	१७७	८३५	९१३
घोड़ा	"	५७	६१	१४१	१२१
अविभाज्य कोष	हजार रुबल	२२.३	११८	७००	१,३३८
मौद्रिक आय	" "	२२	८८	५४७	१,५०

सामूहिक कृषि के विषय में गत पृष्ठ में दी गई तालिका लगभग पूर्ण विवरण प्रदान करती है, जिससे १९३२-१९५७ की पूर्ण दशा का ज्ञान होता है। १९३२ में एक सामूहिक खेत में लगभग ७१ कुटुम्ब थे जिनकी संख्या १९४० में ८१, १९५३ में २२० तथा १९५७ में २४५ हो गई। इसी प्रकार सस्य भूमि का भी औसत क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ाया गया। पशुओं की भी संख्या में वृद्धि हुई। सामूहिक कृषि अविभाज्य कृष तथा मौद्रिक आय में भी गत वर्षा में कई गुना वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

१९५८ में सामूहिक कृषकों की औसत आय १३,००,००० लाख रूबल थी जो १९५७ की अपेक्षा ३,६०,००० लाख रूबल अधिक है। सोवियट संघ, कृषि उत्पात्ति के अतिरिक्त पशुपालन पदार्थ का उत्पादन भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तुल्य शीघ्राशीघ्र करने का प्रयास कर रहा है और यदि यह गति निरन्तर स्थिर रही तो वह दिन दूर भी नहीं है। अब भी उन्नत बहुत उत्तम तो नहीं, फिर भी १३७ की तुलना में अत्यन्त प्रशंसनीय है।

पशुपालन पदार्थों में प्रति इकाई उत्पत्ति (कि० ग्रा० में)

उत्पत्ति पदार्थ	१९३७		१९५३		१९५७	
	संयुक्त रा० अ०	सोवि० संघ	संयुक्त रा० अ०	सोवि० संघ	संयुक्त रा० अ०	सोवि० संघ
विभिन्न प्रकार का मांस आदि...	७१	१७.८	९४	३०.५	९७	३३
दूध	३६८	११७	३४२	१९१	३३५	२६८
मक्खन	७.४	१.८	४.६	२.६	४.१	३.७
कच्चा ऊन	१.७	०.६	०.९	१.२	०.८	१.४

१९१० में 'जार' शासन काल में निम्नकोटि के कृषि साधन उपलब्ध थे:

काष्ठ-हस्थ-हल	...	७८ लाख
अन्य काष्ठ-हल	...	२२ लाख
लोहा-हल	...	४२ लाख
काष्ठ-हैंगी (harrows)	...	१७७ लाख

१९५८ के प्रारम्भ में निम्नलिखित कृषि साधन उपलब्ध थे :

ट्रैक्टर : (१५ अश्वशक्ति इकाई में)	१,७००,०००
अन्न-लवन-यन्त्र :	४८३,०००
मोटर लारी	६६०,०००
हल युक्त ट्रैक्टर	८८२,०००
बीज बोने के यन्त्र युक्त ट्रैक्टर	८२९,०००
हेंगी (cultivators)	६००,०००

१९५८ तक प्रायः सब मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों पर विद्युत् प्रदान की गई है। लगभग ९३ प्रतिशत सम्पूर्ण राज्य खेतों पर तथा ४० प्रतिशत सामूहिक खेतों पर भी विद्युत् का पूर्ण प्रबन्ध किया जा चुका है।

१९२८ में सस्य क्षेत्र, कुल उपज, तथा अन्न अधिग्रहण १९५३ की अपेक्षा १७, ६९, तथा ८४ प्रतिशत अधिक बढ़ा है। १९५८ में खाद्यान्न सस्य क्षेत्र १८५२ लाख हैक्टेयर, कुल उपज ८५,०८० हजार लाख 'पूड', तथा अन्न अधिग्रहण ३४,६५० लाख 'पूड' उत्पन्न हुई है। आवश्यक समक निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण प्राप्त हैं :

सस्य क्षेत्र, कुल उपज, तथा अन्न अधिग्रहण

पद	१९१०-१९१४	१९५३	१९५८	१९.८८ पारवर्तन (१९ = १००)
अन्न सस्य क्षेत्र.	१०२.५	१०५.७	१५५.२	११७
कुल अन्न उपज. (१००० लाख 'पूड')	४३,८००	५०,३६०	८५,०८०	१६९
अन्न अधिग्रहण (१००० लाख 'पूड')	—	१८,६६०	३४,६५०	१८४

प्रारम्भिक वर्षों में तीन प्रकार की सामूहिक खेती सुसंगठित की गई। स्थानीय सुविधानुसार प्रत्येक प्रथा कहीं न कहीं प्रचलित थी। प्रारम्भ में अनुमान करना दुष्कर था कि किस प्रकार की कृषि पद्धति से क्या क्या लाभ तथा हानि होंगी, क्योंकि इस प्रकरण पर पर्याप्त अनुभव न था। अतः स्थानीय दशानुसार निम्न प्रकार की सामूहिक कृषि पद्धति सुसंगठित की गई :

(क) कम्युन (Commune)

(ख) कृषि संयुक्त समितियाँ (Toz)

(ग) कृषि सहयोगी समितियाँ (Artel)

इन प्रथाओं में जो भेद तथा विशेषतायें थीं, वे निम्नलिखित हैं :

(क) कम्युन उन व्यक्तियों का संगठन था जो सर्वरहित वर्ग के थे अर्थात् जिनके पास न भूमि, न कृषि सामग्री, न पूँजी, न पशु तथा न निवास स्थान थे। यह ऐसा वर्ग था जो भू-स्वामियों के यहाँ पारिश्रमिक पर अथवा दासत्व प्रथा के अन्तर्गत काम करते थे। इस संगठन के अनुसार सम्पूर्ण सामग्रियाँ उत्पादन, नियमानुसार, सामाजिक सम्पत्ति बना दी गई। इस वर्ग के पास वैयक्तिक प्रयोग हेतु भी अपनी कोई वस्तु न थी। पशु, भूमि, मुर्गी, बतक तथा अन्य उत्पादन सामग्री कम्युन की थी। कम्युन की उत्पत्ति-आय उनके कुटुम्ब के सदस्यों के अनुसार अथवा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वितरित की जाती थी। कहीं-कहीं वे साथ रहते थे, उनका एक ही शयनागार होता था, समुदायिक चूल्हे में उनका भोजन बनता था तथा उनके बच्चे भी समुदायिक नर्सरी में पोषित होते थे। इसमें सन्देह नहीं कि केवल उन्हीं व्यक्तियों ने इस संस्था को ग्रहण किया, जो स्व-सम्पत्ति शून्य तथा निर्धन थे।

कम्युन अपने सदस्यों के वैयक्तिक तथा सामूहिक हित का समुचित संकलन न कर सका। सबको अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन का अंश दिया जावेगा, यह सिद्धान्त समयानुकूल न था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा कार्य-अवधि पर उचित ध्यान न देने के कारण उनकी भृत्ति एवम् वितरण में अत्यन्त असमानता थी। फलस्वरूप श्रमिक हतोत्साहित होने लगे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सिद्धान्त ऐसे समय प्रयोग किया गया था जब रूसी श्रमिक शक्तिहीन थे। इस कारणवश यह पद्धति असमर्थ सिद्ध हुई।

(ख) कृषि संयुक्त समितियाँ सहयोग का सबसे सरल रूप था, जो 'टॉज़' के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका कार्य केवल उत्पादन संगठन ही था। इनके सदस्यों में आय वितरण साधारणतः इस प्रकार होता था कि आय का एक अंश पारिश्रमानुसार तथा दूसरा अंश पूँजी के अनुसार वितरित किया जाता था। भृत्ति प्रथा भू-अंश पर भी आधारित थी। इनमें दोष यह था कि भू-अंश तथा पूँजी आधार पर आय वितरण करने से निर्धन कृषकों का अनिर्धन होता था, जिसके कारण प्रस्तुत सामूहिक कृषि पद्धति अधिक प्रचलित न हो सकी।

(ग) सामूहिक कृषि आन्दोलन ने जो अधिक प्रगतिशील रूप धारण किया था वह कृषि सहयोग समिति संगठन था, जिसे 'आर्टेल' कहा गया। यह प्रथा रूस की प्रचलित कृषि का मूल रूप बन गई। इसके अन्तर्गत अधिकतर उत्पादन सामूहिक रूप से किया गया तथा अधिकतर उत्पादन साधन भी सामुदायिक थे। प्रत्येक कृषक के पास वैयक्तिक उद्यान हेतु थोड़ी सी भूमि, कुछ

उत्पादक पशु तथा छोटे-मोटे यंत्र थे, जो सदस्यों के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए छोड़ दिए जाते थे। परन्तु कृषि उत्पादन का मूल साधन केवल सामूहिक सम्पत्ति ही थी। इस प्रकार के सामूहिक कृषि संगठन को सहयोग समिति भी कहते थे। इसका आधार उसकी सामूहिक सम्पत्ति थी, जिस पर सामूहिक कृषक अपने श्रम का प्रयोग करके धनोपार्जन करते थे। सम्पूर्ण अन्य, चारा, पशु-पालक उत्पादन, आलू, साग-सब्जी तथा फल आदि का उत्पादन सामूहिक फार्म पर होता था, जिसका वितरण कृषकों के मध्य किया जाता था। सामूहिक फार्म की आय के अतिरिक्त सामूहिक कृषक के पास अपनी वैयक्तिक भूमि तथा पशु थे जो उसकी आय के अतिरिक्त साधन थे, जिसमें वह तथा उसके कुटुम्ब के सदस्य अपने अवकाश में काम करते थे। अनेक कृषक अपनी गृहस्थी अथवा वैयक्तिक सम्पत्ति से इतना अधिक उत्पादन कर लेते थे कि स्वयम् अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के उपरान्त अवशेष उत्पत्ति को राजकीय क्रय संस्थाओं, उपभोक्ता सहयोग समितियों अथवा हाटों में विक्रय अथवा विनिमय करते थे। परिणामस्वरूप उनकी आय में कुछ वृद्धि हो जाती थी। १९५८ के आदेशानुसार सामूहिक कृषकों को यह स्वतन्त्रता दी गई कि वे जिस प्रकार चाहें अपने सहायक गृहस्थी (subsidiary household) के अतिरिक्त उत्पादन को प्रयोग करें तथा सरकार उसके विक्रय-विनिमय में कोई हस्तक्षेप न करेगी।

सोवियट संघ की सामूहिक कृषि के साहसी श्रमिकों की द्वितीय काँग्रेस (Second U.S.S.R. Congress of Collective Farm Shock Workers) की बैठक १९३५ में हुई। इसने कृषि सहयोग समितियों के आदर्श नियमों (Model Rules of Agricultural Cooperative) को स्वीकार करते हुए प्रत्येक कृषक कुटुम्ब को अपने वैयक्तिक प्रयोगों के लिए ०.२५ से एक हैक्टेयर भूमि निःशुल्क प्रदान करने का निश्चय किया। साथ ही साथ उन्हें एक गाय, दो बछड़े, एक या दो बच्चे सहित सुअर, दस भेंड़, बकरियाँ, कितनी भी मुंगियाँ, खरगोश आदि तथा मधुमक्खी के २० छत्ते रखने का अधिकार दिया गया। उन स्थानों पर जहाँ पशु-पालन उद्योग वृहताकार था, सामूहिक कृषक अति-अधिक संख्या में पशु पाल सकते थे।

इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वे सामूहिक कृषकों की सहायक गृहस्थियों को हर प्रकार से आवश्यक सहायता पहुँचावें। कृषकों को अपनी सामूहिक संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अनुकूल शर्तों पर उन्हें सुर्गी तथा पशु आदि भी मिला सकते हैं तथा इन पशुओं के लिये सामूहिक खेतों से उत्तम घास भी निर्धारित अनुपात में प्राप्त होती है।

वैयक्तिक उद्यान में पुष्प एवम् वृक्षारोपण हेतु सामूहिक फार्मों से उत्तम बीज भी मिलते हैं। वर्तमान काल में कृषकों की वैयक्तिक आय में अति अधिक परिमाण में वृद्धि हो गई है।

सामूहिक फार्म की उत्पत्ति एवम् आय वितरण

सामूहिक फार्म की उत्पत्ति एवम् आय वितरण एक जटिल समस्या है। जितना भी उत्पादन अब तक होता था, उसका एक विशाल अंश सर्वप्रथम सरकार ले लेती है।

(क) राजकीय अंश तीन दिशाओं से क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है।

(१) उत्पादन का एक बड़ा अंश सरकार कृषि उत्पादन पदार्थ कर के रूप में लेती है। कृषि योग्य भूमि के अनुपात में अन्न, साग-सब्जी, आलू तथा अन्य खाद्यान्न में कर 'कोटा' निश्चित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक कृषक को इसी के अनुसार कर देना पड़ता है। कच्चे पदार्थ में जैसे चुकन्दर, कपास, सन तथा अन्य पदार्थों में सामूहिक कृषि तथा राज्य के मध्य संविदा होते हैं, जिसके अन्तर्गत अमुक परिमाण में कच्चा पदार्थ सरकार को देना अनिवार्य है।

उत्पादन के पूर्व ही सम्पूर्ण सस्य निश्चित कर दी जाती है, जिसके अनुसार प्रत्येक सामूहिक फार्म का सस्य का पूर्वानुमान करना पड़ता है। इसको "बाइलाजिकल हारवेस्ट" कहते हैं। इसके आधार पर सामूहिक फार्म सामग्री भुगतान करते हैं। उदाहरणार्थ किसी सामूहिक फार्म की सस्य १,४०० किलोग्राम पूर्वानुमान की गई है। यद्यपि बीज उत्तम है, तथापि याद द्रैक्टर एवम् यंत्रों का संचालन असावधानों से होता है, जिससे उत्पत्ति निम्न होती है तथा असमायिक दैविक घटनाओं के कारण तथा उत्पत्ति प्रगतिहीन रह जाने के कारण केवल १,००० किलोग्राम उत्पादन प्राप्त होता है। फिर भी सरकार एक निश्चित पूर्वानुमानित कर 'कोटा' बिना उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए संकलन कर लेता है।

उसी समय 'बाइलाजिकल हारवेस्ट' निश्चित कर दिया जाता है, जब निरीक्षक कृषि निरीक्षण करते हैं। वे न तो इस बात से प्रभावित होते हैं कि सामूहिक कृषकों को सम्पूर्ण अनुकूल सुविधायें प्राप्त हैं अथवा नहीं और न वे किसी प्रकार इस बात से हाँ सम्बन्धित रहते हैं कि सस्य विनष्ट हो जा सकती है। वे यदि 'कोटा' निम्न स्तर पर निश्चित करते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार से अपने इस निर्णय को उच्च पदाधिकारियों के सम्मुख सिद्ध करना पड़ता है तथा यदा-कदा उन्हें दण्ड भी मिल जाता है। परन्तु याद व 'कोटा' उच्च स्तर पर निर्धारित करते हैं, तो सरकार उनको कोई दण्ड नही देता है।

(२) पदार्थ-कर के अतिरिक्त उत्पादन का एक भारी अंश मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों को सेवायें प्रदान करने के उपलब्ध में देना पड़ता है। सामूहिक कृषि के साथ-साथ मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों की भी उन्नति हुई, क्योंकि ट्रैक्टर तथा यंत्रों की आवश्यक माँग की पूर्ति इन्हीं स्टेशनों द्वारा की जाती है। इनका भुगतान भी पदार्थ अंश के रूप में सम्पूर्ण उत्पादन का एक निश्चित अनुपात दर में देना पड़ता है।

(३) सरकार द्वारा अन्य सुविधायें अथवा ऋण आदि प्राप्त करने के उपलब्ध में भी सामूहिक फार्मों को उत्पादन में से एक निश्चित अंश सरकार को देना पड़ता है, जो पूर्व निश्चित रहता है। इन राजकीय माँगों का प्रमुख दोष यह था कि वे किसी भी दशा में कम नहीं की जा सकती थीं। यदि किसी भी कारणवश सस्य यथेष्ट नहीं हुई तो इसका प्रभाव राज्य उत्तरदायित्व पर न पड़कर कृषकवर्ग पर पड़ता है तथा उन्हें राज्य कर निर्धारित माँगों की पूर्ति बाध्यवश करना पड़ता है।

(ख) राजकीय अंश देने के उपरान्त उत्पादन का एक अंश सामूहिक कोष में संचित किया जाता है। बीज तथा पशु हेतु, भविष्य में सस्य नष्ट होने के दृष्टिकोण से अथवा अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं के कारणवश सामूहिक कृषि में संचय अनिवार्य है। सामूहिक सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए कृषि उत्पत्ति का कुछ अंश संग्रहित किया जाता है, जिससे शारीरिक अस्वस्थता, स्थायी चोट तथा अन्य कारणवश कार्य-अयोग्य होने से प्रायः यह आवश्यक हो जाता है कि कृषकों को सामूहिक कोष से सामग्रिक एवम् आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

(ग) तत्पश्चात् सामूहिक कृषक अवशेष का एक निश्चित प्रतिशत स्वेच्छानुसार विक्रय कर सकते हैं। कुछ समय पूर्व तक तो ऐसी व्यवस्था थी कि अधिकतर अंश सामूहिक कृषक राज्य के हाँथ बेचता था। निर्धारित मूल्य होने के कारण वे किसी प्रकार अति अधिक लाभ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अधिकांशतः राजकीय क्रय था। राजकीय उत्तरदायित्व से मुक्त पाने के उपरान्त अतिरेक उत्पत्ति पर कृषकों का पूर्ण अधिकार था कि वे स्वेच्छानुसार उसे विक्रय अथवा वितरण करें।

(घ) सामूहिक फार्म की मौद्रिक आय का वितरण समाजवादी सिद्धान्तों के अन्तर्गत कार्यक्षमता अथवा कार्यकुशलता के आधार पर किया जाता है। इन फार्मों में श्रम माप इकाई 'प्रति दिवस कार्य' होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को ६ वर्गों में विभाजित किया गया है। अपेक्षाकृत सामान्य कार्य हेतु पूर्ण दिवस, उत्पादन की मात्रा इकाई मानी जाती है। उनसे अधिक जटिल एवम्

क्लिष्ट कार्य हेतु इकाई से अधिक तथा कम जटिल एवम् क्लिष्ट कार्य हेतु इकाई से कम माप अनुमानित जाता है। जैसे 'पूर्ण दिवस कार्य इकाई' इस प्रकार थी— ०.१, ०.५, ०.७५, १.२५, १.५, २.०, २.२५ अथवा २.५०। इकाइयों की माप कार्यानुसार निश्चित की जाती है। एक कृषक पूर्ण दिवस कार्य करके 'पूर्ण दिवस कार्य इकाई' का केवल एक अंश अथवा कई दिवस की इकाइयाँ उपलब्ध कर सकता है। कृषक की कार्य कुशलता एवम् श्रमता के अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि निश्चित लक्ष्य को वह कहाँ तक पूर्ण कर सकता है।

पारिश्रमिक प्रत्यक्षतः सामूहिक कृषि की उर्वरता पर निर्भर है। यदि सरकार को, भुक्तान तथा कोष में संचित करने के पश्चात्, शेष अधिक भाग में बचता है, तो भुक्ति दर अधिक रहती है तथा यदि राजकीय उत्तरदायित्व से मुक्त होने के उपरान्त शेष कम बचता है तो उसी अनुपात में भुक्ति दर भी कम हो जाती है। परिणामस्वरूप प्रत्येक सामूहिक कृषक का हित तो अवश्य इस पर निर्भर है कि वह अधिक कुशलता से कार्य करते हुये सामूहिक फार्म की आय वृद्धि से संलग्न रहे, जिससे वह अधिक धन उपार्जन एवम् अधिक उत्पत्ति अंश प्राप्त करके अपना जीवन स्तर उच्च कर सके। आय—मुद्रा तथा पदार्थ, कई किस्मों में दी जाती है।

सोवियट रूस में सामूहिक फार्मों के उत्पादन का वितरण किस प्रकार होता है, इसकी कोई सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था : सांख्यिकीय पुस्तक^१ में भी इस विषय पर कोई समंक प्राप्त नहीं हैं। इसलिये वर्तमान काल की वितरण व्यवस्था का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। १९३७-१९३६ की अवस्था को जो लज़र वॉलिन (Lazar Volin)^२ ने प्रदर्शित किया है, उससे ज्ञात होता है कि १९३६ में सम्पूर्ण उत्पत्ति का २७.५ प्रतिशत केवल राज्य को दे दिया गया था तथा केवल ४ प्रतिशत उत्पत्ति (जो १९३७ तथा १९३८ में ४८ तथा ५.१ प्रतिशत से अधिक न थी) हाट में अथवा राज्य के हाथ विक्रय की गई। सामूहिक कोष में लगभग ३५ प्रतिशत संचित किया गया तथा शेष ३० प्रतिशत के लगभग सामग्री का वितरण श्रमिकों के मध्य 'नित्य दिवस कार्य इकाई' के सिद्धान्त पर किया गया।

^१ The National Economy of the U.S.S.R. : Statistical Returns.

^२ "The Kolkhoz (The collective Farm) in the Soviet Union," Foreign Agriculture, Nov.-Dec. 1947., p. 150.

सामूहिक खेतों के खाद्यान्न का वितरण (१९३७-१९३९)
प्रतिशत

पद	१९३७	१९३८	१९३९
(अ) राजकीय अंश :			
(i) सामग्री-कर तथा अनिवार्य अंश	१२.२	१५.०	१४.३
(ii) मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन को सामग्री भुगतान :	१३.६	१६.०	१६.२
(iii) बीज-ऋण का भुक्तान योग	१.५	२.०	४.०
	२७.६	३३.०	३७.५
(ब) विक्रय (राज्य को तथा हाट में)	४.८	५.१	४.०
(स) सामूहिक आवश्यकताएँ तथा सामूहिक कोष :			
(i) बीज की आवश्यकता तथा संचय	१६.३	१८.६	१८.२
(ii) पशु भोजन की आवश्यकता तथा संचय...	१२.७	१३.६	१३.६
(iii) निर्धनों की सहायता हेतु संचय	१.१	०.८	०.८
(iv) अन्य व्यय योग	१.६	२.०	२.७
	३१.७	३५.०	३५.६
(द) सामूहिक कृषकों के मध्य 'नित्य दिवस कार्य इकाई' के आधार पर वितरण	३५.६	२६.६	२२.६
सम्पूर्ण योग	१००.०	१००.०	१००.०

एक विदेशी यात्री ने सोवियट कृषि की दशा का वर्णन करते हुये विचार प्रकट किया कि "पूँजीवाद उत्पत्ति विक्रय क्षेत्र में अवशेष अब भी कुछ दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि वह नाममात्र है।" सरकार उन्हें "सामूहिक फार्म बाजार" कहती है। उसने सोवियट रूस की यात्रा समाप्त करने के उपरान्त इस पद्धति को समझाते हुए लिखा कि सोवियट संघ में दो प्रकार से खाद्यान्न विक्रय होता है। अधिकांश, राजकीय 'स्टोर' द्वारा, जिनका प्रबन्ध एवम् संचालन सरकार करती है तथा जिनके विक्रय पदार्थों का मूल्य भी पूर्व निश्चित रहता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र बाजार द्वारा, जिसके अन्तर्गत उन पदार्थों का विक्रय होता है जो सामूहिक फार्मों तथा व्यक्तिगत उद्यानों की उत्पत्ति-अतिरेक हैं। एक सामूहिक कृषक, राज्य तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन को कर तथा अन्य भुक्तान देने के पश्चात,

सामूहिक फार्म तथा व्यक्तिगत उत्पत्ति का अवशेष, स्वेच्छानुसार खुले बाजार में लाभ पर विक्रय कर सकता है। स्वतंत्र बाजार में मूल्य निर्धारण माँग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार होता है। उसमें उतार-चढ़ाव भी अधिकतर शीघ्र-शीघ्र सम्भव है। उदाहरणार्थ, मास्को में एक लिटर^१ दूध का मूल्य केवल एक दिन में दो-तीन रुबल घट-बढ़ सकता है। छोटे नगरों तथा स्थानों में ये स्वतंत्र बाजार सप्ताह में केवल दो-तीन दिन लगते हैं। यद्यपि स्वतंत्र बाजार मूल्य राजकाय 'स्टोर' मूल्य से अधिक होता है, तथापि लगभग २२ प्रतिशत खाद्यान्न सामग्री, उपभोक्तागण के हाथ, स्वतंत्र बाजार में विक्रय की जाती है।

जान गन्थर को ओडसा (Odessa) के निकट एक सामूहिक फार्म का निरीक्षण करने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि "उस फार्म की वार्षिक औसत आय ६,७००,००० रुबल (पौन्ड १,०००,०००) है। एक उत्तम वर्ष (good year) में एक व्यक्तिगत सदस्य की नगद आय लगभग १०,०००-१२,००० रुबल होती है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक कुटुम्ब को ४५० किलोग्राम अंगूर, ६०० किलोग्राम साग-सब्जी, एक टन चारा, और इच्छानुसार शराब प्राप्त होता है।" टाशकेंट (Tashkent) के निकट एक सामूहिक फार्म का निरीक्षण करने पर जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा : "यह सामूहिक फार्म अधिक विस्तृत था। यहाँ की अधिकांश उत्पात्ति कपास थी। परन्तु पशुपालन, प्याज, बन्द-गोभी, खरबूजा-तरबूज, रेशम के कोड़े आदि का भी उत्पादन होता था। 'व्यक्तिगत क्षेत्र' अर्थात् उद्यान क्षेत्र सम्पूर्ण ८६१० एकड़ में से ४८० एकड़ भूमि आवरित करते हैं। उस फार्म में १६५० श्रमिकों सहित ११७० कुटुम्ब हैं। कपास उत्पत्ति सम्बन्धी ६० प्रतिशत कार्य यान्त्रिक रीति से होते हैं। इसमें १६-२० प्रतिशत आय पूँजी कोष (capital fund) में संचित की जाती है, तथा २ प्रतिशत सांस्कृतिक कार्यक्रम (पुस्तकालय, क्लब, व्याख्यान) में, १०-१२ प्रतिशत पूँजी आवश्यकता हेतु (बीज, खाद आदि) तथा ८-६ प्रतिशत राजकीय करों में व्यय की जाती है। अवशेष आय सरकार तथा सामूहिक फार्म के मध्य वितरित होती है।"

सामूहिक कृषक की आर्थिक आय के दो साधन हैं। प्रथम, विक्रय द्वारा प्राप्त धन कृषकों के मध्य 'नित्य दिवस कार्य इकाई' के आधार पर वितरित किया जाता है। इस आय के अतिरिक्त द्वितीय साधन कृषक के पास अपनी 'व्यक्तिगत गृहस्थी' है। उपभोग उपरान्त अवशेष उत्पत्ति वह विक्रय करता है, जो उसकी वैयक्तिक आय है। गत वर्ष में उसकी इस आय में वृद्धि हुई है तथा सोव-

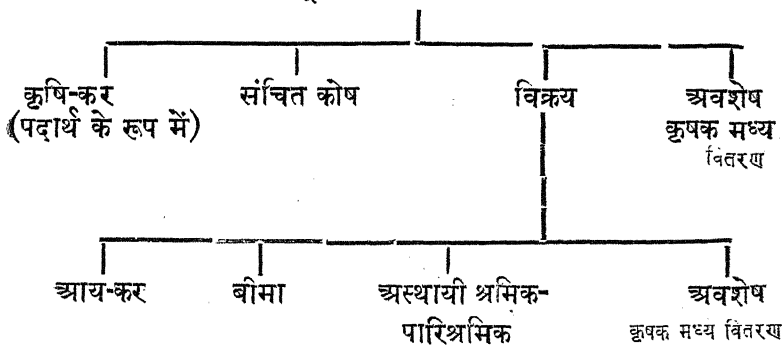
यट संघ का कथन है कि प्राणी जीवन स्तर निरन्तर सुधर रहा है। सामान्य सामूहिक फामा के कृषकों का मौद्रिक आय अधोलिखित है :

१९४०	...	२,०७० करोड़ रुबल
१९५०	...	३,४२० " "
१९५६	...	६,४५० " "

सामूहिक फामों की मौद्रिक आय का वितरण निम्न प्रकार होता है :

- (क) सर्वप्रथम राजकीय आय-कर दिया जाता है।
- (ख) इसके पश्चात सामूहिक उत्पात तथा सस्य बीमा का प्रव्याजि (pre-mium) दिया जाता है।
- (ग) एक अंश सामूहिक कोष में संचित किया जाता है।
- (घ) तत्पश्चात अस्थायी श्रमिकों को पारिश्रमिक दिया जाता है, तथा
- (ङ) अवशेष का वितरण 'नित्य दिवस कार्य इकाई' के आधार पर कृषकों को दिया जाता है।

सम्पूर्ण उत्पादन का वितरण



मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन

सामूहिक कृषि तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। सोवियट रूस की कृषि में जो उन्नति अभी तक हुई है उसका श्रेय मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन पर है। जैसा गत व्यक्त किया जा चुका है कि १९२७ के उपरान्त सोवियट सरकार ने स्थान-स्थान पर मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन स्थापित कर ट्रैक्टर संग्राहित किये तथा उन्हें भाड़े पर सामूहिक फामा को आवश्यकतानुसार प्रदान किया गया। शीघ्र ही इन संस्थाओं में प्रशंसनीय वृद्धि हुई तथा प्रत्येक स्टेशन पर

इनकी मात्रा अधिक हो गई। ये स्टेशन कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण मौलिक कार्य एवम् सेवायें शीघ्र प्रदान करने लगे, जिनके पास विभिन्न प्रकार के सामान तथा साधन उपलब्ध थे, जैसे ट्रैक्टर, घास काटने, भूमि खोदने तथा बीज बोने के यन्त्र आदि। इसके अतिरिक्त यातायात सुविधायें जैसे लारियाँ आदि भी उपलब्ध थीं, जो आवश्यकतानुसार सामूहिक फार्म के लिये उद्धृत रहती थीं। एक सारणी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा चुकी है, जो इनके वर्तमान मौलिक कार्य को स्पष्ट करती है। प्रत्येक स्टेशन के आधिपत्य में कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक २०-२५ सामूहिक फार्म होते हैं। परन्तु अधिकतर ऐसे स्टेशन हैं, जिनके अन्तर्गत प्रायः २० फार्म हैं। इन फार्मों का निरीक्षण तथा अन्य सेवायें यही स्टेशन करते हैं तथा जैसा कि गत अध्यायों से ज्ञात होता है कि अधिकतर कार्य सामूहिक फार्मों पर यान्त्रिक हैं तथा पाँचवीं एवम् छठी योजना में तो स्वतः संचालित मशीनों के प्रयोग में अधिक ध्यान दिया गया है। उत्तम आधुनिक मशीनों द्वारा सोवियट सरकार ने मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों को वैज्ञानिक एवम् प्रौद्योगिक यन्त्रों से सम्पन्न कर दिया था तथा इनको अपनी सेवा-विनिमय में सामूहिक फार्मों से सम्पूर्ण उत्पादन का कुछ प्रतिशत भी प्राप्त होता था। यद्यपि ये उत्पादन का बहुत बड़ा अंश ले जाते हैं, तथापि इनकी सेवायें भी विभिन्न हैं। सोवियट मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन एक राजकीय सम्पत्ति है, जिसका वित्तीय प्रबन्ध संघीय सरकार द्वारा होता है। इनका विशेष कार्य सामूहिक फार्मों को, जिन्हें कालखोज (Kolkhoz) कहते हैं, आवश्यक कृषि यन्त्र प्रदान करना है। ५ जून, १९२६ को श्रम-सुरक्षा समिति ने मशीन ट्रैक्टर-स्टेशन संगठन आदेश द्वारा निर्णय किया कि "मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन को आधार मान कर वैयक्तिक फार्मों को सामूहिक फार्म में सुसंगठित करना है।"

प्रारम्भ में मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन का प्रबन्ध करने के लिये एक मिश्रित संयुक्त पूँजी कम्पनी निर्माण की गई। १९३२ में ही इस कम्पनी का उन्मूलन हो गया तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन को कृषि मंत्रिमण्डल के अधीन रक्खा गया। १९३८ तक इसका वित्तीय प्रबन्ध अलग से था तथा इसके पश्चात् संघीय राज्य बजट में इसका आयोजन किया गया।

युद्ध पूर्व मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन प्रगति का संक्षिप्त लेखा इस प्रकार है :

	१९३०	१९३२	१९३७	१९४०
सम्पूर्ण मशीन ट्रैक्टर-स्टेशन...	१५८	२,४४६	५,८१८	७,०६६
ट्रैक्टर की संख्या	७,१००	७४,८००	३,६५,८००	४,३५,४००

द्वितीय महायुद्ध में लगभग २८९० स्टेशन विनिष्ट हुये, ट्रैक्टर-जमाता लगभग २९ प्रतिशत कम हो गई, 'कम्बाइन' संख्या १८ प्रतिशत, हलयुक्त ट्रैक्टर ३२ प्रतिशत, लवन मशीन (harvester) ४२ प्रतिशत, थ्रेसिंग मशीन ३६ प्रतिशत तथा बीज छींटक ट्रैक्टर ३४ प्रतिशत कम हो गये। उद्धोपरान्त दशा में निम्नलिखित सुधार हुआ :

युद्धोत्तर काल में मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन प्रगति

पद	१९५०	१९५२	१९५४	१९५६	१९५७
सम्पूर्ण मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन की संख्या...	८,४१४	८,८०७	८,६६४	८,७४२	८,०००
ट्रैक्टर की संख्या	४,८०,०००	५,७६,०००	६,४९,०००	६,८५,०००	—
'कम्बाइन' की ,,	१,७३,०००	—	२,६५,०००	२,६४,०००	३,८५,०००
भारवाहन मोटर की संख्या...	५७,०००	७१,०००	८६,०००	१,०४,०००	—
'कम्बाइन' द्वारा कटी हुई सस्य-क्षेत्र (हजार)	५०,०००	७४,०००	८६,०००	९३,०००	—

मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन तथा कालखोज अथवा सामूहिक फार्म के मध्य सम्बन्ध एक आदर्श संविदा द्वारा स्थापित होता है, जिसके अन्तर्गत दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व, मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन के कार्य तथा उनके भुक्तान आदि समस्याओं का समाधान होता है। 'कालखोज' का ईंधन, मशीन-तेल, बीज, खाद आदि आवश्यक उत्पादक सामग्रियाँ प्रदान की जाती हैं तथा इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि सस्य कटने के पश्चात अन्न यथेष्ट स्थान पर शीघ्र ही पहुँचाया जाये। इन स्टेशनों पर नियुक्त श्रमिकों के खाने, रहने आदि का भी प्रबन्ध रहता है। सस्यानुसार उत्पत्ति से भी सहायता प्रदान की जाती है। इन स्टेशनों पर कार्यसंलग्न हेतु सोवियट सरकार ने आज तक लगभग ३००० लाख रुबल से अधिक व्यय किया है, जिनमें से ४१० लाख रुबल बारह वर्ष युद्ध पूर्व कार्य में तथा गत सात वर्ष में १८८० लाख रुबल से अधिक व्यय हुआ है। वर्तमान काल में इनके पास कुल ट्रैक्टरों का ७५ प्रतिशत तथा

१ मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन के पुनर्संगठन से पूर्व

कुल 'कम्बाइन' का ७३ प्रतिशत अंश है। सोवियट सूचनाओं द्वारा १९५६ में मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन ने ६४२० लाख हैक्टेयर भूमि जोती है तथा सामूहिक कृषि का ८० प्रतिशत से अधिक कार्य इन्होंने स्वयम् किया है। इस पर आलोचकों ने यह कहा कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन प्रायः कठिन कार्यों की अवहेलना करते हैं तथा उनमें यथेष्ट क्षमता का भी अभाव है। उदाहरणार्थ, १९५६ में इन्होंने सम्पूर्ण सन सस्य का ६१ प्रतिशत बोया था, जिसका केवल २३ प्रतिशत कटाई कार्य इन्होंने किया तथा इसी प्रकार आलू के पौधे, जो ४७ प्रतिशत लगवाये गये थे केवल १९ प्रतिशत इनके द्वारा खोदे गये, क्योंकि ये अति गहन कार्य थे।

प्रत्येक स्टेशन का संचालक कृषि मंत्रिमण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सम्पूर्ण कार्य मंत्रिमण्डल के आदेशानुसार करता है। यदि विवेचन किया जाये तो ज्ञात होता है कि कालखोज मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों के ग्राहक हैं तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन उनके ठेकेदार। ये ऐसे ठेकेदार हैं जो ग्राहकों को नियंत्रित रखते हैं तथा कृषि सम्बन्धी अधिकांश कार्य करने में सहयोग देते हैं। वे सामूहिक फार्मों को विभिन्न प्रकार के सुझाव देकर राष्ट्रीय उत्पत्ति वृद्धि करने में अत्यन्त सहायक हैं। २२ जनवरी, १९५८ को खुशचेव ने एक सभा में भाषण देते हुये निम्नलिखित शब्दों में मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन की प्रशंसा किया था : "मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों ने गत वर्षों में अगणित राजनैतिक कार्य किये हैं, जिन्होंने वैयक्तिक कृषि को सामूहिक कृषि में परिणित करके गहन कार्य का सुगम बना दिया था। ये स्टेशन अन्न तथा अन्य पदार्थों के सर्वप्रमुख उत्पादक तो थे ही, साथ ही साथ राजकीय वित्त के अद्वितीय शक्तिवर्धक भी थे।"

इस महान नेता ने सितम्बर १९५३ की सोवियट नेताओं की एक बैठक में कृषि स्थिति का निम्नलिखित प्रदर्शन करते हुए यह आशा प्रकट की कि जो त्रुटियाँ सामूहिक कृषि पद्धति तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन के संगठन में सन्निद्ध थीं उनको शीघ्र ही उन्मूलन करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(१) खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थों का उत्पादन जनसंख्या की आवश्यकता-नुसार नहीं हो पाया है।

(२) अनेक सामूहिक फार्मों में खाद्यान्न, सन, चुकन्दर तथा अन्य कच्चे पदार्थों की उत्पादकता औसत से न्यून है।

(३) जिन पदार्थों में उत्पत्ति वृद्धि हुई है (जैसे आलू, साग-सब्जी, पशु-चारा आदि) उनमें उत्पादन और भी बढ़ना चाहिये, क्योंकि उन पदार्थों की अभी अत्यधिक न्यूनता है।

(४) पशुपालन उद्योग की ओर भी सरकार निरन्तर उदासीन रही है। अतः उनकी ओर भी यथेष्ट ध्यान देना चाहिए।

(५) राज्य-खेतों के संगठन में भी अनेक दोष एवम् त्रुटियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनका निवारण अति आवश्यक है।

(६) मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन के कार्यों में भी अनेक दोष आ गये हैं, जैसे अक्षमता, आदि।

मार्च १९५४ में ख़राचेव ने पुनः यह अनुभव किया कि देश में अन्न उत्पादन, माँग की अपेक्षा, न्यून है तथा जितना अन्न राजकीय उत्तरदायित्व पूर्ण करने के पश्चात् सामूहिक फाम के पास अवशेष बचता है, उनसे उनके सदस्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। परणामस्वरूप १९५३-५४ में सोवियट सरकार ने निम्नलिखित प्रादेश पास किये :

(१) सितम्बर २६, १९५३ के प्रादेशानुसार, पशु-पालन व्यवस्था में सुधार किये गये। पशु पालन उत्पत्ति का महान अंश जो पहिले सामूहिक पदाथः द्वारा सरकार को सौंप दिया जाता था, उनमें अनेक परिवर्तन किए गए।

(२) अक्टूबर १, १९५३ के प्रादेशानुसार, आलू, साग-सब्जी के उत्पादन की वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही की गई।

(३) अक्टूबर १, १९५३ के प्रादेशानुसार, मशीन ट्रैक्टर-स्टेशनों की कार्यक्षमता वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही की गई।

(४) सितम्बर २८, १९५४ के प्रादेशानुसार बंजर एवम् ऊसर भूमि के अनुकूल शोषण एवम् खाद्य उत्पादन वृद्धि हेतु अनेक कार्य किये गये।

सोवियट इतिहास में पहिली बार उच्च राज्य कर्मचारियों ने कृषि संगठन की न्यूनता का प्रदर्शन किया है। इसके पूर्व अपनी खाद्यान्न अभाव के विषय में उन्होंने स्थान-स्थान पर चर्चा की थी, पर कृषि त्रुटियों को प्रथम बार उन्होंने स्वीकृति एवम् प्रदर्शित किया है। उपर्युक्त कार्यवाहियाँ होने पर भी, कुछ उच्च पदाधिकारीगण असन्तुष्ट ही रहे तथा उन्होंने अनेक अधिक सुधारों की आवश्यकता प्रकट की।

फलस्वरूप दो और कार्यवाहियाँ १९५५ में की गई।

(क) जनवरी १, १९५५ को पशु-पालन उत्पत्ति तथा ज्वार-मक्का इत्यादि के उत्पादन के बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ नवीन कार्यवाहियाँ की जाने का आदेश प्रकाशित किया गया।

(ख) सामूहिक फार्मों पर योजना सम्बन्धी अनेक परिवर्तन करने का प्रादेश मार्च ६, १९५५ को प्रकाशित हुआ। इन प्रादेशानुसार सामूहिक फामों को

उत्पादन योजना सम्बन्धी अनेक अधिकार दिए गए और पहिले की अपेक्षा अनेक अवसरों पर उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस नवीन योजना पद्धति के अनुसार निश्चित उत्पादन लक्ष्य के अनेक आदेश, जिनके अन्तर्गत उन्हें फार्म पर कार्य करना चाहिए था, सरकार द्वारा प्राप्त हुए।

गत तीन-चार वर्षों में सोवियट कृषि संगठन में बहुत ही विस्तृत सुधार हुये हैं। यद्यपि इन सुधारों की आवश्यकता, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, १९५२ से ही प्रतीत होने लगी थी, तथापि कोई महान कार्यवाही सोवियट सरकार ने १९५५-५६ तक न की थी। सम्पूर्ण देश में लघु-विशाल संघों, समितियों एवम् समुदायों के मध्य वाद-विवाद हुए। कृषि संगठन में किस प्रकार सुधार किया जायें, सोवियट सरकार के सम्मुख एक प्रमुख समस्या थी। खुशचेव ने यह स्पष्ट कहा कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन को सुसंगठित करना अत्यन्त आवश्यक है, जिस पर देश का कल्याण अवलम्बित है। ऐतिहासिक पुष्टि करते हुए उन्होंने स्मरण कराया कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों का निर्माण ऐसे समय में हुआ था जब सामूहिक फार्मों का आधार इतना विशाल न था जितना कि इस समय है। उस समय वे निर्धन थे, उनके पास मशीन तथा यंत्रों के लिए पूँजी की न्यूनता थी तथा उन्हें कोई ऐसा अनुभव भी प्राप्त न था कि वे स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी सहयोग एवम् बिना निरीक्षण के कृषि कार्य स्वेच्छानुसार कर सकते। इसलिए मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन स्थापित किए गए थे तथा उनके पास राजकीय बजट से मशीन तथा ट्रैक्टर रक्खे गए थे ताकि सामूहिक फार्म उनसे सहयोग प्राप्त कर कृषि क्षेत्र को प्रगतिशील बना सकें। परन्तु अब दशा विभिन्न थी।

खुशचेव का विचार था कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन और सामूहिक फार्मों के मध्य संविदा स्थायी हो गया है, अतः उसका परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा अनुमान किया गया कि सामूहिक फार्म इस योग्य हो चुके हैं कि वे स्वावलम्बी बनें और मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों पर प्रत्येक कार्य के लिए आश्रित न रहें। वे इस योग्य हो गये हैं कि उन्हें विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक सुसंगठित किया जा सकता है। उनमें अब इतनी क्षमता है, कि वे विशाल पूँजी विनिमय कर सकते हैं, तथा उनके पास ऐसे साधन संचित हैं कि वे उत्तम मशीनें अपने फार्मों के लिए स्वयं रख कर मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन पर उस प्रकार आश्रित न रहें जिस प्रकार पूर्वानुसार रहते थे। यह भी स्वीकार किया गया कि कार्यक्षमता वृद्धि, उत्पादन शक्ति में प्रगति तथा खाद्यान्न न्यूनता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने हेतु मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन तथा सामूहिक फार्मों के मध्य एक नवीन सम्पर्क

स्थापित किया जाय तथा सामूहिक फार्मों को अति अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि सामूहिक फार्म के प्रबन्ध एवम् संचालन में कृषकों को स्वेच्छानुसार व्यक्तिगत अनुमति देने का अधिकार प्राप्त हो। खुशचेव ने पुनः कहा कि सामूहिक कृषि नींव को सुदृढ़ करने के उपरान्त यह महान् परिवर्तन कार्य किया जा सकता है और फार्मों को अति अधिक स्वतंत्रता भी दी जा सकती है।

मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों की अनेक त्रुटियों को अवलोकित करते हुये खुशचेव ने अपनी विचारधारा स्पष्ट की। मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों पर अधिक कार्य-भार तथा सामूहिक फार्मों के प्रबन्ध एवम् संचालन में स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण सस्य को काटने तथा ढोने में बहुत समय व्यतीत होता है। एक ही भूमि पर दो स्वामी होने के कारण भूमि तथा यंत्रों का समुचित सदुपयोग नहीं हो पाता। इसलिए कृषि संगठन में शीघ्र परिवर्तन आवश्यक समझा गया।

सामूहिक कृषकों का मशीन के क्रय में अधिकार न होने के कारण अनेक मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों को कभी कभी सरकार द्वारा ऐसी मशीनें प्राप्त हुईं जो अधिक उपयोगी न थीं। इस विचार से भी यह आवश्यक था कि सामूहिक कृषकों को भी मशीनों के संकलन एवम् क्रय में अधिकार प्राप्त होना चाहिये। उपर्युक्त लिखा जा चुका है कि सामूहिक फार्मों की आय भी गत कुछ वर्षों में अत्यधिक बढ़ गई है तथा सामूहिक उत्पादन का एक विशाल अंश प्रत्येक वर्ष सामूहिक कोष में संचित किया जाता है। अतः वे इस योग्य हो गये हैं कि अपनी आवश्यकता-नुसार मशीनें स्वयं क्रय कर सकें।

एक महान् तर्क कृषि के सुसंघाटित करने में सोवियट सरकार ने यह उपस्थित किया कि सोवियट रूस एक प्रगतिशील देश है; “समाजवाद से साम्यवाद” एक भावी महान् कार्य है; सामूहिक कृषि की निर्धनता यथेष्ट समाप्त हो चुकी है; तथा वे सर्व सम्पन्न हो रहे हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि सम्पूर्ण उत्पादन साधन उनके पास स्वयं हो जायें। यद्यपि वे राष्ट्रीय नियोजन के आधार पर सम्पूर्ण कार्य करेंगे तथापि उनमें व्यक्तिगत एवम् सामूहिक कार्यों में अति अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो सके सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी।

इन अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सोवियट सरकार ने यह विधान बनाया कि (क) मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों को भाड़े पर मशीन तथा ट्रैक्टर देने के कार्य से वंचित कर दिया जाये; (ख) उनको मशीनों को सामूहिक फार्मों के हाथ विक्रय कर दिया जाये; (ग) उनको मशीनों के मरम्मत केन्द्र के रूप में बनाये

रक्खा जाय और उनका नामीकरण मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन (M.T.S.) के स्थान पर ट्रैक्टर-मरम्मत स्टेशन (Repairing Tractor Station) किया जाये। अतः यह समस्या उत्पन्न हुई कि उनकी मशीनें सामूहिक फार्मों के हाथ किस प्रकार विक्रय की जायें।

इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे मशीन तथा ट्रैक्टरों से शून्य रहेंगे। किन्तु ऐसी अपर्याप्त विशिष्ट एवम् मँहगी मशीनें जिनका प्रयोग प्रत्येक सामूहिक फार्मों में अत्यन्त आवश्यक एवम् लाभप्रद होगा, मरम्मत-ट्रैक्टर-स्टेशन (R.T.S.) में रक्खी जावेंगी।

यह परिवर्तन यथेष्ट अवधि में होगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष तत्परता की आवश्यकता न थी। जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है कि मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन सामूहिक फार्मों के उत्पादन का अधिकांश, अनेक सेवायें प्रदान करने के उपलब्ध में प्राप्त करते थे। इन स्टेशनों के पुनर्संगठन के उपरान्त यह आवश्यक हो गया कि भुगतान पद्धति में अनेक परिवर्तन किये जायें। अब तक तो सरकार को अत्यधिक अन्न इन स्टेशनों द्वारा प्राप्त होता था, परन्तु अब इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत यह सम्भव न था। अतः राजकीय अंश कर के रूप में अथवा अन्य साधनों द्वारा उपलब्ध करने का आयोजन किया गया तथा ऐसी आशा की गई कि इस आधुनिक नवीन परिवर्तन पद्धति से खाद्य समस्या शीघ्र ही हल हो जायगी तथा सोवियट रूस साम्यवाद की ओर अग्रसर हो सकेगा। लुशचेव ने ३१ मार्च १९५८ को सर्वोच्च सोवियट (पाँचवें कानवोकेशन) की पहिली बैठक में भाषण देते हुये यह आशा प्रकट की कि इस गति से रूस साम्यवाद के निश्चित उद्देश्य को शीघ्र ही पूर्ण करेगा।

संलग्नक अध्याय

औद्योगिक संगठन एवम् नियोजन संचालन

सोवियट संघ में १९५४ के पूर्व निम्न व्यवस्थाओं द्वारा औद्योगिक उत्पादन होता था :

- (क) राजकीय उद्योग,
- (ख) औद्योगिक सहयोग समितियाँ, तथा
- (ग) वैयक्तिक उपक्रम अथवा उद्यम

इन व्यवस्थाओं में राजकीय उद्योगों द्वारा उत्पादन अधिक परिमाण में निरन्तर होता रहा, क्योंकि प्रारम्भ से ही सोवियट सरकार का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। औद्योगिक सहयोग समितियों द्वारा भी उपभोग पदार्थों का उत्पादन होता है तथा सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र में अपने ढंग का इसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि वैयक्तिक उपक्रम (private enterprise) का स्थान १९३७ के बाद पूर्णतः आलोप है। १९३७ में भी इनका प्रतिशत केवल ०.२ था, जब कि १९१३ में शत-प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन वैयक्तिक उपक्रम के आधिपत्य में था।

व्यवसायिक स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक उत्पादन का चित्रण

पद	१९१३	१९२८	१९३७	१९५४	१९५५
सम्पूर्ण उद्योग	१००	१००	१००	१००	१००
समाजवादी सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन...	—	८२.४	६६.८	१००	१००
राजकीय उद्योग	—	६६.४	६०.३	६१.८	६.२
औद्योगिक सहयोग समिति	—	१३.०	६.५	८.२	८.०
वैयक्तिक उपक्रम	१००	७.६	०.२	—	—

रूस में समाजवाद की नवीन व्यवस्था के आगमन के कारण एवम् अनेक उद्योग-धंधों का सरकार द्वारा संचालन एवम् प्रबन्ध होने से यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसके औद्योगिक संगठन एवम् नियोजन संचालन का उसी प्रकार अध्ययन करें। १९१७ से वर्तमान काल तक औद्योगिक क्षेत्र के संगठन में सोवियट सरकार ने अनेक रीतियाँ अपनाई तथा अनुभव के अनुसार उद्योग-धंधों के संगठन में निरन्तर परिवर्तन करती रही। यह ऐतिहासिक अध्ययन भी बड़ा रोचक है तथा इससे ज्ञात होता है कि सोवियट समाजवादी नियोजन प्रथा लेनिन के मस्तिष्क में प्रारम्भ से न थी, बल्कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता गया, त्रुटियाँ होती गई तथा सुधार किये गये, वै से-वैसे संशोधन द्वारा कुछ काल के पश्चात् नियोजन प्रथा का एक नव चित्रपट प्रदर्शित होने लगा। गत खण्ड में इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है।

१९१७-१९५६ के ऐतिहासिक अध्ययन तथा काल-क्रमानुसार औद्योगिक संगठन एवम् नियोजन संचालन रीतियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(१) १९१७ में लेनिन तथा उनके सहयोगियों ने आर्थिक संगठन का केन्द्र, सर्वोच्च आर्थिक परिषद् स्थापित किया। इसका कार्य व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करके उनका निरीक्षण तथा संचालन करना था। इस कार्य हेतु बारह कम्पनियों की एक अन्य समिति भी थी। सर्वोच्च परिषद् में ७०-८० सदस्य थे, जिनमें से कुछ अखिल संघ केन्द्रीय कार्यकारणी समिति (All Union Central Executive Committee), कुछ अखिल रूसी श्रमिक निरीक्षण समिति (All Russian Council of Workers' Supervision) तथा कुछ अन्य संघों के भी सदस्य थे।

(१) १९१८ के उपरान्त इस केन्द्रीय कार्यकारणी समिति के अन्तर्गत अनेक समितियाँ निर्मित की गईं, जो पृथक्-पृथक् कारखानों का नियन्त्रण करती थीं। इस केन्द्रीय समिति की रचना एवम् संगठन में समयानुसार अनेक परिवर्तन होते रहे। १९३२ में इसका परित्याग कर, प्रत्येक उद्योग हेतु मन्त्रिमण्डल स्थापित किये गये।

(२) ५ जनवरी, १९३२ के प्रादेशानुसार सोवियट रूस के तीन मौलिक मन्त्रिमण्डल (People's Commissariates) स्थापित किये गये—प्रथम, भारी उद्योग; द्वितीय, हल्के उद्योग तथा तृतीय, काष्ठ उद्योग हेतु। १९३५-४० में खाद्यान्न उद्योग हेतु एक अन्य मन्त्रिमण्डल निर्मित किया गया। ये मन्त्रिमण्डल

संघीय सरकार द्वारा स्थापित हुये थे। कुछ समय पश्चात् लोकतंत्रीय मंत्रिमण्डलों द्वारा भी इस प्रकार के मंत्रिमण्डलों की व्यवस्था हुई।

(३) शनैः शनैः यह अनुभव हुआ कि प्रत्येक औद्योगिक मंत्रिमण्डल का कार्य अत्यन्त विस्तीर्ण हो गया है, विशेषतः भारी उद्योग, जहाँ अनेक दिशाओं में विशिष्ट प्रबन्ध की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलस्वरूप एक विशाल मंत्रिमण्डल को कई भागों में विभाजित करने का निर्णय कर, प्रत्येक भाग में एक नवीन मंत्रिमण्डल स्थापित किया गया। ऐसा करने से १९३६ तक लगभग ३४ मंत्रिमण्डल बन गये जब कि १९३८ में केवल १४ थे। प्रत्येक मंत्रिमण्डल के अन्तर्गत २७ व्यवसायों में व्यवसायानुसार संचालक नियुक्त हुये। कुछ अवधि पश्चात् उद्योग-धन्धों के दूर-दूर स्थापित होने के कारण एक ही उद्योग धन्धे में कई क्षेत्र बनाये गये तथा प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग संचालक नियुक्त हुये।

(४) द्वितीय महायुद्ध काल में औद्योगिक प्रबन्ध एवम् संचालन का अधिक केन्द्रीयकरण हुआ। सम्पूर्ण सोवियट उद्योग, सोवियट रूसी सुरक्षा समिति के अधीन कर दिये गये। वैयक्तिक औद्योगिक मंत्रिमण्डलों से सम्पूर्ण उद्योग का अधिग्रहण कर केन्द्रीयकरण को उच्चतम सीमा तक पहुँचाया गया।

(५) युद्धोपरान्त विभिन्न उद्योगों को उनके व्यक्तिगत मंत्रिमण्डलों^१ को पुनः हस्तान्तरित कर दिया गया तथा यह चेष्टा की गई कि औद्योगिक मंत्रिमण्डलों की संख्या में वृद्धि कर प्रत्येक क्षेत्र को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा दृढ़तापूर्वक नियन्त्रित किया जावे।

(६) ७ मार्च, १९५३ को स्टैलिन की मृत्यु के पश्चात् केन्द्रीयकरण की नीति को अत्यधिक महत्त्व दिया गया। सन् १९५३ के पूर्व जो मोटरगाड़ी-ट्रैक्टर उद्योग मशीन तथा यंत्र उत्पादन एवम् कृषि मशीन तथा लघु यन्त्र मंत्रिमण्डल पृथक्-पृथक् थे, उनका समन्वय करके एक मंत्रिमण्डल बनाया गया, जिसका नाम मशीन-निर्माण मंत्रिमण्डल रक्खा गया। चार अन्य लघु मंत्रिमण्डलों को संयुक्त कर पथ-निर्माण मशीन एवम् यातायात मंत्रिमण्डल की रचना की गई तथा इसी आधार पर विभिन्न शक्ति साधनों के लघु मंत्रिमण्डलों का समन्वय कर एक वृहत् विद्युत् उद्योग एवम् शक्ति स्टेशन नामक मंत्रिमण्डल स्थापित

^१ १९४६ के पूर्व इन मंत्रिमण्डलों का नाम People's Commissariates था। मार्च १९४६ में इनका नाम Ministries रक्खा गया। लेखक द्वारा 'मंत्रिमण्डल' शब्द का प्रयोग दोनों स्थानों पर किया गया है।

किया गया। इस प्रकार प्राचीन ६० मंत्रिमण्डलों के स्थान पर २५ नवीन मंत्रिमण्डलों का पुनर्संगठन किया गया।

(७) छः मास उपरान्त अर्थात् सितम्बर १९५३ तक यह अनुभव हुआ कि स्थापित केन्द्रीयकरण की वृहत् मात्रा समयानुकूल नहीं है। उद्योग-धन्धे दूर-दूर होने के कारण उनका यथेष्ट प्रबन्ध एवम् संचालन केन्द्र द्वारा सम्भव न था। फल-स्वरूप पुनः विकेन्द्रीयकरण की उत्पत्ति हुई। खाद्यान्न एवम् हल्के उद्योग के एक मंत्रिमण्डल को दो भागों में पुनः विभाजित कर दिया गया तथा धातु एवम् शोधन उद्योग मंत्रिमण्डल को भी दो विभागों में पुनः बाँटा गया। इसी प्रकार उपभोग पदार्थ मंत्रिमण्डल को भी दो मंत्रिमण्डलों में पुनः विभाजित किया गया। मार्च १९५३ में जिन मंत्रिमण्डलों की संख्या २५ थी, वे अप्रैल १९५४ में ४६ तथा १९५६ में ५२ कर दी गई।

(८) १४ फरवरी १९५७ को पार्टी की केन्द्रीय समिति में यह प्रादेश पास किया गया कि औद्योगिक संगठन में महान परिवर्तन किये जायें तथा उद्योग-धन्धों के संचालन में विकेन्द्रीयकरण की नीति का अनुकरण किया जाये। इस नीति का पूर्ण विवरण, ख़ुश्चेव की राजनैतिक 'थिसिस' (Thesis), जो मार्च १९५७ में प्रकाशित हुई, प्राप्त होता है। इस महान परिवर्तन द्वारा लघु आर्थिक विभागों में उचित पारस्परिक संबंध स्थापित करना था। उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उन पर उचित निरीक्षण करने का भी आयोजन किया गया। संघीय सरकार के नियन्त्रण के साथ साथ लोकतंत्र राजकीय स्वायत्त शासन (autonomy) तथा स्थानीय निरीक्षण का प्रबन्ध किया गया। 'गासप्लान' द्वारा औद्योगिक संचालन की पूर्ण व्यवस्था केन्द्र से तो रहेगी, परन्तु यह आवश्यक समझा गया कि वार्षिक एवम् प्रचलित नियोजनों को कार्यान्वित तथा सफल बनाने हेतु प्रति दिन के संचालन कार्य में स्थानीय अधिकार भी प्रदान किये जावें। ख़ुश्चेव के आधुनिक औद्योगिक सिद्धान्तानुसार, औद्योगिक पुनर्संगठन उद्योगों के आधार पर प्रशासित न होकर राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रशासित करने का निर्णय किया गया। ऐसा आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक प्रशासन प्रजातंत्रीय केन्द्रीयकरण (democratic centralization) के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिये, जिस सिद्धान्त का प्रचलन लेनिन ने एक समय किया था। इस सिद्धान्त का मूलधार यह है कि औद्योगिक प्रशासन में कार्यशील श्रमिकों का भाग लेना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब स्थानीय साम्यवाद दल तथा अन्य श्रमिकों को औद्योगिक संचालन का अधिकार प्राप्त हो, यद्यपि इसके साथ-साथ केन्द्रीय नियोजन तथा राजकीय प्रबन्ध प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित

रहेगा। उत्पादन तथा श्रमिकों में एकता तथा सन्निद्ध होना उत्पादन का एक विशिष्ट अंग है, जिसके ऊपर साम्यवाद का सफलता आधारित है। केन्द्रीयकरण के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न करने पर नियोजन एवम् साम्यवाद सफलता असम्भव है।

अपने विचार को पुष्ट करते हुए खुशचेव ने कहा कि १९५७ तक औद्योगिक संगठन सफलतापूर्वक मंत्रिमण्डल द्वारा चल रहा था, परन्तु औद्योगिक उत्थान, भारी उद्योगों में उत्पादन वृद्धि तथा विस्तृत विशाल उद्योग निर्माण के कारण यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके प्रशासन एवम् संचालन में सुव्यवस्थित परिवर्तन किये जावें। पहिले तो प्रत्येक उद्योग के लिये एक मंत्रिमण्डल था, जिसके अधीन एक संचालक होता था। संगठन की इस उदग्र पद्धति (vertical system) में अनेक त्रुटियों के कारण आधुनिक प्रगतिशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था असंतुलित थी। अतः केन्द्रीय नियोजन के साथ-साथ स्थानीय संचालन का संलग्न होना अत्यन्त लाभप्रद समझा गया। मंत्रिमण्डल द्वारा प्रशासन एवम् औद्योगिक संचालन देश की परिस्थितानुसार न होने के कारण, निम्नांकित विभिन्न अव-गुणों से कलंकित किया गया।

(अ) नियोजन अयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक व्यवसाय उत्पादन कार्य करता था। प्रायः श्रमिक यही चाहते थे कि उनके व्यवसाय से न्यूनतम माँग हो तथा उन्हें न्यूनतम कार्य करना पड़े। श्रमिक से लेकर संचालक तक कार्यशील न थे तथा इस बात की वे उपेक्षा करते थे कि आधुनिक नवीन मशीन यन्त्रों का आविष्कार न हो, जिसमें अधिक समय, कुशलता, कार्यक्षमता आदि की आवश्यकता पड़ती है। खुशचेव ने यह संकेत किया कि ट्रैक्टर एवम् कृषि यन्त्र मंत्रिमण्डल निरन्तर एक आधुनिक चक्रयुक्त ट्रैक्टर के प्रयोग की अवहेलना करती रही, यद्यपि यह सिद्ध एवम् सत्य था कि अमुक ट्रैक्टर दैशिक एवम् कृषि सम्पत्ति है, जिसका निर्माण एवम् प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद है। पुनः विवेचन करते हुये खुशचेव ने कहा : “अनेक स्थानों पर केवल श्रमिक ही नहीं, किन्तु उच्च पदाधिकारीगण भी गुणात्मक सुधार की अवहेलना करते हुए केवल योजना लक्ष्य के परिमाण को ही पूर्ण सफल बनाने का आयोजन करते हैं।”

(ब) प्रत्येक व्यवसाय अतिअधिक संख्या में श्रमिकों की माँग उपस्थित करता है, क्योंकि योजना लक्ष्य को पूर्ण करने का यह एक सरल साधन है। प्रायः मंत्रिमण्डल के लिये यह अनुमान करना भी दुष्कर हो जाता है कि अमुक व्यवसाय में श्रमिकों की संख्या किस मात्रा में अतिरेक है।

(स) इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल द्वारा प्रशासन के अन्तर्गत श्रमिकों का

निम्न जीवन-स्तर एवम् उनमें वास्तविक उत्साह की न्यूनता गत औद्योगिक संगठन के महान् अवगुण हैं। एक सामान्य श्रमिक में केवल दो उद्देश्य दृष्टि-गोचर होते हैं। प्रथम, योजना लक्ष्यपूर्ण हो तथा द्वितीय, अधिक धन उपार्जन हो सके। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु वे ऐसी रीतियों का समावेश करते हैं जो साधारण वेतन से अधिक प्राप्त हो जाता है तथा जो योजना के गुणात्मक उद्देश्य के घातक होते हैं। वे राष्ट्रीय अथवा सम्पूर्ण योजना हित पर यथेष्ट ध्यान न देकर केवल अपना हित देखते हैं। इस महान् अवगुण को खुशचेव ने “नौकर-शाही तुच्छता” (bureaucratic narrowmindedness) की संज्ञा दी।

इन त्रुटियों के उन्मूलन हेतु यह आवश्यक था कि प्रशासन में स्थानीय स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिये। उनके संगठन उपर्युक्त उद्ग्र पद्धतानुसार न होकर राज्य क्षेत्र एवम् स्थानानुसार किया जाने का निर्णय किया गया। एक क्षेत्र में जितने भी उद्योग हों उनका निरीक्षण क्षेत्रीय आर्थिक समिति (economic council) करें तथा मन्त्रिमण्डलों को समाप्त कर दिया जावे। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु नियोजन आयोग की उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई। इसके अन्तर्गत मौलिक प्रशासन इकाई एक प्रजातंत्रीय राज्य क्षेत्र अथवा एक आर्थिक क्षेत्र होगी, जहाँ आर्थिक समिति निर्मित की जावेगी, जिसका कार्य उस क्षेत्र में जितने उद्योग-धन्धे हैं, उनका प्रबन्ध एवम् संचालन करना है।

आर्थिक समितियाँ

विभागीय प्रशासनानुसार, प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक समितियों का निर्माण किया गया है। ११ संघीय लोकतंत्र राज्यों में आर्थिक समितियाँ स्थापित की गई हैं, जिनका कार्य स्वशासन क्षेत्रों में सम्पूर्ण उद्योगों का प्रबन्ध करना है। चार विशाल संघीय लोकतंत्र राज्यों में ६२ आर्थिक समितियाँ स्थापित की गई हैं, क्योंकि उन्हें औद्योगिक प्रशासन के उद्देश्य से अनेक उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभिन्न स्थानों पर आर्थिक समितियाँ निर्माण हो चुकी हैं, परन्तु उनके पास कोई विशेष लाभप्रद कार्य नहीं हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में जहाँ आर्थिक समितियाँ नहीं हैं, उनके उद्योगों का निरीक्षण एवम् प्रशासन पड़ोस की आर्थिक समितियों द्वारा होता है, जैसे लेनिनग्रेड क्षेत्र की आर्थिक समिति, जो पड़ोस के कुछ उद्योग-धन्धों का भी निरीक्षण एवम् प्रबन्ध करती है।

आर्थिक समितियों की आन्तरिक रचना उद्योगों की विशिष्टता पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, मास्को की आर्थिक समिति जहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे स्थापित हैं अपनी सहायता हेतु अनेक प्रशासन परिषद् नियुक्त किये हुये हैं,

क्योंकि विशिष्ट उद्योग हेतु विशेषज्ञ परिषद् होना आवश्यक समझा गया है। एक आर्थिक समिति के अधिकार में क्षेत्र के सम्पूर्ण उद्योग एवम् कारखाने होते हैं। इनका कार्य यथा समय वार्षिक एवम् लघु कालीन योजनाओं की रचना करना एवम् उनके निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः सफल करना है।

प्रत्येक आर्थिक समिति के साथ एक मंत्रणा परिषद् (advisory board) होती है जिसके अन्तर्गत आर्थिक समिति के मुख्य सदस्य औद्योगिक व्यवसायों के प्रतिनिधि तथा साम्यदल एवम् श्रमिक संघ के कुछ सदस्य होते हैं। मंत्रणा परिषद् के सुझाव आर्थिक समिति स्वीकार करती है तथा उसी के मतानुसार अनेक कार्य निर्धारित किये जाते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल स्थापित किये गये हैं, जैसे रसायनिक विद्युत् शक्ति स्टेशन तथा माध्यमिक मशीन निर्माण उद्योग। इनके कार्यों में कुछ मौलिक परिवर्तन किये गये हैं। इनके अधिकार में जो उद्योग-धन्धे आते हैं उनका प्रशासन आर्थिक समितियों द्वारा ही होता है, परन्तु अन्य राजनैतिक विषयों से सम्बन्धित कार्य, मंत्रिमण्डल द्वारा किये जाते हैं। रेल एवम् जल यातायात तथा संवाद्वाहन आदि का संचालन आर्थिक समितियों द्वारा सम्भव न होने के कारण, प्रशासन मंत्रिमण्डलों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय नियोजन समिति (State Planning Committee)

राष्ट्रीय आर्थिक समितियों पर प्रशासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होने के कारण यह शंका उत्पन्न हुई कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रान्तीयता एवम् स्थानीयता जैसे दोष कहीं उत्पन्न न हो जाय, क्योंकि उनको पूर्ण अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में उद्योगों का प्रबन्ध एवम् वार्षिक योजनाओं का निर्माण स्वयम् करें। अपने क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने हेतु वे संकीर्ण विचारवादी हो सकते थे। इस डर से मुक्त होने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय नियोजन समिति उन पर नियन्त्रण रखे। यद्यपि क्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण आर्थिक समितियों द्वारा ही होगा, तथापि राष्ट्रीय हित हेतु यह आवश्यक है कि कोई संस्था ऐसी हो जो सब के हित का अनुकूल समन्वय कर सके। ऐसी संस्था राजकीय नियोजन समिति ही है। इसको अति अधिक अधिकार केन्द्रीय नियोजन क्षेत्र में दिये गये, ताकि प्रजातंत्रीय केन्द्रीयकरण सिद्धान्त (principle of democratic centralisation) ग्रहण किया जा सके।

वैज्ञानिक एवम् प्रौद्योगिक समिति (The Scientific and Technical Committee)

आधुनिक काल में प्रौद्योगिक उन्नति से पूर्णतः लाभ उठाने हेतु सोवियट

राज्य ने नवीन शिल्पकला सम्बन्धी राजकीय समिति नियुक्त की थी। शनैः शनैः इनमें अनेक त्रुटियाँ एवम् दोष उत्पन्न हो गये। प्रौद्योगिक उन्नति तथा आधुनिक मशीन निर्माण योजना बिना अनुभवी श्रमिकों तथा यन्त्रकारों के परामर्श के निर्माण की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन मशीनों में अनेक त्रुटियाँ प्रति दिन उत्पन्न होने लगीं। तत्पश्चात् इस समिति का पुनर्संगठन कर इसको वैज्ञानिक एवम् प्रौद्योगिक समिति की संज्ञा दी गई। यह समिति देश विदेश के भूत तथा वर्तमान काल के वैज्ञानिक अनुसंधानों का अध्ययन करती है, तथा उनसे अनुभव प्राप्त कर आवश्यकतानुसार नवीन निर्माण में सहयोगी होती है।

सहकारी समितियाँ (cooperative committees)

यद्यपि सोवियट रूस में सहकारी समितियाँ तीन-चार प्रकार की हैं, तथापि मुख्य समितियाँ दो ही प्रकार की कही जा सकती हैं:

- (क) उत्पादक सहकारी समितियाँ अथवा औद्योगिक सहकारी समितियाँ;
- (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ;
- (ग) गृह निर्माण सहकारी समितियाँ;
- (घ) रोगी एवम् अयोग्य व्यक्तियों की सहकारी समितियाँ।

उपभोक्ता सहकारी समितियाँ अधिकतर कच्चे पदार्थ तथा कृषि सामग्री उत्पादन करती हैं। उनका कार्य लघु व्यवसायों को प्रबन्धित करना है। वे अधिकतर डबलरोटी, माँस, साग-सब्जी तथा फल आदि का उत्पादन करती हैं। इन व्यवसायों का वार्षिक उत्पादन लगभग १,१०,००० लाख रूबल होता है। देश में बीस हजार से अधिक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं। प्रायः इनके सदस्यों की सामान्य बैठक होती है तथा इनके प्रबन्ध हेतु एक निर्वाचित परिषद् होती है। ऐसी समितियाँ प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में निर्मित की गई हैं।

उपभोक्ता समितियों की सर्वोच्च संस्था, कांग्रेस, एक केन्द्रीय संघ परिषद् निर्वाचित करती है। एक निरीक्षण आयोग की भी स्थापना चार वर्षों के लिये होता है, जो लेखे का निरीक्षण करता है।

औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से औद्योगिक सहकारी समितियाँ अथवा उत्पादन सहकारी समितियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जो १९२८ में सम्पूर्ण उत्पाद का ३ प्रतिशत, १९३७ में ६.५ प्रतिशत और १९५४ में ८.२ प्रतिशत उत्पादन करते थे। यद्यपि १९५५ से केवल ८ प्रतिशत उत्पादन इनके आधिपत्य में है, तथापि इनका उद्योग-धन्धों में बड़ा सहत्त्व है, क्योंकि अधिकतर यह उन

वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो उपभोग के लिये प्रयोग की जाती हैं। फर्नीचर, भोजनालय-सामग्री, टोकरी, वस्त्र, खिलौने, चमड़े का सामान, जूते, मुलायम लकड़ी, लोहे की सामग्री तथा चीनी के बर्तन, आदि सामग्रियों का उत्पादन इनके अन्तर्गत है। इनके परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।

अयोग्य एवम् रोगी व्यक्तियों की सहायारी समितियाँ सर्वप्रथम १९२१ में स्थापित की गई थीं। द्वितीय महायुद्धोपरान्त उनको संख्या एवम् उनके सदस्यों की संख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई है। इन समितियों द्वारा मशीन, टाइपराइटर तथा घड़ियों की मरम्मत आदि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। प्रत्यक्ष उत्पादन कार्य में इनका अधिक सम्बन्ध नहीं है।

सत्रहवाँ अध्याय

यातायात साधन

आर्थिक उत्थान हेतु सुविधाजनक यातायात साधन होना अत्यन्त आवश्यक है—विशेषकर सोवियट रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसके अन्तर्गत केन्द्रीयकरण, विशिष्टीकरण एवम् राष्ट्रीयकरण पद्धतियाँ दृढ़तापूर्वक जम चुकी हैं। देश का विस्तृत आकार होने के कारण भी, जहाँ उद्योग-धन्धे दूर-दूर स्थापित हैं, जिनको खनिज पदार्थ, कच्चा पदार्थ, एवम् खाद्य सामग्री समयानु-कूल प्राप्त होना चाहिये। यथेष्ट यातायात साधन उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग एवम् समन्वय, सुविधाजनक यातायात, जैसे रेल, सड़क, मोटर आदि पर ही आधारित है। संवादवाहन भी अद्वितीय महत्त्व रखता है। प्रत्येक क्षेत्र का प्रबन्ध तथा योजनात्मक उत्पादन, वितरण एवम् विनिमय बिना सुविधाजनक यातायात के असम्भव है।

१९१७ की क्रान्ति के उपरान्त जब सोवियट शासन स्थापित हुआ, यातायात सुविधायें प्रथम, बहुत ही कम उपलब्ध थीं तथा द्वितीय, जो थीं भी, उन्हें अति क्षति पहुँची थी तथा उनमें से अधिकांश गृह युद्ध एवम् प्रथम महायुद्ध के कारण विनिष्ट हो चुकी थीं। शनैः शनैः कुछ सुधार हुये, नवीन आर्थिक नीति काल में कुछ उन्नति हुई तथा तत्पश्चात् पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हुआ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा निर्माण के विशाल कार्यक्रम को कार्यान्वित होने एवम् योजना को सफल बनाने हेतु यथेष्ट यातायात प्रबन्ध होना आवश्यक था। सोवियट सरकार की प्रारम्भिक त्रुटि यह थी कि उसने भारी उद्योग पर तो अवश्य ध्यान देकर निर्माण कार्य को प्रोत्साहित किया, परन्तु यातायात पर यथेष्ट ध्यान न दिया गया। द्वितीय योजना, प्रथम योजना की अपेक्षा, यातायात क्षेत्र में, अवश्य कुछ समृद्धिशाली थी।

द्वितीय महायुद्ध काल में जर्मन सैनिकों ने रूस के यातायात साधन को विध्वंस किया, यद्यपि पूर्वी प्रदेशों में कुछ यातायात साधन कार्यों में वृद्धि हुई।

युद्धोपरान्त १९४६ की चतुर्थ योजना में एक विशाल रेलवे निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तथा जितना विनाश युद्ध में हुआ था, उसका केवल पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रदेशों में विशाल योजनाओं के आधार पर नवीन साधनों का प्रबन्ध भी किया गया। उद्योग यह कहना अनुचित न होगा कि व्यापार वृद्धि के अनुपात में यातायात सुविधायें उपलब्ध न हो सकी थीं।

रेल यातायात

रूस की रेल व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में इनका निर्माण कुछ प्रदेशों में तो अधिक था तथा कुछ में शून्य। इसका कारण यह था कि 'ज़ार' शासन काल में रेलवे लाइनों केवल पश्चिमी प्रान्तों में निर्मित की गईं, जहाँ देश की अधिक जनसंख्या थी तथा जो भाग अति व्यवसायी थे। मास्को के पश्चिमी क्षेत्रों में अनुकूल यातायात सुविधायें प्रदान करना इसलिये आवश्यक था कि योरोपीय देशों को इस क्षेत्र से अन्न निर्यात किया जाता था। राजनैतिक एवम् सैनिक दृष्टिकोण से भी इन्हीं प्रदेशों में 'ज़ार' काल में रेलवे लाइनें निर्माण की गई थीं।

१९१७ से १९२८ तक रेल निर्माण में विशेष प्रगति न हो पाई थी। यद्यपि व्यापार बढ़ गया था तथा रेल यातायात के ऊपर अति अधिक भार था, फिर भी सीमित साधन होने के कारण, भारी उद्योगों को अधिक महत्त्व देने के कारण एवम् गृह युद्ध में अति व्यस्त होने के कारण सोवियट सरकार रेल निर्माण की ओर उचित ध्यान न दे सकी तथा यह प्रवृत्ति अग्रिम वर्षों में निरन्तर प्रचलित रही। १९२८ से १९५५ तक लगभग २४,००० किलोमीटर नए मार्ग निर्मित किये गये तथा गत वर्ष जटिल यातायात समस्याओं के विद्यालय (Institute for Complex Transportation Problems) ने यह स्वीकार भी किया कि १९५५ में सम्पूर्ण व्यापार का ७८ प्रतिशत प्राचीन रेल द्वारा तथा अवशेष २२ प्रतिशत नवीन निमित्त मार्गों द्वारा होता है। सोवियट सरकार ने गत वर्षों में इंजन चाल की ओर विशेष ध्यान दिया, जो कि १९३२ की अपेक्षा १९४० में औसत ४२ प्रतिशत अधिक थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि १९४० में यातायात व्यापार १९३२ की अपेक्षा ४८.३ प्रतिशत अधिक हो गया। इसके प्रतिकूल उसी समय मालगाड़ियों का भार केवल ३४ प्रतिशत बढ़ा था। युद्धोपरान्त सोवियट सरकार का यह विशेष लक्ष्य हो गया कि रेल यातायात में भार एवम् चाल दोनों में लगभग समान वृद्धि हो। १९१३-५६ काल में मालगाड़ियों का संख्या १८० प्रतिशत तथा उनके आसत भार में २२० प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका प्रभाव

यह हुआ कि भाड़ा यातायात में ३७ प्रतिशत तथा भार में ४१ प्रतिशत वृद्धि हुई, जो कि अगले पृष्ठ में दी गई सारणी से स्पष्ट है :

रेल-सड़क भाड़ा प्रगति

(१९१३-५६)

पद	१९१३	१९२८	१९-२	१९४०	१९५०	१९५६
भाड़ा परिमाण (दस खरब किलोमीटर) ...	७६.४	९३.४	१६९.३	४१५.०	६०२.३	१०७६.१
औसत भाड़ा गाड़ी भार (टन) ...	५७३.०	८१७.०	९६६.०	१३०१.०	१४३०.०	१८३१.०
औसत चाल (किलोमीटर घण्टा) ...	१३.६	१४.१	१४.३	२०.३	२०.१	२४.८
औसत इंजन चाल शक्ति (टन) ...	१०.२	११.८	—	१५.४	१७.०	१८.८

इसके फलस्वरूप लाइनों की शक्ति अति अधिक प्रयोग की जा रही है। मुख्य दोहरे मार्गों पर भाड़ा लाइनों की शक्ति प्रत्येक दिशा में लगभग १४४ गाड़ियाँ ले जाने की है। कुछ क्षेत्रों में दोनों ओर से ११० गाड़ियाँ चलती हैं। एक ही मार्ग की लाइनों पर भी लगभग ४० गाड़ियाँ दोनों ओर से नित्य आती जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि रूस की रेलवे लाइनें अपनी अधिकतम सीमा तक प्रयोग की जाती हैं।

रूसी रेल यातायात साधन की दूसरी विशेषता यह है कि रेल-सड़क पद्धति पर निर्दयी एवम् कठोर अनुशासन की छाप है। १९४३ में रेल-सड़क श्रमिकों पर 'मार्शल कानून' आरोपित किया गया, जो कि युद्धोपरान्त भी प्रचलित रहा। १९४९ में रेल-सड़क के प्रत्येक क्षेत्र में राजनैतिक विभाग स्थापित किए गए, जिनका कार्य श्रमिकों में साम्यवाद बढ़ाना, उनसे अति अधिक काम लेना तथा उनको तानाशाही अनुशासन के अन्तर्गत रखना था।

१९१३-५२ तक एक तीसरी विशेषता रेल यातायात में दृष्टिगोचर होती है। पूर्वी प्रदेशों में रेल द्वारा यातायात गत वर्षों में अधिक हुआ है। यह वृद्धि केवल परिमाण में ही नहीं, बल्कि सापेक्ष रूप में भी निरन्तर हुई है। इसके प्रतिकूल पश्चिमी प्रान्तों में भाड़ा प्रतिशत में हास हुआ है, जैसा कि रूस के विज्ञापन साधनों से पता चलता है।

सोवियट संघ की भाड़ा-गति

(योग प्रतिशत)

प्रदेश	माल भाड़ा देय			माल भाड़ा प्राप्ति		
	१९१३	१९४०	१९५२	१९११	१९४०	१९५९
पश्चिमी प्रदेश	६०.३	७२.७	६५.९	६०.०	७४.५	६७.०
पूर्वी प्रदेश	६.७	२७.३	३४.१	१०.०	२५.५	३३.०
	१००	१००	१००	१००	१००	१००

रेल भाड़ा दर की भी यथेष्ट सूचना प्रर्याप्त नहीं है। विदेशियों ने इस पर रूसी रेल प्रशासन की बड़ी आलोचना की है। १९३०, १९३९ और १९५९ में जो राजकीय कार्य किये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि भाड़ा दर, सेवा के आधार पर, निश्चित किया जाता है, क्योंकि सोवियट रूस में पारिश्रमिक एवम् अन्य उत्पादन साधनों की लागत युद्ध काल से अति अधिक बढ़ गई है। इसलिए ऐसा अनुमान किया जाता है कि भाड़ा दर में भी काफी वृद्धि हुई होगी। पूँजीवाद देशों में यातायात भाड़ा उपभोक्ता की देय शक्ति (ability to pay) पर निश्चित की जाती है। परन्तु सोवियट रूस में इसका वास्तविक सिद्धान्त सेवा-लागत (cost of service) है।

नदी-नहर यातायात

आन्तरिक जल यातायात विशेषतौर से भारी पदार्थों में प्रचलित है। १९१३ में क्रान्ति के पूर्व इसका अति महत्त्व था, परन्तु १९२८ के पश्चात् घटता गया तथा इनके स्थान पर रेल यातायात का महत्त्व बढ़ता गया। आन्तरिक व्यापार में इस यातायात का प्रचलन लगभग ११ प्रतिशत है, जबकि रेल यातायात ८४ प्रतिशत है। कुल व्यापार योग में इनका अंश निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रतिशत
१९१३	४२.२
१९२८	२१.१
१९४०	१२.३
१९५०	१२.०
१९५४	११.६
१९५५	११.७

इस गति से इस निष्कर्ष पर न पहुँचना चाहिए कि जल यातायात का महत्त्व सोवियट रूस में किसी प्रकार कम है। सोवियट राज्य स्थापना के पूर्व जल यातायात सुधार एवम् उत्थान की ओर 'जार' की सरकार ने अति अधिक ध्यान दिया था। परन्तु वैज्ञानिक असुविधाओं के कारण उनका निर्माण कार्य अधिक परिमाण में न किया जा सका। सोवियट पंचवर्षीय योजनाओं में इस यातायात पर विशेषकर ध्यान दिया गया और निर्माण कार्य द्वितीय महायुद्ध से पूर्व प्रारम्भ हो गया। युद्ध काल में इस कार्य में बाधा पड़ी और सम्पूर्ण नियोजन कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गए। १९५०-५२ में स्टैलिन एक शक्तिशाली तानाशाह था और उसने "महान साम्यवादी रचनायें" अथवा "प्रकृति के सम्पूर्ण रूपांतरण हेतु स्टैलिन के कार्यक्रम" नामक विशाल योजनायें निर्माण कीं। स्टैलिन की मृत्यु के पश्चात् निर्माण प्रगति में हास हुआ, जिसके कारण पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध कटाक्ष करना प्रारम्भ किया। छठीं पंचवर्षीय योजना में नद्य इंजीनियरिंग निर्माण के विशाल कार्यक्रम निश्चित किए गए और उनको पूर्ण करने के लिये सप्तवर्षीय योजना में उनका उचित आयोजन किया गया।

समुद्री यातायात

इस क्षेत्र में भी सोवियट रूस अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। बहुत से बन्दरगाह प्रत्येक वर्ष ३ से ६ मास तक बर्फ से आच्छादित रहते हैं। परन्तु विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाने की महान् आकांक्षा से प्रेरित होकर गत वर्षों में सोवियट रूस ने इस ओर अधिक ध्यान दिया है और अनेक नवीन बन्दरगाह विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण किये गए हैं। सोवियट रूस का विदेशी व्यापार भी अधिक न होने के कारण इस ओर अधिक प्रगति न हो पाई है। परन्तु जितनी भी उन्नति गत वर्षों में हुई थी उसका मुख्य कारण सोवियट रूस के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अति अधिक शक्तिशाली होने की आकांक्षा है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व पश्चिमी प्रदेशों में जो नवीन बन्दरगाह स्थापित किये गये थे, युद्ध में उनको अत्यधिक क्षति पहुँची। युद्धोपरान्त १९४६-५० में एक विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल बन्दरगाहों का पुनरुद्धार ही नहीं, बल्कि पूर्वी तटों पर अनेक नवीन बन्दरगाह स्थापित किये गये। चौथी योजना में १९४० की अपेक्षा दुगुना निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

वायुयान यातायात

यह रूस का सर्वोत्तम यातायात साधन है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़कों तथा रेलों से सम्बद्ध नहीं हैं, परन्तु वायुयान यातायात द्वारा उन्हें सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं। पूर्वी प्रदेशों में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रेल तथा सड़कों

का निर्माण लाभप्रद नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों से अधिक परिमाण में सामान यातायात नहीं होता। परन्तु सैनिक एवम् युद्ध के दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों को द्रुतगामी एवम् उत्तम यातायात साधन द्वारा प्रत्येक स्थान से सम्मिलित करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सड़कें अथवा रेल निर्माण में प्रारम्भिक व्यय अधिक होता है। वायुयान यातायात इस दृष्टिकोण से सस्ता पड़ता है, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ विज्ञान, शिल्पकला तथा इंजीनियरिंग अति उन्नति-शील हैं। १९४८ के उपरान्त अनेक स्थानों पर स्थायी रूप से रात्रि वायुयान पद्धति संचालित की गई और शीघ्र ही सुदूर क्षेत्रों में यह प्रचलित हो गई। १९४८ में मास्को एवम् व्लाडीवोस्तोक के मध्य प्रति मास दस बार वायुयान उड़ते थे, जो १९४९ से लगभग प्रति दिन उड़ने लगे। १९४८ में लगभग ५०० मागां पर वायुयान का प्रयोग होता था जो अभिन्न एक वर्ष में ही अति अधिक हो गये। १९४० की अपेक्षा १९४९ में वायुयान सेवायें आठ गुना हो गई थीं। १९५० में सोवियट पदाधिकारियों का अनुमान था कि वायु लाइनों द्वारा सोवियट रूस किसी भी पूँजीवाद देश की अपेक्षा अधिक सामग्री यातायात करता है। १९४० को आधार मानकर यदि अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होता है कि १९५० में वायुयान यातायात सूचकांक ३६२, १९५४ में ६३२ तथा १९५५ में ७२८ था। इससे अधिक उन्नति भाड़ा-विक्रय में हुई। निम्नलिखित सारणी इसकी पुष्टि करती है :

वायुयान यातायात के मूल सूचकांक^१

(१९४० = १००)

यातायात	१९४०	१९५०	१९५४	१९५५
यात्री	१००	३६२	६२	७२८
डाक	१००	२१०	४३३	४६२
भाड़ा	१००	३१८	४८२	५११
भाड़ा-विक्रय	१००	५८६	१,०५४	१,०८२

^१ National Economy of the U. S. S. R. 1957, p. 166.

अठारहवाँ अध्याय

सोवियट ट्रेड यूनियन संगठन

सोवियट संघ के आर्थिक एवम् औद्योगिक जीवन में ट्रेड यूनियन संगठन का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐसा अनुमानित है कि उन्होंने श्रमिका के जीवन-स्तर सुधारने में राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में तथा आर्थिक एवम् औद्योगिक जीवन को कार्यान्वित करने में प्रशंसनीय कार्य किये हैं। विश्व के अन्य किसी देश में ट्रेड यूनियन ने अपने कार्यों में इतनी अधिक सफलता नहीं प्राप्त की है, जितना सोवियट ट्रेड यूनियन ने।

सोवियट संघ में श्रम का स्थान अति उच्च है। उनको अपने कार्य हेतु यथा समय श्रेय, शौर्य, प्रतिष्ठा एवम् ख्याति प्राप्त हुई है। स्टालिन ने कभी कहा था : “हमारे देशवासी पराश्रयी एवम् शोषका हूँ काई कार्य नहीं करते—वे संलग्नता से स्व-वर्ग एवम् स्व-समाज के उत्थान हूँ अध्यवसाय करते हैं, जहाँ शासनसत्ता सर्व-कुशल वर्ग के आधिपत्य में होती है।”

सोवियट विधान के अनुसार, ट्रेड यूनियन श्रमिक समुदाय का ऐसा संगठन है जिसमें सम्पूर्ण देश के लगभग सभी व्यवसाय के श्रमिक एवम् कर्मचारी स्वेच्छानुसार बिना किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम् अन्य वर्गीय भेद-भाव के सदस्य होते हैं। अपने सदस्यों की आत्मा में सोवियट राज्यभक्ति, तथा साम्यवादी कार्यशील प्रवृत्ति कूट-कूट कर भर देते हैं। इस विधान के अनुसार श्रमिकों के मध्य सांस्कृतिक एवम् भौतिक प्रगति में वे सहयोग देते हैं। सोवियट नेताओं के कथनानुसार ट्रेड यूनियन संगठन का सर्वहारा वर्ग के प्रत्येक प्राणी में अन्तर्राष्ट्रीय एकता-वृद्धि कार्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे ज्ञान एवम् कार्यक्षमता वृद्धि हेतु मौलिक स्तम्भ हैं। लेनिन के वक्तव्यानुसार :

“ट्रेड यूनियन एक ऐसी शिक्षा सम्बन्धी संस्था एवम् संगठन है, जो विशिष्ट श्रमिकों की नियुक्ति तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह एक ऐसा केन्द्र है,

जिसको प्रशासन स्कूल, प्रबन्ध स्कूल अथवा साम्यवादी स्कूल की संज्ञा दी जा सकती है।”

ट्रेड यूनियन के कार्य

(१) वे श्रमिकों एवम् कर्मचारियों में समाजवादी प्रतिस्पर्धा सुसंगठित करके, राज्य योजनाओं द्वारा निश्चित लक्ष्य केवल पूर्ण ही नहीं करते, बल्कि उन्हें अत्यधिक प्रबल बनाते हैं, श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तथा उत्पत्ति गुण में सुधार करके उत्पन्न लागत ह्रास में सहयोग प्रदान करते हैं।

(२) वे श्रमिकों के पारिश्रमिक निर्धारण एवम् नियोजन में भाग लेते हैं। तथा इस पर अधिक ध्यान देते हैं कि श्रमिकों को वेतन, उनके कार्य एवम् समयानुसार, सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके।

(३) वे श्रमिकों एवम् कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता वृद्धि में सहयोग देते हैं।

(४) वे श्रमिकों के मध्य संघर्ष अथवा वैमनस्य निवारण करते हैं।

(५) वे राजकीय सामाजिक बीमा प्रबन्ध, गृह निर्माण निरीक्षण, सांस्कृतिक सुविधायें, कैंटीन, स्थानीय यातायात तथा अन्य राजकीय सेवाओं के प्रबन्ध हेतु उपयोगी होते हैं।

(६) वे सामान्य शिक्षा एवम् सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक स्तर के वृद्धि में स्वयम् पूर्ण अधिकार रखते हैं।

(७) वे महिलाओं के मध्य एकता की भावना जागृति कर, उन्हें राजकीय समस्याओं को सुलझाने में सुयोग्य बनाते हैं।

(८) वे विभिन्न राजकीय समितियों एवम् राजकीय आयोगों में श्रमिकों के प्रतिनिधि बनकर श्रम कल्याण एवम् सांस्कृतिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यों में हाथ बटाते हैं।

ट्रेड यूनियन के सदस्यों के सामान्य अधिकार

(१) ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्य को यूनियन की सामान्य बैठक में भाग लेने का अधिकार है।

(२) विभिन्न सभा, समिति तथा परिषद् में उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार है।

(३) उसे ट्रेड यूनियन की सभाओं के सम्मुख यूनियन के कार्यों तथा समस्याओं के सुधार सम्बन्धित सुझाव उपस्थित करने का अधिकार होता है।

(४) वे स्थानीय एवम् अन्य यूनियन क्रियाओं की आलोचना ट्रेड यूनियन की बैठकों में कर सकते हैं।

(५) वे अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से ट्रेड यूनियन

के सम्मुख औद्योगिक प्रबन्धकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

(६) ट्रेड यूनियन सभा में व्यक्तिगत समस्याओं को प्रस्तुत करते समय उनको स्वतः उपस्थित रहने का अधिकार है।

ट्रेड यूनियन सदस्यों के विशिष्ट अधिकार तथा सुविधायें

(१) एक ट्रेड यूनियन के सदस्य को साधारण श्रमिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक बीमा के हित प्राप्त हैं।

(२) एक ट्रेड यूनियन के सदस्य को विश्राम-गृह, 'सनीटोरियम' तथा स्वास्थ्य व्यायामशालाओं में साधारण श्रमिकों की अपेक्षा प्रधानता मिलती है। उनके बच्चों को साधारण श्रमिकों के बच्चों की अपेक्षा 'किंडरगार्टन' तथा युवक "पाइनियर कैम्प" की प्रदर्शिनी एवम् मेलों में सम्मिलित होने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है।

(३) एक ट्रेड यूनियन के सदस्य को ट्रेड यूनियन संचित कोष से आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

(४) इसके सदस्य को बिना किसी व्यय के आवश्यकता पड़ने पर विधिक परामर्श (legal advice) प्राप्त होती है।

(५) उसके कुटुम्ब को ट्रेड यूनियन द्वारा संचालित अनेक मनोरंजक खेल-कूद एवम् नाटक आदि कार्य क्रमों में सम्मिलित होने का पूर्व अधिकार होता है, तथा

(६) उसे ट्रेड यूनियन संगठन की पारस्परिक सहयोगी समिति द्वारा प्रदान की हुई सम्पूर्ण सुविधायें प्राप्त होती हैं।

ट्रेड यूनियन संस्थाओं की रचना

उद्योग को आधार मान कर सोवियट रूस में ट्रेड यूनियन का संगठन किया गया है, जैसे :

(क) एक कारखाने के श्रमिक, संचालन, इंजीनियर तथा प्रत्येक कर्मचारी, उस उद्योग अथवा व्यवसाय की समिति (shop committee) के सदस्य होते हैं।

(ख) प्रत्येक नगर में कारखाने एक नगर समिति के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं।

(ग) प्रत्येक जिले में एक निर्वाचित जिला समिति स्थापित की जाती है।

(घ) प्रत्येक प्रान्त में एक निर्वाचित प्रान्तीय अथवा प्रादेशिक समिति स्थापित होती है।

(ड) प्रत्येक जनतंत्र राज्य में एक निर्वाचित जनतंत्र समिति निर्मित की जाती है।

(च) सम्पूर्ण जनतंत्र समितियों द्वारा एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की जाती है, जिसको "अखिल संघ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन समिति" की संज्ञा दी गई है।

(छ) ट्रेड यूनियन की आदेश संस्थाएँ (directing bodies) निम्न-लिखित होती हैं :

- (i) कारखाने समिति की सामान्य बैठक (general meeting);
 - (ii) नगर, जिला, प्रान्तीय तथा जनतंत्र समितियों की सभा (conference) ;
 - (iii) सम्पूर्ण देश की केन्द्रीय समिति की कांग्रेस (congress) तथा
- (अ) कार्य संचालन हेतु सामान्य बैठक, सभा तथा कांग्रेस अपनी-अपनी परिषद् निर्वाचित करते हैं, जैसे :

- (i) फैक्टरी की सामान्य बैठक में एक कारखाना परिषद् निर्वाचित की जाती है।
- (ii) नगर, जिला, प्रान्तीय अथवा जनतंत्र राज्य की समितियाँ भी स्वतः परिषद् निर्वाचित करती हैं, तथा
- (iii) ट्रेड यूनियन कांग्रेस में केन्द्रीय परिषद् निर्वाचित की जाती है।

रूसी ट्रेड यूनियन के विशेष गुण

(उनकी विदेशी ट्रेड यूनियन से तुलना)

(१) सोवियट संघ के ट्रेड यूनियन का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वे राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में पूर्ण सहयोग देते हैं। उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वे केवल सामूहिक रूप से अपनी अवस्था सुधारने, वेतन बढ़ाने, न्यूनतम लागत पर निर्वाह करने तथा अनेक सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु ही केवल नहीं स्थापित किये गये हैं, तथापि उन पर अनेक उत्तरदायित्व हैं जिनको उन्हें पूर्ण करना है। वे श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा समय की अपव्ययता का निरीक्षण करते हैं। वे केवल आयोजित लक्ष्य ही पूर्ण नहीं करते, बल्कि उत्पादन वृद्धि हेतु भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनका दृष्टिकोण औद्योगिक स्वार्थमय के स्थान पर राष्ट्रीय होता है। ट्रेड यूनियन की सभाओं, बैठकों तथा कांग्रेस में श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा राष्ट्रीय योजना के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी त्रुटियों तथा उनके निवारण आदि विषयों पर वाद-विवाद होते हैं, उदाहरणार्थ सोवियट ट्रेड यूनियन की १२ वीं कांग्रेस में जो मास्को में मार्च १३ से २८ तक (१९५६) हुई, "अग्रिम सत्रवर्षीय योजना एवम् उसके महान्

कार्य, श्रमिक-उत्तरदायित्व, समाजवाद प्रतिस्पर्धा, श्रमिकों को कार्यक्षमता आदि" विषयों पर विवेचन हुआ। उस बैठक में अधिकांशतः वक्ताओं का यही विचार था कि "श्रमिकों को भविष्य में महान कार्य करने हैं, राष्ट्रीय उन्नति में सहयोग प्रदान करना है तथा सप्तरवर्षीय योजना को पूर्णतः फलीभूत करना है।" मार्च २७-२८, १९५६ की अखिल संघ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभापित वी० ग्रिशिन (V. Grishin) ने ट्रेड यूनियन के सम्मुख यूनियन का प्रधान कार्य निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया :

"अर्थ व्यवस्था नियोजन कार्य में सोवियट ट्रेड यूनियन प्रगतिशील कार्य कर रहे हैं योजनाओं तथा श्रम उत्पादन वृद्धि हेतु वे यथेष्ट कुशलता एवम् सम्पूर्ण शक्ति सहित संलग्न हैं।"

सोवियट सरकार ने प्रारम्भ से ही ट्रेड यूनियन द्वारा श्रमिकों में कार्य कुशलता वृद्धि का उद्देश्य निर्धारित किया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मई ५, १९३५ को स्टैलिन ने घोषणा की : "कर्मचारीगण स्वतः सब कुछ निर्णय कर सकते हैं।" १५ मई को ही ट्रेड यूनियन की एक बैठक में इन्जीनियर तथा शिल्पकला के कर्मचारी एवम् अन्य श्रमिकों ने यह निश्चय किया कि कार्य पद्धति में आवश्यक सुधार होना चाहिये, भूति वैज्ञानिक ढंग से कार्यक्षमता पर आधारित होना चाहिये तथा उत्पादक शक्तियों को पूर्ण कुशलता उपलब्ध होनी चाहिये। इन विषयों पर विवेचनात्मक वाद-विवाद हुये। अगस्त ३०, १९३५ को एक खान प्रबन्धक "स्टेकनाव" (Stakhanov) ने ६ घन्टा कार्य कर १०२ टन कोयला उत्पादन करके सम्पूर्ण प्राचीन अभिलेखन (old record) सीमालंघन कर दिया। कार्य उत्पादनानुसार उसे २२५ रुबल भूति केवल उस अवधि के प्राप्त हुये, जो एक सामान्य श्रमिक के मासिक भूति के तुल्य था।

इस विस्मित कार्य से अत्यन्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसी आधार पर ट्रेड यूनियन द्वारा क्षमता वृद्धि हेतु आन्दोलन संचालित किया गया। समाचार पत्रों में 'स्टेकनाव' की महान प्रशंसा हुई तथा उसी के नाम से 'स्टेकनाव आन्दोलन' संचालित किया गया। इस प्रकार की अनेक आश्चर्यजनक घटनायें सोवियट इतिहास में प्राप्त हैं, जिनसे ट्रेड यूनियन अत्यन्त प्रोत्साहित हुआ है।

गत कुछ वर्षों से सोवियट ट्रेड यूनियन ने एक नवीन समाजवादी प्रति-द्वन्द्वता (socialist emulation) कार्य पर अधिक महत्त्व दिया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक अपने प्रति दिवस कार्य अंश को पूर्ण कर अति अधिक उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। यह आन्दोलन १९५६ में चलाया गया था, जिसका श्रेय डानबास को खान के श्रमिक, निकोली ममाई

(Nikoli Mamai) को है ।^१ ऐसे कार्य पूँजीवाद देशों में ट्रेड यूनियन द्वारा नहीं किये जाते ।

(२) सोवियट संघ में ट्रेड यूनियन रचना का आधार एक कारखाना अथवा उद्योग है । इससे तात्पर्य यह है कि एक कारखाने के श्रमिक तथा कर्मचारी शिक्षित-अशिक्षित, कुशल-अकुशल, तथा प्रबन्धक-संचालक आदि सब उस कारखाने के यूनियन के सदस्य हो सकते हैं । ऐसा पूँजीवाद देशों में नहीं है, जहाँ वर्गीय-विभिन्नता बृहत्ताकार है । एक पूँजीवाद देश में जहाँ कारखाने वैयक्तिक व्यापारियों अथवा पूँजीपतियों के अधिकार में रहते हैं, संचालक अथवा प्रबन्धक वर्ग श्रमिक वर्ग से भिन्न समझे जाते हैं तथा वे श्रमिक संघ में सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि वहाँ श्रम-पूँजी संघर्ष होने के कारण श्रम तथा पूँजी दो विभिन्न वर्ग हैं ।

(३) सोवियट सरकार के मतानुसार ट्रेड यूनियन एक स्वाधीन निर्वाचित संस्था है । सरकार उनके निर्माण, निर्वाचन अथवा संगठन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती । उनके सम्पूर्ण कार्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा होते हैं । पूँजीवाद देशों में ट्रेड यूनियन के सम्पूर्ण कार्य नियुक्त-व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, जो वेतन पर कार्य करते हैं । इसके प्रतिकूल सोवियट रूस में ट्रेड यूनियन सदस्य सम्पूर्ण कार्य स्वयम् करते हैं ।

(४) यद्यपि ट्रेड यूनियन राजकीय विभाग नहीं हैं, तथापि उनकी प्रवृत्ति सरकार से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना है । ट्रेड यूनियन अनेक ऐसे कार्य अवश्य करते हैं, जो साधारणतः सरकार द्वारा किये जाने चाहिये । उदाहरणार्थ अल्पकालीन समाज बीमा का पूर्ण प्रबन्ध सोवियट रूस में ट्रेड यूनियन करते हैं, जब कि अन्य देशों में यह कार्य राजकीय विभाग द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार राजकीय कारखाने होने के कारण उनके निरीक्षण का कार्य राजकीय पदाधिकारियों द्वारा होना चाहिये, परन्तु सोवियट रूस में यह कार्य भी ट्रेड यूनियन ही करते हैं ।

१ फरवरी ५, १९५८ को 'प्रवदा' ने समाई के विषय में लिखा : "उसका जन्म कुवान ग्राम में हुआ था । प्रारम्भ में वह एक सामूहिक फार्म पर कार्य करते थे । उसके पश्चात् एक सेना में नियुक्त हुये, किन्तु कोई विशेष योग्यता न प्रदण कर सके । १९५३ में सेना से उनकी छटनी हो गई । तत्पश्चात् वह अपने पिता एवम् भाई के यहाँ डानबास आये । कोयले की खान पर उन्हें काम करना पड़ा, जिससे वह अत्यन्त असंतुष्ट रहे । परन्तु शीघ्र ही इस कार्य में निपुण होने के उपरान्त वह एक 'टोली' के नेता हो गये । अप्रैल १९५७ को उन्हें 'वीर पुरुष' ('hero') की पदवी दी गई । वह इस समय साम्यवाद पार्टी के सदस्य हैं और १९५८ में सर्वोच्च सोवियट में निर्वाचित किये गये हैं । सितम्बर १९५६ में उनकी 'टोली' ने प्रतिस्पर्धा द्वारा १ टन कोयला प्रति दिन के निश्चित अंश से अधिक उत्पादन किया । उसी समय से समाजवादी प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिद्वन्दता पद्धति का प्रचलन हुआ ।

(५) अखिल संघ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन समिति ऐसी संस्था है जिससे विभिन्न ट्रेड यूनियन सम्बद्ध हैं तथा उसके निर्णयों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है।

(६) सर्वमहान गुण तो यह है कि सोवियट ट्रेड यूनियन संगठन अनिवार्य नहीं है। अपनी स्वेच्छानुसार अंशदान प्रदान कर कोई व्यक्ति ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। परन्तु जैसा कि उपर्युक्त लिखा जा चुका है कि कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार एवम् सुविधाएँ एक सदस्य को प्राप्त होते हैं जिनके कारण प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ट्रेड यूनियन सदस्य होना चाहता है। मार्च १९५६ में सोवियट रूस में लगभग ५२७.८० लाख श्रमिक ट्रेड यूनियन के सदस्य थे।

स्पष्ट है कि सोवियट रूस में ट्रेड यूनियन संगठन कुछ ऐसे कार्य करते हैं, जो अन्य देशों में उनके द्वारा नहीं किये जाते। पूँजीवाद देश में उनके विभिन्न उद्देश्य रहते हैं। वे अपने को पूँजीपति वर्ग से अत्यन्त भिन्न समझकर उनसे संघर्ष करना ही तथा वेतन अथवा पारिश्रमिक वृद्धि ही अपना महत्त्वपूर्ण कार्य समझते हैं। सोवियट रूस में इस संघर्ष का कोई स्थान नहीं है।

आलोचनात्मक अध्ययन : आलोचकों का विचार है कि सोवियट ट्रेड यूनियन सरकार के आश्रित हैं और उनका अपना स्वयम् कोई व्यक्तित्व नहीं है। साम्यवाद पार्टी जो सोवियट सरकार एवम् सोवियट अर्थ व्यवस्था को संचालित एवम् नियन्त्रित करती है, उसी के अधीन सोवियट ट्रेड यूनियन भी हैं तथा उसका ट्रेड यूनियन पर पूर्ण आधिपत्य है। इसमें आश्चर्य नहीं कि ऐसी दशा में वे हड़ताल अथवा कोई औद्योगिक असंतोष एवम् अशान्ति उत्पन्न नहीं कर सकते और यही कारण है कि आज २५ वर्षों से ट्रेड यूनियन द्वारा कोई हड़ताल अथवा औद्योगिक अशान्ति की कोई घटना सोवियट रूस में सुनने में नहीं आई है। वेतन तथा पारिश्रमिक भी सरकार द्वारा निश्चित है जो ट्रेड यूनियन को भी स्वीकृत है। पश्चिमी देशों की आलोचना है कि सोवियट ट्रेड यूनियन सरकार का एक अंग है, उस पर पूर्णतः आश्रित हैं, तथा उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है।

सोवियट संघ का कथन है कि रूस श्रमिकों की एक सरकार है जहाँ कारखाने तथा व्यवसाय भी श्रमिकों द्वारा प्रबन्धित तथा संचालित किये जाते हैं। अतः अर्थव्यवस्था की इस संयुक्त संघ (company union) प्रकृति में स्वामी तथा श्रमिक के मध्य में संघर्ष निर्मूल है, जो पूँजीवाद देशों में मूलाधार हैं। समाजवादी देश में स्वामी तथा श्रमिक के हित में कोई मौलिक अन्तर नहीं रहता। वे दोनों एक ही वर्ग के समझे जाते हैं, जैसा पूँजीवाद देश में नहीं हो पाता। सोवियट ट्रेड यूनियन उत्पादन कार्य में हाँथ बटाते हैं तथा श्रमिकों की

कार्यक्षमता में वृद्धि एवम् योजना के निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण करके उन्हें अति अधिक सफल करने के कार्य में संलग्न रहते हैं। अतः उत्पादन वृद्धि एवम् राष्ट्रीय प्रगति से श्रमिकों का कल्याण एवम् उन्नति होती है, क्योंकि समाजवादी देश में पूँजीपति वर्ग शून्य होता है।

१९२०-१९२१ में इस विषय पर यथेष्ट वाद-विवाद हुआ था। एक दल का तो यह विचार था कि ट्रेड यूनियन का स्वतः व्यक्तित्व रहे तथा उनको स्वतंत्रता हो कि वे औद्योगिक संगठन के कार्य अपने अधिकार में करें। दूसरे दल का यह विचार था कि सोवियट संघ में ट्रेड यूनियन का स्वतंत्र रहना अमान्य है। उनको राज्य में सम्मिलित कर श्रम विभाग उनके अधीन कर दिया जाये। स्पष्ट शब्दों में ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीयकरण हो जाये। १९२० में ट्राट्स्की (Trotsky) का यही मत था, जिसने विभिन्न दल के नेताओं को तर्क द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि सोवियट राज्य में ट्रेड यूनियन का स्वतंत्र रहना एक अनुचित बात है। इसके प्रतिकूल मिकेल टाम्स्की (Mikhail Tomsky) का, जो उस समय ट्रेड यूनियन के प्रधान थे, विचार था कि सोवियट संघ का एक विभिन्न स्वतंत्र जीवन है, जिन्हें अपने हित को राजकीय एवम् कारखाना संचालकों से हमेशा सुरक्षित रखना है। लेनिन का यही विचार था, जिसने मार्च १९२१ में व्यक्त किया : “यद्यपि हमारी श्रमिक-सरकार है, तथापि उसमें कर्मचारी विवृति सन्निद्ध हैं। फलस्वरूप यह कहना अनुचित न होगा कि सर्व-हारा वर्ग को सुसंगठित एवम् राजकीय कर्मचारियों से सुरक्षित कर, उन्हें स्वतः सुव्यवस्थित एवम् दृढ़ करना, ट्रेड यूनियन का परम कर्त्तव्य है।”

१९२२ तथा १९२६ में भी इसी प्रकार राजनैतिक मतभेद निरन्तर बना रहा। टाम्स्की तथा उनके अनुयायियों को जिन्होंने ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता स्थिर रखने की पूर्ण चेष्टा की थी, राजकीय पद से हटा दिया गया तथा शेवर्निक (Shvernik) आदि जैसे व्यक्तियों को उस पद पर आसीन किया गया, जो स्टैलिन के अनुयायी थे।

जर्मनी की एक पत्रिका^१ ने जून १९५६ में ट्रेड यूनियन की रचना तथा कार्यों की कठोर आलोचना करते हुए, अपने निम्नलिखित विचार प्रकट किए :

(१) १९२२ के उपरान्त प्रत्येक द्वितीय वर्ष ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक हुई, जो कुछ अवधि पश्चात् प्रत्येक वर्ष होने लगी। १९३२-४६ में कोई ट्रेड

^१ Bulletin : Institute For The Study Of The U.S.S.R., Munich, Germany.

यूनियन कांग्रेस न मिली, यद्यपि ट्रेड यूनियन संगठन में अनेक परिवर्तन हुये। १९४९ के उपरान्त प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार बैठक होने लगी, यद्यपि विधानानुसार उनको ४ वर्ष के अन्तर्गत की मिलना चाहिये था। जून १९५४ में ११वीं कांग्रेस की बैठक हुई। अतः विधान के अनुसार दूसरी कांग्रेस की बैठक जून १९५८ के पूर्व ही हो जानी चाहिये थी। फरवरी २७, १९५६ को एक प्रादेशानुसार कांग्रेस की बैठक मार्च २३, १९५६ को होना निश्चित हुई। मा. को. में यह बैठक मार्च २३ से मार्च २८ तक रही। आलोचकों का कथन है कि सोवियट ट्रेड यूनियन की यह महान् बैठक जिसको कि निश्चित समयानुसार मिलना चाहिये, कभी नहीं हो पाई है।

(२) इस पत्रिका में यह भी प्रकाशित हुआ कि गत कांग्रेस में ४३ वक्ताओं ने वक्तव्य दिये जो कि अनेक प्रान्तीय ट्रेड यूनियन के सभापति थे। जितने भी वक्तव्य हुए उनका एक ही दृष्टिकोण था, सप्तरवर्षीय योजना की महानता एवम् श्रेष्ठता तथा भविष्य में प्रत्येक वस्तु की पूर्ति में अधिकता। इसी प्रकार के अनेक आशाजनक वार्त्तालाप हुये। एक ट्रेड यूनियन संगठन से सम्बन्धित अनेक सामान्य लघु समस्याओं की विवेचना की जानी चाहिये थी, जो न की गई तथा ट्रेड यूनियन संगठन की त्रुटियों पर भी फिर ध्यान नहीं दिया गया।

(३) इस १२वीं कांग्रेस द्वारा अनेक प्रादेश, जो पूर्व पास किए गए थे, प्रमाणित किया गया। इस बैठक के सभापति ग्रिशिन (Grishin) ने कहा कि विधानों की प्रमाणिता इसलिए हुई कि ट्रेड यूनियन के अधिकारों को बढ़ाया जाये। वक्ता बरीव (Bureev) ने इन प्रादेशों से सम्बन्धित कुछ भिन्न बात कही। उनके अनुसार, ट्रेड यूनियन कार्यों में सुसंगठन हेतु इन प्रादेशों की आवश्यकता प्रतीत हुई है। युद्धोत्तर काल में तीसरी बार ट्रेड यूनियन सम्बन्धित प्रादेशों को प्रमाणित किया गया है। अन्य दो अवसर १९४९ तथा १९५४ में प्रस्तुत हुये थे। अतः सोवियट ट्रेड यूनियन को दिन प्रतिदिन अधिक आर्थिक तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं में भाग लेना आवश्यक समझा गया है। १९५७ के उद्योग संगठन में अनेक परिवर्तनों के कारण ट्रेड यूनियन संचालन में अनेक सुधारों की आवश्यकता हुई है। कुछ ट्रेड यूनियन संस्थाओं का उन्मूलन कर दिया गया है। १२वीं ट्रेड यूनियन कांग्रेस में केवल २३ ट्रेड यूनियन दल के सदस्य उपस्थित थे, जबकि ११वीं ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ४३ दल के सदस्य थे। इसमें सन्देह नहीं कि गत दो तीन वर्षों में बहुत से परिवर्तन उनके संगठन में हुए हैं, परन्तु उनकी विस्तारपूर्वक विवेचना इस कांग्रेस में नहीं की गई। राजकीय

प्रादेशों के अनुसार निम्नलिखित आदेश गत दो तीन वर्षों में प्रकाशित किये गये हैं :

(अ) पार्टी केन्द्रीय समिति की एक सार्वजनिक बैठक में, जो दिसम्बर १७, १९५७ को हुई थी, प्रादेश पास किया गया, जिसका शीर्षक “सोवियट ट्रेड यूनियन के कार्य” था ।

(ब) १५ जून १९५८ को सोवियट रूस के सर्वोच्च सोवियट ने “नियोजित कारखाने, तथा स्थानीय ट्रेड यूनियन समिति के अधिकार पर” एक प्रादेश पास किया ।

(स) जुलाई ९, १९५८ को ट्रेड यूनियन की अखिल संघ केन्द्रीय समिति ने “औद्योगिक व्यवसाय, निर्माण स्थान, सामूहिक कृषि, मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन तथा मरम्मत-ट्रैक्टर स्टेशन के उत्पादन आयोग पर” प्रादेश पास किया ।

(द) अखिल संघ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन समिति ने अन्य अनेक प्रादेश पास किये जिन सबका एक ही उद्देश्य है कि सोवियट ट्रेड यूनियन का महत्त्वपूर्ण कार्य योजना सफलता में निरन्तर वृद्धि करना है । आलोचकों ने उन पर आक्षेप करते हुये कहा कि ‘सोवियट ट्रेड यूनियन सम्पूर्ण कार्य साम्यवाद पार्टी के आदेशानुसार करते हैं ।’

(४) इस कांग्रेस में अधिकतर ट्रेड यूनियन सदस्यों के उत्तरदायित्व के विषय पर वात्तालाप हुये । प्रत्येक सदस्य को (अ) सोवियट राज्य की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवम् आर्थिक उन्नति बढ़ाने में सहायता पहुँचानी है, नियोजन द्वारा निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण करना है, श्रम उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करनी है तथा समाजवादी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना है । (ब) उत्पादन साधनों की त्रुटियों का उन्मूलन करना है । इन उत्तरदायित्व के अतिरिक्त उनके अन्य अधिकारों की अवहलना की गई है । वे हड़ताल नहीं कर सकते, किसी प्रकार की औद्योगिक अशान्ति नहीं फैला सकते तथा अन्य कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं कर सकते । ट्रेड यूनियन की एक विचित्र स्थिति है—एक ओर तो पार्टी और राज्य को आश्वासन दिलाना कि वह नियोजन के आर्थिकलक्ष्य पूर्ण करेंगे तथा दूसरी ओर श्रमिकों के हित पर ध्यान देकर संरक्षण प्रदान करना । आलोचकों के मतानुसार इन दो धाराओं का समन्वय कैसे हो सकता है ? सम्भवतः इसका उत्तर सोवियट सरकार के पास यह है कि सोवियट सरकार श्रमिकों को सरकार है; सोवियट कारखाने श्रमिकों के कारखाने हैं तथा सरकार एवम् श्रमिकों के हित विरोधाजनक नहीं हैं । वे केवल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने को ही दिशा को और उन्मुख हैं ।

(५) आलोचकों का यह भी कहना है कि सोवियट ट्रेड यूनियन का कोई भी सम्बन्ध अन्य देश के ट्रेड यूनियन से नहीं है। यदि वे राज्य के अंग नहीं हैं तथा उनका अपना स्वतः व्यक्तित्व है, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समुदाय से उनका अच्छा सम्बन्ध होना चाहिए। यह लिखा जा चुका है कि सोवियट ट्रेड यूनियन का सम्बन्ध संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी के ट्रेड यूनियन के साथ शून्य है। परन्तु मिशिन ने, जो ट्रेड यूनियन की अखिल राष्ट्रीय समिति के सभापति हैं, बतलाया कि सोवियट ट्रेड यूनियन संगठन का सम्बन्ध विश्व के ६० देशों से है। आलोचकों का कहना है : “जिनमें से ४० तो ऐसे देश हैं जो साम्यवाद से प्रभावित हैं। अधिकतर सोवियट रूस के अनुयायी हैं।”

सोवियट रूस में सामाजिक सुरक्षा

सोवियट रूस सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एक पूर्ण सम्पन्न देश है। अत्येक प्राणी वर्ग को अनेक प्रकार की सुरक्षा राज्य द्वारा प्राप्त है। गत कुछ वर्षों में सोवियट रूस ने इस ओर महान प्रगति की है। यद्यपि १९२२ से निरन्तर इस ओर ध्यान दिया गया है, तथापि १९३३ के पश्चात् इसकी प्रगति अधिक प्रशंसनीय है। सोवियट रूस के वित्त मंत्री ने हाल में लिखा : “सोवियट रूस में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा अंश (लगभग $\frac{3}{4}$) श्रमिकों की भौतिक एवम् सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग किया जाता है। अवशेष (लगभग $\frac{1}{4}$) जो भी श्रमिकों का ही अंश है, समाजवाद अर्थव्यवस्था को पुनः प्रगति मार्ग पर बढ़ाने के लिये व्यय किया जाता है।”^१

सोवियट कार्यशील पुरुषों की आय निरन्तर बढ़ रही है। प्रायः आलोचकों ने अनेक प्रकार से इस पहलू पर प्रकाश डालते हुये, रूस की सामाजिक सुरक्षा हितों की आलोचना की है, परन्तु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उनका जीवन स्तर कितना ही निम्न क्यों न हो, उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन सुधर रही है। जुल्लेस मोच (Jules Moch), एक फ्रान्सीसी समाजवादी दल के नेता ने १९५६ में उल्लेख किया : ‘सोवियट श्रमिक को अपनी आर्थिक अवस्था से सन्तुष्ट रहना चाहिये, क्योंकि उसकी भौतिक अवस्था अनेक कोण से निरन्तर सुधर रही है।’

१ A. G. Zverev : What Soviet Working People Get Besides Wages : Published by the Information Department of the U. S. S. R. Embassy in India and printed at the New India Press, New Delhi.

विशेष गुण

(१) सोवियट रूस में सामाजिक सुरक्षा की रचना तथा प्रगति पूँजीवाद देशों की सामाजिक बीमा से बहुत ही भिन्न है। यद्यपि ब्रिटेन में 'बेवरिज रिपोर्ट' (Beveridge Report), एक विस्तृत एवम् व्यापक योजना कार्यान्वित की गई थी जिससे जनसंख्या के अधिकतर पुरुषों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई, तथापि सोवियट रूस की सामाजिक सुरक्षा नीति उससे अधिक व्यापक एवम् विस्तृत है। इसका विशेष कारण यह है कि रूस में यह सुरक्षा पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित की जाती है जब की ब्रिटेन तथा अन्य देशों में यह योजना अनेक स्थान पर विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित है।

(२) सामाजिक सुरक्षा हेतु अंशदान केवल सरकार तथा मिल प्रबन्धकों द्वारा संग्रहित किया जाता है। मिल के प्रबन्धक केवल राजकीय पदाधिकारी ही हैं, अतः सम्पूर्ण व्यय-भार राज्य पर होता है।

(३) प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारी तथा कृषक को इस सुरक्षा व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है।

(४) सामाजिक सुरक्षा पद्धति के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की प्राप्ति-हित दर उन श्रमिकों से अधिक होती है, जो कि ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं।

(५) सोवियट रूस में वृत्तिहीन बीमा (unemployment insurance) का कोई स्थान नहीं है क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति वृत्तिहीन नहीं है।

(६) बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम कल्याण हेतु सम्पूर्ण सेवायें सम्मिलित हैं। केवल स्वास्थ्य सुरक्षा इसके अन्तर्गत नहीं आती, क्योंकि उसके संगठन एवम् संचालन हेतु अन्य राजकीय विभाग हैं। बीमा सुरक्षा एवम् स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के मध्य संयुक्त समितियों द्वारा समन्वय किया गया है, ताकि विभिन्न सेवाओं से अति अधिक क्षमता प्राप्त की जा सके।

(७) सामाजिक बीमा तथा सुरक्षा संचालन एवम् संगठन के कार्य कुछ विभागों में ट्रेड यूनियन तथा कुछ में सामाजिक कल्याण मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं।

सामाजिक बीमा का विस्तार

देश के प्रत्येक कर्मचारी को बीमा-हित प्राप्त हैं। कारखानों में श्रमिकों को यह सुरक्षा तो दी ही जाती है। इनके अतिरिक्त लघु व्यवसाय के भी कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कर्मचारियों को जब किसी विशेष कार्य में

किसी विशिष्ट प्रशिक्षा हेतु भेजा जाता है, तब भी वे सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। सामूहिक कृषक तथा अस्थायी कृषक एवम् श्रमिक हेतु विशिष्ट बीमा योजनायें प्राप्त हैं। अनेक लघु योजनायें श्रमिकों की इच्छानुसार तथा उनके सीमित साधनों द्वारा संचालित की जाती हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं।

सम्पूर्ण सुरक्षा हित दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं : (१) आर्थिक हित (२) सांस्कृतिक एवम् स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणात्मक हित। आर्थिक हित में निम्नलिखित हित अति महत्त्वपूर्ण हैं : (अ) लघुकालीन हित (ब) दीर्घकालीन हित तथा (स) विशेष हित।

लघुकालीन हित में (क) रोग हित (ख) अस्थायी आयोग्यता हित (temporary disability benefit) तथा (ग) वृत्ति-आघात हित (employment injury benefit) प्रमुख हैं।

एक रोगी श्रमिक को पहिले दिन से ही राजकीय हित प्रदान किये जाते हैं। जब तक कि वह इस योग्य नहीं हो जाता कि साधारण कार्य कर सके, यह सहायता प्राप्त रहती है। घर के किसी अस्वस्थ की देखभाल हेतु यदि कोई पुरुष अपने कार्य पर नहीं जा सका है, ऐसी दशा में भी उसको बीमा कोष से सहायता मिलती है। वृत्ति अवधि के अनुसार हित दर (rates of benefit) निश्चित किये जाते हैं, जो साधारणतः श्रमिक की भृत्त के ५५-६० प्रतिशत हो सकते हैं।

अस्थायी आयोग्यता हित (temporary disability benefit) सामाजिक बीमा कोष से उद्योग एवम् दफ्तर के श्रमिकों को दिए जाते हैं। यहाँ भी लगभग वही दर होते हैं जो रोगी हित हेतु उपलब्ध हैं। कारखानों में काम करते समय अपकृति अथवा चोट लगने पर भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का उचित प्रबन्ध किया गया है। ये सभी हित सामाजिक बीमा कोष से प्रदान किये जाते हैं, जिनमें वित्त संग्रह सरकार स्वयम् करती है तथा इनके प्रबन्ध एवम् संचालन का उत्तरदायित्व भी ट्रेड यूनियन पर आभारित है।

दीर्घकालीन स्थायी आयोग्यता (permanent disability), वृद्धावस्था एवम् मृत्यु से सम्बन्धित है। स्थायी आयोग्यता हित, वृद्धावस्था में पेन्सन एवम् मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को आर्थिक सहायता बीमा कोष से न देकर राज्य बजट से प्राप्त होती है। राज्य पेन्सन देश के सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारी, विद्यार्थीगण तथा वे सभी व्यक्ति जो किसी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने में संलग्न हैं द जाती है। वेतन अथवा श्रम पर काम करने वाले पुरुषों को २५ साल की वृत्ति तथा ६० वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर, पेन्सन प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए शर्त २० वर्ष

की वृत्ति तथा ५५ वर्ष की अवस्था होना अनिवार्य है। पेन्सन की दर इस प्रकार है—न्यून वेतन अथवा पारिश्रमिक पर काम करने वाले श्रमिकों को वेतन अथवा पारिश्रमिक का शत-प्रतिशत, तथा उन व्यक्तियों को जो १००० रुबल प्रति मास से अधिक प्राप्त करते हैं वेतन अथवा पारिश्रमिक का ५० प्रतिशत दिया जाता है। खान में काम करने वाले श्रमिकों को अधिक सुविधायें प्राप्त हैं। पुरुषों के लिए २० वर्ष की वृत्ति तथा ५० वर्ष की आयु एवम् महिलाओं के लिए १६ वर्ष की वृत्ति तथा ४५ वर्ष की आयु, पेन्सन प्राप्त करने के लिये यथेष्ट है। पेन्सन का प्रगतिशील दर ५५ प्रतिशत से १०० प्रतिशत है। वर्तमान समय में न्यूनतम पेन्सन ३०० रुबल प्रतिमास है तथा अधिकतम १२०० रुबल है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने १५ वर्ष से अधिक कुशलतापूर्वक कार्य किया है, उनको पेन्सन का १० प्रतिशत तथा १० प्रतिशत ऐसे पेन्सन वालों को और मिलता है जिनके एक आश्रित है। एक से अधिक आश्रितों के लिये पेन्सन का १५ प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त होता है। कर्त्तव्यस्थ पुरुष जो स्थायी रूप से अयोग्य हो जाते हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूर्णतः अयोग्य होने पर अधिक हित प्राप्त हैं तथा न्यून आवात पर हित दर कम हैं। ये सम्पूर्ण सुविधायें राज्य बजट द्वारा दी जाती हैं, जिसके लिये वेतन से कोई अंशदान नहीं लिया जाता। पेन्सन पर कर भी नहीं लगता।

१९४० की अपेक्षा यदि १९५६ तथा १९५७ की तुलना की जाए तो प्रतीत होता है कि वर्तमान काल में दीर्घ कालीन सहायताएँ काफी परिमाण में प्रदान की जा रही हैं। १९४० में राज्य कोष से केवल ४२०,००० लाख रुबल इस क्षेत्र में वितरित किया गया जो १९५६ तथा १९५७ में १६,६०,००० लाख तथा लगभग १६,२०,००० लाख क्रमशः व्यय हुआ। निम्नलिखित सारणी से यह स्पष्ट होता है :

राज्य कोष द्वारा प्राप्त सामाजिक हितों में वृद्धि^१

(दस हजार लाख रुबल)

१९४२		१९५०		१९५५		१९५६		१९५७
४२		१२२		१५४		१६६		१६२

विशेष हितों में प्रसूति अनुदान (maternity grant) और वैवाहिक अनुदान (marriage grant) मुख्य हैं। उन महिलाओं को जिन्होंने तीन

मास किसी भी व्यवसाय में कार्य किया है, अवकाश की सम्पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। जिन्होंने दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि कार्य किया है, उन्हें शत-प्रतिशत पारिश्रमिक अथवा वेतन उपलब्ध होता है। सन्तान उत्पन्न होने पर एक विशेष अनुदान दिया जाता है, जिसमें वे सन्तान का पालन पोषण तथा आवश्यक वस्तुएँ क्रय करती हैं। गर्भवती स्त्रियों हेतु विशेष प्रादेश निर्मित किये गये हैं। उनको प्रसूति अवकाश ११२ दिवस का दिया जाता है। अस्वस्थ रहने पर अधिक अवकाश प्रदान किया जाता है। लगभग ६,००० प्रसूति गृह (maternity homes) तथा बहु-संख्या में चिकित्सालयों में कमरे राज्य द्वारा निर्माण किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सामूहिक कार्यों में भी प्रसूति गृह स्थापित हैं। ६५ प्रतिशत सन्तान या तो प्रसूति गृहों में होते हैं अथवा चिकित्सालयों में जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधि तथा चिकित्सा निर्मूल्य प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं को राजकीय परामर्श केन्द्रों (state consultation centres) में पूर्व से ही नामांकित किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यथासमय विभिन्न प्रकार की सुविधायें उन्हें प्राप्त हो सकें।

ऐसी माताओं को जिनका वृहत् कुटुम्ब है, राज्य से अनेक भत्ते (allowances) दिये जाते हैं। तीसरी सन्तान होने पर २०० रुबल का आर्थिक अनुदान, चौथी सन्तान पर ६५० रुबल तुरन्त अनुदान तथा ४० रुबल प्रतिमास भत्ता मिलता है। पाँचवीं सन्तान उत्पन्न होने पर ८५० रुबल तथा ६० रुबल क्रमशः, छठी सन्तान पर १,००० रुबल और ७० रुबल क्रमशः, सातवीं तथा आठवीं सन्तान होने पर १,२५० रुबल तथा १०० रुबल एवम् नवीं तथा दशवीं सन्तान पर १,७५० और १२५ रुबल आर्थिक सहायता दी जाती है। दस बच्चों की माँ के ११वीं सन्तान होने पर २,५०० रुबल शीघ्र अनुदान तथा १५० रुबल मासिक भत्ता सरकार की ओर से दिया जाता है। इस प्रकार की आर्थिक सहायता १९५६ में राज्य कोष से ५,००० लाख रुबल दी गई थी। ऐसी माँ जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, उनको भी राज्य सरकार से सहायता मिलती है। ऐसी माताओं को जिनके दस अथवा उससे अधिक बच्चे हुए हैं “मातृ वीराङ्गना” (Mother Heroine) की उपाधि से सुसज्जित किया जाता है। उनको सर्वोच्च सोवियट से प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है। ऐसी मातायें जिनके पाँच अथवा छः सन्तान हुई हैं, उनको “मातृत्व पदक” (Motherhood Medal) प्रथम एवम् द्वितीय श्रेणी के क्रमशः प्राप्त होते हैं। ऐसी मातायें जिनके ७, ८ तथा ९ बच्चे हुए हैं, उनको “मातृत्व कीर्ति पद” (Order of Motherhood Glory) तृतीय द्वितीय एवम् प्रथम वर्ग के क्रमशः प्रदान किये जाते हैं।

तीन वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध सरकार द्वारा 'किंडरगार्टन' में किया जाता है। जब कि उनकी मातायें कार्य संलग्न रहती हैं, पढ़ी लिखी नर्स तथा डाक्टर उनके निरीक्षण के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों के लालन-पालन तथा खाने-पीने का प्रबन्ध उनकी अवस्थानुसार सरकार करती है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए नागरिकों को कोई व्यय नहीं करना पड़ता। सोवियट सरकार का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक नागरिक को अधिक-समीपवर्ती स्थान पर स्वास्थ्य अथवा रोग सम्बन्धी यथेष्ट सुविधायें प्रदान की जायेंगी। वर्तमान काल में सोवियट रूस में लगभग १ लाख ६० हजार मेडिकल क्लिनिक्स हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्यकोष से संचालित किये जाते हैं। एक नागरिक जो किसी भी प्रान्त का निवासी क्यों न हो वह अपने समीपवर्ती चिकित्सालय से चिकित्सा एवम् निर्मूल्य औषधि प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों को रोगियों के निवास स्थान पर भी भेजा जाता है।

कारखानों में भी उनके स्वयम् चिकित्सालय होते हैं। कुछ विशाल कारखानों में वृहत्कार चिकित्सालय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। १९५६ में इनकी संख्या १००० थी। इनके अतिरिक्त देश में बहुसंख्या में लघु औषधि स्टेशन एक अथवा दो चिकित्सकों के अधीनस्त हैं। इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा नवीन चिकित्सालयों का दिन प्रति-दिन निर्माण होता जा रहा है। इनमें अनेक पत्रिकायें तथा आधुनिक पुस्तकें रहती हैं, जिनके द्वारा विज्ञान सम्बन्धी नवीन औषधियों का अधिकतम प्रचलन तथा प्रशिक्षा प्रत्येक नागरिक को प्रदान करने की पूर्ण चेष्टा की जाती है।

सोवियट सरकार श्रमिकों के लिये विश्राम करने का यथेष्ट प्रबन्ध करती है। श्रमिकों इन्जीनियरों, शिल्पकारों तथा कर्मचारियों को १२ से २४ दिवस तक प्रत्येक वर्ष विश्राम करने का अवकास पूर्ण वेतन पर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार अधिक जोखिम के अथवा संकटमय कार्यों में १८ से ४८ दिवस का अवकास ग्रहण किया जाता है। स्कूल के प्राथमिक अध्यापकों, माध्यमिक शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों को ४८ दिन का वार्षिक अवकास प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष सोवियट संघ बहु-संख्या में निवास गृह निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को इस कार्य हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है। सामूहिक कृषकों को सामूहिक कोष से अति अधिक सहायता मिलती है। युद्धकाल से ही सरकार सामूहिक ग्रामीण कृषक तथा नगरों में नागरिक हेतु निवास

स्थान प्रबन्ध कर रही है तथा प्रत्येक योजना में अत्यधिक धन विनियोग किया जा रहा है ।

सामाजिक बीमा एवम् सुरक्षा प्रशासन

उपर्युक्त लिखित सम्पूर्ण लघु कालीन हितें ट्रेड यूनियन द्वारा संगठित की गई हैं । दीर्घकालीन हितें सामाजिक कल्याण मंत्रि-मण्डल द्वारा संचालित की जाती हैं । स्वास्थ्य सम्बन्धी राजकीय सुरक्षा स्वास्थ्य मंत्रि-मण्डल द्वारा आयोजित किया जाता है । यह भी उपर्युक्त लिखा जा चुका है कि बीमा हितें सरकार द्वारा दी गई अंशदानों से जो कि बीमा कोष में श्रमिकों की संख्या के अनुपात में संचित होते हैं, संचालित की जाती हैं । प्रत्येक श्रमिक का अंशदान उसके कुल श्रुति के अनुपात में होता है । स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षाएँ बिना किसी अंशदान के प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

सोवियट रूस का विदेशी व्यापार तथा नीति

एक समाजवादी देश जहाँ केवल सम्पूर्ण उद्योग ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था राज्य के अधीन है, वहाँ विदेशी व्यापार भी राज्याधिकार में होना कोई विशेष आश्चर्यजनक बात नहीं है। सोवियट सरकार ने अप्रैल १९१८ से ही विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसकी इस स्थायी नीति में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्रान्ति के पश्चात् साम्यवाद नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण विदेशी व्यापार सोवियट सरकार स्वयम् करती थी। नवीन आर्थिक नीति काल में जब कि अनेक क्षेत्रों में आन्तरिक व्यापार स्वतः पूँजीपतियों के आधिपत्य में था, विदेशी व्यापार में राष्ट्रीयकरण नीति स्थापित रही। प्रस्तुत अपरिवर्तन-शील तथा स्थायी राष्ट्रीयकरण नीति के अनेक कारण थे^१ :

(१) समाजवादी देश में यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में राजकीय एकाधिकार हो। यदि यह सम्भव न हो तो इतना तो अवश्य होना चाहिये कि ऐसे प्रमुख केन्द्रीय उद्योगों पर, जिन पर अन्य उद्योग आश्रित हैं, राजकीय आधिपत्य स्थापित हो। विदेशी व्यापार उनमें से एक है। यदि राज्य इस नीति की अवहेलना करता है तो आन्तरिक योजनात्मक अर्थव्यवस्था सफल नहीं हो सकती, क्योंकि बाह्य समस्यायें आन्तरिक स्थिति को निरन्तर प्रभावित करती रहेंगी। यह एक सरल सिद्धान्त है कि आन्तरिक प्रगति को बाह्य बाधाओं से सुरक्षित करने के लिये किसी देश का संरक्षण नीति अपनानी पड़ती है। एक ऐसा देश जहाँ निजी पूँजीपतियों का स्थान शून्य है, विदेशी व्यापार को व्यक्तिगत पूँजीपतियों के आधिपत्य में रखना अनर्थ होगा। किसी भी योजनात्मक प्रगतिशील देश हेतु यह आवश्यक है कि वह आन्तरिक हाट को विदेशी हाट

^१ Harry Schwartz : Russia's Soviet Economy, 1951, pp. 492-93.

की आर्थिक अस्थिरता तथा चंचलता के प्रभाव से वंचित रखे। यदि ऐसा नहीं होता तो सम्पूर्ण निर्धारित लक्ष्य अपूर्ण रह जावेंगे, क्योंकि एक ओर तो उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन स्थापित कर योजना निर्माण की जावेगी तथा दूसरी ओर विदेशी आयात निश्चित लक्ष्यों को प्रभावित करेगा, मूल्य ह्रास होगा, आन्तरिक उत्पत्ति नष्ट होगी तथा विनियोग निर्धारित लक्ष्यानुसार न हो सकेगा। अतः प्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप तथा ऐसा हस्तक्षेप जिसमें किसी भी क्षेत्र में नियन्त्रण का अभाव न हो, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संतुलित कर वाह्य व्यापार-चक्र से सुरक्षित कर सकता है। इसी सिद्धान्त पर सम्भवतः व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

(२) आर्थिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त राजनैतिक विचार से भी यह आवश्यक अथवा लाभजनक समझा गया कि सोवियट रूस के विदेशी व्यापार का पूर्ण प्रबन्ध अथवा प्रशासन केवल सरकार द्वारा ही किया जावे। यह एक राजनैतिक अद्वितीय चातुर्य नीति है कि सोवियट सरकार ने विदेशी व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। क्योंकि सोवियट सरकार विदेशी व्यापारियों से सामग्री क्रय-विक्रय स्वयम् करती है, अतः किसी भी देश के विषय में कोई भी जानकारी यथासमय प्राप्त कर सकती है।

(३) विदेशी व्यापार पर राजकीय एकाधिकार होने के कारण सोवियट सरकार, विदेशी व्यक्तिगत विक्रेताओं के मध्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से पूर्ण लाभ उठा सकती है। यह भी इसीलिये सम्भव है कि विदेशों से अधिक लाभार्जन हेतु सोवियट रूस अपनी सम्पूर्ण राजनैतिक एवम् आर्थिक शक्ति विनियोग कर निर्धन तथा निर्बल देशों को क्षति पहुँचा सकता है।

(४) विदेशी व्यापार पर एकाधिकार होने के कारण यह सम्भव है कि सोवियट रूस में किसी सामग्री के आन्तरिक मूल्य को विश्व के अस्थायी एवम् लोचमान मूल्य से सम्पूर्णतः पृथक् रक्खा जा सके। जिस मूल्य पर सोवियट संघ सामग्री आयात-निर्यात करती है, उसका रूस के आन्तरिक सामान्य मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यह भी सोवियट रूस के हित का एक तथ्य है। परन्तु राजकीय एकाधिकार के उपर्युक्त गुणों के साथ-साथ निम्नलिखित अव-गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं :

(१) सोवियट संघ में क्रेता एवम् विक्रेता वैयक्तिक व्यापारी न होने के कारण पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से शून्य होते हैं। आलोचकों के कथनानुसार उन्हें नवीन कार्य अथवा व्यापार में यथेष्ट उत्तेजना एवम् उत्साह नहीं रहता।

(२) विदेशी क्रियायें बहुसंख्यीय होती हैं। अन्य देशों में विभिन्न रूप से वे सुसंगठित की जाती हैं तथा सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परन्तु सोवियट संघ में वे सम्पूर्ण क्रियायें सरकार द्वारा ही संचालित होने के कारण, उनमें आवश्यक समन्वय होना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है।

(३) सोवियट रूस का विदेशी व्यापार, सरकार के आधिपत्य में होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक अशान्ति के कारण प्रायः एक बलि बन जाता है। प्रायः विदेशों में राजनैतिक तनातनी ईर्ष्या एवम् प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण सोवियट संघ के साथ आयात-निर्यात करना अन्य विदेशी अपना तिरस्कार एवम् अपमान समझते हैं, जिसके फलस्वरूप सोवियट संघ को अत्यन्त व्यापारिक क्षति पहुँचती है।

कितनी ही त्रुटियाँ क्यों न हों, सोवियट सरकार को यह पूर्ण विश्वास था कि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण, योजनात्मक अर्थव्यवस्था का एक मूल अवयव है। साधारण दृष्टिकोण से सोवियट रूस की विदेशी व्यापारिक नीति इस बात से अधिक सशक्त रहती है कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक शक्तिशाली तथा समृद्धशाली राष्ट्र बनना है। स्वतः आदर्श शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण हेतु सोवियट संघ ने सम्पूर्ण आर्थिक, राजनैतिक एवम् सैनिक शक्तियों को प्रयुक्त किया है तथा विभिन्न काल में उसने विभिन्न साधन अपनाये हैं, जिनमें दो अत्यन्त महत्त्वशाली हैं :

(अ) सोवियट रूस ने पूँजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन नियम को विदेशी व्यापार से पृथक् रक्खा है। प्रायः पूँजीवाद देशों की यह नीति निरन्तर रही है कि वे अधिकतम निर्यात एवम् न्यूनतम आयात करें ताकि व्यापार संतुलन उन्हीं के पक्ष में रहे। यह एक आश्चर्यजनक एवम् प्रमुख बात है कि सोवियट रूस पर इस नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम आयात भी करते हैं, यदि कार्य राष्ट्रीय हित का होता है। १९२८ के पश्चात् सोवियट रूस ने समाजवाद राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने हेतु मशीनों तथा यन्त्रों का आयात अधिक परिमाण में किया, जबकि उसका निर्यात अति न्यून तथा व्यापार-संतुलन भी प्रतिकूल था। सोवियट रूस के इतिहास में “आयात अधिक तथा निर्यात न्यून” की नीति अधिक काल तक प्रधानता पाती रही, क्यों कि इस नीति से रूस की महानता अन्तर्राष्ट्रीय विश्व एवम् राजनैतिक क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती थी। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु वे अपनी सम्पूर्ण गृह शक्तियों का प्रयोग करते रहे हैं। उनका दावा था कि इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिये

जनता कोई भी त्याग एवम् बलिदान कर सकती है। उनको व्यापार संतुलन पक्ष-विपक्ष में होने की कोई चिन्ता न थी।

(ब) रूस का विदेशी व्यापार अनुग्रही देशों के प्रति विशेष ध्यान रखता है तथा वे स्वतः राजनैतिक एवम् शासन सत्ता वृद्धि हेतु निर्बल देशों को निरन्तर आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अनेक देशों में राजनैतिक प्रभुत्व वृद्धि हेतु सोवियट रूस विदेशी व्यापार एवम् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध को प्रयोग करता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रूस की विदेशी व्यापारिक नीति जो एशिया में परसिया, अफगानिस्तान, टर्का, मंगोलिया, टानूटूवा तथा पश्चिमी चीन पर प्रयोग की गई, राजनैतिक कारणों से अधिक प्रभावित थी, जिसके अन्तर्गत रूस की राजनैतिक सत्ता का अधिक ध्यान दिया गया। गत वर्ष में रूस की यह नीति अनेक देशों के प्रति इसी प्रकार थी। आलोचकों ने तो रूस की इस नीति की घोर निन्दा की है। डी० जे० डालिन (D.J. Dallin) ने अभी हाल में लिखा कि “मास्को की सरकार” विश्व के अधिकांश देशों को पाँच भागों में विभाजित करती है। (१) सावियट-संघ जो साम्यवाद के प्रदर्शक हैं। (२) इसके ११ अनुग्रही देश (satellites) जो भी उसी दिशा की ओर उन्मुख हैं। (३) निष्पक्ष देश (neutral countries), जिसमें फिनलैंड, मिश्र, सीरिया, आस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, स्वीटजरलैंड, भारत, इन्डोनीसिया, तथा अफगानिस्तान हैं। (४) नाटो (NATO), ‘सीटो’ (SEATO) तथा बगदाद संधि के सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हैं तथा (५) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आलोचक डालिन के अनुसार, सोवियट नीति का प्रयोग रूसी सत्ता विस्तृत करने के उद्देश्य से किया जाता है। ‘नाटो’ तथा ‘सीटो’ को खण्डन कर अमेरिका एवम् इंग्लैंड को पृथक् रखना, फ्रान्स को निष्पक्ष होने का परामर्श देना तथा जर्मनी से विलग रहना, बॉन (Bonn) को यह मंत्रणा देना कि संयुक्त जर्मनी का पुनर्निर्माण तभी हो सकता है जब पश्चिमी जर्मनी निष्पक्ष क्षेत्र में सम्मिलित हो जाये तथा जापान को आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन देना, यदि वह अमेरिका से विमुख हो जाये आदि ऐसी घटनायें हैं, जो सोवियट संघ की विदेशी नीति के विरुद्ध प्रदर्शित की गई हैं। इन्डोनीसिया तथा सीरिया को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रूस ने उनको कितना सहयोग दिया है, सम्पूर्ण विश्व को ज्ञात है।

डालिन का कहना है कि ख्रुश्चेव ने इस नीति के आधार पर गत वर्षों में अनुग्रही देशों को अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की है। अनेक राजनैतिक कार्यों से भी यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समक्ष सोवियट संघ स्वमान्यता एवम् प्रधानता बढ़ाना चाहता है तथा विश्व शक्तियों में

प्रधान स्थान ग्रहण करने की आकांक्षा रखता है। उनका विचार है कि विदेशी व्यापार एवम् विदेशी आर्थिक नीति इस उद्देश्य को पूर्ण करने के मौलिक साधन हैं। युद्ध काल से सोवियट रूस ने निम्नलिखित देशों को लगभग ७८०,८०० हजार डालर आर्थिक सहायता प्रदान की है, जो निम्नलिखित अंकों से ज्ञात है। गत वर्षों में उसकी इस प्रवृत्ति में यथेष्ट वृद्धि हुई है।

अफगानिस्तान :	१०६,८००,०००	डालर	
वर्मा :	२३,०००,०००	"	
भारत :	२४१,५००,०००	"	
इन्डोनीसिया :	१००,०००,०००	"	
एशिया :			७१,३००,००० डालर
फिनलैण्ड :	२०,०००,०००	"	
योगोस्लाविया :	२८१,५००,०००	"	
योरप :			३०१,५००,००० "
अन्य देश :			८,०००,००० "
सम्पूर्ण योग			७८०,८००,००० "

अनेक अनुग्रही एवम् मैत्रिक देशों को गत वर्षों में सोवियक सरकार की सहायता अद्वितीय रही। १२वीं पार्टी कांग्रेस में खुशचेव ने स्पष्ट कहा कि ५२.५ खरब डालर सहायता इन देशों को दी गई है।

इसके अतिरिक्त सोवियट रूस ने अपनी पूँजी विदेशों में भी विनियोग किया है। इसका प्रभाव रूस के निवासियों के हितकर न होगा, क्योंकि अब भी उनको उपभोक्ता पदार्थ उत्पत्ति एवम् सामान्य जीवन स्तर उच्च करने हेतु अनेक कार्य करने हैं। ऐसा कहा जाता है कि इतनी अधिक उन्नति करने पर भी सोवियट रूस अभी एक निर्धन देश ही है, जहाँ उपभोक्ता पदार्थों की अब भी अत्यधिक न्यूनता है।

आलोचकों का विचार है कि यदि सोवियट रूस में साम्यवाद पार्टी के अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी और होती, तो सम्भवतः ऐसा न हो पाता कि सोवियट रूस जनता के हित को बलिदान कर रूसी पूँजी विदेशों में केवल इस उद्देश्य से विनियोग करता है कि उसकी प्रधानता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष हो जाये। वर्मा में विद्युत् शक्ति स्टेशन, भारतवर्ष में लोहा-इस्पात के कारखाने तथा चीन में मोटरगाड़ी उद्योग आदि की स्थापना कोई सरल एवम् साधारण कार्य न था तथा देश में यदि विरोधी पक्ष होता तो प्रस्तुत योजना की भी सम्भवतः अवहेलना ही की जाती।

संगठन : विदेशी व्यापार पर राजकीय एकाधिकार होने के कारण निम्नलिखित राजकीय संस्थायें एवम् समितियाँ संचालन हेतु स्थापित की गई हैं :

(क) एक विदेशी व्यापार मंत्रिमण्डल है, जिसके अधीन अनेक व्यापारिक आयात-निर्यात संस्थायें भी हैं जैसे, एक्सपोर्ट्स (Exportles), एक्सपोर्ट-क्लैब (Exportkhleb), एक्सपोर्टलें (Exportlen) प्राम्पसिरोइम्पोर्ट (Promsyroimport), राजनोइम्पोर्ट (Raznoimport), सॉयुजपुशिना (Soyuzpushina), सॉयुजनेफ्टेक्सपोर्ट (Soyuznefteexport) सॉयुज-प्रामेक्सपोर्ट (Soyuzpromexport), तथा माशिनोइम्पोर्ट (Mashinoimport) आदि। विदेशी व्यापार मंत्रिमण्डल के अधीन देश की सीमा-शुल्क सेवा भी आती है। इसका प्रबन्ध भी मंत्रिमण्डल ही करता है।

(ख) सोवियट रूस में एक 'वाणिज्य मण्डल' (Chamber of Commerce) विदेशों से आर्थिक सम्बन्ध वृद्धि हेतु स्थापित है। इस मण्डल के सदस्य औद्योगिक व्यवसाय तथा अनेक सहकारी एवम् राजकीय संस्थायें होती हैं। इस मण्डल के निम्नलिखित कार्य हैं :

- १—देश-विदेश में औद्योगिक प्रदर्शनी की व्यवस्था;
 - २—औद्योगिक उत्पत्ति के गुण का निरीक्षण;
 - ३—निर्यात की गई सामग्री हेतु प्रमाण पत्र का प्रदान;
 - ४—आविष्कारों को अधिकार पत्र तथा व्यापार चिन्ह को पंजीकरण करना;
 - ५—निर्यात सामग्री के व्यापार चिन्ह को पंजीकरण करने की व्यवस्था।
- सोवियट संघ 'वाणिज्य मण्डल' के अन्तर्गत एक विदेशी व्यापार निवाचन आयोग (Foreign Trade Arbitration Commission) तथा एक समुद्री निवाचन आयोग (Marine Arbitration Commission) की स्थापना की गई है।

(ग) सोवियट संघ का व्यापार प्रतिनिधि (The Trade Representative of the U.S.S.R.) एक ऐसा संगठन है जिसे विदेशी व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त है। यह प्रतिनिधित्व (representation) एक व्यापार प्रतिनिधि द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जिसकी नियुक्ति सोवियट संघ मंत्री समिति द्वारा की जाती है। व्यापार प्रतिनिधि अपनी शाखायें उन सभी देशों में रखते हैं जिनसे उनका व्यापार होता है। कुछ देशों में प्रतिनिधि नहीं होते जहाँ व्यापार अभिकर्तृत्व (trade agencies) स्थापित की गई हैं। किसी विशेष देश के कुछ जिलों में कुछ नवीन अभिकर्तृत्व स्थापित की जा सकती हैं तथा साथ ही

समथ प्रतिनिधि भी नेतृत्व में नियुक्त किये जा सकते हैं। साधारणतः व्यापार अभिकर्तृत्व तथा व्यापार प्रतिनिधि के समान कार्य होते हैं।

(घ) इसके अतिरिक्त हाल में सोवियट संघ ने कुछ व्यापारिक संविदा भी किये हैं। व्यापारिक संधि एवम् संविदा केवल समाजवादी देशों से ही नहीं हुये हैं, वरन् पश्चिमी योरप के मध्यवर्ती देश तथा एशिया के दक्षिणीपूर्वी अनेक देशों में भी स्थापित किये गये हैं। भारतवर्ष, अफगानिस्तान, मिश्र, तथा अन्य एशिया के देशों से १९५७ में गत वर्ष की अपेक्षा व्यापारिक संधि एवम् संविदा द्वारा दुगुना व्यापार हुआ है।

(ङ) इसके अतिरिक्त सोवियट संघ ने अन्य देशों से वैज्ञानिक एवम् प्रौद्योगिक सहयोग से सम्बन्धित अनेक स्वीकार पत्र लिखे हैं, जिनके अन्तर्गत शिल्पकला सम्बन्धी वैज्ञानिक परामर्श एवम् सहायता प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु पृथक-पृथक संगठन स्थापित किये गये हैं।

विकास तथा प्रगति

प्रथम महायुद्ध काल में सोवियट रूस के विदेशी व्यापार को अत्यधिक क्षति पहुँची थी। इसका कारण १९१७ की क्रान्ति, गृह युद्ध तथा प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन न्यूनता थी। कुछ अवधि तक तो विदेशी व्यापारीगण रूस के साथ व्यापार भी करने से भय एवम् शंका करते थे। उसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध ने भी विदेशी व्यापार को केवल रूस में ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में काफी क्षति पहुँचाई थी। इन कारणों से रूस का व्यापार इस समय लगभग शून्य था। निम्न सारणी से वास्तविक दशा का उचित अनुमान लगाया जा सकता है :

सोवियट संघ का विदेशी व्यापार^१

(१९१८-१९२१)

(दस लाख रुबल)

	निर्यात	आयात	अन्तर
१९०९-१९१३	६,५१३.९	४,९९.१	+ १,५१९.८
१९१३	६,५६६.४	६,०२२.५	+ ५४३.९
१९१८	३५.५	४६०.८	- ४२५.३
१९१९	०.४	१४.०	- १३.६
१९२०	६.१	१२५.७	- ११९.६
१९२१	८८.५	६००.६	- ५१२.१

^१ Harry Schwartz : Russia's Soviet Economy, p. 507.

१९२० के उपरान्त रूस का व्यापार कुछ बढ़ा था जिसका कारण यह था कि रूस के व्यापार-प्रतिनिधि तथा उनकी आभकृत्व योरोप के अनेक देशों में स्थापित हो गई थी। साथ ही साथ अन्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध वृद्धि करने की पूर्ण चेष्टा भी की गई थी।

नवीन आर्थिक योजना काल में रूस का आन्तरिक उत्पादन बढ़ा तथा उसका कुछ अंश भी निर्यात किया गया। १९२६ के उपरान्त राष्ट्रीय प्रगति हेतु सोवियट रूस को बाह्य सहयोग की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसके कारण उसको जर्मनी, इटली, नार्वे तथा आस्ट्रिया आदि देशों से ऋण लेना अनिवार्य हो गया। आयात सामग्रियों में विशेषतः निर्मित मशीन एवम् यन्त्र थे।

निम्नलिखित सारणी से प्रस्तुत परिस्थिति दृष्टिगोचर होती है :

सोवियट रूस का विदेशी व्यापार

(१९२१-१९२८)

(दस लाख रुबल)

वर्ष	निर्यात	आयात	अन्तर
१९२२	३५७.४	१, ८१.७	- ८०४.४
१९२३	६५४.८	६२७.२	+ ३२७.६
१९२४	१,४७४.१	१,१३८.८	+ ३३५.३
१९२५	२,६६४.४	३,६२०.६	- ९५६.५
१९२६	३,१७३.७	३,०१६.५	+ १५७.२
१९२७	३,२६७.०	३,७२०.५	- ४५३.५

१९२६ के उपरान्त निर्यात की अत्यधिक उन्नति हुई। अनेक देशों ने रूस को ऋण भी प्रदान किया, यद्यपि व्याज साधारण प्रचलित दर से अधिक था। १९२८ में योजना प्रारम्भ होने के उपरान्त उत्पादन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई जिससे १९३५ तक उसके ऋण तथा उत्तरदायित्व की अवस्था अत्यन्त सुधर गई थी।

सोवियट रूस में सब से अधिक आयात प्रथम योजना काल में हुआ। उस समय औद्योगिक अवस्था अति संकटमय थी। औद्योगीकरण नव निर्मित होने के कारण निर्यात अधिक नहीं हो सकता था। परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही केवल परिस्थिति ऐसी थी कि निर्यात में वृद्धि तथा आयात में ह्रास हुआ अन्यथा १९२८ के

उपरान्त निरन्तर आयात अधिक तथा निर्यात न्यून होता गया । द्वितीय महायुद्ध पूर्व परिस्थिति अधोलिखित थी ।

सोवियट रूस का विदेशी व्यापार

(१९२८-१९३८)

(दस लाख रुबल)

वर्ष	निर्यात	आयात	अन्तर
१९२८	३५१८'९	४१७४'६	- ६५५'७
१९२९	४०४५'८	३८५७'०	+ १८८'८
१९३०	४५३९'३	४६३७'५	- ९८'२
१९३१	३५५३'१	४८३९'९	- १२८६'८
१९३२	२५१८'२	३०८३'५	- ५६५'३
१९३३	२१६७'५	१५२५'१	+ ६४२'४
१९३४	१८३२'४	१०१८'०	+ ८१४'४
१९३५	१६०९'३	१०५७'२	+ ५५२'१
१९३६	१३५९'१	१३५२'५	+ ६६
१९३७	१७२८'६	१३४१'३	+ ३८७'३
१९३८	१३३१'९	१५२२'९	- १९०

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सोवियट रूस ने अधिकतर मशीनें आयात किया तथा उसका मुख्य निर्यात खाद्यान्न था, जो वह अत्यन्त कठिनाई से राष्ट्रीय उपभोग से बचाता था । १९२९ की मन्दी के कारण रूस की निर्यात सामग्री उसकी आयात सामग्री से अधिक सस्ती थी, क्योंकि खाद्यान्न का मूल्य निर्मित सामग्री के मूल्य से कम था । इसी कारण सोवियट रूस को विदेशी व्यापार में दोनों दिशाओं से क्षति पहुँची । सामग्री क्रय में उसे अधिक मूल्य देना पड़ता था तथा विक्रय में भी उसे कम प्राप्त होता था । यह कहना अनुचित न होगा कि सोवियट रूस को कम आयात हेतु अधिक सामान निर्यात करना पड़ता था जब कि उस समय देश में प्रत्येक वस्तु का अभाव था । विशेषकर आयात मशीन, लोहा-इस्पात एवम् विद्युत् सामग्री आदि तथा निर्यात सामग्री अधिकतर काष्ठ, खनिज पदार्थ एवम् कच्चा पदार्थ आदि थीं ।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक काल में तो आयात-निर्यात यथेष्ट संतुलित था । परिमाण में न तो अधिक निर्यात था और न आयात ही । १९४२-४३ में

आयात लगभग ६ गुना हो गया। जून १९४१ में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, उस समय सोवियट रूस ने मित्र राष्ट्रों से आयात किया। गत पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि सोवियट रूस एक ऐसी व्यवस्था है, जहाँ आवश्यकतानुसार राष्ट्र-हित हेतु अधिकतम बलिदान किया जा सकता है तथा सम्पूर्ण व्यापार सरकार के आधिपत्य में होने के कारण राजनैतिक एवम् सैनिक उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। फलस्वरूप सोवियट रूस का आयात जितना बढ़ गया था सम्भवतः निर्यात उतना ही घट गया, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से प्रदर्शित है :

(दस लाख रुबल)

वर्ष	निर्यात	आयात
१९३८	१,३३१'९	१,४२२'९
१९४०	१,४१२'०	१,४४६'०
१९४२	३६६'०	२,७५६'०
१९४३	३७३'०	८,४६०'०

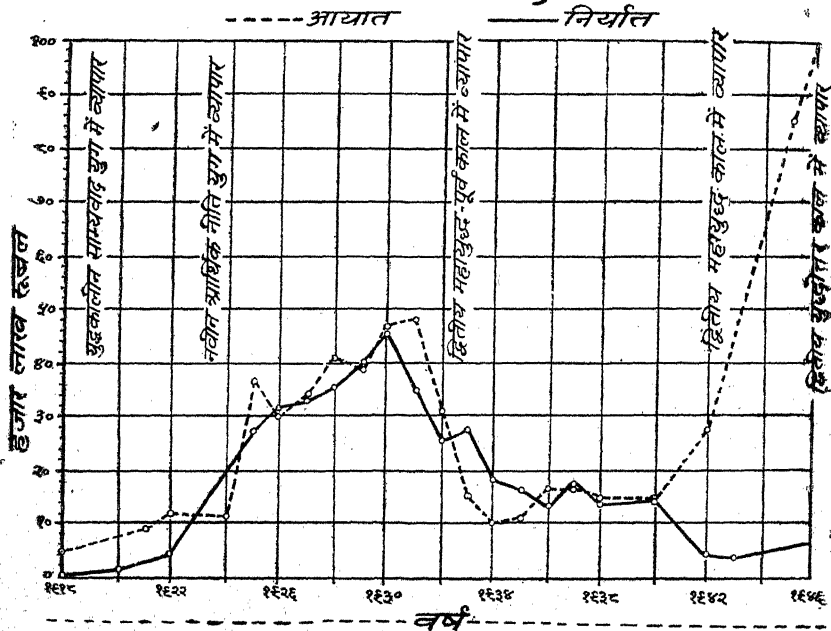
युद्धकाल में जब सोवियट रूस का पश्चिमी भाग जर्मनी के आधिपत्य में आ गया था, उसकी अवस्था अति अधिक निर्बल हो गयी थी। औद्योगिक सामग्रियों की अधिकतम न्यूनता थी। इसके अतिरिक्त युद्ध सामग्री भी इसे विभिन्न देशों से आयात करना पड़ा था। अमेरिका के 'उधार-पट्टा' (Lend-Lease) तथा ब्रिटेन एवम् कनाडा के सहायक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सोवियट रूस को विभिन्न सामग्रियाँ प्रदान की गईं, जिनका आधार दीर्घकालीन ऋण था। इस समय लगभग १३० हजार लाख डालर की सामग्री सहायता मित्र राष्ट्रों से प्राप्त हुई, जिसमें केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ११.२ हजार लाख डालर थी।

अधिकतर आयात युद्ध कालीन सामग्रियों का ही था। लगभग १४,५०० वायुयान, ७,५०० टङ्की तथा १०,००० लाख डालर के गोले-बारूद केवल अमेरिका से आयात किये गये थे। 'उधार-पट्टा पद्धति' (Lend Lease Scheme) के अन्तर्गत प्रायः २० लाख टन खाद्यान्न, ४,७५,००० ट्रक तथा मोटर-गाड़ियाँ, ३०,००० मशीन-यन्त्र, ११० लाख जूते, प्रायः २००० रेलवे इंजन, ३००,००० टन अलमोनियम, ताँबा एवम् अन्य धातु पदार्थ, २०० लाख सैनिकों के लिये सूती-बख्त एवम् अन्य विविध सामग्रियाँ प्रदान की गईं। ग्रेट ब्रिटेन ने १००,००० टन से अधिक खाद्यान्न, लगभग इतना ही रबर, एवम् शक्ति संचालन सामग्री,

१५,००० विद्युत् मोटरें, १००,००० टन से अधिक अलौहमय धातुयें तथा विविध सामग्रियाँ प्रदान कीं। कनाडा ने लगभग २,००,००० टन गेहूँ तथा आटा, १००,००० टन अलमोनियम, ताँबा, जस्ता, निकल तथा अलौहमय धातु, १३,००० टन से अधिक रेल आदि निर्यात किये।

निःसन्देह युद्धकाल में सोवियट रूस का आयात अति अधिक परिमाण में था। इसके विनिमय में बहुत ही थोड़ी सामग्री सोवियट संघ ने निर्यात किया। इतना अवश्य है कि यूक्रेन में अमेरिका के वायुयानों द्वारा खाद्यान्न तथा अन्य खाद्यार्थ भेजने हेतु पूर्ण प्रबन्ध किया गया तथा अमेरिकन सैनिक को अन्य सुविधायें उपलब्ध की गईं। इसके अतिरिक्त सोवियट संघ के बन्दरगाहों पर अमेरिकन समुद्री जहाजों की मरम्मत आदि करने का पूर्ण आयोजन भी किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सोवियट संघ का जर्मनी से युद्ध कर उन्हें परास्त करना सम्भवतः उसकी सर्वोच्च सेवा है, जो उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कनाडा हेतु की है।

सोवियट संघ का विदेशी व्यापार



सोवियट रूस की वर्तमान प्रवृत्ति विदेशी व्यापार में किस ओर उन्मुख है, इसका अनुमान करना तो सरल है, परन्तु इस विषय पर पूर्णतः सांख्यिकी उपलब्ध

नहीं हैं। जुलाई १९५६ में प्रकाशित सांख्यिकीय पुस्तिका भी व्यापार के विषय में केवल एक सारणी प्रस्तुत करती है, जिसके अन्तर्गत सोवियट व्यापार की व्यवस्था का उल्लेखन १९१३, १९२८, १९५०, १९५४ तथा १९५५ में किया गया है। इस सारणी द्वारा सम्पूर्ण तथ्य स्पष्ट नहीं है और न यह ही ज्ञात है कि सोवियट व्यापार में निर्यात-आयात की क्या अवस्था है तथा गत वर्षों में उनमें कितनी वृद्धि हुई है। इस सारणी से केवल इतना ही उपलब्ध है कि सम्पूर्ण निर्यात का लगभग २२ प्रतिशत मशीन तथा निर्माण यन्त्र, ६० प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा कच्ची सामग्री, १० प्रतिशत अन्न एवम् केवल ८ प्रतिशत उपभोग पदार्थ निर्यात किया जाता है, जब कि १९१३, १९२८, १९३८, १९५०, १९५४ तथा १९५५ में दशा बिल्कुल भिन्न थी। १९२८ में उपभोग पदार्थ अधिक निर्यात होते थे, जब कि १९५४-५५ में खनिज पदार्थ एवम् कच्ची सामग्री आदि। अधिकतर आयात मशीनों का ही है। तथा उपभोग पदार्थ की न्यूनता होते हुए भी सोवियट संघ ने विदेशों से इनकी अति न्यून मात्रा में आयात किया है।

गत वर्ष सोवियट व्यापार बहुत ही वृहत् आकार में हुआ। उप-प्रधान मंत्री अनास्तस मिकोयन (Anastas Mikoyan) ने बतलाया कि लगभग ८०,००० लाख डालर का व्यापार किया गया। जिन देशों में तथा जिन सामग्रियों में गत वर्षों में सोवियट रूस का व्यापार हुआ है उससे भी प्रतीत होता है कि राजनैतिक उद्देश्यों का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। सूचना प्राप्त हुई है कि रूस द्वारा निर्यात किया हुआ मिट्टी का तेल पश्चिमी योरप में अति अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर अर्जनटाइना, ब्राजील तथा चिली से ऊन, एवम् तौबा यथेष्ट मात्रा में आयात करने में सहयोग प्रदान करता है। रूस का अलमोनियम, टिन, प्लैटिनम तथा जस्ता विदेशों को वृहत् मात्रा में निर्यात किया गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन पदार्थों को सोवियट रूस ने निर्यात किया है, वे सब उसके आवश्यक पदार्थ हैं, जिनकी उसे औद्योगिक प्रगति हेतु अति अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों को उसने न्यूनतम मूल्य पर निर्यात करके विदेशी बाजारों में महान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूस वर्तमान काल में, प्रत्येक योरपीय देश से अपना व्यापार स्थापित कर राजनैतिक सम्बन्ध दृढ़ करना चाहता है। रूस ने गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की थी। हो सकता है कि इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य गुप्त रहा हो। फिर भी अमेरिका से उसका व्यापार शून्य रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रूस की इस नीति से अधिक भयभीत दिखलाई पड़ता है। गत वर्ष व्यापारिक वाद-विवाद होते समय सोवियट रूस ने अमेरिका

से व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने का आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त व्यापार बाधक विभिन्न कारणों की विवेचना की गई। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि सोवियट रूस को अन्तराष्ट्रीय व्यापार में भी अनेक प्रकार से लाभ हो सकता है, क्योंकि सरकार का प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण आधिपत्य है। उदाहरणार्थ रूस के लिये यह भी सम्भव है कि यदि वह अमेरिका से कोई पदार्थ आयात करना चाहता है और यदि अमेरिका ने उस पदार्थ के निर्यात की स्वीकृति भी दे दी है, तो वह उसी के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन का संशोधन करेगा। गत वर्ष सोवियट रूस ने २० हजार टन अलमोनियम, ब्रिटेन को निर्यात किया है इसलिए नहीं कि उसके पास अलमोनियम अतिरेक में था वरन् इसलिए कि ब्रिटेन को मुद्रा की आवश्यकता थी तथा यह ऐसे समय हुआ जब कि रूस को अलमोनियम की स्वयम् आवश्यकता थी। हाल में मिर्कोयन ने बताया कि सोवियट रूस में अलमोनियम उद्योग प्रगति उसी समय से आयोजित की गई है जब से अमेरिका ने योरप के अनेक देशों को सोवियट रूस के साथ अलमोनियम विक्रय न करने के लिये उकसा दिया था। इस बात की हास्यप्रद उपेक्षा करते हुए मिर्कोयन ने अमेरिकन पत्रकार स्टीवेन्सन से कहा “अब हम लोगों ने एक हास्य-प्रद एवम् मार्मिक परिस्थिति उत्पन्न कर ही है। सोवियट संघ उन्हीं देशों को अब अलमोनियम प्रदान कर रहा है, जिन देशों ने उसे अलमोनियम भेजने से इन्कार कर दिया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन सज्जन देशों की हास्य का कोई अनुभव नहीं है।” इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि सोवियट संघ व्यापारिक नीति प्रवृत्ति अधिकतर राजनैतिक है। इसके अतिरिक्त १९५५ से सोवियट संघ ने लगभग १५० औद्योगिक कारखाने अन्य देशों में स्थापित किये हैं जिसके अन्तर्गत कुछ इस्पात, कुछ सूती वस्त्र तथा कुछ सीमेन्ट आदि के सम्मिलित हैं। लगभग १५ देशों से सोवियट संघ का शिल्पकला एवम् यंत्र सम्बन्धी संविदा है। यही नहीं बल्कि लगभग २० हजार लाख डालर की आर्थिक सहायता भी इन देशों को प्रदान की गई है। इसको अवलोकित करते हुये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यह व्यक्त किया कि हम पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता इसलिए प्रदान करते हैं कि हमारे पास अतिरेक में सामग्री है तथा हमारा जीवन-स्तर अति उच्चतम है। परन्तु सोवियट रूस, साम्यवाद एवम् साम्राज्यवाद को विस्तृत करने के दृष्टिकोण से विदेशी व्यापार में इस नीति को ग्रहण किये हुए है।

इक्कीसवाँ अध्याय

सोवियट रूस की अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन

सोवियट रूस की प्रगति सदा से ही एक विवादास्पद का विषय रहा है। पश्चिमी देशों में इस विषय पर अनुसंधान हुये हैं तथा अर्थशास्त्र एवम् राजनीति के विद्यार्थियों ने सोवियट रूस के अनेक आर्थिक पहलुओं का आलोचनात्मक अध्ययन कर सोवियट रूस द्वारा प्रकाशित अंकों को भ्रामक प्रमाणित किया है। कॉलिन क्लार्क (Colin Clark) का नाम इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। अमेरिका में लॉरीमर (Lorimer), कुलिशर (Kulischer), तथा ईज़न (Eason) ने जनगणना सम्बन्धी अनेक रहस्यमय एवम् कटु निष्कर्ष प्राप्त किये हैं तथा सोवियट रूस की जनसंख्या-गणना पर प्रकाश डाला है। खाद्यान्न की न्यूनता तथा उपभोग के विषय पर जॅसनी (Jasny), वोलिन (Volin), टिमोशिन्को (Timoshenko) ने जो अनुसंधान किये, उससे सोवियट रूस के उपभोग क्षेत्र में असफलता की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर है। श्रीमती चैपमैन ने हाल ही में रूसी उपभोक्ता क्रय शक्ति पर अपने विचार प्रकट किये हैं, जो सोवियट रूस की राजकीय सूचना प्रकाशन से पूर्णतः भिन्न है। १९५५ में सासनोवी (Sosnovy) ने निवास गृह समस्या पर कुछ विशेष तथ्य प्रमाणित किये हैं, जिसको पढ़ कर सोवियट रूस की यथार्थ निर्धनता का अनुमान होता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में अनेक विशाल, सुसज्जित तथा प्रचलित संस्थाओं एवम् विश्वविद्यालयों ने भी समाजवाद व्यवस्था के अनेक विषयों पर अनुसंधान किये हैं, जिनको पढ़कर एक साधारण विद्यार्थी को विस्मय एवम् आश्चर्य होता है कि एक ओर तो सोवियट संघ के कथनानुसार उसकी सफलतायें अवर्णनीय

हैं, दूसरी ओर उसके विपक्षियों के अनुसार सोवियट संघ अब भी योरोपीय देशों की अपेक्षा एक पिछड़ा हुआ देश है। कुछ योरोपीय विद्वानों के अनुसार सोवियट संघ द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय भ्रामक हैं, जहाँ अनेक पहलुओं पर तो समंक प्रकाशित ही नहीं किये गये हैं। कॉलिन क्लार्क ने गत २०-२५ वर्षों में इस कार्य में व्यस्त होकर यह निरन्तर अन्वेषण किया है कि सोवियट रूस में प्रगति योरोप के अन्य देशों के समान नहीं हुई है। द्वितीय महायुद्ध के समय में कॉलिन क्लार्क ने सोवियट उत्पत्ति एवम् आय प्रति इकाई की अन्य देशों से तुलना करते हुये परीक्षा की तथा यह निष्कर्ष निकाला कि सोवियट संघ की दशा योरोप के अन्य देशों से अधिक अच्छी नहीं है। १९३८ तक वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर जापान की अपेक्षा कम था, तथा १९२५-१९३२ में यह विश्व के अनेक देशों से निम्न था (केवल भारत, चीन, बाल्टिक राज्य, रोमानिया, बुल्गारिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के अतिरिक्त)। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविक इकाइयों में माप निर्धारित कर आंकड़ों का प्रयोग एक वैज्ञानिक विधि से किया। कॉलिन क्लार्क ने सिद्ध किया कि सोवियट रूस के एक नागरिक का जीवन-स्तर ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का $\frac{1}{2}$ है युद्ध से पूर्व जर्मनी की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ है तथा भारतवर्ष एवम् बर्मा की तुलना में लगभग दुगुने से भी कम है।^१ प्रति

१ कॉलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक The Conditions of Economic Progress (p. 44) में अन्य देशों के साथ सोवियट संघ की तुलना की है। उनका कहना था कि सोवियट रूस की प्रथम एवम् द्वितीय योजनाओं के कार्यान्वित होने के बाद भी उसका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही निम्न है। यह बात इन सारणियों से स्पष्ट है जो कॉलिन क्लार्क ने प्रकाशित की है।

(१८६०-१९३८)

प्रति कार्यशील पुरुष की वास्तविक आय (अन्तर्राष्ट्रीय इकाई में ४८ घण्टा प्रति सप्ताह की दर से)

देश	१८६०	१८८०	१९००	१९२०	१९२८	१९३२	१९३४	१९३६	१९३७
न्यूजीलैण्ड	—	—	८८०	—	१२६७	११६७	१३८२	१६०५	१९०२
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	७६९	८१३	११६१	१२५८	१५५७	९१०	११७९	१४२९	१४८५
ग्रेट ब्रिटेन	५२१	६८७	८६५	—	१०९०	९३२	१०९३	११९८	१२७५
स्वीडन	१५५	२०९	३२५	६५१	६६०	६५०	७१५	८०४	—
जर्मनी	—	५२२	६१८	—	६७५	५५७	६३१	७४१	८२८
फ्रान्स	—	४६९	५३०	—	—	—	—	—	—
जापान	—	(१८८७)७२	(१९०८)९९	१५३	२९३	३१९	३४२	३३७	—
रूस	१८७	—	२२८	११७	२९०	—	२६७	—	३७९

इकाई उत्पादन भी इसी प्रकार १६३८ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा १/२, ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा १/३ से कुछ ही अधिक तथा जर्मनी की तुलना में आधे से भी कम है ।^१

कोलिन क्लार्क तथा अन्य अमेरिकन अर्थशास्त्र एवम् राजनीति के विद्यार्थी-गण सोवियट रूस की उन्नति को स्वीकार नहीं करते तथा अंकों द्वारा यह सिद्ध करने की पूर्ण चेष्टा करते आये हैं कि :

(क) सोवियट रूस ने उतनी अधिक उन्नति नहीं की है जितना कि उसका दावा है ,

(ख) अनेक क्षेत्रों के विषय पर सांख्यिकी उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) जो प्राप्त भी हैं वे अपूर्ण हैं तथा

(घ) वे अधिकतर आश्वासनीय हैं ।

सोवियट रूस द्वारा प्रकाशित समंको पर कॉलिन क्लार्क तथा उनके सह-पाठी पूर्ण विश्वास ही नहीं करते तथा वे उसकी मिथ्या प्रशंसा करने के पूर्णतः विरोधी हैं । अधिकांशतः ऐसा अनुमान था कि “सोवियट रूस की आर्थिक उन्नति अन्य देशों की अपेक्षा अति प्रगतिशील है तथा अल्पकाल में ही रूसियों का जीवन-स्तर अमेरिकन निवासियों के जीवन स्तर से उच्च हो जावेगा” आदि, आदि । यहाँ तक कि अमेरिका में भी अनेक संस्थाओं तथा विद्यालयों ने कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से ही सोवियट संघ की सफलताओं को स्वीकार कर लिया था । किन्तु कॉलिन क्लार्क ने इनको “कल्पित” तथा “अर्द्ध-सत्य” कहकर

‘(१८६०-१९३८) प्रति पुरुष राष्ट्रीय आय

(कार्य का २५०० घण्टा प्रति अन्तर्राष्ट्रीय इकाई)

देश	१९०९-१०	१९११-१२	१९१५-१६	१९३०-३१	१९३५-३६
न्यूजीलैण्ड	४४०	५१२	५५०	५३०	७१०
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	४८४	५०६	५९०	४३८	५४५
ग्रेट ब्रिटेन	४३४	४०३	५०२	४८८	५८४
स्वीडन	१६५	२४०	२७५	३०१	३६७
जर्मनी	२६३	२७९	२९२	२६१	३४३
फ्रान्स	२७९	३०२	३१०	३१६	३५८
जापान	४९	७२	१०२	११३	१३९
रूस	१०२	५७	९५	९०	१०८

सोवियट सांख्यिकी की हँसी उड़ाई। सोवियट राज्य के पदाधिकारियों को कॉलिन क्लार्क ने “चालाक तथा धूर्त” की संज्ञा दी तथा उनके द्वारा प्रकाशित समकों की घोर निन्दा की। उसने अमेरिका के उन व्यक्तियों पर भी कोप प्रकट किया जो शनैः शनैः सोवियट संघ की स्वतः प्रशंसा से प्रभावित होकर या तो उसकी सफलताओं के गुण गाने लगे, अथवा उनकी आलोचना करने में निरोत्साहित हो गये हैं। अगस्त १९५५ में लंदन की एक पत्रिका^१ में लिखते हुये उसने विचार प्रकट किया : “पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का ध्यान शान्तियुक्त व्यग्र विषयों पर से विचलित हो गया है, जिन पर यदि वे किंचित मात्र भी प्रयास करते तो उन्हें यथेष्ट आलोचनात्मक सामग्री प्राप्त हो सकती थी। इसके स्थान पर उन लोगों ने अपना ध्यान उन विषयों पर एकाग्र किया है, जिनको सोवियट सरकार सफलतापूर्वक विज्ञापित करती है। जिसके फलस्वरूप वे वास्तविकता से दूर हो जाते हैं तथा सोवियट रूस के विषय पर भ्रमक धारणायें ग्रहण कर लेते हैं।”

कॉलिन क्लार्क ने अनेक ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनके द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि सोवियट रूस अपनी वास्तविकता को भली प्रकार आवरित किये हुई है। सम्मुख कुछ तथा पीछे कुछ और। सोवियट सरकार ने निर्वाह व्यय सांख्यिकी १९२९ में तथा जन्म एवम् मृत्यु सम्बन्धी संकलित सामग्री का प्रकाशन १९३० में स्थगित कर दिया। यद्यपि १९३७ में एक जनगणना हुई थी, तथापि उसके भी अंक प्रकाशित न किये गये तथा तत्पश्चात् ज्ञात हुआ कि अधिकांश जनगणना अधिकारीगण क्रान्तिकारी, तानाशाही तथा ट्राट्स्की दल के अनुयायी थे, जिन्होंने सांख्यिकी विज्ञान के सम्पूर्ण नियमों का उल्लङ्घन किया था। इसी प्रकार जिस आधार पर सत्य सांख्यिकी संकलन करके प्रकाशित की जाती थी, वह भी १९३१ में परिवर्तित कर दी गई। सर्व प्रथम वास्तविक सत्य का प्रकाशन होता था, परन्तु अब सत्य सामग्री संकलन का आधार दूसरा है। इसके अन्तर्गत सामान्य वातावरण एवम् जलवायु तथा प्रस्तुत परिस्थिति में प्राणीतत्वज्ञ (biologists) कितना उत्पादन करते हैं, अनुमान किया जाता है। कॉलिन क्लार्क का कहना है कि किसी भी रूसी विशेषज्ञ से निम्नलिखित प्रश्न करिये, आप देखेंगे कि उसको उत्तर देने में असुविधा होती है तथा वह प्रश्नोत्तर समुचित न दे सकेगा :

(क) रूस की जनगणना क्या है तथा किस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है ?

(ख) औसत रूसी खाद्यान्न प्रति इकाई उपभोग क्या है तथा इसकी तुलना ३८-४० वर्षों से किस प्रकार की गई है ?

(ग) औसत रूसी कुटुम्ब के पास कितना निवास स्थान है ?

पुनः ध्यान आकर्षित करते हुये उसने कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि कोई साम्यवाद पार्टी का नेता अथवा राजनीतिज्ञ कुशल पुरुष इन प्रश्नों का उत्तर “चीचपड़ तथा टालमटोल” करके दे देगा, पर एक सुलझे हुए संतुलित विशेषज्ञ के लिये इनका उत्तर देना सरल न होगा। वे केवल इतना कह सकेंगे : “मुझे इन विषयों पर वर्तमान जानकारी नहीं है। सोवियट रूस ने गत वर्ष ‘सल्फूरिक एसिड’ का कितना उत्पादन किया है और वे अमेरिका से कितने आगे इस क्षेत्र में है, इसकी जानकारी हमें अच्छी प्रकार है, जिस पर हम प्रकाश डाल सकते हैं।”^१

हारवर्ड विश्वविद्यालय के एक गवेषणा-विद्यार्थी, ग्रीगोरी ग्रासमैन (Gregory Grossman) ने १९५३ के एक सुसंगठित निबन्ध संग्रह (सिम्पोजियम) के प्रथम लेख में, जिसको कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्रम बर्गसन (Abram Bergson) ने सम्पादित किया था लिखा कि सोवियट रूस की प्रगति छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हुई है। कॉलिन क्लार्क ने इसकी व्यंगात्मक हँसी उड़ाई है तथा इस विचाराधारा की तुलना माल्थस के जनगणना सिद्धान्त से की है, जिसके अनुसार जनसंख्या की गुणोत्तर वृद्धि की गति अखण्डनीय है। उसका कहना है कि दोनों परिस्थिति-गणित विद्या के मिथ्या अभिमान का अद्भुत तथा भयंकर चित्र है जिसमें अति संदिग्ध तथ्यों में निर्विवाद गणित पद्धतियों का प्रयोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये किया जाता है।

ग्रीगोरी ग्रासमैन ने १९२८-३७ तथा १९४८-५० के दो युगों की प्रगति दर की गणना की। प्रथम युग हेतु उन्होंने ६½ प्रतिशत वार्षिक दर का अनुमान लगाया। डा० जैसनी तथा कॉलिन क्लार्क^२ द्वारा प्रगति दर ४½-५ प्रतिशत अनुमानित की गई। कॉलिन क्लार्क ने सोवियट रूस द्वारा प्रकाशित अंक गणना के

१ Encounter : August, 1955, p. 44.

२ ग्रीगोरी ग्रासमैन तथा कॉलिन क्लार्क ने इस विषय पर प्रतिवाद १९५५-५६ में हुआ था जो अगस्त १९५५ तथा फरवरी १९५६ के ‘एन्काउन्टर’ (Encounter) के अंक में प्रकाशित हुई थी। ग्रीगोरी ग्रासमैन के अनुसार युद्ध-पूर्व काल में सोवियट रूस ने प्रगति दर ८-९ प्रतिशत वार्षिक दर से की तथा युद्धोत्तर काल में (१९४८-५०) यह प्रगति-दर १३ प्रतिशत थी। ‘सोशल रिसर्च’ (Social Research) नामक पत्रिका में १९५४ के वसंत-ऋतु अंक में डा० जैसनी ने ग्रीगोरी ग्रासमैन के अनुमान की आलोचना करते हुये यह निष्कर्ष निकाला कि वे बहुत ही न्यून थे।

विषय में प्रकाश डालते हुये कहा कि सोवियट संघ ने १९२६-२७ वर्षों पर अधिक महत्त्व तथा भार दिया, क्योंकि ऐसा करने से प्रगति-दर अनुपात में वास्तविकता से अधिक प्रतीत होती है, जब कि वास्तव में इस युग में सोवियट कृषि की दशा चिन्तनीय थी। इस दृष्टिकोण से कृषि उत्पत्ति समंक पर यथेष्ट भार न दिया गया था। हर एक आलोचक रूस की वृद्धता तथा मिथ्या वर्णन से परचित है। यही कारण है कि ग्रासमैन तथा प्रोफेसर बर्गसन ने १९३७ को आधार मान कर विभिन्न अन्वेषण किये तथा १९२६-२७ अवधि पर भार न दिया। कॉलिन क्लार्क के अनुसार १९३७ का वर्ष भी सामान्य वर्ष से भिन्न है, क्योंकि इस समय भी रूस में अनेक सामग्रियाँ वास्तविक मूल्य से अधिक परिव्यय पर निर्मित की जा रही थीं। इस कारण भी प्रगति दर पर सांख्यिकीय भार एक विकृति रूप से पड़ा। कृषि पदार्थों के उत्पादन में यथेष्ट ह्रास हुआ था, परन्तु इसका उचित भार समकों पर न पड़ पाया। इन तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुये कॉलिन क्लार्क ने १९२८-३७ की प्रगति दर को $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक अनुमानित न किया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक प्रगति दर भविष्य में स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के प्रारम्भ में प्रगति-दर बाद के प्रगति-दर से अधिक होगी। अतः १९४८-५० के विषय में ही नहीं बल्कि उसके उपरान्त भी उनका विचार है कि अति न्यून दर से सोवियट संघ में प्रगति होनी चाहिये। १९२८-३८ में प्रति-पुरुष-वन्टा-उत्पत्ति सम्भवतः १६ प्रतिशत वार्षिक दर थी जो १९२८-५३ में २ प्रतिशत हो गई। कॉलिन क्लार्क के अनुसार यह साधारण कोटि के दर हैं। उनका विचार है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने १८९० से प्रगति का एक अचल वार्षिक दर (steady rate) २.३ प्रतिशत स्थापित कर लिया है, जिससे तात्पर्य यह है कि सोवियट संघ एवम् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य अन्तर न्यून होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, फ्रान्स, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे, स्वीडन, तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी उसी काल में अति अधिक दर से उन्नति की है तथा इसलिये यह विचार करना कि सोवियट संघ अन्य देशों को प्रगतिशील प्रतियोगता एवम् प्रतिद्वन्द्वता में शीघ्र ही पराजित कर देगा, एक भ्रामक धारणा है। कॉलिन क्लार्क का अनुमान है कि सोवियट रूस की कृषि उत्पादन निर्बलता सम्पूर्ण सांख्यिकीय संकलन को यथेष्टतः प्रभावित नहीं करती। यही नहीं इस विद्वान अर्थशास्त्री ने सोवियट कृषि की प्रगति का ऐतिहासिक अध्ययन करते हुये सिद्ध किया कि विश्व के थोक मूल्यों पर आधारित रूस की सकल कृषि उत्पत्ति केवल १०० पौण्ड प्रति कृषक श्रम-शक्ति थी। वर्तमान काल में सम्भवतः ही योरोप का

कोई ऐसा देश हो जहाँ प्रति पुरुष कृषि उत्पादन इतना न्यून हो। इटली में भी इतना न्यून उत्पादकता आज से ३०-४० वर्ष पूर्व थी।^१

यारपीय अर्थशास्त्रियों का कथन है कि सोवियट संघ में समंक प्रहस्तन (manipulation of statistics) इस प्रकार किया जाता है कि विशेष हितों का स्वार्थ सिद्ध हो सके। कई महत्वपूर्ण तथ्य, जिनका समंको पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है, जानबूझ कर छोड़ दी जाती हैं। निष्पत्ति होकर वैज्ञानिक निरपेक्षता के साथ समंको का संकलन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भ्रमात्मक परिणाम निकाले गये हैं, जिसके कारण समंक अविश्वासनीय भी हैं। जून २६-२७, १९५७ को म्यूनिच (Munich) में सोवियट रूस के ४० वर्ष की राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में एक निबन्ध संग्रह ('सिम्पोजियम') किया गया। जार्ज ए० टास्किन (George A. Taskin) ने सोवियट रूस की समंक प्रहस्तन पर प्रकाश डालते हुये कहा :

(क) सोवियट अधिकारीगण अपनी प्रतिशतक आर्थिक प्रगति प्रकाशित करके स्व-सफलता का अनुमान लगाते हैं। उसी आधार पर वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सोवियट समाजवाद ने पूँजीवाद प्रगति-स्तर को केवल ग्रहण ही नहीं कर लिया है वरन् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्मित किया है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि सोवियट संघ का पूँजीवाद देशों को पकड़ने अथवा परास्त करने की बात तो दूर रही, उनके समकक्ष प्रतिशतक प्रगति अनुपात में भी वह पिछड़ गया है। उदाहरणार्थ, १९४० में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ६१० लाख टन तथा सोवियट संघ ने १८० लाख टन इस्पात उत्पादन किया। १९५५ में यह संख्यायें १०६० तथा ४५० लाख टन थीं। उसी तथ्य का विश्लेषण १९५६ में 'पार्टी लाइफ' नामक पत्रिका में एक लेखक ने निम्न शब्दों में किया : "१९४० में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उत्पादन सोवियट संघ के उत्पादन से ३.३ गुना अधिक था, जो १९५५ में केवल २.४ गुना शेष रह गया।" परिणामस्वरूप, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सोवियट संघ तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अन्तर न्यून हो रहा है तथा सोवियट संघ की प्रतिशतक प्रगति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कहीं अधिक है। जार्ज टास्किन के मतानुसार अंको का इस प्रकार प्रयोग भ्रामक है, जिनको प्रस्तुत करने में सांख्यिकीय रीतियों का उचित उपयोग नहीं किया गया है।

(ख) सोवियट संघ एक अन्य रीति का प्रयोग करता है, जो प्रतिशतक

गणना में परिभ्रान्ति है। गत उदाहरण को समझाते हुये यह कहना अनुचित न होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस्पात का उत्पादन १९४० तथा १९५५ में ६१० तथा १०६० लाख टन होने के कारण क्रमशः ७५ प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार सोवियट संघ में १९४० की अपेक्षा उत्पादन वृद्धि १९५५ में १५० प्रतिशत थी। इन प्रतिशतक प्रगति से सोवियट संघ योजना ने शीघ्राति-शीघ्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को परास्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परन्तु वास्तव में यदि इन प्रतिशतक वृद्धि को पृथक् रक्खा जावे, तो परिस्थिति अत्यन्त भिन्न दृष्टिगोचर होती है। १९४० में इस्पात का उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियट संघ में ६१० तथा १८० लाख टन क्रमशः था। उनमें परिमाणिक अन्तर ४३० लाख टन था। १९५५ में उत्पादन क्रमशः १०६० तथा ४५० लाख टन था अर्थात् अन्तर ६१० लाख टन हो गया। इससे स्पष्ट है कि सोवियट संघ तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्पादन अन्तर बढ़ गया है, तथा यह कहना अनुचित होगा कि सोवियट संघ ने प्रतिशतक अधिक उन्नति की है इसलिये उसकी प्रगति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अधिक प्रभावशाली है। ऐसा कहा गया है कि कितनी भ्रामक गणना हो सकती है यदि केवल प्रतिशतक उन्नति ७५ तथा १५० प्रदर्शित की जावे। केवल निरपेक्ष अंक (absolute figures) से वास्तविकता का पता चलता है, जो अधिकांशतः सोवियट संघ में गोप्य है।

केवल इस्पात ही नहीं वरन् अन्य पदार्थों के विषय में इसी प्रकार की सांख्यिकीय गणना की जाती है। टास्किन ने अन्य पदार्थों के भी समको पर प्रकाश डाला है। ऐसा कहा गया है कि मिट्टी के तेल के नये क्षेत्रों का अन्वेषण जो गत वर्षों में हुआ है, उसकी प्राप्ति के पश्चात् भी सोवियट संघ को अमेरिका के वर्तमान उत्पादन स्तर ग्रहण करने में बीसों वर्ष लग जावेंगे, क्योंकि निरपेक्ष परिमाण में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उत्पादन सोवियट संघ से कई गुना अधिक है। सोवियट संघ १९१३-१९१७ में एक अति पाश्चवर्ति देश था, अतः जितना भी उत्पादन तत्पश्चात् हुआ वह प्रतिशत में अति अधिक प्रतीत होता है, जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक ही गति से निरन्तर उत्पादन में वृद्धि किया है।

प्रस्तुत दोनों राष्ट्रों में सीमेन्ट का उत्पादन भी यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर करता है तथा वहाँ उत्पादन में अन्तर वृद्धताकार है। १९५६ में सोवियट संघ ने २५० लाख टन सीमेन्ट उत्पादन किया जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ५३० लाख टन। इस प्रकार विद्युत् में भी सोवियट संघ ने गत वर्षों में जो उन्नति की है वह अवर्णनीय एवम् प्रशंसनीय है, परन्तु अभी सोवियट संघ केवल १९१०

लाख किलोवाट उत्पादन करता है, जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ६८२० लाख किलोवाट ।

पश्चिमी योरप के आलोचक कहते हैं कि सोवियट संघ में उत्पादन प्रति इकाई फ्रान्स, जर्मनी तथा ब्रिटेन का १/२ है। उनका कथन है : "सोवियट संघ ने जिस गति से उन्नति की है विश्व हेतु कोई नवीन घटना नहीं है और न यह कोई समाजवाद का विशेष चमत्कार ही है। एक समय था जब पूँजीवाद देशों में भी उसी गति से उन्नति हुई थी। क्योंकि सोवियट संघ ने प्रगति निम्न श्रेणी से की है, इसलिये प्रतिशतक प्रगति अस्वाभाविक प्रतीत होती है।" सांख्यिकीय दुरुपयोगिता पर ध्यान आकृष्ट करते हुये टास्किन ने पुनः कहा : "यदि मुझे ५०० डालर तथा किसी व्यक्ति 'अ' को १०० डालर प्रति मास मिलते हैं और मेरे २० प्रतिशत तथा उसके ५० प्रतिशत वेतन में वृद्धि हो जाती है, मुझे आशा है कि पाठकगण समझ सकेंगे कि परिमाण में मेरा २० प्रतिशत उसके ५० प्रतिशत से अधिक है। उत्पादन प्रति इकाई की ओर भी दृष्टि ले जाने से ज्ञात होता है कि सोवियट संघ अब भी एक पश्चवर्ती देश है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा १२ अन्य योरप के स्वतंत्र देशों की प्रति इकाई उत्पादन का अध्ययन करने से अनुभव हुआ है कि सोवियट संघ का स्थान विद्युत् शक्ति उत्पादन में १३वाँ, इस्पात उत्पादन में ८वाँ तथा सीमेन्ट में १३वाँ है। वर्तमान काल में उसका स्थान प्रति इकाई मक्खन उत्पादन में १२वाँ, मार-गेराइन में १३वाँ तथा चीनी में ९वाँ है।"

(ग) सोवियट रूस ने समकों की सापेक्ष तुलना उन क्षेत्रों में अधिक की है जिनमें विज्ञान की प्रगति के कारण उतना महत्त्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नहीं दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गत वर्षों में रेल निर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूँजीवाद प्रगति को समाजवाद प्रगति ने परास्त कर दिया है (यद्यपि सोवियट संघ ऐसी ही धारणा बनाये हुये है), वरन् वास्तव में सत्य तो यह है कि रेल यातायात का महत्त्व अन्य आधुनिक यातायात पर अधिक ध्यान देने के कारण न्यून हो गया है। दो पुरुष दौड़ रहे हैं, परन्तु एक ने दौड़ना स्थगित कर दिया है, तब दूसरा चाहे जितना धीरे दौड़े, प्रथम पुरुष से आगे हो जावेगा। कोयले उत्पादन में भी ऐसा ही हुआ। सोवियट संघ में कोयला उत्पादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष हो गया है। पर क्यों ? इसलिये कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कोयले के उत्पादन पर यथेष्ट ध्यान न देकर तेल तथा गैस शक्ति पर अधिक ध्यान दिया है, जो कि कोयले का पूरक है। गैस का उत्पादन संयुक्त राष्ट्र में

२,१० घन मीटर है, जब कि सोवियट संघ में केवल २०० है। तेल में भी लगभग ऐसा ही विभिन्नता है। यही कारण है कि कोयला उत्पादन सोवियट संघ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समान स्तर पर है। इसी प्रकार यदि सोवियट संघ ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रेलवे निर्माण में परास्त कर दिया है, तो इसका कारण यह है कि सोवियट संघ 'प्राचीन' यातायात साधन की प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपेक्षा अधिक ध्यान दे रहा है। टास्किन के मतानुसार सोवियट संघ सांख्यिकीय गणना के आधार पर उन तथ्यों पर अधिक प्रभाव डालता है जो उसको प्रगति को अत्यधिक आकार में प्रकाशित करते हैं। यदि उद्देश्य दंषित है तो समंको का दुरूपयोग किया जा सकता है। सोवियट संघ स्पष्टतः एक ज्वलंत उदाहरण है।

जुलाई १९५६ को एक सांख्यिकीय प्रकाशन उपलब्ध हुआ, जिसमें सोवियट संघ की गत २० वर्षों की प्रगत का उल्लेख किया गया। इससे यह न समझना चाहिये कि इस प्रकाशन के पूर्व सोवियट संघ सांख्यिकी के महत्त्व की निरन्तर अवदलना करता रहा है। कदापि नहीं। लनिन ने एक बार कहा था कि "मूल रूप से समाजवाद स्वयम् समंक है।" स्टालिन का कथन था कि आर्थिक गणना बिना सांख्यिकी के निर्मूल तथा संज्ञारहित है। इससे यही प्रतीत होता है कि सोवियट संघ ने पश्चिमी देशों को अपनी प्रगति के विषय पर प्रारम्भ से ही भ्रम में रखना चाहा है। कुछ समय तक तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी सोवियट रूस के विषय पर यथेष्ट समंक समाचार-पत्र तथा संवाद-दातों द्वारा अपर्याप्त मात्रा में भिन्न भिन्न खण्डों से संकलित करते थे। सांख्यिकी प्राप्त करने का सर्व प्रधान साधन केन्द्रीय सांख्यिकीय प्रकाशन (Central Statistical Administration) की वार्षिक रिपोर्ट थी, जिसके अन्तर्गत योजना के लक्ष्य की सफलता, राजकीय बजट से सम्बन्धित प्रादेश, पार्टी कांग्रेस की बैठक में राज्य पदाधिकारियों के भाषण तथा सर्वोच्च सोवियट के अधिवेशन (Sessions of the Supreme Soviet) का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होता था। अनेक प्रधान रूसी लेखकों द्वारा समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में जो समंक प्रकाशित किये जाते थे वे ही जनसाधारण को प्राप्त थे। द्वितीय महायुद्ध काल में सोवियट अर्थव्यवस्था की दशा पर प्रकाश डालने वाली केवल एक ही साधन सामग्री उपलब्ध है।^१ उस समय समंक केवल अंशों में ही प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त युद्धकालीन परिस्थिति के अन्तर्गत कहाँ तक सोवियट रूस ने सत्य समंक प्रकाशित किये हैं, एक

१ The Wartime Economy of the U. S. S. R. During the Patriotic War, Moscow, 1948.

संदिग्ध विषय है। युद्धोपरान्त सोवियट संघ से कुछ समय तक कोई भी सूचना प्रकाशित करना स्थगित कर दिया गया था। इसके उपरान्त भां सोवियट रूस द्वारा प्रकाशित अधिकतर समंक प्रतिशतक थे तथा केवल निरपेक्ष संख्यायें थीं। वे केवल भूतकाल से प्रतिशत में सापेक्ष अध्ययन प्रदान करते थे, जिनका महत्त्व वास्तविक संख्याओं के न होने के कारण अधिक न था। इसके पारणामस्वरूप, जब १९५६ में एक सांख्यिकीय प्रकाशन उपलब्ध हुआ, विश्व को यह आश्वासन हुआ कि गंभीर गवेषणा एवम् अध्ययन के दृष्टिकोण से यह पुस्तक भविष्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगी। इसके पूर्व १९३६ में सोवियट संघ ने समंको की एक पुस्तक^१ प्रकाशित की थी, जिसमें लगभग १००० पृष्ठ थे, जब कि इस बार यह केवल २६२ पृष्ठों की एक पुस्तिका है जिसमें १४ पृष्ठ तो सोवियट संघ के विषय पर भी नहीं हैं। यह पुस्तिका निम्नलिखित विषयों पर समंक प्रस्तुत करती है :

- (क) ३४ सारणी : जनसंख्या तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उत्थान;
- (ख) ७१ सारणी : उद्योग-धन्धे;
- (ग) ५२ सारणी : कृषि;
- (घ) १६ सारणी : पूजी निर्माण;
- (ङ) २२ सारणी : यातायात तथा संवादवाहन;
- (च) १४ सारणी : श्रमिकां तथा विशेषज्ञां का संख्या एवम् योग्य श्रमिकों का प्रशिक्षण;
- (छ) २१ सारणी : व्यापार;
- (ज) २४ सारणी : संस्कृति;
- (झ) ७ सारणी : स्वास्थ्य सेवा।

इतना सब होते हुये भी यह पुस्तिका सर्वव्यापक नहीं है। इसकी भूमिका में लिखा है : “अनेक सांख्यिकीय गणनायें जो इस पुस्तिका में प्रस्तुत नहं हैं, केन्द्राय सांख्यिकीय प्रशासन द्वारा प्रकाशित अनेक व्यापार सम्बन्धा सांख्यिकीय पुस्तिका में दी जावेंगी, जब कि संघीय एवम् गणतंत्र राज्य सम्बन्धा विस्तृत समंक केन्द्राय सांख्यिकीय प्रशासन द्वारा प्रकाशित किए जावेंगे।” इसके अतिरिक्त जो भी समंक उपलब्ध हैं वे प्रातिशतक हैं, जिससे कि उनका महत्त्व क्षीण हो जाता है। यदि आधार वर्ष के विषय पर निरपेक्ष अंक प्राप्त हों तो यही समंक बड़े उपयोगी हो सकते हैं, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है।

इस पुस्तिका में अंकों को भिन्न-भिन्न सारणी में इस प्रकार रक्खा गया है कि वे अतुलनात्मक हैं। पिछले अंकों का आधार वर्ष प्रस्तुत सांख्यिकी से भिन्न है, जिसके कारणवश उन अंक समूहों की तुलना भी असम्भव है। सांख्यिकी का विद्यार्थी भली प्रकार जानता है कि समंको की तुलना तभी हो सकती है, जब कि उनका मूलाधार सामान्य हो। सोवियट रूस के विषय में यह कथा प्रचलित है कि वे सांख्यिकीय तथ्य प्रदान करने में उतने उदार तथा सत्यनिष्ठ नहीं हैं जितना किसी राष्ट्र को होना आवश्यक है। आलोचकों का अनुमान है कि सम्भवतः सोवियट संघ द्वारा प्रकाशित सारणी तथा समंक त्रुटियुक्त न भी हों, फिर भी जो उपलब्ध हैं वे इस प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं कि सोवियट रूस के विषय में परिशुद्ध विचार न कर मिथ्यावादी एवम् संदिग्ध धारणा ही उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में इसकी न्यूनता तथा असफलता अधिक है उन विषयों पर वह प्रायः नीरव तथा निश्चेष्ट है तथा यदि कुछ अंक वह प्रस्तुत भी करता है तो इस ढंग से कि भ्रामक धारणायें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। पश्चिमी जर्मनी के एक आलोचक ने लिखा : “राज्य तथा सहकारी उद्योग में श्रम उत्पादकता सम्बन्धी सारणी ने “सकल अंक” प्रस्तुत किये हैं। प्रत्येक उद्योग में पृथक-पृथक कितने परिमाण में उत्पादन है अप्राप्य है। ज्ञात हुआ है कि ईंधन उद्योग में श्रम उत्पादन स्तर अति न्यून है, जिसका वथेष्ट अनुमान सोवियट सांख्यिकी से प्राप्त नहीं होता।” जनवरी १, १९५६ को सोवियट संघ के पास १,७६० हजार धातु काटने की मशीनें थीं, जो १९०८ के अंकों का २,३४७ प्रतिशत है। यह अज्ञात है कि कितने यन्त्र स्वचालित हैं तथा कितने अस्वचालित हैं। इसी प्रकार यद्यपि लोहा तथा इस्पात उत्पादन सम्बन्धी समंक प्रकाशित हुये हैं, फिर भी आलोचक का कहना है कि भट्टियों का आकार तथा उनके भौगोलिक विवरण सम्बन्धी कोई सूचना ज्ञात नहीं है। उसने पुनः कहा कि १९५५ को सोवियट संघ ने ४४५,३०० मोटरगाड़ी उत्पादन किया था जब १९५० में केवल ३६२,९०० मोटरगाड़ियाँ निर्माण की गईं, जो संख्यायें १९५६ में प्रकाशित सांख्यिकीय पुस्तिका में दी गई हैं। इसके विपरीत १९५६ में जब चौथी पंचवर्षीय योजना निर्माण की गई थी, योजना का उत्पादन लक्ष्य ५ लाख मोटरगाड़ियाँ था तथा १९५० में जब योजना कार्यान्वित होकर पूर्ण हुई, तो राजकीय घोषणा होती है कि मोटरगाड़ी उत्पादन लक्ष्य पूर्ण हो गये हैं। इसी प्रकार ट्रक निर्माण लक्ष्य ४२८ हजार था जब कि पुस्तिका में वास्तविक उत्पादन २९४ हजार प्रदर्शित किया गया था। मोटरों का भी निर्माण ६५,५०० लक्ष्य किया गया था, जब कि १९५० में वास्तविक निर्माण की संख्या ६४,५००

दी गई थी। ऐसी असंलग्नता रूस के समंको की महान त्रुटि है।^१ प्रस्तुत असंलग्नता अन्य क्षेत्रों में भी दृष्टिगोचर होती है।

उपर्युक्त आलोचनात्मक तथ्यों में से अनेक पहलुओं पर सोवियट संघ के पास कोई उत्तर नहीं है। सांख्यिकीय सम्बन्ध में अनेक आलोचनाओं में यथेष्ट सत्यता है। मार्च २२, १९५८ को 'जर्नल आफ कामर्स' के प्रकाशक एरिक रिडर (Eric Ridder) तथा उसके सम्पादक, हेयन्ज ल्यूडिक (Heinz Luedicke) ने खुशचेव से भेंट की तथा कुछ प्रश्न पूँछे, जिनमें से एक प्रश्न रूसी सांख्यिकीय त्रुटियों से सम्बन्धित था। खुशचेव का उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक था। उन्होंने सैद्धान्तिक तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अधिक फेर-फार की बातें की।^२ खुशचेव को अस्वीकार था कि सोवियट संघ आवश्यक सांख्यिकी प्रकाशित नहीं करता है। कुछ भी हो, आलोचना करते समय यह न भूलना चाहिये कि अधिकतर आलोचक पूँजावाद प्रचारक एवम् समाजवाद के विरोधी हैं।

लेखक को यह आशंका है कि उपर्युक्त वर्णन से पाठकगण कहीं यह न निष्कर्ष निकालें कि सोवियट रूस एक पश्चवर्ती देश है तथा जो कुछ राजकाय सूचना सोवियट प्रगति हेतु प्रकाशित हुई है, भ्रामक है। वास्तव में आधुनिक सोवियट रूस एक उन्नतिशील राष्ट्र है, जिसका विश्व में द्वितीय स्थान है, जैसा कि गत पृष्ठों में लिखा जा चुका है। परन्तु प्रस्तुत लेखक, पाठकों का ध्यान सोवियट रूस तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य शीत युद्ध (cold war) की ओर अवश्य ले जाना चाहता है, जिसके कारण सत्य एवम् भ्रमरहित तत्वों का ज्ञान दुष्कर हो गया है। आज सोवियट रूस न तो असावधान है, न रक्त-पिपासु प्रलुण्ठक (bloodthirsty marauders) और न प्रादेशिक प्रसारवादी ही। यह भी कथन भ्रामक होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही युद्ध इच्छुक है। दोनों राष्ट्र यह अस्वीकार करते हैं कि उनकी आकांक्षा अथवा प्रकृति किसी भी ओर से आक्रमणकारी है। परन्तु फिर भी वे निरन्तर प्रयास करते हैं कि दूसरे की सापेक्ष शक्ति विनिष्ट हो जाये तथा वे एक दूसरे से अति अधिक प्रबल हो

१ A. Polezhaev : Soviet Heavy Industry and the Latest Statistical handbook (Bulletin : Institute For the Study of the U.S.S.R., February, 1957.)

२ N. S. Khrushchev : For Victory In the Peaceful Competition with Capitalism, Foreign Languages Publication House, Moscow, 1959, p. 225.

जायें। परिणामस्वरूप उनके मध्य विपत्तिजनक एवम् संचयी आतति अथवा मनमुटाव बढ़ता गया है।

जनरल लॉरिस नस्टेड (General Lauris Norstad) ने, जो योरप में सर्वोच्च संबद्ध सेनापति (Supreme Allied Commander) थे, जून १९५७ को कहा : “पश्चिमी योरप के पास अब इतनी शक्ति है कि वह ‘कुछ ही घण्टों में’ सोवियट रूस की निरपेक्ष युद्ध शक्ति का विनाश कर सकता है।” यह वाक्य सोवियट रूस के दीर्घ क्षेप्यास्त्र (Long Range Missile) तथा स्पुटनिक से पूर्व व्यक्त किया गया था। फिर भी खुशचेव का उत्तर था : “ऐसे अविवेकी एवम् उग्र पुरुषों के प्रति असावधान न रहना चाहिये और सम्भवतः हम उन्हें भूल भी नहीं सकते। हम उस मेमने के समान नहीं रहना चाहते, जो भेड़िये के आक्रमण का उत्तर न दे सके। हमारे दाँत होने चाहिये, ताकि भेड़िया केवल खाल च्याँत ही न हो; याँद हो सके, तो उसका सिर भी काट लिया जाये।” इसके उपरान्त ही दोनों देशों में प्रतिस्पर्धाजनक वैज्ञानिक प्रगति, अन्वेषण, अनुसंधान, खोज आदि होने लगा तथा इस होड़ में सोवियट रूस, जनता के कल्याण अथवा हित पर उचित ध्यान न दे सका। सोवियट रूस का भय है कि : “संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तृतीय महायुद्ध का आयोजन कर रहा है। सम्भवतः उनका उद्देश्य यह है कि योरप के देशों को पारस्परिक वृद्ध में संलग्न कर दिया जाये..... लगभग वैसा ही जैसा गत महायुद्ध में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध से पुनः धनोपार्जन करना चाहता है।..... ये पूँजीपति, शीत युद्ध को तिलांजलि देना नहीं चाहते..... सम्भवतः शीत युद्ध ही उनकी व्यवस्था का संचालक है।” सोवियट संघ भली प्रकार समझता है कि भारी उद्योग, शिल्पकला, प्रौद्योगिक प्रगति, विज्ञान आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिनको प्रधानता देना अत्यन्त आवश्यक है तथा जिन क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अन्य देशों को आतक्रमण कर चुका है। उनमें भारी परिमाण में हानिकारक भावना है, जिसके फलस्वरूप वे शीघ्रातिशीघ्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इन क्षेत्रों में पकड़ना चाहते हैं। इसके प्रांतकूल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कथन है : “हम भली प्रकार जानते हैं कि यदि कल संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका एवम् सोवियट संघ में युद्ध हो जाये तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विजय होगी। परन्तु इसका यह यह तात्पर्य नहीं कि सोवियट संघ परास्त हो जावेगा। यह अब ऐसा देश नहीं है जो सरलतापूर्वक परास्त किया जा सके, जहाँ विदेशी सेना रक्खी जा सके, तथा जिस पर विदेशी सत्ता राज्य कर सके।” १९४९ में सोवियट रूस ने अणु बम्ब (atomic bomb) का निर्माण किया। इसके पूर्व

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बिना किसी प्रतिशोध की शंका के एक रात्रि में सोवियट संघ को नष्ट कर सकता था; ठीक उसी प्रकार सम्भवतः सोवियट संघ भी 'नाटो' (NATO) के पूर्व पश्चिमी योरप को एक बार में परास्त कर अपने अधीन कर सकता था। परन्तु ऐसा कुछ न हुआ। केवल शीत युद्ध ही स्थायी रहा। अमेरिकन अपने को 'लोक-तांत्रिक' एवम् 'शान्ति-अनुरागी पुरुष' कहते हैं। परन्तु साम्राज्यीय साहसिक कायों में निरन्तर संलग्न रहते हैं। जार्डन में आयुध-लिफ्ट (arms lift) घटना ज्वलंत उदाहरण है। परन्तु यह घटना सम्भवतः स रिया में सोवियट आयुध-लिफ्ट के प्रतिशोध में घटी। इस शीत युद्ध दौड़ में संवियट रूस के उपभोक्ता का बलिदान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो एक सम्पत्तिवान देश है। अथाह सम्पत्ति, उपभोग पदार्थ, मोटरगाड़ी, कल्याणकारी एवम् समाज सुरक्षा हेतु विशाल सुविधायें वहाँ उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस दौड़ में संयुक्त राष्ट्र अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु शीत युद्ध से ईंधन प्राप्त होता है। परन्तु इसके विरुद्ध सोवियट संघ के उपभोक्ता-गण जूते, वस्त्र, साबुन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों से त्रासत हैं।

बहुत समय तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दृष्टिकोण था कि अमेरिकन हवाई-आक्रमण से सोवियट रूस सरलतापूर्वक पराजय है। उसके पास दीर्घ क्षेत्रीय बाम्बर हैं तथा पूर्णतः अक्षति सहित वे सोवियट संघ के मूल-उद्योग, मूल-केन्द्रों तथा मूल नगरों को विध्वंस कर सकता है। अमेरिका के आधार-केन्द्र सम्पूर्ण पश्चिमी योरप में विस्तृत हैं तथा भूमध्य सागर में इंग्लैण्ड, उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, तथा ओकिनवा (Okinawa) आदि केन्द्र से सफलतापूर्वक आक्रमण किया जा सकता है। परन्तु सोवियट संघ की दशा भिन्न थी। पश्चिमी योरप तथा जापान में तो वे बम्ब-लक्ष्य निर्धारित कर सकते थे। परन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूर्णतः सुरक्षित था। इसी तरह मास्को को एक झलक में विनिष्ट किया जा सकता था, परन्तु न्युयार्क अथवा वाशिंगटन सुरक्षित थे, स्पुटनिक तथा अन्तर महाद्वीप क्षेप्यास्त्र के उपरान्त दशा पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है। कम से कम कल्पना में मास्को से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर बिना किसी चेतावनी के वार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सेनापति, जनरल कर्टिस ई० लिमें (Genral Curtis E. Lemay) ने मई, १९५६ को कहा : 'मेरा अनुमान है कि सोवियट संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को १९५६ तक अचानक आक्रमण कर विनिष्ट कर सकता है।' १९५५ में सिनेट उपसमिति (Senate sub-Committee) के प्रधान, सिनेटर स्टुवार्ट 'सिमिंगटन' (Senator Stuart Symington) ने सूचना दी : "सोवियट संघ के पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा अधिक कुशल

विमान हैं ।” मई १९५७ को एक ऋतु-विज्ञान विशेषज्ञ ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कांग्रेस को बतलाया कि १९६० तक सोवियट संघ इस योग्य हो जावेगा कि २५० थर्मो-न्यूक्लियर बम्ब प्रयोग कर कम से कम कल्पना में ८२,०००,००० व्यक्तियों को मार सकता है । ये अनुमान स्पुटिन के पूर्व किये गये थे । उसके बाद के अनुमान अति अधिक भयानक होने चाहिये । इस शीत युद्ध दौड़ के अन्तर्गत कुछ भी अनुमान लगाना कोई सरल कार्य नहीं है । सोवियट संघ में शीत युद्ध ने सांस्कृतिक क्षेत्र को अत्यन्त प्रभावित किया है । शिक्षा, विद्या, विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में सोवियट संघ ने अपनी सामर्थ्य का उलंघन कर विशाल परिमाण से प्रधानता प्रदर्शित की है । सोवियट संघ के सामर्थ्य का प्रचार भी अत्यधिक हुआ है । प्रस्तुत शीत युद्ध के उपरान्त ही सोवियट संघ के विषय में कुछ निश्चित परिमाणिक तत्व उल्लेख किये जा सकते हैं । तब तक तो यह शंका स्थायी रहेगी कि क्या सोवियट संघ द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी पूर्णतः सत्य हैं ?

परिशिष्ट

आलोचकों का कथन है कि सोवियट अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च न्यूनता रूसियों का न्यून जीवन स्तर है। यह सत्य है कि कुछ सोवियट प्रगति पूर्व बिन्दु-हीन साधनों द्वारा हुई, परन्तु अधिकांश उन्नति वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर का बलिदान है, जो १९१७ से निरन्तर निम्न होता गया है।

कृषि समूहन (collectivization) कृषकों का महान हत्याकाण्ड उपस्थित करता है जो उग्रता एवम् असम्यक्ता का अद्वितीय इतिहास है।^१ इसने उन प्रबल सम्बन्धों को खण्डित किया है जो शताब्दियों से देश में बड़े गये थे। अनेक स्थानों पर उच्चकोटि के फामा की समृद्धि को भंग किया है, लाखों की संख्या में पशुओं की अत्या को प्रोत्साहन दिया है तथा कृषि उत्पादक को भारी परिमाण में क्षति पहुँचाई है। सोवियट सामूहिक कृषि, जो १९३३ में यथेष्टतः स्थापित हुई, रूसी इतिहास में सर्वोच्च ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इसके साथ रूसी कृषकों का करुण-क्रन्दन है, उनका बलिदान—भयानक बलिदान जिसके अन्तर्गत कम से कम ५० प्रतिशत^२ पशुओं की हत्या हुई तथा जिस क्षति को आज तक सोवियट सरकार पूर्ण नहीं कर पाई है। यही नहीं कृषकों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष

१ 'कुलक' वर्ग का अवसायन असाधारण प्रक्रिया द्वारा किया गया था। प्रादेशों में सोवियट सरकार ने अनेक बार इस कार्य की घोषणा भी की। ग्रामों में ग्रामाण समितियों ने 'सामान्य बैठक' के अन्तर्गत प्रस्ताव पास किये तथा सूचियाँ बनाईं जिनमें उन 'कुलकों' के नाम अंकित किये गये, जिनकी पूर्ण सम्पत्ति अधिग्रहण करनी है तथा जिन्हें वर्ग-स्तर से अधिकार-च्युत किया गया है। इसके अन्तर्गत घोर अत्याचार हुये छल-कपट अथवा विद्रोहसत्ता कर, जिज्ञा-अधिकारियों ने 'कुलक वर्ग' को केवल निर्धन ही न किया, वरन् जिस निन्द्यता से उन पर अत्याचार किये, एक अवर्णनीय कथा है। कृषकों ने भी प्रतिहिंसात्मक उक्तें बना प्रदर्शित कर खेतों पर सत्य अपन्न्य होने में सहयोग प्रदान किया। वास्तव में 'कुलक' अवसायन नीति उतनी आनोचनात्मक न थी, जितनी कि उसे कार्यान्वित करने के लिये अत्याचार, प्रतिअत्याचार, एवम् हिंसा, प्रतिहिंसा आदि दुःखमय विविधा अथवा उपपन्न (implications) उत्पन्न हुये थे।

रूप से राजकीय नीतियों का विरोध किया, तथा उनकी निन्दा करते हुए, उनके आधिपत्य में कार्य करने के प्रति विमुखता एवम् उदासीनता दिखलाई, जिसके कारण पदाधिकारियों ने उन्हें दण्डित किया। ऐसा कहा जाता है कि स्टैलिन-युग में वे इतने अधिक दरिद्र हो गये कि लगभग ५० लाख क्षुधा पीड़ित कृषकों की हत्या हुई। यह भी कथा प्रचलित है कि “कृषकों ने प्रथम पशुओं की हत्या की तत्पश्चात् आत्मघाट कर डाला।” किसी आलोचक ने लिखा :

“सोवियट संघ में आये हुये सभी विदेशी यात्री, रूसी नागरिकों की दरिद्र आकृति से अति उच्छेदित हो जाते हैं। उनका गँवारु लबादा अति अधिक विस्मय प्रदान करता है। उनका निवास-स्थान स्तर सम्भवतः निम्नकोटि का होता है। उच्च पदाधिकारीगण के पास तो सम्भवतः कुछ कमरे होते भी हैं, परन्तु अधिकांश जनता “एक कमरा-एक कुटुम्ब” के सूत्राधार (formula) पर जीवन निर्वाह करती है। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य-सम्बन्धी जीवन-स्तर अवर कोटि का है, प्रायः सामान्य जीविका-दशा असम्भव प्रतीत होती है, नैतिक अवस्था पतित हो गई है तथा साधारण रूसी सामान्य सुख-सामग्री का अभाव अनुभव करते हैं। इसका विशेष कारण ऐतिहासिक औद्योगीकरण राष्ट्रीय प्रवृत्ति है।” आलोचकों द्वारा निम्नलिखित सूची निर्मित की गई है, जिसमें सोवियट रूस की प्रारूपिक न्यूनता प्रदर्शित है :

- (१) कृषि : (क) निम्न कोटि की उपज ; (ख) कृषि सम्बन्धी कार्यों में असंतोष-जनक योग्यता (ग) आपत्तियों को दूर करने में असाधारण अयोग्यता ; (घ) कृषि-शिल्प-विज्ञान की अवहेलना ; (ङ) कीड़े एवम् महामारी सुरक्षा हेतु रसायनिक पदार्थ एवम् खाद की न्यूनता ; (च) उचित सस्य निर्वाचन का अभाव ; (छ) सस्य वपन (crop sowing), यन्त्रों की अपूर्ण देख भाल एवम् निगरानी ; तथा (ज) संलवन (harvesting) में विशाल क्षति ।
- (२) पशु पालन : (क) अपर्याप्त पशु-धन ; (ख) मन्द वृद्धि एवम् निम्न उत्पादकता ; (ग) निर्धन पशु पालन के कारण महामारी में भारी आपतन (incidence) ; (घ) यथेष्ट भोजन एवम् पोषण का अभाव ; (ङ) अस्तवल एवम् घुड़साल आदि की कमी ; (च) अस्वास्थ्यकर दशा एवम् असंतोषजनक जल-प्रबन्ध ; तथा (छ) मौलिक कार्य प्रणालियों में यन्त्राकरण की न्यूनता ।
- (३) मशीन तथा ट्रैक्टर स्टेशन : (क) मशीन निर्धार्य रहना ; (ख) अनेक प्रकार की मशीनों का अभाव तथा जटिल यन्त्रीकरण की असाध्यता ; (ग) योग्य प्रशासकीय संवर्ग (administrative cadre) की कमी ; (घ) मशीन में

विलम्बित तथा निम्नकोटि की मरम्मत ; (ङ) यन्त्रों के अतिरिक्त भाग (spare parts) की कमी ; (च) मशीन का प्रायिक (frequent) विभञ्जन (breakdown) ; (छ) श्रम शक्ति का घटाव-बढ़ाव, एवम् श्रमिकों, ट्रैक्टर तथा अन्य यातायात वाहन के चालकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण ; (ज) मरम्मतशाला, वहित्रगृह (garage), शालिका (shed) आदि की अव्यवस्था ; तथा (झ) उपकरण (equipment) में अपर्याप्त भुगतान ।

(४) खद्याच तथा हल्के उद्योग : (क) उपभोग पदार्थों में विविधता (variety) की कमी ; (ख) बाजारू खाद्यान्न पदार्थों की न्यूनता ; (ग) उत्पत्ति का न्यून आविर्भाव (poor appearance) ; (घ) अनुपयुक्त एवम् कम-जोर पैकिंग ; (ङ) शौकीन वस्तुओं का अभाव ; (च) जूते तथा वस्त्र-फैशन में स्थिरता, एकस्वरता एवम् विरसता ; तथा (छ) असामयिक (out of date) आदर्श (models) के अनुसार उपभोग पदार्थों की उत्पत्ति ।

(५) व्यापार : (क) व्यापार विक्रय-राशि (trade turnover) योजनाओं की अपूर्ति ; (ख) व्यापार-जाल (trading net-work) में अव्यवस्था ; (ग) माल के परिवहन में परिभ्रान्ति ; (घ) वस्तु राशि में भारी अपाहरण ; (ङ) दूकानों पर अपर्याप्त उपकरण ; (च) बिगड़ी हुई वस्तुओं को अधिक प्रतिशतक संख्या ; (छ) क्रियताओं को अनुपयुक्त सेवा प्रदान करना ; (ज) वस्तुओं के संचय हेतु यथेष्ट सुविधाओं की कमी ; तथा (झ) सामान को पैक करने हेतु वेष्टन (wrapper) की कमी ।

(६) परिवहन एवम् यातायात साधन : (क) चक्रियान (rolling stock) की न्यूनता एवम् उसकी पूर्ति में विलम्ब ; (ख) उद्यम संचालन में परिभ्रान्ति एवम् अस्त-व्यस्तता ; (ग) अनेक ट्रकों का कार्य रहित रहना ; (घ) सामग्री उतारने-चढ़ाने में यन्त्रों का अपर्याप्त मात्रा में प्रयोग ; (ङ) गाड़ियों का विलम्ब से आवागमन ; (च) शीतल यन्त्र एवम् हिमीकर का न्यून प्रयोग ; तथा (छ) लोकोमोटिव एवम् अन्य यन्त्रों के मरम्मत का अभाव ।

सोवियट रूस में उपभोग पदार्थों की न्यूनता सम्पूर्ण विश्व को ज्ञात है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रथम स्थान उपभोग पदार्थ के उत्पादन को दिया जाता है, क्योंकि वैयक्तिक उद्योग प्रथा होने के कारण उपभोक्ता-सेवा पर वहाँ विशेष ध्यान दिया गया है । इसके प्रतिकूल रूस में उपभोग पदार्थ का स्थान विभिन्न

योजनाओं में निम्न स्तर का रहा है। हाल में स्वर्गीय डालस ने सोवियट रूस की निर्बलता पर प्रकाश डालते हुये कहा था : “सोवियट संघ प्रति वर्ष केवल १००,००० सवारी गाड़ियाँ (passenger cars) उत्पादन करता है।” उनका विश्वास था कि यह अंक सोवियट संघ की निर्बलता का प्रतिनिधि है। परन्तु वास्तव में यह तत्व उसकी सबलता का द्योतक हो सकता है। वह दिन दूर नहीं है जब सम्भवतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने उपभोग पदार्थ, फैशन-सामग्री तथा विलास पदार्थ उद्योगों को बलिदान कर भारी उद्योगों की ओर अधिक महत्त्व देना पड़े, ताकि वह भी सोवियट संघ की संचयी प्रगति प्रतिद्वन्द्वता की उपेक्षा सफलतापूर्वक कर सकें। इसमें संदेह नहीं कि अधिकतर सांख्यिकी प्रतिशत समंक हैं। परन्तु कुछ ‘विशाल योगफल’ आदरणीय एवम् सम्मान्य भी हैं। जैसे, १९१३ में कच्चे लोहे की उत्पादन ४२ लाख टन था, १९४० में १५० लाख टन, १९५५ में ३३० लाख टन तथा १९५७ में ३७० लाख टन। कोयला हेतु अनुरूप संख्यायें २६१ लाख, १६६० लाख, ३६१० लाख तथा ४६०० लाख टन क्रमशः थीं। इसी प्रकार मिट्टी का तेल, इस्पात, एवम् अन्य भारी पदार्थों में उत्पादन प्रशंसनीय है।

पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सोवियट रूस अपने को प्रबल एवम् सम्पन्न बनाने में पूर्णतः सफल हो सका है। युद्ध में अर्थव्यवस्था को अति अधिक क्षति पहुँची, फिर भी चौथी, पाँचवीं तथा वर्तमान सप्तवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस एक विशाल एवम् शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है। वर्तमान काल में सप्तवर्षीय योजना के अन्तर्गत समाजवाद को प्रभावशाली बनाने तथा साम्यवाद को ग्रहण करने हेतु अनेक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। रूसी प्रशासकों ने कठिन से कठिन परिस्थिति की उपेक्षा संतोष, धैर्य एवम् साहस द्वारा सफलतापूर्वक किया है तथा एक नवीन समाजवाद व्यवस्था का निर्माण किया है। योरप तथा एशिया के पिछड़े हुये देश के लिये रूसी समाजवाद एक महत्त्वपूर्ण आदर्शवादी व्यवस्था समझी जाती है।

जिन क्षेत्रों को आधार मानकर हम सोवियट रूस की असफलता की व्याख्या करते हैं, वर्तमान काल में रूसी उन दिशाओं की ओर उद्भ्रान्त (crazy) हैं। विद्या, शान्ति तथा उपभोग पदार्थ की माँग एक रूसी नागरिक की वर्तमान काल में अभूतपूर्व आकांक्षा है। शायद ही कोई ऐसा रूसी हो जो शिक्षा अथवा विद्या के विषय में अति अधिक उत्तेजित न हो। कोई भी रूसी युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध उसकी उपभोग पदार्थ की न्यूनता को बढ़ाने में सहयोगी होगा। अग्रिम कल में वे उत्तम से उत्तम जीवन स्तर के लिये लाला-

यित होकर हर समय इस पहलू पर सजग हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शीघ्र से शीघ्र इस न्यूनता को दूर करने की दिशा की ओर वे सम्पूर्णतः उन्मुख हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री खुशचेव, स्वर्गीय ड्लेस को पसन्द नहीं करते थे, इसका एक कारण यह था कि आवश्यक उपभोग पदार्थों की अत्यधिक न्यूनता होने के कारण, स्वर्गीय ड्लेस, सोवियट संघ को कभी भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समकक्ष नहीं समझते थे। सोवियट संघ की यह एक सर्वोच्च आकांक्षा है कि वे शीघ्रातिशीघ्र उन पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करें जिनको प्राप्त करने के लिये सामान्य रूसी वर्षों से वृसित हैं। रूसी नागरिक इस निर्वलता के प्रति इतने अधिक चेतनायुक्त हैं कि वे अधिकतर अपनी श्रेष्ठता की ही गाथा गाते हैं। कहा जाता है कि उनमें उच्च कोटि की हीनक-भावना (inferiority complex) है। यह उनका स्वाभाव है। अधिकतर रूसियों को भ्रामक विश्वास है कि “केवल धनी अमेरिकन बच्चे ही कालेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं”। उनको सरलतापूर्वक विश्वास नहीं होता कि “आइसनहावर के पिता एक रेल कर्मचारी थे” ; अथवा हॉर्ला यच० कर्टिस (Harlow H. Curtice) के भ्राता एक पेन्ट तथा धातु निरीक्षक (paint and metal inspector) हैं, जिनकी पेन्सन अवकास ग्रहण करने पर केवल ६३ डालर प्रति मास होगी। जान गन्थर का कथन है कि उन्होंने एक रूसी बच्चे को आश्चर्यजनक होकर पूछते हुये देखा : “क्या अमेरिका में भी पर्वत हैं ? क्या वहाँ भी संतरा (Oranges) उत्पन्न होता है ?” जब एक विदेशी यात्री ने एक रूसी लड़की को बतलाया कि प्रत्येक वर्ष लगभग १००,००० अमेरिकन पेरिस (Paris) की यात्रा करते हैं, उसने तुरन्त कहा : “इससे प्रतीत होता है कि अमेरिकनों को अपना देश अधिक प्रिय नहीं है।” जब उस यात्री ने अनेक रूसियों को अमेरिकन सिगरेट पीने को दी, अधिकांश लोगों का यही कथन था : “ओह ! बहुत ही सुन्दर, परन्तु उतनी तीव्र नहीं है, जितनी रूसी सिगरेट।” सारा विश्व जानता है कि सोवियट रूस की क्या कमियाँ हैं। सोवियट संघ की जनता, वहाँ की सरकार तथा नियोजन संचालक उन त्रुटियों को छिपाते हैं, जिससे यही प्रतीत होता है कि वे दिन-रात इस प्रयास में हैं कि किस प्रकार आवश्यक उपभोग पदार्थों की न्यूनता को दूर कर राष्ट्र को इस दृष्टिकोण से भी स्वावलम्बी बना सकें।

एक अमेरिकन यात्री सोवियट संघ का भ्रमण करने के उपरान्त जिन क्षेत्रों एवम् तत्वों से अति अधिक प्रभावित हुआ, उनको इस स्थान पर प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है :

(क) नियन्त्रण में शिथिलता (relaxation), औद्योगीकरण में प्रचण्डता,

कृषि में समूहवाद, विवृत आतंक^१ (overt terror) का परित्याग तथा शिक्षा एवम् विद्या का गतिवर्द्धन आदि सोवियट संघ की महान् प्रबलता के द्योतक हैं।

(ख) सोवियट राज्य में केवल शिखर (top) से ही समनुरूपता (conformity) प्रदान नहीं का गई है, बल्कि अवर (below) से अनायास ही उसमें यह उच्च गुण उपस्थित है। लेनिन ने एक बार कहा था : “बच्चों को शिक्षा हेतु केवल तीन वर्ष चाहिये—पुनः देखिये, जो बोज मैंने बोये हैं, कदापि हटाये नहीं जा सकते।” रूसी नागरिक गंभीरतापूर्वक राजकीय क्रियाओं को सहयोग प्रदान करते हैं तथा राजकीय सफलताओं पर गर्व करते हैं, जिससे शासन-सत्ता को अति अधिक शक्ति प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि रूसी नागरिक केवल शिक्षा एवम् प्रचार के सहयोग से ही भ्रान्त में नहीं रखे गये हैं, बल्कि वे अविच्छेद्यतायुक्त उसके अंश हैं—उसमें लिप्त हैं तथा उनको इससे कदापि तात्पर्य नहीं कि राज्य संलग्न होने में उनमें कितनी भावबर्धता एवम् क्रूरता उत्पन्न हो सकती है।

(ग) सम्भवतः नवीन शिल्पी (technician) तथा औद्योगिक प्रशासक एवम् प्राचीन मत अनुयायी नेताओं के मध्य अंतर्द्वन्द्व एवम् अन्तर्विरोध अनिवार्य है। कितना भी प्रयास क्यों न किया जाये, याद एक वैज्ञानिक का प्रशिक्षण एवम् वैज्ञानिक शिक्षा दी जायेगी, वह कुछ समय उपरान्त मानसिक स्वतंत्रता की माँग अवश्य करेगा।

(घ) राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सोवियट संघ का स्पष्टवाद समाचार-पत्र महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। समाचार-पत्रों में स्पष्ट अभियोग महान संख्या में प्रकाशित होते हैं। वे अमेरिकन जो समझते हैं कि सोवियट समाचार-पत्र (प्रेस) स्वच्छाचार प्रवृत्ति का आलोचना नहीं करते, सम्पूर्णतः भ्रान्त हैं।

१ सोवियट अर्थव्यवस्था के प्रारम्भिक काल में विवृत आतंकवाद था, जिसका प्रमुख साधन गुप्तचर पुलिस के रूप में एक व्यापक संगठन था, जिसे ट्चेका (Tcheka) कहते थे तथा जो १९३४ में ‘आगपू’ (Ogpu) के नाम से विख्यात था। १९१८-१९२२ में ‘ट्चेका’ को अनियन्त्रित विकाराल शक्ति एवम् अधिकार प्राप्त थे, जिनके अन्तर्गत किमी भी पुरुष का जीवन सुरक्षित न था। ‘ट्चेका’ द्वारा (नरकुश गिरफ्तारों, संक्षेपतः दोष सिद्ध तथा तत्क्षण प्राणदण्ड, गुप्तचर अधिकरण द्वारा अत्याचार एवम् संत्रास तथा जासूनों द्वारा जाल रच कर मानवता के प्रति अति अत्याचार आदि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ घटीं, जिन्हें योरोप को विभिन्न भाषाओं में वर्णन कर, ऐतिहासिकारों ने रूस के इतिहास को घोर कलंकित किया है। १९२२ में नवीन आर्थिक नीति काल में ‘ट्चेका’ के स्थान पर संघीय राजनैतिक प्रशासन नामक संस्था स्थापित की गई, जिसे संक्षेप में ‘आगपू’ (Ogpu) अथवा ‘ग्य’ (Gpu) कहते थे।

(ङ) इस देश में राजनैतिक एवम् व्यवसायिक क्षेत्र में बुद्धि एवम् ज्ञान-शक्ति पर अति अधिक महत्त्व दिया जाता है। शिक्षा एवम् प्रशिक्षा पर विशेष-कर ध्यान दिया गया है।

(च) शिक्षा एवम् विद्या का असीम गतिवर्द्धन विशेषकर प्रौद्योगिक प्रगति सोवियट संघ के उत्थान का विशेष गुण है, जैसा कि स्पुटनिक तथा अन्तर-महा-द्वीपीय क्षेत्रास्त्र की प्रगति से सिद्ध है।

(छ) सांस्कृतिक उन्नति सोवियट नागरिकों का अद्वितीय उद्देश्य है। आज भी 'संस्कृति' शब्द सार्वजनिक दृष्टिकोण से जादू के समान समझा जाता है। उत्कटता एवम् संकल्प सहित, जो कि हम सब के लिये केवल कल्पनातांत है, रूसी नागरिक स्व-सुधार हेतु लालायित होकर उसे प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।

(ज) शासन-सत्ता के प्रति आत्म विश्वास, उसकी अप्रशाम्य प्रफुल्लता, कठोरता, व्यवहार कुशलता, चतुरता, अल्प दृष्ट तथा विश्वास एवम् निश्चित उद्देश्य के प्रति स्थिरता आदि ऐत महत्वपूर्ण गुण हैं जिनको कोई भी देश अत्यधिक प्रशंसा ही करेगा।

(झ) सोवियट श्रमिकों के जीवन निर्वाह पर दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। हाल में अनेक विधान पास हुये हैं, जिनके द्वारा श्रम की मान्यता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। (अ) जनवरी १, १९५७ से न्यूनतम पारिश्रमिक विधान कार्यान्वित किया गया। स्थान एवम् उद्योग के अनुसार पारिश्रमिक निश्चित किया गया, जो ३००-३५० रुबल औसत प्रातमास है। इस नवीन विधान के कार्यान्वित होने से लगभग ८० लाख श्रमिकों को लाभ हुआ क्योंकि वे इसके पूर्व वेतन अथवा पारिश्रमिक, निश्चित न्यूनतम स्तर से, कम पा रहे थे। (आ) सप्ताह में ४८ घन्टा कार्य अवधि के स्थान पर ४६ घन्टा कर दिया गया, जिसके अन्तर्गत शनिवार को २ घन्टे का अवकाश भी सम्मिलित था। सरकार आशा करती है कि १-६० तक साप्ताहिक कार्य अवधि केवल ४१ घन्टा कर दी जायेगी, अर्थात् पाँच दिवस, ७ घन्टा प्रति दिवस का दर से तथा शनिवार को केवल छः घन्टा। (इ) पेन्सन योजना अति उन्नतिशाल एवम् तात्त्विक पारमाण्य में कार्यान्वित की गई है। इसका पूर्ण विवरण गत पृष्ठों में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सोवियट संघ में कोई भी व्यक्ति वित्तहीन नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अपने वित्त में परिवर्तन कर सकता है—शर्त केवल यह है कि दो सप्ताह को सूचना देना अनिवार्य है। उपभक्ता पद्धति के उत्पादन में भी दशा सुधार रही है। ख शचेव ने हाल ही में कहा था : "यह अत्यन्त आवश्यक

है कि मार्क्स के सिद्धान्तों में सुधार करने के साथ-साथ रोटी एवम् मांस के टुकड़े का भी प्रबन्ध करना चाहिये ।” परन्तु दिन प्रतिदिन उपभोक्ता के लिये अधिक परिमाण में केवल पदार्थों की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिक गुणी एवम् उत्तम पदार्थों की भी अति आवश्यकता अनुभव की गई है । रूसी नागरिक केवल मोटर-स्कूटर, रेशम, पिठर (casserole), छाता, स्टोव, वर्तन आदि के लिए लालायित ही नहीं है, बल्कि सुन्दर एवम् शौकीन सामग्रियों के लिये भी तृपित हैं । वे केवल मोटर प्राप्त करने की ही आकांक्षा नहीं रखते, बल्कि रंगीन अथवा विविध गुण की गाड़ी पाने की अभिलाषा करते हैं । सोवियट समाचार-पत्रों में यह निरन्तर प्रश्न प्रकाशित हुये हैं कि ‘सोवियट संघ क्यों नैपकिन तथा डेबुल क्लाय, उत्तम डिजाइन एवम् बुनावट (texture) का उत्पादन नहीं कर रहा है ।’ इस उदाहरण में सोवियट रूस की न्यूनता एवम् प्रगति हेतु चेष्टा का सम्पूर्ण चित्र प्रदर्शित है ।

सोवियट नियोजन संचालन की प्रशंसा एवम् दोष के विषय में दो शब्द कहना अत्यन्त आवश्यक है । वैयक्तिक इच्छाओं को त्याग कर, योजनात्मक एवम् समन्वित प्रगति, सोवियट अर्थव्यवस्था की सम्भवतः सर्वोच्च प्रवीणता है । वैयक्तिक उद्योग एवम् व्यक्तिगत नेतृत्व, जिसका आधार ‘लाभ-हानि’ उद्देश्य है, तथा जिस शिला पर पूँजीवाद आलम्बित है, सोवियट अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उनका कोई स्थान नहीं है । वहाँ प्रेरणा तथा दण्ड ऐसे तत्त्व हैं, जिन पर लाखों सोवियट नागरिकों के कार्य, निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से, संचालित हैं । विश्व में सम्भवतः अन्य कोई ऐसा देश नहीं है, जहाँ जनसमुदाय की सामूहिक कर्म-शक्ति का समन्वय एवम् समिश्रण अतिअधिक सावधानी से एवम् सफलतापूर्वक किया जा सका है ।

‘सोवियट अर्थव्यवस्था की योग्यता एवम् सामर्थ्य’ के विषय पर अति-अधिक मतभेद है । आलोचकों का विचार है कि ‘प्रतिस्पर्धामूलक अर्थव्यवस्था’ (competitive economy), ‘नियोजित अर्थव्यवस्था’ की अपेक्षा अधिक कुशल एवम् कार्यक्षम होगी, क्योंकि लाभार्जन उद्देश्य तथा अन्य सहायक प्रेरणायें ‘प्रतिस्पर्धामूलक अर्थव्यवस्था’ की संचालक हैं, जो नियोजित ‘अर्थव्यवस्था’ में स्थान रहित हैं । १९३०-१९४० की अवधि में अधिकांश लोग यही समझते थे कि प्रतिस्पर्धा के उन्मूलन से अर्थव्यवस्था संचालन हेतु आवश्यक प्रेरणा जाती रहेगी, क्योंकि समाजवाद के अन्तर्गत उत्पादन एवम् वितरण का भार राज्य एकाधिकार के अन्तर्गत होता है, जहाँ वैयक्तिक लाभ तथा हानि का कोई स्थान नहीं है । अतः अधिकतम कार्य कौशल एवम् सामर्थ्य प्राप्त करने में ‘नियोजित अर्थव्यवस्था’ सम्पूर्णतः असफल रहेगी ।

परन्तु व्यवहार में उपर्युक्त लिखित आलोचना पूर्णतः सिद्ध न की जा सकी । अनेक अर्थशास्त्री एवम् ऐतिहासिकारों ने पाठकों का ध्यान उन अनार्थिक (non-economic) प्रेरणाओं की ओर आकृष्ट किया, जिनका स्थान सोवियट समाजवाद अर्थव्यवस्था में उच्चकोटि का है । वैयक्तिक प्रतिद्वन्द्विता की भावना अधिक उत्तरदायी एवम् विश्वसनीय पदों पर नियुक्त तथा सार्वजनिक सम्मान ऐसी कुछ सकारात्मक प्रेरणायें हैं जिनको समाजवादी रूस में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । इसी प्रकार कुछ नकारात्मक प्रेरणायें भी दण्ड के रूप में प्रचलित हैं, जैसे सार्वजनिक निन्दन (public censure) का भय तथा पदावनति अथवा पदच्युति की आशंका आदि । निःसन्देह लाभार्जन उद्देश्य सार्वजनिक स्वामित्व व्यवस्था के अन्तर्गत न होगा, परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना भ्रामक है कि श्रमिकों अथवा प्रबन्धकों को आवश्यक कार्य-प्रेरणा उपलब्ध न होकर, अर्थव्यवस्था यथेष्ट कुशलता एवम् कार्यक्षमता रहित होगी । पूँजीवाद अर्थव्यवस्था में केवल साधारण एवम् पूर्वाधिकार अंश-धारी ही ऐसे व्यक्ति हैं, जो लाभ अथवा हानि से प्रभावित हो सकते हैं, परन्तु आश्चर्य तो यह है कि वे संचालन कार्य में कोई भाग नहीं लेते । अतः अर्थव्यवस्था 'लाभार्जन उद्देश्य' से कार्य संचालन हेतु किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं हो सकती । प्रसिद्ध समाजवाद अर्थशास्त्रियों का कथन है कि आधुनिक संयुक्त पूँजी कम्पनी व्यवस्था के अन्तर्गत से लाभार्जन तथा कार्यक्षमता में सकारात्मक सम्बन्ध जाता रहा है । अतः यह कहना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्य-प्रेरणा रहित होगी, क्यों कि वह 'लाभार्जन उद्देश्य' रहित है, कोई अर्थ नहीं रखता ।

कुछ समाजवाद अर्थशास्त्रियों का मत है कि रूसी अर्थव्यवस्था किसी भी पूँजीवाद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यक्षम एवम् कुशल है, क्योंकि (क) समाजवाद अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक साधनों का विवेकशील उपयोग एवम् परिशुद्ध समन्वय होता है ;

(ख) नियोजित अर्थव्यवस्था विविध प्रकार की हानि एवम् अपव्यय से परिवर्जित रहती है । प्राकृतिक, भौतिक, एवम् मानवीय साधनों का विनाश एवम् अपव्यय जो पूँजीवाद अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत 'लाभ-हानि' शक्ति से प्रभावित होकर निरन्तर होता रहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन प्रणालियों के प्रचलन के कारण नहीं हो पाता ।

(ग) नियोजित अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली एवम् प्रक्रिया में निरन्तर परिवर्तन एवम् सुधार करने में समर्थ रहती है तथा पूँजीवाद अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता का प्रभाव डालती है ।

(घ) नियोजित एवम् नियन्त्रित अर्थव्यवस्था व्यापार-चक्र (trade cycle), आर्थिक मंदी, तथा आर्थिक असंदिग्धता रहित होकर, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवम् सुडौल बनाने का पूर्ण आयोजन करती है। डर्बिन (Durbin), एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने नियोजित अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता एवम् कुशलता के उपलक्ष में निम्नलिखित तत्व प्रस्तुत किये :

(क) केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक विवृत-चक्षु-व्यवस्था है। एक अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धामूलक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग-धन्वे वैयक्तिक प्रबन्धकों द्वारा संचालित किये जाते हैं। विविध उद्योगों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रहता। प्रत्येक उद्योगी सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन का इतना लघु अंश उत्पादन करता है कि उसे अन्य उद्योगियों का तो क्या, अपने कार्यों के परिणाम का स्वयम् ज्ञान नहीं रहता। इसके प्रतिकूल एक केन्द्रीय अर्थव्यवस्था इस योग्य होती है कि वह सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का पर्यवलोकन स्वयम् कर सके।

(ख) एक नियोजित अर्थव्यवस्था दूरदर्शी होती है। पूर्वदर्शिता के आधार पर योजना निर्माण की जाती है। एक केन्द्रीय सरकार, जिसका उत्पादन क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार रहता है, खनिज अथवा खाद्य पदार्थ की समाप्ति, प्राकृतिक साधनों का अपव्यय तथा मानवता के शोषण आदि जैसी क्लिष्ट आपत्तियों का सरलतापूर्वक पूर्वानुमान कर सुधार कर सकता है।

(ग) एक नियोजित अर्थव्यवस्था वित्त एवम् उत्पादन के सम्बन्ध का सफलतापूर्वक अध्ययन करती है। किसी अन्य क्षेत्र में अनियोजित अर्थव्यवस्था इतनी अधिक असफल नहीं हुई है, जितनी इस क्षेत्र में। आर्थिक आपत्ति तथा मंदी का क्रमागत पुनरावर्तन तथा समृद्धि एवम् सफलता में अस्थिरता, पूँजीवाद अर्थव्यवस्था के महान् अवगुण हैं। इस असंदिग्धता एवम् असन्तुलन के विशेष कारण दो हैं :

(अ) वे व्यक्ति जो बचत करते हैं तथा वे जो विनियोग करते हैं, प्रत्यक्षतः सम्बन्ध रहित होते हैं तथा अर्थव्यवस्था में किसी को यह अधिकार भी प्राप्त नहीं होता कि बचत एवम् विनियोग में संतुलन अथवा समन्वय स्थापना पर यथेष्ट ध्यान दें।

(आ) वैयक्तिक बैंकिंग संस्थाएँ विनियोग में निरन्तर उलट-फेर करती रहती हैं, जब कि बचत अथवा संचय गति पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं हो पाता।

इन्हीं कारणवश पूँजीवाद, एक असंदिग्ध एवम् असन्तुलित अर्थव्यवस्था मानी गई है, जिसके अन्तर्गत वित्तहीनता, अपव्यय, मानव शोषण आदि जैसे

दोष पाये जाते हैं तथा जो अर्थव्यवस्था को कौशल एवम् कार्यक्षम बनाने में बाधा पहुँचाते हैं।

अनेक ऐतिहासकारों तथा अर्थशास्त्रियों ने रूसी समाजवाद का उदाहरण लेकर नियोजन सिद्धान्तों की कटु आलोचना की है। उनका विचार है कि नियोजित अर्थव्यवस्था पूर्णतः महागुल्मीय व्यवस्था है, जहाँ उपभोक्ता, तथा उत्पादक की स्वतंत्रता का सम्पूर्ण हनन होता है। सोवियट रूस एक ज्वलंत उदाहरण है। आलोचकों के अनुसार :

(क) एक व्यापक योजना का जन्म, स्वच्छन्द (arbitrary) प्रशासनीय निर्णय द्वारा किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था से विविध नियम (rule of law) लुप्त हो जाता है।

(ख) उपभोक्ता-प्रभुता (consumers' sovereignty) तथा उपभोग-स्वतंत्रता का हनन होता है।

(ग) वैयक्तिक सम्पत्ति के लुप्त हो जाने के कारण तानाशाही राजनैतिक सत्ता में वृद्ध होती है।

(घ) लोक-तंत्र के प्रति विरोध उत्पन्न होने के कारण, दुष्ट व्यक्ति शासन शक्ति ग्रहण कर लेते हैं तथा संकेन्द्रण-शिविर (concentration camp), एवम् यंत्रणा-सदन (torture chamber) उनके सहयोगी होते हैं।

(ङ) योजना फलीभूत होने के उद्देश्य से नागरिकों को अनेक बलिदान निरन्तर करने पड़ते हैं।

अर्थशास्त्रियों का विशेष ध्यान उपभोक्ता-प्रभुता तथा मूल्य-यान्त्र (price mechanism) की ओर है। प्रारम्भ में सोवियट नियोजन के प्रांत सब से कठोर आलोचना यह था कि इसने मूल्य-यान्त्र अन्मूलन कर, अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। परन्तु वास्तव में ऐसा न था। अपारवर्तित रूप से मूल्य-यान्त्र संचालित की गई। फिर भी मूल्यों के विरुद्ध अब भा अर्थशास्त्रियों की कटु आलोचना है। जान गन्थर ने सोवियट भ्रमण करने के पश्चात् व्यक्त किया :

“यह अनुमान करना कठिन है कि एक रूसी के लिये ‘रुबल’ का क्या मूल्य है। यही नहीं अनेक पदार्थों का परिचय (cost) भी अदभुत एवम् विलक्षण है तथा उनमें महान एवम् अभिचकित विभेद एवम् असंगत है। एक अमेरिकन जाज्ज रिकार्ड (jazz record) का मूल्य काले बाजार में ०० रुबल (३५ पौन्ड) है जो कि एक अच्छे रेडियो का भा मूल्य होगा। १२ जोंड़े जूतों के मूल्य के समान एक मोटरगाड़ी का मूल्य है। कितना आश्चर्यजनक

कर, उनकी श्रमिक स्वधीनता को सीमित कर दिया है। हजारों-लाखों की संख्या में सोवियट युवक योजनात्मक कार्य हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो राज्य द्वारा उनके लिये निर्वाचित की जाती हैं। कुछ समय पूर्व तो प्रशिक्षण उपरान्त सुविस्तृत एवम् अति विशाल सोवियट संघ के किसी भी कोने में सरकार उन्हें नियुक्त कर सकती थी। सामूहिक कृषक को केवल वही सस्य उत्पन्न करने का अधिकार है जो सरकार निश्चित करती है; केवल उतना ही उत्पादन कर सकती है जो सरकार निर्धारित करती है; तथा लक्ष्यानुसार कार्य फलीभूत न होने पर कहा जाता है एक समय ऐसा था जब सरकार प्राणदण्ड भी देती थी। श्रम-वेद से उत्पन्न किये हुये पदार्थ सर्वप्रथम सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाते हैं। एक अमेरिकन आलोचक ने लिखा : “सोवियट संघ में असंख्य दास-श्रमिक अति-शय एवम् उत्कट बल-प्रयोग से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या असीमित है, जिनको राजनैतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक स्वतंत्रता दुर्लभ है, जो राज्य के आदेशानुसार दासों की भाँति योजना कार्य में संलग्न रहते हैं तथा जिनका अपना कोई व्यक्तित्व भी नहीं है।”

एक लेखक ने व्यक्त किया : “जब हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्रतिबन्ध तथा असहमति एवम् अभिव्यक्ति निरोध पर दृष्टि डालते हैं, तो अति असित एवम् तिमिर चित्र प्रदर्शित होता है। सोवियट अर्थव्यवस्था एवम् समाज आज समाजवाद आदर्शवादियों के पत्याजन के मानववाद दर्शन से अत्यधिक दूर है। श्रमिक वर्ग के नाम पर सोवियट राज्य ने दासत्व प्रथा को प्रचलित कर, श्रम तथा राष्ट्रीयता का अधिकतम दुरुपयोग किया है। वर्तमान काल में किसी भी लोकतांत्रिक पूँजीवाद देश में एक पूँजीपति अथवा औद्योगिक निगम अपने श्रमिकों को इस प्रकार शोषण करने का साहस नहीं कर सकता है, जैसा कि सोवियट संघ में तमाम कारखाने, रेल-सड़क, तथा कारखानों में श्रमिकों का शोषण सरकार द्वारा किया जाता है। सोवियट समाज की सामान्य तुलना एक सेना से की गई है। एक सैनिक अधीन होने पर भी, सेना में निर्धारित लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में उत्साही एवम् उमंगी रहता है तथा अपना जीवन बलिदान भी आवश्यकता पड़ने पर दे सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको सेना में भाग लेने का कभी भी अवकाश प्राप्त हुआ है, भली प्रकार समझता है कि उप-संकोचित (constricting) अधिनियम (regulation) के संचार के अन्तर्गत (within the framework), प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन अथवा दण्ड आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो अत्यन्त प्रभावतापूर्वक संचालित रहती हैं। पदोन्नति एवम् प्रगति को आकांक्षा तथा पदावनति (demotion) की शंका ऐसे प्रबल

उत्तेजक एवम् प्रवर्तक हैं, जिनके सहस्र सोवियट अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक प्रयोग किये जाते हैं ।

कहा जाता है कि देश की सामान्य अवस्था युद्ध काल से अत्यधिक परिवर्तित हो गई है । सामाजिक जीवन तीन मूल तत्वों से प्रभावित है :

(अ) अर्थशास्त्र, (आ) सामाजिक संगठन तथा (इ) मानवीय अनुभव । कुछ लोगों का कथन है कि एक विचित्र समाजिक व्यवस्था स्थापित कर, बाल-शेविक मत के अनुयायियों ने, आंतकवाद काल में सर्वोच्च कठोरता एवम् अत्याचार सहित, औद्योगिक प्रगति की ओर उन्मुख होकर, मानवीय भौतिक निर्माण की आकांक्षा प्रकट की थी । परन्तु वास्तव में यह पूर्ण न हो सकी । ऐतिहासिक कारणों ने उपर्युक्त लिखित तीन तत्वों को अस्त-व्यस्त कर दिया है । युद्ध, देश-भक्ति, अन्य देशों के साथ उनका सम्पर्क, स्टैलिन की मृत्यु तथा सिंहासन च्युति —आदि घटनाओं ने मानवीय मनोविज्ञान पर अत्यधिक प्रभाव डाल कर, देश में महान परिवर्तन किये हैं जैसे, आंतकवाद शासन सत्ता को निर्बल बनाने में इन कारणों ने अधिक सहायता पहुँचाई है । वर्तमान काल में सोवियट संघ अथाह गुणों से सम्पन्न एक ऐसा देश है, जहाँ आर्थिक साधनों का विवेकशील उपयोग एवम् परिशुद्ध समन्वय होता है ; नियोजित अर्थव्यवस्था विविध प्रकार की हानि एवम् अपव्यय से परिवर्जित रहती है, तथा व्यापार-चक्र आर्थिक मंदी तथा आर्थिक असंदिग्धता रहित होकर सुदृढ़ एवम् सुझौल बनने का पूर्ण आयोजन करती है ।

BIBLIOGRAPHY

- Baykov, A. *Soviet Foreign Trade*, Princeton University Press, Princeton, 1946.
- Baykov, A. *The Development of the Soviet Economic System*, The Macmillan Company, New York, 1947.
- Bergson, A. *The Structure of Soviet Wages*, Harvard University Press, 1944.
- Blodgett, R. H. *Comparative Economic Systems*, The Macmillan Company, New York, 1949.
- Brutzkus, B. *Economic Planning in Soviet Russia*, George Routledge & Sons, Ltd., London, 1935.
- Carr, E. H. *The Bolshevik Revolution, Vols. I-IV*, Macmillan, London, 1954.
- Carr, E. H. *The Soviet Impact on the Western World*, The Macmillan Company, New York, 1947.
- Chamberlin, William Henry. *The Russian Enigma*, Charles Scribner's Sons, New York, 1943.
- Chamberlin, William Henry. *Russia's Iron Age*, Brown and Company, Boston, 1935.
- Consumers' Cooperatives in the U. S. S. R.*, Centrosoyuz Publishing House, Moscow, 1956.
- Charques, R. D. *A Short History of Russia*, E. P. Dutton and Company, Inc., New York, 1956.
- Clark, Colin. *A Critique of Russian Statistics*, Macmillan and Company Limited, London, 1939.
- Commercial Geography of the U.S.S.R.* Foreign Languages Publishing House, Moscow 1956.
- Crankshaw, Edward. *Cracks in the Kremlin Wall*, The Viking Press, New York 1951.

[222]

- Crankshaw, Edward. *Russia and the Russians*, The Viking Press, New York, 1948.
- Crankshaw, Edward. *Russia without Stalin*, Michael Joseph, London, 1956.
- Dallin, David J. *The Changing World of Soviet Russia*, Yale University Press, New Haven, 1956.
- Dallin, David J. *The Real Soviet Russia*, Yale University Press, New Haven, 1944.
- Dobb, Maurice. *The Soviet Economy and the War*, George Routledge and Sons, Limited, 1941.
- Dobb, Maurice. *Soviet Planning and Labour in Peace and War*, International Publishers, 1943.
- Dobb, Maurice. *Soviet Economic Development Since 1917*, Routledge and Kegan Paul, Limited, London, 1953.
- Dunn, R. W. & Wallace, G. *Life and Labour in Soviet Union*, International Publishers, New York, 1937.
- Duranty, Walter. *A short History of the U. S. S. R.*, Hamish Hamilton, London, 1944.
- Eastman, M. *Stalin's Russia and the Crisis in Socialism*, W. W. Norton and Company, Inc., New York, 1940.
- Fischer, Louis. *Russia Revisted*, Jonathan Cape, London, 1957.
- Gunther, John. *Inside Soviet Russia*, Hamish Hamilton, London, 1958.
- Gunther, John. *Inside Europe*, Hamish Hamilton, London, 1937.
- Hubbard, L. E. *Soviet Labour and Industry*, Macmillan and Company Limited, London, 1940.
- Hubbard, L. E. *Soviet Trade and Distribution*, Macmillan and Company Ltd., London, 1938.
- Kulski, W. W. *The Soviet Regime*, Syracuse University Press, Syracuse, 1956.
- Kursky, A. *The Planning of the National Economy of the U. S. S. R.*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1949.
- Karpinsky, V. *How The Soviet Union is Governed*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954.
- Khrushchov, N. S. *For Victory in the Peaceful Competition with Capitalism*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1959.

Bibliography]

[२५०]

- Larov, V. *The Soviet Budget*, Foreign languages, Publishing House, Moscow, 1959.
- Lenin, V. I. *Selected Works*. Vols. I-XII, Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the U. S. S. R. Moscow-Leningrad, 1934.
- Lenin, V. I. *The Development of Capitalism in Russia*, Foreign Languages Publishing House, 1956.
- Miller, Jacob. *Soviet Russia*, Hutchinson's University Library, London, 1955.
- National Economy of the U. S. S. R.* Statistical Return, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1957.
- Pares, Sir Bernard. *A History of Russia*, Jonathan Cape, London, 1926.
- Rubinstein, M. I. *Soviet Science and Technique in the Service of Building Communism in the U.S.S.R.*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954.
- U.S.S.R. Reference Book*, The Information Department of the U.S.S.R. Embassy in India, New Delhi, 1957.
- Reddaway, W. B. *The Russian Financial System*, Macmillan and Company Limited, London, 1935.
- Rothstein, Andrew. *A History of the U. S. S. R.* Penguin Book, 1950.
- Salisbury, Harrison E. *Stalin's Russia and After*, Macmillan, London, 1955.
- Schuman, Frederick L. *Russia Since 1917*, Alfred A. Knopf, New York, 1957.
- Schwartz, Harry. *Russia's Soviet Economy*, Jonathan Cape, London, 1951.
- Sethe, Paul. *A Short History of Russia*, Gateway Editions, Inc., Chicago, 1956.
- Shabad, Theodore. *Geography of the U. S. S. R.* Columbia University Press, New York, 1951.
- Stalin, Joseph. *Problems of Leninism*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1953.
- Strumilin, S. G. *Planning in the Soviet Union*, Information Department of the U. S. S. R. Embassy in India, New Delhi, 1957.
- Strauss, E. *Soviet Russia*, John Lane, London, 1941.

Sydney and Webb, *Soviet Communism : A New Civilization*, Longmans Green and Company, London, 1936.

Turin, S. P. *The U. S. S. R.* Methnew and Company, London, 1944.

Watson, Hugh Seton. *From Lenin to Malenkov*, Frederick A. Praeger, New York, 1953.

Yefanov, V. *National Question and the Community of Nations in the U. S. S. R.* Information Department of the U. S. S. R. Embassy in India, 1958.

Zhinerin, D. G. *Economy of the Soviet Union, Past and Present*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1958.

Statesman's Year Book ;

Encyclopaedia Britannica ;

Bulletin : Institute for the Study of the

U. S. S. R. Munich, Germany ;

Langer's W. L. Encyclopaedia of World History ;

Various Publications of Foreign Languages

Publishing House, Moscow.

The University Library

ALLAHABAD

283600

Accession No.....

Call No..... 332-H

Presented by..... W. H. S. 10.4